# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

**अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चौतीसवां दिवस [संख्या: 14**

**बुधवार,**

**26 फरवरी 2020**

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

### एम-सैण्ड उद्योगों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

**198. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उपरान्त नदियों से बजरी निकासी पर पूर्ण रूप से रोक होने के कारण एम-सैण्ड का उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार एम-सैण्ड उद्योगों को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस गाइड लाइन के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में बजरी के संकट से निपटने के लिए सरकारी विभागों में नवीन कार्यों के निर्माण के लिए एम-सैण्ड के उपयोग का प्रावधान लागू करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार प्रदेश में बजरी संकट को दूर कर एम-सैण्ड उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उक्त उद्योग लगाने पर लागत पूंजी एवं ब्याज पर छूट देने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में नदी-नालों में बिना रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी एवं पर्यावरण क्लियरेंस के खनिज बजरी के खनन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के रोक के आदेश के पश्चात् निर्माण कार्यों में बजरी के विकल्प के रूप में एम-सैण्ड का उपयोग हो रहा है। प्रदेश में एम-

(उद्योग मंत्री)

सैण्ड का उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए राजस्थान एम-सैण्ड नीति विचाराधीन है।

(2) सरकारी विभागों में नवीन कार्यों के निर्माण के लिए एम-सैण्ड के उपयोग के सम्बन्ध में समुचित प्रावधान विचाराधीन राजस्थान एम-सैण्ड नीति में प्रस्तावित किये गये हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2019 से राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2019 लागू की गई है जिसमें एम-सैण्ड क्षेत्र को विनिर्माण थ्रस्ट सैक्टर्स की सूची में सम्मिलित किया गया है। एम-सैण्ड विनिर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये या अधिक का निवेश करने वाले उद्यमों को प्लाण्ट एण्ड मशीनरी क्रय करने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से लिए गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (पांच वर्षों के लिए तथा अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक) अथवा प्लाण्ट एण्ड मशीनरी पर किए गए निवेश का 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान (अधिकतम 25 लाख रुपये तक) अतिरिक्त परिलाभ के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में समुचित प्रावधान विचाराधीन राजस्थान एम-सैण्ड नीति में प्रस्तावित किये गये हैं।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगी। मेरा प्रश्न नंबर-1 है, प्रदेश में एम-सैण्ड के उद्योग किस-किस जिले में कब-कब से संचालित हैं तथा इन उद्योगों के संचालन हेतु कितना-कितना अनुदान सरकार द्वारा कब-कब दिया गया?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एम-सैण्ड की नयी पालिसी अभी विचाराधीन है और पहले से जो जिलेवाइज उद्योग हैं, वह करीब 47 उद्योग प्रदेश में स्थापित हैं खान विभाग की सूचना के अनुसार और इसमें काफी, अभी हमने जो नयी पालिसी जारी की है उसमें एम-सैण्ड को थ्रस्ट सैक्टर के रूप में विकसित करने का भी प्रावधान है और यह बजरी की रोक के बाद, अध्यक्ष महोदय, एक तरह से विकल्प के रूप में इस नीति में हम ला रहे हैं और जल्दी ही इस नीति को हम जारी करेंगे।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): दूसरा मेरा सवाल है, इन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

उद्योगों से कितनी-कितनी एम-सैण्ड का उत्पादन हुआ एवं इससे सरकार को रायल्टी की कितनी-कितनी राशि प्रति उद्योगवार प्राप्त हुई? यह बताने का कष्ट करें।

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो खान विभाग की जो सूचना मैंने मंगवाई है, उसके अनुसार 90.73 लाख मैट्रिक टन इसमें अभी वार्षिक उत्पादन हो रहा है और इसकी कितने उद्योगों को क्या दी, वह सूचना अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वैसे तो माइंस से है। माइंस विभाग इसकी पालिसी बना रहा है और वही इसको जारी करेगा, फिर भी मैंने माननीय सदस्या की जानकारी के लिए सूचना मंगवाई है और इसमें बहुत ज्यादा निवेश करने की जो हमारी एमएसएमई पालिसी आई है नयी, एमएसएमई एक्ट आया है नया, उसके बाद मुख्यमंत्री लघु उद्योग रोजगार योजना में हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और भी ज्यादा अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ तक का जो एमएसएमई में इसमें लगाएगा एम-सैण्ड में उसको हम 6 परसेंट तक सब्सिडी देंगे और उससे अधिक 5 करोड़ से 10 करोड़ का निवेश होगा, उसको हम पांच परसेंट सब्सिडी पांच वर्ष तक देंगे इसलिए इसको काफी गंभीरता से ले रही है सरकार।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, लास्ट सवाल है मेरा। क्या यह सही है कि इन उद्योगों की आड़ में हाई कोर्ट की रोक होने के बावजूद भी बजरी का अवैध खनन लगातार हो रहा है? चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करें, चाहे जो लगातार अखबारों में आ रहा है साहब, पूरे प्रदेश में।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, खनिज मंत्री का प्रश्न आ गया। माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो एम-सैण्ड है, क्या राज्य सरकार यह कहने की स्थिति में है कि जितने भी सरकारी काम राजस्थान में चल रहे हैं, वहां सब जगह इसी रेती का उपयोग होता है या अन्य रेती का भी उपयोग होता है? अगर होता है, तो क्या वह अधिकृत है?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी रोक केवल नदी-नालों की बजरी पर है, बाकी निजी खातेदारी में सरकारी लैंड में बहुत सारी, माइंस विभाग से जो जानकारी आई है, बहुत सारी उन्होंने बजरी की

(श्री परसादी लाल)

लीज दे रखी है। अगर वहां से सरकारी विभागों को बजरी अवेलेबल हो तो सरकार को इसमें क्या एतराज है? जहां बजरी नहीं मिलेगी वहां एम-सैण्ड का उपयोग करें सरकारी विभाग। प्रतिबंधित सरकार नहीं कर सकती कि आपको एम-सैण्ड ही लगाना पड़ेगा। जो लीज हमने जारी कर रखी है निजी खातेदारी में गवर्नमेंट लैंड पर, वहां से बजरी का अगर सरकारी कामों में उपयोग हो तो सरकार को क्या एतराज है?

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा कहना यह है कि आप और हम सब लोग इस चीज से परिचित हैं कि जो हमारे सरकारी काम चल रहे हैं, उन पर भी बजरी इन बजरी माफियाओं के द्वारा ही ठेकेदारों को सप्लाई की जा रही है। यह सत्य है। मानें न मानें, वह अलग बात है, लेकिन यह सत्य है तो क्या इस प्रकार के किसी स्थान पर चलने वाले काम का रिकार्ड चैक करके यह आप कहने की स्थिति में हो कि इसमें जितनी भी रेती का उपयोग हुआ है यह अधिकृत रेती ही यहां आई है?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष की भावना बहुत ठीक है और इस पर हम विचार करेंगे। सरकारी कामकाज में एम-सैण्ड का ही उपयोग करें, इस पर हम निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय जल्दी लेंगे।

## प्रश्न संख्या-199

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री गिरधारीलाल।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

## जिला क्षय चिकित्सालय को पुन: ब्यावर स्थानान्तरित करने की योजना

**200. श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में पत्थर पीसने की फैक्ट्रियों का मण्डी हब होने के कारण यहां सिलिकोसिस एवं क्षय रोग के मरीजों की संख्या अधिक है?

(2) जिला क्षय चिकित्सालय ब्यावर को अजमेर स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय ब्यावर को अजमेर स्थानान्तरित करने से उक्त मरीज अजमेर जाकर इलाज नहीं करा पाने के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को पुन: ब्यावर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां।

(2) जिला क्षय निवारण केन्द्र, ब्यावर को अजमेर स्थानान्तरण नहीं किया गया है। जिला क्षय निवारण केन्द्र, ब्यावर में ही स्थापित एवं निरन्तर संचालित है।

(3) जी नहीं। ब्यावर क्षेत्र के सभी क्षय रोगियों का इलाज ब्यावर में संचालित जिला क्षय निवारण केन्द्र, ब्यावर में किया जा रहा है।

(4) जिला क्षय निवारण केन्द्र, ब्यावर में ही स्थापित एवं निरन्तर संचालित है।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने जवाब दिया है, मैंने पूछा था जिला क्षय रोग चिकित्सालय और आपने जवाब दिया है जिला क्षय निवारण केन्द्र, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आपसे आग्रह है कि जिला क्षय रोग चिकित्सालय ब्यावर में ही बना हुआ है और वह अजमेर शिफ्ट कर दिया गया है, क्या वापस आप उसको ब्यावर शिफ्ट करोगे या नहीं? और करोगे तो कब करोगे?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि जिला क्षय निवारण केन्द्र ब्यावर में ही कार्यरत था और ब्यावर में ही कार्यरत है और ब्यावर में ही कार्यरत रहेगा सिर्फ इसमें एक परिवर्तन यह किया गया है कि जो पुराना भवन बना हुआ था वह जर्जर हो गया था और उस भवन के जर्जर होने की स्थिति में क्योंकि एमसीएच की नई विंग वहां बन गई है तो एमसीएच की विंग उसमें शिफ्ट कर दी, तो जो खाली भवन था अस्पताल परिसर के अंदर ही, उसमें से 7 कमरों में जिला क्षय निवारण केन्द्र चल रहा है आज भी, सिर्फ जो मशीन है, जो

(श्री रघु शर्मा)

किस प्रकार की टीबी हुई है मरीज को, उसकी जांच करती है, सीबी नोट वह मशीन, एक कमरा ठीक है पुरानी बिल्डिंग में, वहां कार्यरत है और दोनों की डिस्टेंस सौ या पचास मीटर के करीब है इसलिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हो केन्द्र और मैं कह रहा हूं जिला क्षय रोग कार्यालय वहां बना हुआ था पुराना और उसी में चल रहा था वह। अधिकारी सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए अजमेर बैठे रहते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): इसको क्लियर करें थोड़ा। आप वह ब्यावर में लगाने के लिए करें।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं आपका जो भी जिला क्षय निवारण केन्द्र है,...

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): आप केन्द्र का कह रहे हैं।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अस्पताल है। केन्द्र क्या होता है?

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): केन्द्र अलग होता है।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केन्द्र अलग क्या होता है? बताओ आप मुझे। जबर्दस्ती बात कर रहे हो।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मंत्री जी कह रहे हैं कि केन्द्र, तो कार्यालय सम्मिलित हैं, क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं आप बिना मतलब।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वहीं सारी सुविधाएं हैं। इनकी चिंता यह है कि वहां सिलिकोसिस और टीबी के मरीज ज्यादा हैं तो उनका इलाज वहीं हो और वह हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है।

## प्रश्न संख्या-201

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न स्थगित किया गया। 5 तारीख को आएगा। श्री गोविंद राम जी का प्रश्न।

**(स्थगित)**

अगला प्रश्न, श्री चेतन सिंह चौधरी।

## डीडवाना में वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

**202. श्री चेतन सिंह चौधरी** (डीडवाना): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियां कहां-कहां पर कितनी-कितनी हैं? क्षेत्रफल, कच्चे-पक्के निर्माण व बाजार में प्रचलित अनुमानित कीमत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उक्त क्षेत्र में वक्फ सम्पत्तियों पर बहुत्सी जगह अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि व सम्पत्ति पर किन-किन लोगों द्वारा कब से अतिक्रमण किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध विगत पांच वर्ष में प्राप्त शिकायतों व उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने व अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**वक्फ मामलात मंत्री** (श्री शाले मोहम्मद): (1) डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की 212 वक्फ सम्पत्तियां राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हैं तथा राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् वक्फ रिकार्ड में बतौर जदीद (नई) पंजीकृत 05 वक्फ सम्पत्तियां हैं, जिनकी सूची परि. अ/1 एवं अ/2 पर संलग्न है। इस प्रकार डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में कुल 217 वक्फ सम्पत्तियां वक्फ रिकार्ड में पंजीकृत हैं। इनमें 61 मस्जिद, 82 कब्रिस्तान, 21 दरगाह एवं मजार, 10 तकिया (विश्राम स्थल) एवं 43 अन्य वक्फ सम्पत्तियां दर्ज हैं। संलग्न सूचियों में वक्फ सम्पत्ति के नाम के साथ ही क्षेत्रफल भी अंकित है। वक्फ सम्पत्तियां पवित्र, धार्मिक एवं परोपकारी कार्य हेतु होती हैं तथा वक्फ सम्पत्ति का बेचान नहीं किया जा सकता है इसलिए वक्फ सम्पत्तियों की कीमत सम्बन्धी रिकार्ड का संधारण नहीं है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र की कुल 12 वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण है। पूर्ण विवरण सूची परि. ब/1, ब/2 व ब/3 पर संलग्न है।

(3) गत 05 वर्ष में डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में स्थित वक्फ सम्पत्ति पर अतिक्रमण की शिकायत सूची परि. ब/1 प्राप्त हुई है, जिस पर केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2013) की धारा-54 के तहत मुख्य

(वक्फ मामलात मंत्री)

कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई है परन्तु माननीय न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण द्वारा इससे सम्बन्धित प्रकरण संख्या-13/2017 में पारित स्थगन आदेश दिनांक-28/03/2017 के कारण निर्णय पारित नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2006 में दर्ज 08 प्रकरण जिनकी सूची परि. ब/2 पर संलग्न है, में अतिक्रमियों के खिलाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा बेदखली का आदेश पारित उपखण्ड दण्डनायक डीडवाना नागौर को कब्जा दिलाने हेतु प्रकरण प्रेषित कर दिये गये। तत्पश्चात् समय-समय पर जिला कलेक्टर नागौर एवं उपखण्ड दण्डनायक डीडवाना को भी लिखा गया है, जिसकी सूची परि. स पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र की वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परि. ब/3 पर संलग्न है। इन शिकायतों के सम्बंध में जिला कलेक्टर नागौर को अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखे गये हैं। सूची परि. द पर संलग्न है।

(4) जी हां। केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-54 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा उभय पक्षकारान को प्रकरणों में सुनवाई हेतु उचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाता है। तत्पश्चात् प्रकरण केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 54(4) (संशोधित-2013) अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

सूची ब/1 में अंकित प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण न्यायालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड के समक्ष लम्बित है।

सूची ब/2 में अंकित 8 प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा बेदखली के आदेश पारित कर कब्जा दिलवाने हेतु उपखण्ड दण्डनायक डीडवाना को प्रकरण प्रेषित किये गये हैं।

सूची ब/3 के क्रम में जिला कलेक्टर नागौर को कार्यवाही हेतु विभाग द्वारा लिखा गया है।

अतिक्रमण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही शीघ्र करवाने हेतु विभाग प्रयासरत है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री चेतन सिंह चौधरी** (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, उत्तर के खण्ड 2 में परिशिष्ट ब-3 पर मेरे पास तीन नामों की एक सूची है, जिसमें जो काबिज व्यक्ति हैं, एक नंबर पर स्थानीय निवासी बताया गया, दो नंबर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग बताया गया और तीन नंबर पर स्थानीय निवासी बताया गया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो एक और तीन नंबर पर स्थानीय निवासी हैं, उनके नाम आपके पास हैं या नहीं हैं? विभाग के पास यह जानकारी है या नहीं है कि वह स्थानीय निवासी कौन हैं?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, बी-3 पर जो अनुसूची दी है, उसमें हमने इनको बाकायदा लिस्ट भी दी है।

**श्री अध्यक्ष**: परिशिष्ट ब-3 में अतिक्रमियों का नाम पूछा है और आपने उसमें लिखा है स्थानीय निवासी, वह इनके नाम पूछ रहे हैं।

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): मैं उसके लिए माननीय सदस्य को बता रहा हूं, नाम मैं इनको अलग से दे दूंगा। दूसरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना द्वारा किया गया था, उसमें जो दरगाह के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें संबंधित विभाग को हमने पाबंद किया...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, उन्होंने सीधा प्रश्न पूछा है ब-3 में जो आपने लिखा है उसमें दो में लिख रखा है स्थानीय निवासी। वह पूछ रहे हैं कि स्थानीय निवासियों के नाम क्या हैं, सीधी बात है।

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको अलग से सूची उपलब्ध करा दूंगा। (व्यवधान) आप सुनो पहले, सुनो। अध्यक्ष महोदय, आप भी वक्फ मंत्री रहे हैं, पांच साल तक आपने कुछ किया नहीं उसमें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का जवाब।

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो स्थानीय निवासियों की सूची मांगी है, वह मैं अलग से माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी अतिक्रमण करते हैं, पहली बार हमने पूरे वक्फ को 100 परसेंट रिजर्वेशन किया है और इसके साथ जितनी भी हमारी सम्पत्ति हैं, उनको हम जियो टैगिंग कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय, उन्होंने पहला सप्लीमेंट्री पूछा है, स्थानीय है या नहीं है, फिर उनको दूसरा प्रश्न पूछने दें, बैठें आप। दूसरा प्रश्न पूछें।

**श्री चेतन सिंह चौधरी** (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, ब-3 में तीन नंबर पर खसरा नंबर 3006 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, इसमें मेरी जानकारी यह है कि यह खसरा नंबर रेवेन्यू रिकार्ड और बर्थ रिकार्ड, दोनों में वक्फ के नाम पर बोलता है। अगर यह बात सही है तो यह बताने की कृपा करें कि क्या इसके एक भाग की किन्हीं निजी व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई है? यह बात अगर आपकी जानकारी में है तो उन लोगों के नाम बताएं, जिनके नाम रजिस्ट्री हुई है और अगर रजिस्ट्री हुई है तो उन लोगों और उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की होगी जिन्होंने रजिस्ट्री की और जिन लोगों के नाम रजिस्ट्री हुई है।

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वक्फ सम्पत्ति की कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती है क्योंकि इसमें जो सम्पत्तियां होती हैं। वह दानदाताओं द्वारा या सम्पत्ति में सब लोग ट्रस्टी के रूप में होते हैं, या तो वह लीज पर दी जाती है या विभाग के द्वारा किराया नीति है, उस किराये पर दी जाती है। इसलिए अभी तक किसी भी वक्फ सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है।

**श्री चेतन सिंह चौधरी** (डीडवाना): अध्यक्ष जी, मेरा पूछना यह था कि यह जो खसरा नंबर 3006 है, इसके एक भाग की निजी लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है, उन लोगों की जानकारी अपने पास है क्या कि किनके नाम रजिस्ट्री हुई है? और किन अधिकारियों ने की है और अगर की है तो उनके खिलाफ विभाग कोई कार्यवाही करेगा?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माननीय सदस्य को निवेदन किया है कि वक्फ की किसी भी सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है। किसी भी सम्पत्ति को लीज पर दिया जा सकता है या उसको किराये पर दिया जा सकता है। यदि कोई ऐसी शिकायत इनके पास है तो वह मुझे दें, उसकी जांच हम करायेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगल प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

## सामूहिक विवाह पर देय अनुदान

**203. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) क्या यह सही है कि विवाह समारोह में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एवं सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा सामूहिक विवाह अनुदान योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो दी जाने वाली अनुदान राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत वर्ष 2019 में कितनी संस्थाओं ने कब-कब अनुदान हेतु आवेदन दिया, उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए व कितने आवेदन किन कारणों से लम्बित हैं तथा कितनी संस्थाओं को अनुदान की राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास** (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। यह सही है कि विवाह समारोह में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 के अन्तर्गत सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत संस्था को प्रति जोड़ा अनुदान राशि रु. 18,000/- देय है, जिसमें से 15,000 हजार रुपये वधू को व 3,000 हजार संस्था को अनुदान देय है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षो में सामूहिक विवाह अनुदान योजना को बढ़ावा देते हुए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की जाएगी।

(3) सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले एक वर्ष 2019 में 309 संस्थाओं द्वारा जिन तिथियों पर अनुदान हेतु आवेदन किये गये, इसकी सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है, 214 संस्थाओं के आवेदन स्वीकृत हुए 159 आवेदन लम्बित हैं। इनके लम्बित होने के कारणों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

50 संस्थाओं को अनुदान की राशि प्राप्त हुई है। सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अध्यक्ष जी, परिशिष्ट-अ आपके पास भी रिप्लाई में है, इसमें विभाग द्वारा अधूरी सूचना दी गई है, क्योंकि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसमें इन्होंने लिखा है कि सामूहिक विवाह में कितने जोड़े आये, अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि कितने जोड़े होने पर यह सामूहिक विवाह मानेंगे कि इतने जोड़े अगर संस्था देती है तो इसको सामूहिक विवाह का लाभ मिल सकता है? पहला। इसी में इन्होंने अधूरी जानकारी दी है, आप परिशिष्ट-अ को देखेंगे तो इसमें 10 नंबर तक तो इन्होंने लिखा कि 21 जोड़े स्वीकृत हैं, 11 के बाद इन्होंने सिर्फ स्वीकृत, स्वीकृत लिख दिया, अस्वीकृत लिख दिया। कितने जोड़े हैं कहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। इस प्रकार से एक तो अधूरी सूचना जवाब में दी है। स्वीकृत लिखा है लेकिन कितने जोड़े आये, क्या हुआ, यह सब कुछ नहीं लिखा।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें आप।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहूंगी कि अगर परिशिष्ट-अ को देखेंगे तो 309 कुल संख्या है। 309 में से यह जानना चाहूंगी कि कितने स्वीकृत हुए कितने अस्वीकृत हुए? कुल कितने जोड़े उसमें स्वीकृत हुए, कितने अस्वीकृत हुए और उनमें कितनों के भुगतान कर दिये गये और कितने प्रक्रियाधीन हैं, पहला तो यह प्रश्न, फिर बाद में पूछती हूं।

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 309 संस्थाओं ने आवेदन किया था, उनमें से 214 संस्थाओं को मान्य माना गया, उन 214 संस्थाओं में से 50 का भुगतान कर दिया गया और अभी 159 लम्बित हैं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आप 159 ये देखिए।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न पूछिए।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): यह जो योजना शुरू की गयी, आपने खुद ने जवाब में दिया कि फिजूलखर्ची को बचाने के लिए हम सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। सामूहिक विवाह को जब आप प्रोत्साहन देते हैं और जब संस्थाएं आगे आती हैं, संस्थाएं इस अच्छे काम को करना चाहती हैं तो उनको भुगतान नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछें।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): जिन 159 संस्थाओं का भुगतान नहीं हुआ है उनका कब तक भुगतान करेंगे, क्या उसकी कोई टाइमलाइन है?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 में इसके नियमों का संशोधन किया गया और मुझे सदन को बताते हुए बड़ा दुख है कि इन्होंने जब इसमें संशोधन किया तो उसके अंदर इतनी जटिलताएं कर दीं कि जो संस्थाएं मान्य नहीं हो पा रही हैं, 15 दिन के अंदर जोड़ों को अपना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, जो कि अव्यावहारिक लग रहा है। मुझे इस समय सदन को बताते हुए हर्ष है कि हम लोग आनलाइन प्रक्रिया कर रहे हैं। जो इन्होंने जटिलताएं कीं संस्थाओं को सामूहिक विवाह के लिए आवेदन करने के लिए, उन जटिलताओं का सरलीकरण किया जा रहा है। इन्होंने जो 15 दिन किये, उनको हम 60 दिन करने जा रहे हैं। हमारी ये सभी जटिलताएं शीघ्र अच्छी हो जाएंगी, जिससे इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह योजना सरकार द्वारा की जाती है, इसके अंदर संस्थाओं को फायदा मिलेगा। जोड़े लाभान्वित होंगे, यह हम लोग अभी कर रहे हैं। माननीय सदस्या ने जो 159 संस्थाओं की चर्चा की है, उनमें 90 परसेंट संस्थाओं की प्रक्रिया पूरी नहीं है, जिसकी सूची इसमें है। जैसे 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं दिये हुए, संस्थाओं ने अपनी पूरी जानकारी नहीं दी। जो लम्बित प्रकरण हैं, संस्थाओं और जोड़ों के रजिस्ट्रेशन की और जो मैरिज सर्टिफिकेट अभी जमा नहीं कराए, जो पूर्व सरकार ने 2017 के संशोधन में सिर्फ 15 दिन दिये थे, उस वजह से ये लम्बित हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बित होने का कारण यह है कि 2018-19 में जब इनकी सरकार थी तो 5 करोड़ 84 लाख रुपये इन्होंने लम्बित छोड़े और हम लोगों ने अभी लगभग साढ़े छह करोड़ रुपये दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री जी बैठें। अगला प्रश्न, श्री जगसी राम। यह कोई तरीका नहीं है। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, मंत्री बोल रहे हैं। कटारिया जी, माफ करें। I will not allow it. आप लीडर हैं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री जी को सुनना नहीं चाहें। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। माननीय सदस्या को आप बताएं। आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, इनका काम तो मैं नहीं कर सकता हूं। आप लीडर हैं, आप पूछें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं। बहुत लंबी बात नहीं है। कोई समस्या या जटिलता होगी, वह तो बाद की बात है। आपने जिन 214 को स्वीकृत कर लिया, उसमें से 50 को ही आपने अनुदान क्यों दिया? क्या बाकी को देने में आर्थिक संकट है?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही चीज बताना चाह रही थी कि वित्त विभाग ने हमें पैसा दिया और 2018-19 की पैंडेंसी में ये लोग 5 करोड़ 84 लाख रुपये की पैंडेंसी छोड़कर गये थे तो पहले तो हमने 4 करोड़ रुपये वे भरे हैं। ये पैंडेंसी नहीं छोड़कर जाते तो हम तो 214 को पूरा पैसा दे चुके होते। इनकी पैंडेंसी, जो ये कुआ खोदकर गये, चारों सालों में इन्होंने बकाया पैसे छोड़े, कभी 3 करोड़, कभी 4 करोड़, कभी 5 करोड़, तो हमको तो उनको पूरा करना है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहती हूं कि वित्तीय प्रबंध होते ही हम तुरंत इन जोड़ों की अनुदान राशि भी स्वीकृत कर देंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): कोई भी सरकार हो, पैंडेंसी छोड़ती है, क्या करती है, वह अपने साथ चली गयी। पैंडेंसी क्या है, कितनी है? इस भाषण से काम नहीं चलेगा। यह बताइये कि जब आपने 214 को स्वीकृत कर दिया तो यह आपकी और विभाग की जिम्मेदारी है या नहीं है? किसने किया, क्या किया, वह छोड़िये। यह 214 जो संस्थाएं हैं, जो कि आपने अधिकृत मानी हैं, उनमें से केवल और केवल 50 को ही पैसे क्यों दे पाए? क्या फाइनेंस ने आपको पैसा नहीं दिया?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 संस्थाओं की पेपर कार्यवाही पूरी थी, जिनको तुरंत दे दिया गया था, बाकी जो 214 हैं, वे प्रक्रियाधीन हैं, जैसे ही विभाग के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, हम तुरंत उन संस्थाओं को भी भुगतान कर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री जगसी राम।

## रेवदर के जनजाति छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण

**204. श्री जगसी राम** (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावास, कालेज छात्रावास, प्रतिष्ठित विद्यालयों में जनजाति छात्र-छात्राओं के अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण, खेल प्रतिभाओं के विकास आदि योजनाओं के तहत जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित समयावधि में लाभान्वित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों प्रतियोगी परीक्षाओं के पात्र उम्मीदवारों को उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य सीमा तक लाभान्वित करने की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास** (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी नहीं। विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु आवासीय विद्यालयों, आश्रम छात्रावास व खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए छात्रावासों का संचालन कर उसमें छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| **आश्रम/खेल छात्रावास का नाम** | **छात्र-छात्रा संख्या** |
|---|---|
| आश्रम छात्रावास, सांतपुर | 100 छात्र |
| खेल छात्रावास, सांतपुर, बालक | 50 छात्र |
| खेल छात्रावास, सांतपुर, बालिका | 75 छात्राएं |
| आश्रम छात्रावास, गिरवर, बालक | 130 छात्र |
| कन्या आश्रम छात्रावास, मानपुर | 145 छात्राएं |
| एकलव्य माडल रेजिडेन्शियल स्कूल, दानवाव | 421 छात्र |

जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के माध्यम से समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लाभान्वित किया जाता है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं बिखरी क्षेत्र में जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों प्रतियोगी परीक्षाओं के पात्र उम्मीदवारों को लाभान्वित करने के लिए निम्न योजनाएं हैं:-

**स्कूल व कालेज में अध्ययनरत जनजाति वर्ग छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने की योजनाएं:-**

**1. प्रतिभावान छात्रवृत्ति**

जनजाति वर्ग के कक्षा 10, 12, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को राशि रु. 350 प्रति माह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

**2. छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता**

जनजाति छात्राओं को महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 500 रु. प्रति माह की दर से 10 माह तक सहायता दी जाती है।

**3. कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को आर्थिक सहायता**

जनजाति वर्ग की कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 350 रु. प्रति माह की दर से 10 माह तक सहायता दी जाती है।

**4. नि:शुल्क स्कूटी वितरण**

बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 65 प्रतिशत अथवा अधिक अंक लाने पर नि:शुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है।

**5. छात्र गृह किराया (अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत छात्र-छात्राओं हेतु)**

स्नातक एवं स्नातकोतर कक्षाओं में अध्ययनरत जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को संभाग मुख्यालय पर रु. 500, जिला मुख्यालय पर रु. 400 तथा अन्यत्र स्थान पर रु. 300 प्रति माह की दर से 10 माह की राशि का मकान किराये हेतु पुन: भरण किया जाता है।

**खिलाड़ियों हेतु संचालित योजना**

1. दो खेल छात्रावासों क्रमश: सांतपुर बालिका एवं खेल छात्रावास, सांतपुर, बालक संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

**प्रतियोगी परीक्षाओं के पात्र उम्मीदवारों हेतु योजना**

1. विभागीय अधीनस्थ कार्यालय माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा समय-समय पर राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग व केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु विशेषज्ञ अध्यापकों से कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री जगसी राम** (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है, वह बहुत ही गोलमोल दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मैंने बिंदु संख्या 1 में जो पूछा है कि जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के दौरान टीएसपी ग्राम पंचायतों के अंदर जनजाति छात्राओं में प्रतिभावान छात्राओं को छात्रावास आबंटित किये गये हैं, इसकी जानकारी मैंने पूछी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गिरवर, मानपुर और दानवाव छात्रावास हैं, इन छात्रावासों के अंदर क्षमता से अधिक जो बालक प्रवेश करना चाह रहे हैं, क्या मंत्री जी इन छात्रावासों के अंदर, आपने जो एक साल की योजना बनायी कि आने वाले समय के अंदर टीएसपी क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को लाभ देने के लिए आपने कोई योजना बनायी हो तो बताएं।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, संख्या को अधिक बढ़ाने के लिए उसका परीक्षण कराकर उसकी व्यवस्था के अनुरूप उसको भर्ती किया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा प्रश्न को पढ़ रहा हूं, उसके अनुसार उत्तर चाहिए था। जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित समयावधि में लाभान्वित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें। इसमें तो कहीं दिखता नहीं है, मेज पर तो है नहीं। यह विवरण कहां पर है? आपके पास हो तो आप पढ़ो, हमारे पास तो है नहीं।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विवरण इन छात्रावासों में दिये गये हैं। इसके अलावा, हम समय-समय पर जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हैं। अभी भी टीआरआई के अंदर 18 तारीख से पुलिस की कोचिंग का सेंटर चल रहा है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): पहले जो बात पूछ रहा हूं, वह बताओ। इन छात्रों को पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला तो वे कौन बच्चे हैं, जिनको नहीं मिला? यदि मिला है, तो बता दो मिला।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, यह तो ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माफी चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: कटारिया जी, एक मिनट आप बैठिए। मंत्री जी।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतियोगी परीक्षा के पात्र उम्मीदवारों में से माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने पर विज्ञप्ति जारी कर अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग से जो प्रतियोगी परीक्षा में योग्यता पूर्ण करते हैं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी, एक सीधा प्रश्न है लाभान्वित, कितने बेनिफिट हुए हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। आप जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक, ये जो अलग-अलग आपने बताई हैं, उसमें कितने बालक लाभान्वित हुए, उसकी संख्या पूछ रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): इसमें लिपिक गणना में 30, द्वितीय ग्रेड 154, अध्यापक ग्रेड 120 एवं स्कूल व्याख्याता में 60, फाउंडेशन कोर्स में 39, पुस्तकालय ग्रेड में 32...

**श्री अध्यक्ष**: ये तो लाभान्वित किये गये हैं। कितनों को नहीं किया, वह संख्या बता दें। माननीय मंत्री जी, दो तरह का है, एप्लीकेंट इतने थे, इतने लाभान्वित हुए, इतने आदमी लाभान्वित नहीं हो पाए, ये स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक जितने बच्चे एलीजिबल थे, संख्या बता दी है आपने, दे दी, कितने बच गये, उनके बारे में पूछ रहे हैं।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। यहां जो ...(व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, क्या मजाक कर रखा है? ये हाउस है या मजाक है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): कोई तैयारी करके आते नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री जी खड़े हैं, आप बैठो तो सही। ये कोई तरीका है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब क्या है? हम प्रश्न पूछते हैं। हर कोई खड़ा होता है कि पता नहीं है, पता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। प्लीज बोलिए। अपनी पूरी बात बोलें।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा आवेदन लिया जाता है, जो हमारे वहां आता है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): कितने हैं, आप यह बता दें।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैं बता रहा हूं आपको सारे ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। कोई आवेदन बाकी नहीं है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो सूची मांगी है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे को प्रोटेक्ट कीजिए। यह प्रश्न को जिस हल्केपन में लेते हैं, न तो पूरा पढ़ते हैं और न पढ़ने के अनुसार उत्तर बनाते हैं। बहुत सीधे-से पूछा है कि वे कौन लोग हैं, जो इसमें वर्णित हैं, उनकी सूची दे दीजिए। अगर नहीं है, तो कहिए कि एक भी व्यक्ति इसमें से बाकी नहीं रहा। यह सूची थी, इस सारी सूची को दे दिया गया। दो ही तो प्रश्न के जवाब हैं। तैयारी करते नहीं हैं और आ जाते हैं।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। यह भाषण नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): हमारे पास में आए आवेदन वह हमने उपलब्ध करा दिए। कोई भी ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्लीज, आप बैठिए। मंत्री जी बोल रहे हैं। नहीं सुनना है? अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

## तिजारा में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर रोक

**205. श्री संदीप कुमार** (तिजारा): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा भारी प्रदूषण फैलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, वन** (श्री सुखराम विश्नोई): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा भारी प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संज्ञान में नहीं है। तथापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है जिसके दौरान कतिपय उद्योगों द्वारा अवहेलना/प्रदूषण करते हुए पाये गये उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संदीप कुमार** (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। कई बार इफका के चेयरमैन ने भी लगातार फटकार लगाई है और स्विस बेस्ड कंपनी के एयरविजुअल एंड ग्रीन पीस के आंकड़ों के अनुसार भिवाड़ी का वर्ल्ड में पांचवां स्थान है एयर पाल्यूशन में। इसके अलावा..

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, सीधे प्रश्न पूछिए।

**श्री संदीप कुमार** (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अधिकारी इसमें गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई फैक्ट्रियां नहीं हैं, जबकि आये दिन अखबारों में ख़बरें लगती हैं, बार-बार इफका के द्वारा, इफका के चेयरमैन ने अभी फरवरी में भी मीटिंग ली थी और उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निवेश कर रहे हैं, क्षेत्र को बर्बाद मत करो। मानव जीवन की कीमत पर विकास बर्दाश्त नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट लगातार अखबारों में आ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

**श्री संदीप कुमार** (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह बड़ी गंभीर समस्या है। इस पर विचार किया जाए। अधिकारी बार-बार आंकड़े झूठे दे रहे हैं, सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न क्या है?

**श्री संदीप कुमार** (तिजारा): मेरा यह प्रश्न है कि जो फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं, उन फैक्ट्रियों के पाल्यूशन पर रोक लगनी चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार रखती है? पाल्यूशन पर रोक लगाने का कोई उपाय करना चाहती है या नहीं चाहती है? बराबर..

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए। भाषण नहीं। माननीय मंत्री जी।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, भिवाड़ी में 904 इकाइयां हैं और 904 इकाइयों के लिए सीईटीपी बनी हुई है। बाकायदा पानी ट्रीट होकर जा रहा है। जो शिकायतें आई हैं, उसमें से करीब 17 शिकायतें आने के बाद में कनेक्शन काटे गये हैं। 4 शिकायतें इसी महीने मिली हैं, पैंडिंग हैं। व्यवस्थित तरीके से जो गंदा पानी है, उसको ट्रीट करके बाहर खेतों में दिया जा रहा है।

**श्री संदीप कुमार** (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, एयर पाल्यूशन की बात हो रही है। एयर पाल्यूशन में भिवाड़ी को पांचवां नंबर दिया गया है। अभी जब 2 दिसम्बर को पूरा विश्व..

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय मंत्री जी, प्रश्न सीधा-सा पूछ रहे हैं कि एयर पाल्यूशन के संबंध में हम कुछ कर रहे हैं क्या? पानी के संबंध में आपने बताया।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): एयर पाल्यूशन में वहां पर तीन मानव चलित और एक सर्विस सेंटर लगा हुआ है। बाकायदा उसमें रोज हवा की जांच होती है।

**श्री संदीप कुमार** (तिजारा): अध्यक्ष जी, अभी इफका के चेयरमैन भूरेलाल जी ने सारे दावों को खारिज किया है। मेरे पास इसका सबूत भी है। इसमें डेटा भी है। तीन दिन-तीन रात तक वह भिवाड़ी में घूमे हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से जो सारा पाल्यूशन है, वह दिखाया है। अभी तक उन अधिकारियों पर हमने कोई कार्यवाही की है क्या?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, उद्योगों

(श्री सुखराम विश्नोई)

द्वारा किये जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा विजिलेंस स्क्वाड का गठन किया गया है। यह अलवर, पाली, जोधपुर, भिवाड़ी सब जगह कार्यवाही कर रही है। साथ ही 496 उद्योगों की जांच करके 9.56 करोड़ की उन पर पैनल्टी की गई है।

## प्रश्न संख्या 206

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न स्थगित किया गया शकुन्तला जी का।

**(स्थगित)**

अगला प्रश्न, श्री कन्हैया लाल।

## मालपुरा में श्रम कल्याण की संचालित योजनाओं में प्राप्त आवेदन

**207. श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में योजनावार कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदन स्वीकार किये गये तथा कितने लम्बित हैं और कितने आवेदनों को निरस्त किया गया? कारण सहित योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के किस-किस ई-मित्र के द्वारा कितने-कितने आवेदन स्वीकृत किये गये हैं? ई-मित्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, श्रम** (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में 01.01.2019 से 31.01.2020 तक की अवधि में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में कुल 3456 आवेदन प्राप्त हुए, 492 आवेदन स्वीकृत, 622 निरस्त, 339 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित तथा 2003 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लम्बित हैं, जिनका योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। मुख्यत: निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना,

(राज्य मंत्री, श्रम)

दस्तावेजों में कांट-छांट होना तथा जांच उपरान्त अपात्र होने के कारण आवेदन निरस्त किये जाते हैं।

(2) जी हां। मंडल द्वारा संवेदनशीलता के मद्देनजर सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। प्रासंगिक है कि शुभशक्ति योजना व सुलभ्य आवास योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हित लाभ देने का निर्णय लिया गया है। आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु मंडल मुख्यालय स्तर पर विशेष कण्ट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसमें अब तक 5.96 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ पद्धति से किया जा रहा है।

(3) निर्माण श्रमिकों का मंडल में पंजीकृत होने के पश्चात् योजनाओं में सिटीजन आई डी/ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर वरीयता व पात्रतानुसार योजना आवेदन स्वीकृत किये जाते हैं। प्रासंगिक है कि आवेदनों की स्वीकृति ई-मित्रों द्वारा नहीं की जाती है। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रस्तुत योजना आवेदनों में स्वीकृत हुए आवेदनों का ई-मित्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शुभ शक्ति योजना के तहत जनवरी, 2019 से जनवरी 2020 के बीच लगभग 328 आवेदन आपके विभाग को प्राप्त हुए, जिसमें से एक का भी निस्तारण नहीं किया गया, इसका क्या कारण है? इसके साथ-साथ निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 2923 आवेदन आए, जिसमें से केवल 405 का निस्तारण किया, बाकी क्यों नहीं हुए, इसका कारण बताइये।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है उसके संबंध में मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जो पैंडिग प्रकरण हैं, यह कोई आज के नहीं हैं। 2015-16 के 6 पैंडिग हैं, 2016-17 के 89 हैं, 2017-18 के 328 हैं, 31.12 से पहले व 01

(श्री टीकाराम जूली)

अप्रैल से 523 हैं। नये प्रकरण 1.1.2019 से आए हैं, वह 131 व 197 हैं, यानी कुल मिलाकर 1274 प्रकरण अब आए हैं। 325 के आस-पास प्रकरण अब के हैं, बाकी 950 के आस-पास प्रकरण हैं, वह पुराने हैं। कोई बात नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा, आपकी लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन जो योजनाएं हैं, उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है। शुभ शक्ति की बात है, शुभ शक्ति में जिन प्रकरणों की जांच की गई उनमें 35 प्रतिशत से अधिक फर्जीवाड़ा था, जिसकी वजह से इसमें डिले हुआ है।

दूसरा, जो प्रकरण है, उनकी पैंडेंसी इतनी ज्यादा थी, मैंने अभी आपको बताया कि 5 लाख 96 हजार प्रकरणों का हमने एक साल में निस्तारण किया है। बीडीओ के यहां आपके सारे प्रकरण पैंडिग थे, वह सारे आए, तब हमने कंट्रोल रूम बनाकर इसकी व्यवस्था की है कि जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण हो।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि निस्तारण नहीं हो रहा, वहां हर प्रकरण के लिए, बच्चियों की शादी के लिए 55 हजार मिलते हैं, 15 हजार से, दलालों का पूरा वह बना हुआ है। जिला स्तर पर गरीब आदमी नहीं जा सकता। पंचायत समिति स्तर पर बीच में जब पावर दिया था, तब बजट नहीं मिल पाया, पंचायत समिति पर आप करने का विचार रखते हैं, जिससे स्थानीय जन प्रतिनिधि, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, उसकी मोनिटरिंग हो, गरीब के साथ अन्याय नहीं हो, इसका विचार रखते हैं कि नहीं रखते?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति स्तर पर, चूंकि विभाग में अधिकारियों की कमी है, करीब 50 परसेंट से अधिक पद खाली हैं। हम भी चाहते हैं कि पंचायत समिति स्तर पर हमारा अधिकारी बैठे, लेकिन विकास अधिकारियों को एक बार हमने, आपके ही द्वारा सारा दिया गया था, नतीजा यह हुआ कि विकास अधिकारियों में मात्र तीन प्रतिशत विकास अधिकारियों ने इसका निस्तारण किया, बाकी 97 प्रतिशत लोगों ने फार्म ही उठाकर नहीं देखे। सारे पैंडिंग पड़े रहे।

आपने 15 हजार की भ्रष्टाचार की बात कही, वह आपके समय में

(श्री टीकाराम जूली)

था। हमारे आने के बाद इस पर रोक लगाई है। हम इसको सैंक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार कहां से होगा। हमने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इनको जारी किया है। अभी 2016-17 की पैंडेंसी हम जारी कर रहे हैं। अगर हमें भ्रष्टाचार ही करना होता तो हम भी आपकी तरह करते, मर्जी आए जो एप्लाई करें और पैसे लेकर चला जाए। हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय कटारिया जी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए आपको धन्यवाद। पुराने पैंडिग हैं, यह आपने स्वयं ने बोला। आपके पास मालपुरा में 3456 प्रकरण आए, आप बता रहे हो निस्तारण 492 हुए, इसका मतलब क्या हुआ? इतने लोगों ने एप्लाई किया, उसमें से रिजैक्ट तो इतने किए, अगर 600 और मान लो तो 1000 रिजैक्ट हो गए। 2003 तो आप स्वयं मान रहे हो कि पैंडिग हैं। आप यह भी कह रहे हो कि बहुत लंबे समय से पैंडिग हैं। आखिर उस आदमी का क्या दोष है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी। जो पीड़ित परिवार हैं, उसको इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसकी मोनिटरिंग का काम चाहे वह बीडीओ हो या कोई भी अधिकारी हो, है या नहीं?

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा, आपने जो बात कही है, आपके समय पंजीयन का रेशो, 2015-16 में 67 परसेंट, 2016-17 में 69 परसेंट, 2017-18 जो चुनाव का था उसमें 81 परसेंट, जब चुनाव हो रहे थे उस समय 75 परसेंट था, लेकिन हमारा इस साल का रेशो 93.19 परसेंट है, इनके निस्तारण का।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): जो पीड़ित है वह तो इन फीगर को चाहता है कि उसको इसका लाभ कब मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है।

**श्री टीकाराम जूली** (राज्य मंत्री, श्रम): मैं पेमेंट का भी बताना चाहूंगा। 2015-16 में आपने 3.40 करोड़ किया था। 2016-17 में 13.47 करोड़ किया था टोंक में। 2017-18 में 9.79 करोड़ किया था। हमारे समय हमने इस वर्ष 18.55 करोड़ रुपये टोंक में दिए हैं। पैंडेंसी इतनी ज्यादा है कि आपको लग

(श्री टीकाराम जूली)

रहा है कि काम नहीं हो रहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप पंजीयन का निस्तारण देख लें, योजनाओं का निस्तारण देख लें, आपके समय का और हमारे समय का बजट देख लें, आपको हर जगह अंतर मिलेगा। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, मेवाराम जैन।

## राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय, अबडासर (बाड़मेर) का पुन: संचालन

**208. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत दूदाबेरी में स्थित राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अबडासर की स्थापना कब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय विगत कुछ समय से शिक्षकों के पद रिक्त होने से बंद है? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों को पदस्थापित कर उक्त विद्यालय को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

**राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा** (डा. सुभाष गर्ग): (1) बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दूदाबेरी में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, अबडासर रणयाई मगरा की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई। नवीन विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में विभागीय आदेश दिनांक 12.07.2011 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालय में लगातार विद्यार्थी संख्या कम होने एवं सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में कोई प्रवेश न होने के कारण विद्यालय सत्र 2017-18 से असंचालित है।

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 12.07.2011 से 2018-19 तक उस विद्यालय में कौन-कौन से अध्यापक पदस्थापित रहे? जब अध्यापक ही नहीं हैं तो उसमें बच्चे कैसे रहेंगे? न तो पास में कोई दूसरा विद्यालय है कि वहां से बच्चे जाएं।

(श्री मेवाराम जैन)

अल्पसंख्यक बहुल विद्यालय है। आज भी अगर वहां स्कूल खोलो तो आपको वहां 30 बच्चे मिलेंगे। जब आपके अध्यापक ही नहीं हैं...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया।

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा 2011 में इसकी स्थापना की गई। एक अध्यापक का पद स्वीकृत था, 2011 से 2013 तक श्री अजय कुमार रहे। 2013 से 19.6.2017 तक श्री रिगमल रहे। जून 2017 में जब सामान्य शिक्षा की भर्ती हुई तो यह शिक्षक त्यागपत्र देकर चला गया, जिसकी वजह से वहां पद रिक्त हो गया। जुलाई में प्रवेश संख्या नहीं होने की वजह से, फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, यह कह रहे हैं कि इसी ग्राम पंचायत, जो रेवेन्यू गांव है, ग्राम अबडासर में ही दूसरा स्कूल अबड़ों की बस्ती में संचालित है, जिसमें 25 विद्यार्थी नामांकित हैं। माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए, जुलाई में प्रवेश, जो हमारे नोर्म्स हैं, 25 व 40 के बीच में हो जाते हैं तो आपके इस विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोल दिया जाएगा।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विलेज में दूसरा कोई विद्यालय नहीं है, आपकी यह गलत जानकारी है। दो किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं है, अगर आज एडमिशन करोगे तो बच्चे अवेलेबल हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस विद्यालय की घोषणा करें।

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं, प्रवेश संख्या होगी तो हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: आप घोषणा कर दें, बच्चे नहीं आएं तो बंद कर देना।

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अबड़ों की बस्ती ग्राम पंचायत अबडासर में नहीं है?

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): वह रेवेन्यू विलेज अलग है। अबड़ों की बस्ती अलग है और अबडासर अलग है।

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सदस्य, मुझे बताइये अबड़ों की बस्ती कहां है?

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): वह रेवेन्यू विलेज अलग है।

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): कितनी दूर है।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): वहां से ढाई किलोमीटर है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, बैठें। ऐसे प्रश्न-उत्तर होते हैं क्या? अगला प्रश्न, लाखन सिंह।

## करौली में भारत फोर्ज एवं सेंट गोबिन कम्पनियों के प्रस्तावित प्लांट

**209. श्री लाखन सिंह** (करौली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की दृष्टि से जिला करौली में भारत फोर्ज एवं सेन्ट गोबिन कम्पनियों के प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त कम्पनियों द्वारा लगाये जाने वाले प्लान्ट के लिए कहां-कहां पर, कितनी-कितनी भूमि आबंटित व चिन्हित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों कम्पनियां ज़िले में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे प्लान्ट लगाने की इच्छुक हैं? क्या सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव दिया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री परसादी लाल): (1) जिला करौली में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की दृष्टि से भारत फोर्ज द्वारा स्टील प्लान्ट लगाना प्रस्तावित था, जो कि लौह अयस्क के खनन पर आधारित था। MMDR Act-2015 में 31 मार्च, 2015 के पश्चात् हुए संशोधन के पश्चात् लौह अयस्क के खनन के आबंटन हेतु क्षेत्र को नोटिफाई करना अनिवार्य हो गया। इस खनन क्षेत्र का मुख्य भाग वनीय क्षेत्र मे आने के कारण इस लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नोटिफाई नहीं किया गया। अत: भारत फोर्ज द्वारा इकाई स्थापित नहीं की जा सकी। सेन्ट गोबिन कंपनी द्वारा करौली जिले में किसी प्रकार का औद्योगिक निवेश प्रस्तावित नहीं था।

(2) जी नहीं।

(3) केवल भारत फोर्ज द्वारा स्टील इकाई हेतु कुल रुपये 15 हजार करोड़ का निवेश किया जाना प्रस्तावित था। इस हेतु राज्य सरकार को 11 नवम्बर, 2010 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति अनुसंलग्नक-1 पर

(उद्योग मंत्री)

संलग्न है। MMDR Act-2015 में 31 मार्च, 2015 के पश्चात् हुए संशोधन के पश्चात् लौह अयस्क के खनन के आबंटन हेतु क्षेत्र को नोटिफाई करना अनिवार्य हो गया। इस खनन क्षेत्र का मुख्य भाग वनीय क्षेत्र में आने के कारण इस लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नोटिफाई नहीं किया गया। अत: भारत फोर्ज द्वारा इकाई स्थापित नहीं की जा सकी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री लाखन सिंह** (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था जिसमें भारत फोर्ज 1500 करोड़ और सेंट गोबिन 1000 करोड़ निवेश करने वाले थे। क्या सरकार इस खनन क्षेत्र को लौह अयस्क के लिए नोटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है या नहीं?

**श्री परसादी लाल** (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि बताया, भारत फोर्ज द्वारा यह प्रस्तावित था, यहां से कैबिनेट की अप्रूवल होकर भी भारत सरकार को भेजा, परंतु एम.एम.डी.आर. एक्ट, 2015 में 31 मार्च के पश्चात् अमैंडमेंट हुआ, उसके कारण जो मेजर मिनरल थे, उन पर भारत सरकार के एक्ट में प्रावधान हुआ कि आक्शन से ही आप उनकी नीलामी कर सकते हैं। इसके बाद 4-5 साल तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इसके बाद अभी हमने, एन.एम.ई.टी. नेशनल मिनरल एक्सचेंज को, इसके लिए अभी 12 फरवरी, 2020 को ही एक पत्र लिखा है, जिसमें वे परीक्षण करेंगे कि कितना इसमें खनन मिल सकता है। उस परीक्षण के बाद ही इसको नोटिफाई करने के लिए और इसका आक्शन करने की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी।

## प्रश्न संख्या 210

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री छगन सिंह।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, श्री मंजीत धर्मपाल।

## मुण्डावर में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना

**211. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(1) जिला अलवर में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**आयुर्वेद मंत्री** (श्री रघु शर्मा): (1) जिला अलवर में 177 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने नीरोगी राजस्थान संकल्प में आयुर्वेद चिकित्सा को शामिल किया है? अगर आपका उत्तर 'हां' है तो इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्या विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को आप आज के समय के अनुरूप ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मुण्डावर के बारे में पूछें। माननीय मंत्रीजी, बोलना है?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन नीरोगी राजस्थान के बारे में बहस की थी, मैंने पूरे विस्तार से आयुर्वेद के लिए, होम्योपैथी के लिए, योग के लिए, यूनानी के लिए सारी चीजें विस्तार से बता दी थीं। अब कोई प्रश्न बचता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर इनको कुछ अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में अख़बार में कल छपवाना हो तो वह मैं बता सकता हूं कि हम आपके यहां औषधालय खोल रहे हैं जो हमारे जन घोषणा पत्र में अंकित बिंदु है।

**श्री अध्यक्ष**: बात हो गई, मंत्रीजी, विराजिए।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बताऊं आपको?

**श्री अध्यक्ष**: हो गया। आपके यहां आयुर्वेदिक अस्पताल खोल रहे हैं। विराजिए आप।

## प्रश्न संख्या 212

अगला प्रश्न, श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

**(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)**

अगला प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

## अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को देय सहायता

**213. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष अध्ययन एवं अन्य योजनाओं में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों के कितने विद्यार्थियों को कितनी सहायता दी गई एवं उक्त समुदायों के कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से उक्त समुदायों को वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में दिए गए ऋण एवं सहायता से उक्त समुदायों के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मदरसों की तर्ज पर सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना करने एवं उन्हें सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**अल्पसंख्यक मामलात मंत्री** (श्री शाले मोहम्मद): (1) वर्तमान एवं विगत 3 वर्षों में छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष अध्ययन एवं अन्य योजनाओं में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों के 1,17,610 विद्यार्थियों को 5330.47 लाख रुपये की सहायता दी गई। विवरण परिशिष्ट-1 से 4 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा लाभान्वित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय) के 4776 व्यक्तियों को वर्तमान व विगत 3 वर्षों में दिये गये ऋण व सहायता का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(3) विभाग द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी के लिए किसी विशिष्ट संस्था की स्थापना नहीं की जाती है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा संचालित IDMI एवं मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा सहायता अनुदान योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों को शैक्षणिक संबल हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, तीनों सवाल एक साथ ही पूछ लेती हूं, फिर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए।

राजस्थान मदरसा बोर्ड इस्लामी इतिहास, इस्लामी संस्कृति, इस्लामी धर्म शास्त्रों की शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा देने को प्रोत्साहन देने की संस्था है। क्या सरकार इस प्रकार अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का विचार रखती है? पहला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न, क्या सरकार जिस प्रकार मदरसों को पैरा शिक्षक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्थाओं को भी पैरा शिक्षक एवं वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है?

तीसरा प्रश्न, क्या सरकार मुस्लिम समुदाय के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी पृथक् छात्रावासों की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या द्वारा जो बताया गया कि अन्य वर्गों की संस्थाओं के लिए यह जो मदरसा बोर्ड द्वारा जिन शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, वे संस्थाएं खुद आप में स्वत: ही तैयार, जो हमारे पास में आवेदन आते हैं, विभाग द्वारा कोई भी संस्था नहीं बनाई जाती है। ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कोई भी अपनी संस्था तैयार करेगा तो सरकार की तरफ से उन्हें स्वत: ही अनुदान दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी अलग-अलग योजनाएं बनाई गई हैं, IDMI योजनाएं, मौलाना आजाद ट्रस्ट हैं, इस प्रकार की कई योजनाएं हैं, जिनके द्वारा वे आवेदन करेंगे तो सरकार द्वारा उनको समय-समय पर अनुदान दिया जाएगा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): पैरा टीचर्स?

**श्री शाले मोहम्मद** (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): पैरा टीचर्स की भी अभी ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह पालिसी डिसीजन है। मंत्रीजी से पालिसी प्रश्न पूछ लिया आपने।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नहीं, पालिसी तो अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, पालिसी सीक के लिए, रुल के लिए नहीं करेंगे। पालिसी का मंत्री कहां जवाब देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न, श्री सुरेश टाक।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आप संरक्षण दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: संरक्षण दे रहा हूं। आप मंत्री रहे हुए हैं। पालिसी पर क्वेश्चन आवर में नहीं होता है। श्री सुरेश टाक।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): नहीं होता है। इसके अलावा ... (व्यवधान)

## किशनगढ़ में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

**214. श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत केन्द्रों में से किन-किनके भवन बने हुए हैं व किन-किनके नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास** (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अन्तर्गत तीन परियोजनाएं क्रमश: किशनगढ़ शहर, किशनगढ़ ग्रामीण, अराई संचालित हैं, जिनके संचालन की स्थिति निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** | **संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या** | **विभागीय भवन** | **किराये के भवनों में संचालित** | **विद्यालय भवनों में संचालित** | **अन्य सामुदायिक भवनों में संचालित** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अराई | 108 | 73 | 03 | 24 | 08 |
| 2. | किशनगढ़ शहर | 105 | 03 | 86 | 13 | 03 |
| 3. | किशनगढ़ ग्रामीण | 108 | 75 | - | 23 | 10 |
| | योग | 321 | 151 | 89 | 60 | 21 |

आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि भूमि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध हो जाने के बाद विभाग भवन निर्माण की प्रक्रिया कब तक शुरू कर देगा और प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? नम्बर एक।

नम्बर-2, मैं दोनों पूछ लेता हूं, समय कम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय भवनों में 91 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है, कहीं फर्श खराब है, किसी की दीवार टूट रही है, किसी की खिड़कियां टूट रही हैं, पानी भी टपकता है। ये पूरे भवन असुरक्षित हैं, क्षतिग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न, प्रश्न।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): ऐसी स्थिति में बच्चों को शिक्षण-पोषण की व्यवस्था सुचारु नहीं हो रही है। क्या इनकी रिपेयर करने के लिए विभाग कोई कार्यवाही करेगा?

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय

(श्रीमती ममता भूपेश)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पूछा कि कितनी भूमि की आवश्यकता होती है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्र का जो कमरा है, उसका जो मेजरमेंट है, वह 10x14 का होता है, उसके साथ बरामदा, किचन, टोटल लगभग 200 गज जमीन के आसपास, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में सिर्फ कमरे और बरामदे की आवश्यकता रहती है।

माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बच्चों की स्थिति क्या रहेगी आंगनबाड़ी केन्द्रों के अन्दर भवन के बिना, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, जो सी.एस.आर. फंड के माध्यम से भी आंगनबाड़ी सैन्टर्स को बना रही हैं।

**(12.00 बजे)**

माननीय सदस्य, आप तो किशनगढ़ के विधायक हैं, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप तो व्यापारिक जगह के विधायक हैं आप अपनी संस्थाओं को भी आग्रह करके हमारे आंगनबाड़ी सैंटर्स को बनवाने में मदद करें जिससे कम से कम किशनगढ़ सी.एस.आर. और संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से एक आइडियल विधान सभा क्षेत्र बन सके, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं। इसमें पांच लाख रुपये नरेगा के माध्यम से खर्च किये जाते हैं और दो लाख रुपये विभाग के द्वारा, इस प्रकार लगभग पूरे सात लाख रुपये में नए आंगनबाड़ी सैंटर्स बनाये जाते हैं। हमारे पास में भारत सरकार और हमारा 60 अनुपात 40 का रेशो रहेगा। भारत सरकार अगर हमें नए आंगनबाड़ी सैंटर्स की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देगी तो राजस्थान सरकार 40 परसेंट का अपना हिस्सा निश्चित तौर पर देगी, अपनी बिल्डिंग्स बनाने का कार्य प्रारम्भ करेगी।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टिटोडा जागीर के भवन की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा थर्मल पावर प्लांट की इकाइयों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से ए.सी.बी. की कार्यवाही में पकड़े गये परिवहन विभाग के दलाल की सम्पत्ति को जब्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में युवाओं को ड्रग्स सप्लाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी में गुजरात सीमा पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लम्बे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त होने से आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(6) श्री गुरदीप सिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से हनुमानगढ़ जिले में नशे के अवैध कारोबार से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तख्तगढ़ कस्बे के किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाएं।

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से सीकर व जयपुर में CAA, NRC व NPR के विरोध में धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांटों के द्वारा निविदाओं की पात्रता शर्तों में बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से बदलाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से बूंदी जिले की नदियों से हो रहे बजरी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से नई दिल्ली उपद्रव में

(श्री अध्यक्ष)

दहशतगर्दों की गोलीबारी में मृतक सीकर निवासी श्री रतनलाल को शहीद का दर्जा व मुआवजे की मांग को लेकर दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से पिछले कुछ महीनों में लूणकरणसर में हुए 40 हिरणों के शिकार को लेकर हुए आंदोलन एवं रेंजर के निलम्बन संबंधी आदेश बार-बार बदलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

राज्य सरकार आज इस पर वक्तव्य देगी। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर आज राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

(13) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पुलिस द्वारा पूर्व सैनिक को प्रताड़ित करते हुए बेरहमी से मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से बारां जिले के कवाई कस्बे में दलितों के घरों में आग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी भर्ती, 2018 में विज्ञप्ति के अनुसार बिना कट-आफ मार्क्स जारी कर सीधे ही साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुभाष पूनिया, श्री मदन दिलावर एवं श्री नारायण बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार की राशि बढ़वाये जाने के संबंध में।

38] नियम 295 के अन्तर्गत-26 फरवरी 2020-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से अलवर जिले के नीमराना उपखंड पर सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के संबंध में।

(3) श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसपुर में वर्ष 2018-19 में स्वीकृत एनीकटों के बंद पड़े निर्माण कार्य को चालू करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से पूर्व सरकार के समय से जनजाति सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष पद गैर-जनजाति वर्ग के व्यक्ति से भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर ब्लाक में 220 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के श्रम कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर की सीकरी तहसील में उपखंड कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(8) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रही गौ-तस्करी पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(10) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम द्वारा बिल्डिंगों के पार्किंग शुल्क को 5.00 लाख प्रति ई.सी.यू. किये जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती रमीला खड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में स्वीकृति के बाद भी कृषि उपज मंडी नहीं खोले जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(12) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम पंचायत डबलीखुर्द के पम्पिंग स्टेशन का सरकारीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में गुड़, शक्कर, घी व अरण्डी को टैक्स मुक्त करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दिसम्बर, 2019 में अतिवृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

(15) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों को बोलना है, अत: इनको पढ़ा हुआ माने जाने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्यों की भावना है कि आज इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, जिससे हम डिबेट कर सकें।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

**(नियम-295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट देखें)**

# पर्ची

आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 17 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

| क्र. सं. | नाम माननीय विधायक | विषय |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रताप लाल भील | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा के परिसर में वर्षा जल की निकासी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| 2. | श्री ज्ञानचंद पारख | पाली विधान सभा क्षेत्र के उपखंड रोहट के कतिपय गांवों में उत्पन्न भीषण पेयजल संकट के संबंध में। |

(श्री अध्यक्ष)

| क्र. सं. | नाम माननीय विधायक | विषय |
|---|---|---|
| 3. | श्री खुशवीरसिंह | पाली जिले में किसानों को भूमि बैंक द्‌वारा कुड़की आदेश जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। |
| 4. | श्री धर्मनारायण जोशी | मावली विधान सभा क्षेत्र में फतहनगर व सनवाड़ में पानी की टंकियों के जीर्णशीर्ण होने की स्थिति के संबंध में। |

माननीय सदस्यगण, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के संबंध में जो घटना कल विधान सभा और आज विधान सभा के बीच में हो, उन्हीं को मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिए अलाउ करूंगा। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

# सूचना

## लाखेरी में मेज नदी में बस पलटने से दुर्घटना

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले ही मुझे यह पता लगा कि लाखेरी मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक कस्बा है, वहां पर मेज नदी के ऊपर एक बस पलटकर नीचे नदी में गिर गयी है और सूचना मिली है कि 23 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कुछ अभी भी पानी में ही डूबे हुए हैं। तुरंत प्रभाव से उन्हें चिकित्सा उपचार भी मिले और आर्थिक सहायता के लिए भी सरकार कुछ आश्वासन दे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, मैंने यह जानकारी मंगवाई है कि कोटा से सवाईमाधोपुर बारात को ले जा रही करीब 28 सवारियों की भरी बस लाखेरी बूंदी के पास करीब दस बजे मेज नदी में गिरी है। इसमें करीब 18 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है और एक लड़की घायल है, जो बोल रही है। पांच एस.एच.ओ. मौके पर पहुंच गये हैं, एस.पी., डी.एम. और बाकी सीनियर अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और मौके पर बचाव कार्य जारी है।

माननीय कटारिया साहब।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): यही मामला है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: I will not allow it. Please excuse me. श्री सुभाष पूनिया। Please excuse me. I will not allow it. Please. रिकार्ड नहीं होगा। श्री सुभाष पूनिया। रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा। श्री सुभाष पूनिया।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## सूरजगढ़ थाने में पूर्व सैनिक की पुलिस द्वारा मारपिटाई

**श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली 6 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक श्री मुंशी सिंह शेखावत को सूरजगढ़ के थानेदार ने और हैड कांस्टेबल ने, उन दोनों ने जाकर उसको बेरहमी से पीटा और वहां के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण जब गये और पूछा कि इसका क्या दोष था तो एस.एच.ओ. ने कहा कि भाई, यह शराब बेचता है तो वहां पर ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली। उसके बावजूद भी उसको 151 में बंद करना और उसके साथ मारपीट करके थाने में 48 घंटे तक उसको रखा है और वह एस.एच.ओ. इस टाइप का आदमी है कि वह हमेशा जो हिस्ट्रीशीटर होते हैं हरियाणा के, वह वहां पर बैठे रहते हैं इसलिए हैड कांस्टेबल और एस.एच.ओ. के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसका हमने मेडिकल भी करवाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उसकी मार पिटाई की फोटो मेरे पास है और पुलिस में डी.जी. साहब को भी मैंने कहा, उसके बाद आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस तरह के जुर्म के खिलाफ क्योंकि पुलिस बेकाबू होती जा रही है और आपने यहां की घटनाएं देखी होंगी, चाहे नागौर की घटना हो, चाहे अपने यहां राजस्थान पत्रिका की घटना हो तो कम से कम आप इस तरह के अधिकारियों पर अंकुश लगायें और उन थानाधिकारी और हैड कांस्टेबल को वहां से हटाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह बिलकुल गलत परम्परा है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज।

## बारां जिले के कवाई कस्बे में आगजनी में पीड़ित दलित परिवारों को सहायता

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी 23 तारीख को बारां जिले के कवाई कस्बे में शाम को चार बजे जो

(श्री मदन दिलावर)

कालबेलिया समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके घरों में जाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी और घरों को ढहाकर सारा मलबा हटाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। वह थाने के सामने का ही मामला है तो वह तुरंत ही चार बजे थाने पहुंचे तो थानेदार ने उनसे लिखवाकर ले लिया, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उनको तो कहा, इसकी मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद देखूंगा। यानी ठीक थाने के सामने घटना हो रही है, उसकी जांच करेंगे और फिर देखेंगे। उनके घर जला दिये, खाने-पीने का सारा सामान जल गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने एडिशनल एस.पी. से बात की तो उसके बाद जाकर उन्होंने संबंधित डीवाई.एस.पी. को कहा होगा तो फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी बाबू खां मास्टर पकड़ा नहीं गया है और वहीं जाकर धमका रहा है कि तुम समझौता कर लो, नहीं तो हम तुमको रहने नहीं देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से धमकाया जा रहा है। यह विधवा महिला है जो विकलांग है गुलाब बाई, उसका मकान तक तोड़ दिया है। इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनके पालनहार का पैसा आता है, वह उसका रखा हुआ था। इसकी पेंशन का पैसा आता है, वह रखा हुआ था। इसके खाने-पीने का सामान था, वह रखा हुआ था। वह सारा का सारा जल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एट्रोसिटी एक्ट है, यह कहता है कि जिसने लापरवाही बरती है एफ.आई.आर. दर्ज करने में, उसके खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज हो एट्रोसिटी में और उसको भी गिरफ्तार किया जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी मांग है जिन-जिन अधिकारी और कर्मचारियों ने इसमें लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होकर उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रावधान है, इन लोगों के जो मकान तोड़ दिये हैं, वह तुरंत मकान बनवा कर दिये जाएं और समाज कल्याण की तरफ से इनको कम-से-कम 60 हजार की सहायता प्रथम किश्त में तुरंत दी जाए और फिर चालान पेश करने के बाद जितना पैसा बनता है, वह तुरंत दिया जाए। मेरी यह मांग है। यह छह परिवार हैं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री नारायण बेनीवाल।

## सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती परीक्षा के कट-आफ मार्क्स जारी करने में विलम्ब

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान बेरोजगारों के साथ हुई नाइंसाफी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 2019 में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती की परीक्षा का परिणाम घोषित कर पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अगले माह की चार तारीख को बुलाया है, जबकि इस परीक्षा के परिणाम की कट-आफ जारी नहीं की गयी। अभ्यर्थियों द्वारा संकलित अनौपचारिक सूचना के अनुसार अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम अंक लाने पर भी साक्षात्कार में शामिल कर लेने का अंदेशा है। इस संबंध में आर.टी.आई. के अन्तर्गत कट-आफ अंकों की सूचना मांगने पर जवाब दिया कि आप द्वारा चाही गयी साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के कट-आफ मार्क्स एवं प्राप्तांक से संबंधित सूचना उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किये जाने एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व दिया जाना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज तक जो भी भर्तियां हुई उसके अंदर कट-आफ हमेशा साक्षात्कार से पहले घोषित की जाती है और चूंकि आर.पी.एस.सी. बहुत बड़ी संस्था है। जब तिरंगा झंडा बहुत ऊंचाई पर लहराता है तो हर आदमी वहां से सिर झुकाकर चलता है तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि इस मामले पर तुरंत सरकार को आप भी निर्देशित करें कि इस मामले को दिखवाएं और ओ.बी.सी. वर्ग के जो छात्र हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो, ऐसे आप दिशा-निर्देश जारी कराएं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री प्रताप लाल भील।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## गोगुन्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में वर्षा जल की निकासी का अभाव

**श्री प्रताप लाल भील** (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

विधान सभा क्षेत्र में गोगुन्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और लम्बे समय से यहां बारिश के समय दो-दो, तीन-तीन फीट पानी भर जाता है और निकासी का कोई साधन नहीं है। यहां आने वाले मरीजों को और हम लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केन्द्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन से यह कार्य प्रस्तावित भी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस कार्य को अतिशीघ्र बारिश से पूर्व करवाया जाएगा तो उचित रहेगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्री ज्ञानचन्द पारख।

## पालीके उपखण्ड रोहट के गांवों में भीषण पेयजल संकट

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। करोड़ों रुपया व्यय करके सरकार ने जगह-जगह पाइप लाइन बिछायी है, जी एल आर और एस एल आर बनायी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और घोर लापरवाही के चलते गांव फेकारिया, इसमें चार महीने में मुश्किल से चार-पांच बार पानी पहुंचा। पुख्तारी में 15-20 दिन में एक बार, गेलावास में, वहां भी 15-20 दिन में एक बार, पांचपदरिया में भी 15-20 दिन में एक बार, भीलों की ढाणी में भी 15-20 दिन में एक बार, सरगरों की ढाणी उमकली, भगवान भरोसे पड़ी है। गांव धींगाना, वहां भी पानी नहीं है। विश्नोइयों की ढाणी, सांवलता कलां, विश्नोइयों की ढाणी भाकरीवाला, विश्नोइयों की ढाणी कलाली, यह सारे गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछी हुई है सिस्टम आपका पूरा-का-पूरा अच्छा बना हुआ है। जब तक आपके अधिकारी गंभीर नहीं होंगे और पानी पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे न, तो पानी होने के बावजूद भी, सिस्टम होने के बावजूद भी यह जनता प्यासी रहेगी। मेरा माननीय जलदाय मंत्रीजी, आपसे यह आग्रह है कि आप उनको थोड़ा टाइट करो मेहरबानी करके। जवाब भी ढंग से नहीं देते और आपकी लाइन यदि क्षतिग्रस्त हो जाती हैं न, तो ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। जो पानी बेशकीमती है, पीने के लिए चाहिए, वह व्यर्थ चला जाता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि एक बार आप थोड़ा उनको खींचकर कह दोगे न, तो शायद पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: खुशवीरसिंह।

## पाली जिले में किसानों की भूमि की बैंक द्वारा कुर्की

**श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में किसानों की भूमि को कुर्क करने का जो आदेश जारी हुआ है मैं उसके संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। आज भी 70 प्रतिशत हमारी आबादी कृषि प्रधान आधारित है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, अध्यक्ष महोदय, कि किसानों के ऊपर चारों तरफ से मार पड़ रही है। एक तरफ पाले की मार, दूसरी तरफ यह जो जंगली जानवर हैं रोजड़ा, उनकी मार और तीसरी तरफ हमारे गांवों में जो पिग्स रहते हैं, वह रात को खेतों में जाकर नुकसान कर देते हैं तो चारों तरफ से उस पर मार पड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने आते ही किसानों के फसली ऋण तो माफ कर दिये हैं, उसके लिए तो गहलोत साहब को धन्यवाद। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, किसानों ने जो किसान कल्याण फसल ऋण लिया है और किसान संबल ऋण लिया है, उसमें किसानों के डेढ़ गुना पैनल्टी लगायी जा रही है और 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत पैनल्टी लगाकर और दो दिन पहले ही राजस्थान पत्रिका में खबर छपी की उनकी भूमि कुर्क की जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह उद्योगों को सिक यूनिट मानकर अरबों-करोड़ों रुपये तो लोन लेते हैं, उनको तो आप सिक यूनिट मानकर पुनः स्थापित करने के लिए सरकार व्यवस्था करती है और किसानों के लिए यह व्यवस्था मैं चाहूंगा कि समझौता किया जाए और उनसे चार किश्तों में पैसे लिए जाएं और इनकी पैनल्टी माफ की जाए और जो दो वर्ष की राशि जमा करा दे, उनको रैगुलर खातों में जोड़ा जाए। यही निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री धर्मनारायण जोशी।

## मावली में फतहनगर व सनवाड़ में पानी की जीर्ण-शीर्ण टंकियां

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की घोर समस्या है। सरकार प्रयत्नशील है, मैं मान सकता हूं परंतु पिछले कई वर्षों से फतहनगर व सनवाड़ की टंकियां जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं। उनका प्लास्टर गिर गया है। पानी में जब सफाई के लिए कहा गया कि टंकी की सफाई कब हुई तो टंकी की सफाई कर नहीं

(श्री धर्मनारायण जोशी)

सकते, क्योंकि सफाई के लिए टंकी पर चढ़ेंगे तो टंकी गिरने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, आपसे मेरी प्रार्थना है कि लदानी क्षेत्र ऐसा है, लदानी गांव में मैंने अधिकारियों से पूछा पानी की योजना के लिए, ओपन वैल दो बनाए, पानी की पाइप लाइन बिछा दी। अधिकारियों ने कहा कि पानी पहुंच जाएगा पर पानी नहीं पहुंचा। जिला परिषद् की बैठक में भी कहा। पिछली बार विधान सभा में भी निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि पानी पहुंच गया है पर वहां अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची और पाइप भी उठाकर ले गये। मेरे यहां एक सरे पंचायत नई बनी है, वह आदिवासी जनजाति की पंचायत है। वहां पर चार टंकियां बनीं। चार में से केवल एक टंकी में पानी की सप्लाई हो रही है और तीन टंकियां खाली पड़ी हैं। कोई और व्यवस्था नहीं है। अनेक ऐसे गांव हैं जहां टंकियां तो बन गई हैं। आमली पंचायत में साढ़े तीन करोड़ की पानी की योजना बनी, पांच गांवों में पानी सप्लाई होना था, योजना उल्टी पड़ी हुई है, केवल एक गांव में पानी की सप्लाई हो रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। एक पंचायत में आमली में ही, जब कुए से वाटरवर्क्स की सप्लाई थी, पंचायत को पैसा जमा करवाना था, पंचायत ने 60 हजार रुपये बकाया थे, जमा नहीं करवाये, कनेक्शन कट गया और लोग पानी के बिना परेशान हो रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि साकरोदा में 2008 में टंकी बनी, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला, एक बार एक टैंकर डाला जो पानी निकल गया तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें। आप पिछले 15 वर्ष का हिसाब देखें कि एक ही ठेकेदार, एक ही अधिकारी है तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि मावली क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइडयुक्त पानी है, ढूंडिया पंचायत में, वहां भी आप समाधान कराने का कष्ट करें। यही निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: 131, श्री हरीश चन्द्र मीना।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

## देवली-उनियारा में ट्रैक्टर चालक की हत्या के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): सर, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**श्री अध्यक्ष**: आप 131 में ध्यान आकर्षित करें, यह बोलना है उनको।

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री जी, हां। मंत्री जी, इधर।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 29.05.2019 को एक व्यक्ति हरभजन मीणा को थाना उनियारा जिला टोंक के तत्कालीन थानाधिकारी मनीष चारण व अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा नगरफोर्ट अस्पताल में घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस में लाया गया जहां डाक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के परिजनों द्वारा थाना उनियारा के पुलिसकर्मियों पर मृतक की हत्या का आरोप लगाया व धरने पर बैठ गये, जिससे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। दिनांक 03.06.2019 को समय रात्रि 11:30 बजे मृतक के परिजनों ने घटना के सम्बन्ध में एक लिखित रिपोर्ट पेश की। प्राप्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 74/19 धारा 147, 302 आई.पी.सी. व 3/2/v एस.सी. एस.टी. एक्ट थाना नगरफोर्ट जिला टोंक में दिनांक 04.06.2019 को समय 1 बज करके 5 मिनट ए.एम. पर, मतलब सुबह, पर पंजीकृत किया जा करके ज्योति स्वरूप शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. सी.बी. रेंज सेल अजमेर को प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। इनके स्थानांतरण के बाद अग्रिम अनुसंधान नव पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति चौधरी ने किया। प्रकरण में उनियारा थाने के निम्न पुलिसकर्मियों को एफ.आई.आर. में दर्ज नामजद आरोपी अंकित किया गया जिन्हें दिनांक 04.06.2019 को पुलिस अधीक्षक टोंक के द्वारा निलंबित किया गया जो निम्नांकित हैं: मनीष चारण, उप निरीक्षक तत्कालीन थानाधिकारी, उनियारा, हैडकांस्टेबल राजेश गुर्जर, कांस्टेबल भगवान गुर्जर, कांस्टेबल लक्ष्मीचंद, कान्स्टेबल सांवरा जाट और कांस्टेबल चालक रामअवतार जाट, इन छह आदमियों को निलंबित किया गया।

प्रकरण हत्या एवं गंभीर अपराध का पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दर्ज होने से प्रकरण में समस्त पहलुओं का वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण किया गया है। प्रकरण में प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने हेतु गहन अनुसंधान करते हुए 46 गवाहों के बयान लिए गये तथा 168 दस्तावेज जब्त कर पत्रावली पर लिए गये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अनुसंधान अधिकारी द्वारा अब तक किये गये अनुसंधान की रिपोर्ट दिसम्बर, 2019 के अंत में प्रस्तुत की गई है, जिसका विश्लेषण व विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है।

समस्त पहलुओं का विशेषज्ञ की राय व विधिक राय का गहन और वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण व विवेचन कर शीघ्र ही अनुसंधान को पूर्ण किया जाएगा। प्रकरण पत्रावली लगभग 800 पृष्ठ की है।

कथित मारपीट व हत्या के अपराध के अतिरिक्त आरोपी पुलिसकर्मियों के विभागीय दुराचरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक से पृथक से जांच करवाई गई है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नियम 16/18 सीसीए नियम के महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज द्वारा दिनांक 04.12.2019 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। इन नियमों में वृहत दंड देने का प्रावधान है।

पुलिस द्वारा गंभीरतापूर्वक पेशेवर एवं वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान किया गया है। यदि कोई भी पुलिसकर्मी अपराध में लिप्त पाया जाता है अथवा विभागीय दुराचरण का आरोप प्रमाणित होता है तो ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस बिंदु पर बोलने का मौका दिया।

सर, यह एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। सर, 29.05.2019 को सुबह 5 और 6 के दरमियान एक आदमी को दिनदहाड़े मारा जाता है। गर्मी के दिन थे पांच-छह बजे उजाला हो जाता है, इसके सैकड़ों महिला और पुरुष गवाह हैं। पुलिस आती है, मारती है और जब लोग उसको बचाने भागते हैं तो उसकी लाश को लेकर पुलिस गाड़ी में भागती है, गांव वाले पीछे भागते हैं। पुलिस एक घंटे तक उस डैड बाडी को लिए हुए जगह-जगह घूमती रहती है। लोगों ने देखा है साहब, कि यहां लेकर घूमे थे, जगह-जगह खून पड़े हुए थे। फिर अंत में जब पुलिस को कहीं जगह नहीं मिली तो उसको हास्पिटल में ले गये, डाक्टर को रैफर किया कि, साहब, इसका मेडिकल करो, इसको एडमिट कर लो। उसने कहा यह मरा हुआ है, इसको किसमें एडमिट करूंगा। जो मंत्री ने बताया वह तथ्यों से परे है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। 29.05.2019 की घटना और आप 04.06.2019 को मुकदमा दर्ज करते हैं, 7 दिन बाद, यह आपकी संवेदनशीलता है? आप कुछ तो करिये। और, सर, यह तो जब 7 दिन मैंने स्वयं ने आंदोलन किया मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तफ्तीश के लिए नहीं, सर। सर, मेरी मांग यह थी कि इसका पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जाए, बोर्ड से पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। उप मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान को मौके पर आना पड़ा, उनकी मौजूदगी में तो पोस्टमार्टम हुआ। अब मैं तफ्तीश की क्या उम्मीद करूं? क्या वहां मुख्य मंत्री महोदय को लेकर जाऊं? आप गंभीरता को सोचिए, यह दलित अत्याचार का मामला है।

सर, यही नहीं, 4 तारीख को जिस दिन पोस्टमार्टम होना था 12 घंटे में तीन अलग-अलग बोर्ड बनाये गये, 12 घंटे में डाक्टरों के पोस्टमार्टम बोर्ड बदले गये ताकि कैसे मुलजिमों को राहत दी जा सके।

साहब, यह मैं सोच बता रहा हूं पुलिस की जो वहां की स्थानीय पुलिस की सोच थी। मुकदमा दर्ज करने में देरी की, पोस्टमार्टम में देरी की और सब तरह के साक्ष्य मिटाने के पूरे 7 दिन इनको मौका मिला।

सर, इसलिए इसमें मेरा यह आग्रह है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, इसकी cause of death-multiple fractures in his head and skull. अगर धारीवाल साहब यह नहीं समझ पाये तो यह मेरी पीड़ा रहेगी। सर, ये पेशे से वकील हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जवाब आ गया और आपने दे दिया।

सर, पुलिस में एक प्रावधान है, पुलिस में दो है एक सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच एक एडिशनल डी.जी. होता है सिविल राइट्स का जो एस.सी., एस.टी. अत्याचारों को, पुलिस अभिरक्षा में जो लोगों को मारा जाता है, उनकी जांच के लिए, उसको नहीं देकर जो ब्रांच इस चीज के लिए बनी हुई है, आपने सी.आई.डी. में मुकदमा दिया ताकि इसमें रफा-दफा कर दो। जो पुलिस का प्रावधान है उसकी तो पालना कर दो जिसके इसकी जहां तफ्तीश होनी चाहिए वहां तो जांच करवा लो। सर, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जो जिस चीज के लिए बनाया गया है, धारीवाल साहब से घोषणा करवाएं कि केस कम से कम उस ब्रांच में तो जाए। धन्यवाद, सर।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ...

**श्री अध्यक्ष**: एक सैकंड, मंत्री जी की बात सुन लें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, घटना 29.05.2019 की है, घटना के दिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, दर्ज करवाने के लिए कोई आया ही नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़**: 7 दिन ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, डोंट इंटरवीन, यह गलत परंपरा है।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह देख लो आप।

**श्री अध्यक्ष**: 131 किसी का है, बीच में ही हाईजैक कर रहे हैं। नहीं, प्लीज। (व्यवधान) मंत्री की नहीं सुनेंगे, चर्चा को बंद कर दें? यह तरीका ठीक नहीं है।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मृतक का साला था दिनेश, दिनेश को कमलेश ने फोन किया कि इस-इस तरीके की घटना हो गई है और आप जाकर के आपके जीजा हरभजन की स्थिति देखिये। तब जाकर के, आगे जाकर के फिर 3 तारीख की रात के 11.30 बजे यह थाने पर पहुंचे हैं और 4 तारीख को सुबह 1:00 बजे एफ.आई.आर. दर्ज हो गई। एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए कौन गया? आप धरने पर तो बैठ गये, आप भी जाते। आपको जाने से कौन रोक रहा था? आप भी एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। अगर कोई दूसरा उसको नहीं करवा सकता था तो, एक बात। जहां तक सवाल पोस्टमार्टम का है, उसमें निश्चित रूप से उसके 5 चोटें आई हैं। ब्लंट आब्जैक्ट, इम्पैक्ट और ट्रोमा, यह सब उसमें अंकित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि उसको मारा गया या आप ही एक्सीडेंट से मर गया? अगर उसकी जांच यह एडीजी, सिविल राइट्स से करवाने की मांग करते हैं तो हम जांच एडीजी, सिविल राइट्स से भी करवाने को तैयार हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप संतुष्ट हैं? ठीक। चर्चा समाप्त हुई।

अगला ध्यानाकर्षण। श्री बाबुलाल।

## कोटड़ा उपखण्ड के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में भ्रष्टाचार

**श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) द्वारा प्रायोजित बैंक है, जो कोटड़ा में वर्ष 1994 से मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक की शाखा के रूप में और 1.04.2014 से राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में समाहित होकर कार्यरत है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीगण, प्लीज। हां, आप बोलें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दुबारा पढूं?

**श्री अध्यक्ष**: आप जारी रखें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की कोटड़ा शाखा में कुल 12571 जमा खाते हैं, जिनमें 6 करोड़ 22 लाख की जमाएं हैं। शाखा में 20 ऋण खातों में 21 लाख 64 हजार के बकाया ऋण भी हैं। शाखा में कुल 10500 के करीब आदिवासी/काश्तकारों के जमा व ऋण खाते हैं।

दिनांक 28.01.2020 को श्रीमती धर्मी देवी पत्नी जोगाराम, श्री गेना पुत्र साजा गरासिया के खातों से अनधिकृत तरीके से आहरण मतलब विड्राल क्रमशः राशि 10 हजार व दूसरी राशि 20 हजार करने की शिकायत प्राप्त हुई। शाखा द्वारा उक्त शिकायत की प्राथमिक जांच बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारी, एसबीआई से करवाई जा रही है।

प्रकरण की विस्तृत जांच बैंक के सतर्कता विभाग के द्वारा भी करवाई जा रही है। बैंक द्वारा आश्वस्त किया गया है, राज्य सरकार को आश्वस्त किया गया है और जो खातेदार हैं, उनको भी आश्वस्त किया गया है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई वित्तीय हानि नहीं होने दी जाएगी।

बैंक द्वारा प्राथमिक जांच में कार्यालय सहायक श्री रामलाल ने बताया कि उक्त दोनों व्यक्ति पासबुक लेकर नहीं आए थे। सिस्टम से फोटो का

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मिलान करके भुगतान कर दिया गया था। जबकि नियम यह है कि अनपढ़ व्यक्ति अगर है तो पास बुक के साथ-साथ फोटो का मिलान करके ही भुगतान करना चाहिए था। ऐसा न करके बैंक के निर्देशों की अवहेलना की गई है। बैंक द्वारा राज्य सरकार को एश्योर किया गया है कि खातेदारों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जाएगी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में यह 2 नाम बताए। इसमें तीसरा नाम और है। पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था। कैश भुगतान किया जाता था। उसमें लोग पूरा पैसा नहीं देकर के कम देते थे। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार रुके, भ्रष्टाचार नहीं हो, यह हम सबकी इच्छा है। इसी कारण से जो भी सरकारी योजना का पैसा है, उनके खातों में वह पैसा सरकारें डालने का काम करती हैं।

दूसरा, पहले लोग अपना पैसा अपने घर पर भी रखते थे। लेकिन अब समझदारी आने के कारण लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। सबसे भरोसेमंद संस्थान अगर है तो वह बैंक है। घर पर लूटपाट हो जाती है। कोई चोरी हो जाती है। इसके कारण से लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं क्योंकि वहां सुरक्षित मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उस बैंक में सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर कोई अनपढ़ है, वह विदड्राल भरकर के देता है तो वहां पर गवाह के दस्तखत भी कराए जाते हैं। उसका खाता नंबर भी होता है। उसकी पहचान करके ही उनको भुगतान किया जाता है। जो विदड्राल हैं, उन पर गवाहों के दस्तखत हैं। अब जो बैंक का खाता संख्या है, वह उन्होंने मिलान किया कि नहीं किया? उसके बाद में उनका पैसा आपने जैसा बताया, एक का तो 9600 उठा है और एक का 10 हजार उठा है। एक का आपने 20 हजार बताया। उस व्यक्ति का पैसा साबरमती बांध योजना बनी थी तो उनकी जमीन डूबत में गई, उसका पैसा जमा था।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आज वह लोग उन व्यक्तियों के चक्कर लगा रहे हैं कि आप समझौता कर लो। यह एक मामला नहीं है, यह एक प्रकरण नहीं है। उस बैंक की थानों में भी कई बार रिपोर्टें गई हैं। वहां पर कैशियर तथा अन्य जो लोग हैं, वह फर्जी तरीके से पैसा उठाकर के लोगों के

(श्री बाबुलाल)

साथ में धोखा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरी आपसे अपेक्षा यह है कि एक मैसेज जाएगा और अगली बार कोई ऐसा काम नहीं करें, इसके लिए उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि अगला आने वाला भी उससे सबक लेगा और ऐसी घटना नहीं होगी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 नाम बताए, लेकिन माननीय सदस्य का कहना है कि तीसरा नाम भी है। इन्होंने नाम नहीं बताया और न ही यह बताया कि उसके खाते में से कितना पैसा गया है। अब मैं बैंक को लिखूं तो क्या लिखूं, कि इसकी भी जांच करो।

नियम यह हैं कि खातेदार पास बुक और फोटो लेकर जाएगा, पास बुक पर भी फोटो होता है। लेकिन अलग से भी फोटो मांगा जाता है। उसके बाद वह फोटो का मिलान करते हैं। मिलान करने के बाद में उसका विदड्राल करते हैं। अब यह सब कुछ तो उन्होंने बताया कि इस नियम की अवहेलना की गई है। यह अनपढ़ आदमी थे। पास बुक लेकर के नहीं गए थे, वैसे ही चले गए और विदड्राल करवा लिया। अब इसकी तो सारी जांच हो ही रही है। जांच होने पर बैंक ने एश्योर किया है कि चाहे कैसे भी हो, लेकिन इनका नुकसान नहीं होने देंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है?

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री जी, यह तो ठीक है। वह जो इनका कंसर्न है, ये तो 2-3 उदाहरण हैं। कोटड़ा और इंटीरियर इलाके में बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ हैं। बैंक का अपना तरीका है, लेकिन सरकार भी कोई डायरेक्शन दे जिससे पुलिस वाले भी इसका ध्यान रखें कि उन आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं हो।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

## सदन पटल पर रखे गए पत्र

## प्रतिवेदन एवं लेखे

### स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

### वर्ष 2018-19

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: याचिका का उपस्थापन।

श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्री कैलाश चन्द्र मीणा (अनुपस्थित)। श्री अविनाश।

## याचिका

## जैतारण के ग्राम मेघड़दा एवं मालनी की रपटों पर पुलिया निर्माण

**श्री अविनाश** (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम मेघड़दा एवं मालनी के बीच पड़ने वाली दो रपटों पर पुलिया निर्माण करवाए जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2019-20 का उपस्थापन एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

## अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2019-20 का उपस्थापन

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

## मुखबन्द

## अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2019-20) का पारण

**श्री अध्यक्ष**: अनुदान की मांगों पर मुखबन्द।

### मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1- राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,53,10,000/- (नौ करोड़ तिरेपन लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 2-मंत्री परिषद्**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2- मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,88,77,000/- (एक करोड़ अठासी लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 3-सचिवालय**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 9-वन**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,89,88,000/- (अठारह करोड़ नवासी लाख अठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10- विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,34,88,000/- (अठासी करोड़ चौंतीस लाख अठासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 12-अन्य कर**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,04,22,24,000/- (दो अरब चार करोड़ बाइस लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 16-पुलिस**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16- पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,48,89,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ अड़तालीस लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 17-कारागार**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,38,19,000/- (बारह करोड़ अड़तीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19- लोक निर्माण

(श्री अध्यक्ष)

कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 20-आवास**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,86,000/- (पिचासी लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,86,63,000/- (तिरेसठ करोड़ छियासी लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22- क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,00,22,000/- (बासठ करोड़ बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 95,99,13,000/- (पिचानवे करोड़ निन्यानवे लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 27-पेयजल योजना**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,52,78,000/- (पचास करोड़ बावन लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त

(श्री अध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,89,50,000/- (अठावन करोड़ नवासी लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,45,01,000/- (चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35- विविध

(श्री अध्यक्ष)

सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,04,58,000/- (नवासी करोड़ चार लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 36-सहकारिता**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,84,77,54,000/- (आठ अरब चौरासी करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 37-कृषि**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,000/- (सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 38-लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38- लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,68,34,000/- (पन्द्रह करोड़ अड़सठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

**मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39- पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,58,40,56,000/- (तीन अरब अठावन करोड़ चालीस लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 43-खनिज**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,37,29,000/- (उनहत्तर करोड़ सैंतीस लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,49,46,000/- (एक करोड़ उनचास लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

**मांग संख्या 46-सिंचाई**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46- सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 64,88,27,000/- (चौसठ करोड़ अठासी लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 48-विद्युत**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50- ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,02,000/- (चवालीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,000/- (तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मैं, श्री शान्ती कुमार धारीवाल से निवेदन करता हूं कि वे विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन का प्रस्ताव रखें।

# विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री जी विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे।

# विधेयक पर विचार

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, थर्ड रीडिंग में जो सीनियर हैं, वे इस पर बोलेंगे, जिससे कि सभी सदस्यों को जानकारी रहे कि विनियोग विधेयक में कैसे भाग लिया जाता है। थर्ड रीडिंग में मैं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल विधेयक के पारण का प्रस्ताव करेंगे।

## विधेयक का पारण

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 विचारार्थ लिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सरकार कन्सोलिडेटेड फण्ड से जो राशि ले रही है, वह है 2 हजार 937 करोड़ 12 लाख 62 हजार रुपये। यह सही है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आर्टिकल 204 और 205 में इस सदन को यह अधिकार है कि उसकी अनुमति लेकर आप इस कन्सोलिडेटेड फण्ड से और राशि जारी कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस राशि को देखें आप, 2 हजार 937 करोड़ 12 लाख 62 हजार रुपये, यह मंत्री महोदय, आपकी सरकार के लचर वित्तीय अनुशासन का नायाब नमूना है। यह सही है कि कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो एप्रोप्रियेशन बिल लेकर न आती हो, पर इस एप्रोप्रियेशन बिल के माध्यम से कन्सोलिडेटेड फण्ड से जो आप अनुमति ले रहे हैं, उसे देखें और फिर आप अपनी वित्तीय हालत को देखें। मैंने पहले भी बजट पर कहा था कि यह सरकार आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ चुकी है। यह मैंने इसलिए कहा, क्योंकि आपके आंकड़े कह रहे हैं कि इस बार जो बीई आपने प्रस्तुत की थी, उसमें जीएसडीपी राजकोषीय घाटा फिस्कल डैफिसिट का अनुपात जो था, वह तलवार की धार पर लाकर आपने छोड़ दिया यानी 2.99, यह तो बीई है।

आपकी आर ई के सारे आंकड़े यह कह रहे हैं कि आपने बजटीय प्रावधानों का जितना मजाक किया है, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आप तो अचानक आकर अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि आपके कंधों पर इस सरकार का 80 प्रतिशत भार है। चूंकि यह मुझे भी रात को मिला है, आपने इसके पन्ने नहीं पलटे होंगे, पर आप अब कुछ न कुछ नयी बात नायाब तरीके से कह देंगे। कम से कम इस सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार कैसी वित्तीय स्थिति में जा रही है। आपके पहले साल में आपने सबसे पहले जो बात कही थी, मुझे याद है कि यही सरकार है, आप आसन पर नहीं विराजकर उस समय पंचायती राज मंत्री के रूप में विराजे थे इस सदन में।

जब पहली बार इस राजस्थान विधान सभा में पिछली सरकार का श्वेत पत्र जारी हुआ था, कर्जे का बहुत बड़ा विरोध हुआ था। उस समय भैरोंसिंह जी की सरकार गयी थी। इस बार भी जब फरवरी में आपके सदन के नेता ने अपना श्रीमुख खोला और पहला वक्तव्य जो सदन में प्रस्तुत किया, आपने पानी के गिलास पी-पीकर पूर्ववर्ती सरकार पर एक के बाद एक प्रहार किया था कि हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गये और हमने राजस्थान को कंगाल कर दिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके कन्सोलिडेटेड फण्ड की हालत क्या है, जिससे आप अनुमति आज ले रहे हैं।

आपने बात तो इस तरह कही थी कि आप अब और कर्जा नहीं लेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने पहले वर्ष में तीस हजार करोड़ का कर्जा लिया। दूसरे वर्ष में आपने 34 हजार करोड़ का कर्जा लिया। अध्यक्ष महोदय, 3 लाख 75 हजार करोड़ के कर्जे के साथ राजस्थान आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जिस पर आपको निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हालात क्या हैं? जो बात मैंने पहले कही थी, आज राजस्थान की किसी भी ट्रैजरी के टीओ से पूछ लें, आपके यहां से पांच लाख रुपये से ज्यादा का बिल पास करना हो तो आपके फाइनेंस सैक्रेटरी टेलीफोन करते हैं। मैंने भी एक-दो बार इन्हें कहा था कि ठेकेदार धरने पर बैठे हैं, इनका करें।

यह हालत क्यों पैदा हुई है? अध्यक्ष महोदय, यह हालत इसलिए पैदा हो गयी, Budget at a glance इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसमें इनका own tax revenue, जैसा मैंने पहले कहा, आज राजस्थान आर्थिक आपातकाल की जकड़ में पहुंच गया है, आपने इस बार बजट एस्टीमेट में यह कहा कि हमारा जो own tax revenue है, total tax revenue है, वह है 77029 करोड़, अब आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपकी किताबें क्या कहती हैं? आप लम्बी-चौड़ी घोषणाएं कर रहे हैं न, इतनी हजार नियुक्तियां दे दीं और इतनी हजार नियुक्तियां और दे देंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर देंगे, जरा देखें, मुलाहिजा फर्माएं।

मैं चाहूंगा आप या सदन के नेता जब कभी भी जवाब दें और मेरा दावा भी है, मैं जो बात रखता हूं, आज माननीय मंत्री महोदय नहीं हैं, एक बात कहकर मेरा विकेट आउट करना चाहते हैं कि मेरे सारे आंकड़े कपोल कल्पित हैं। मंत्री जी, अगर कपोल कल्पित हों तो या तो सदन छोड़ देंगे या दुबारा खड़े होकर बात नहीं कहेंगे।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): घोषणाएं तो आप कई बार कर चुके हैं सदन छोड़ने की।

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक बार छोड़कर ही दिखा दें आप।

**(12.57 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आपके आसन ग्रहण करने के बाद मुझमें हौसला आ जाता है। उसका एक कारण भी है। सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, हर जगह वाद चलता है, पर शेखावाटी वाद में जितनी पैनी धार है, कहीं और नहीं है।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, यह आपके सामने हैं। जब मैंने एक बार आपके लिए निवेदन किया था कि आपको इस कुर्सी पर बैठे देखकर मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं तो इन्होंने बाहर जाते ही मुझ पर ताना मारा था, ये वही हैं।

**श्री सभापति**: हमारी बहुत पुरानी मित्रता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मेरे जैसा निरीह आदमी, एक बार जोर से बोलते ही मैं थर-थर कांपने लग जाता हूं, मंत्री महोदय। मैं तो आपके संरक्षण में ही बात कर सकता हूं, इसलिए मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा था...

**श्री सभापति**: कांपने क्रोध के मारे हैं या डर के मारे?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आपने बिलकुल सही कहा। जांच का विषय तो यही है।

**श्री सभापति**: सब्जेक्ट यह है कि डर के मारे कांपना अलग बात है और क्रोध के मारे कांपना अलग बात है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक क्रोध में हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आपसे ज्यादा रणबांकुरों का इतिहास कौन जानता है?

**श्री रघु शर्मा** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनके चक्कर में न आना। ये बहुत चालाक आदमी हैं। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): अपने स्थान पर तो जाएं। अपनी जगह से बोलें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, 'चालाक' शब्द को आप कार्यवाही से निकालें।

**श्री सभापति**: विनियोग विधेयक पर बात हो तो इसी माहौल में होनी चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): मैं उसी पर आ रहा हूं, पर यह 'चालाक'

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शब्द कहकर इन्होंने मुझे आरोपित किया है। चालाक शब्द को आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब है- जो धूर्त है, झूठ बोलता है, वह चालाक है। मैं समझता हूं कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है इस सदन में, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपने 'चालाक' शब्द कहकर के उस काम को स्वयं ही वापस कर दिया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन कर रहा था, 2020-21 में जो आपने अपने own tax revenue के आंकड़े दिये हैं 77 हजार 29 करोड़ रुपये। आपका वेतन कम्पोनेंट पर क्या है? वेतन पर आपका खर्चा आपकी किताब बता रही है, Budget at a Glance बता रहा है, 64 हजार 21 रुपये टोटल हमारे आज राजस्थान को सर्व करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर चीफ सैक्रेटरी तक के वेतन में जाते हैं और उस पर जो आपने 3 लाख करोड़ का ले लिया न लोन, जिसको अब आप 3 लाख 75 हजार करोड़ कर रहे हैं, इस लोन पर अब तक का आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता हर साल, वह है 25 हजार 494 करोड़ रुपये

**(13.00 बजे)**

और पेंशन 23 हजार 959 करोड़ है। सभापति महोदय, इसका आप टोटल करो तो यह एक लाख 11 हजार 474 करोड़ रुपये है। विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य विशेषज्ञ हैं। यह 145 परसेंट हो गया, 145 परसेंट रुपया आपको आपके टोटल टैक्स रेवेन्यू से 45 परसेंट और लेकर तो आपको यह चुकारा करना पड़ता है। यह हो क्या रहा है? पिछली बार जो आंकड़े थे, यह 139 परसेंट था, उस समय 30 हजार 351 करोड़ का, आप आर ई के लिए जब 2019-20 में आये तब आन टैक्स रेवेन्यू था। उस समय वेतन पर था 52 हजार 262 करोड़, ब्याज पर था 23 हजार 759 करोड़, पेंशन पर था 22 हजार 224 करोड़ और कुल था 98 हजार 245 करोड़। मैं आज सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं और सदन के माध्यम से राजस्थान के अवाम को कह रहा हूं कि यह पहली सरकार होगी, आप ओवर ड्राफ्ट में जाओगे, वेज एण्ड मीन्स के लिए जाओगे, मंत्री महोदय। आप बात क्या कर रहो हो, इस तरह की हालत आपकी पैदा हो गई क्योंकि आपका जो राजकोषीय घाटा है वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा है। कहां से कहां पहुंच गये आप? 33 हजार 922 करोड़ पर। अब आप करोगे क्या?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर बहुत-सी बातें चलीं। इस सदन के अन्दर पिछली सरकार पर भी बहुत-सी बातें चलीं। यहां यह बात भी कही गई कि केन्द्र सरकार एयर इण्डिया बेच रही है, यह आपके श्रीमुख से भी कई बार निकलता है। एलआईसी के शेयर बेच रही है, मतलब डिस-इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपके पास कौनसा चारा बचा है और आपने पहला कदम कौनसा उठाया है? आप याद कर लो, पहली बार जब आप और हम यहां नये अंदाज में मिले थे, गर्वित मुद्रा में आप यहां थे और हम ताजा-ताजा हारे हुए थे। उस समय आपने क्या आरोप लगाया था? आपने कहा था, खुद खड़े होकर इन्होंने कहा, कालीसिन्ध थर्मल पावर बेच रही है, 2X600 मेगावाट की दोनों यूनिट को बेच रही है, 2X205 यूनिट की छबड़ा को बेच रही है। तब मैंने कहा था कि इसका एकुमुलेटेड लॉस ज्यादा हो गया, लोड फैक्टर कम है, लगातार लॉस बढ़ रहा है इसलिए हमने आर. वी. साही, जो पूर्व सचिव थे भारत सरकार के, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, अर्नेस्ट यंग इण्डिया को सलाहकार नियुक्त किया था, मामला काबीना में गया था, काबीना के बाद में चीफ सैक्रेटरी की सदारत में एक कमेटी बनी थी और उसके बाद में डिस-इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। बात सही है। अब आप क्या कर रहो हो? यह माजरा क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंसोलिडेटेड फण्ड का जो आप पैसा ले रहे हो, इस पैसे को भरने के लिए पिछले दरवाजे से मत आओ, आगे के दरवाजे से आओ। यह जो गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 125-125 की दो यूनिट हैं, इन पर 1865 करोड़ रुपये सरकार के लगे हैं। क्यों जी किस आधार पर आपने मिनिमम प्राइस इसकी 900 करोड़ लेकर बेचने का निकाल दिया, डिस-इन्वेस्टमेंट करने का निकाल दिया? कौनसी काबीना की बैठक में आप लेकर गये? अब आप हम पर आरोप लगा रहे हो, कभी अडानी का, कभी किसका तो यह कौन है अडानी और इसको पर्दे के पीछे से निकाल कर कब सामने लेकर आओगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सभापति महोदय, इस गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का लोन था, इसको जब निर्माण किया तो 1500 करोड़ रुपये का लोन था और आज इस पर सिर्फ 300 करोड़ का लोन रह गया। इनका खुद का विद्युत उत्पादन निगम, आज आपके पड़ौस में ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, ये कमजोर नहीं हैं जो आप समझ रहे हो, इन्होंने खड़े होकर सही बात बयान कर दी तो सदन में सन्नाटा आ जाएगा। इनका खुद का विद्युत उत्पादन निगम, माननीय मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव कर रहा है कि यह गिरल लिग्नाइट यूनिट आप बेचो मत, हमें गिरल माइन की जगह है, जहां से यह लिग्नाइट निकालते हैं उसमें चूंकि सेल पर 5 से 7 परसेंट है, उसकी जगह कपूरड़ी और जालपा, दो जगह भारत सरकार की माइंस हैं, उनसे हमें सिर्फ लिग्नाइट निकालने की अनुमति दे दो और 170 करोड़ रुपये आपने मांगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपकी साफगोई पर, आपकी ईमानदारी पर हमें गर्व है, पर यह हो क्या रहा है? यह माजरा क्या है? इस लाइन के अन्दर और कितनी चीजों को बेचकर आप कंसोलिडेटेड फण्ड भरना चाहते हो? यह पर्दे के पीछे से असली चेहरा है। शीशे के महल में बैठकर दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हम पर आपने आरोप लगाये हैं कालीसिंध के लिए, छबड़ा के लिए और आज आप कर क्या रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी काबीना की बैठक में, कौनसी हाई पावर टास्क फोर्स के आधार पर आपने डिस-इन्वेस्टमेंट के आधार पर यह कर दिया? एक सलाहकार ले आये, आजकल बहुत मिलते हैं, एक रिपोर्ट ले ली और हाथों-हाथ बेचना चालू कर दिया। आज वह समय आ गया है, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए गम्भीरता से कह रहा हूं कि राजस्थान की हुकुमत वेज एण्ड मींस के लिए ओडी. में जा रही है, आर्थिक आपातकाल की जकड़ में आ गई है और आपने राजस्थान की असैट्स को बेचना चालू कर दिया जिसका पहला उदाहरण यह है। आज आपकी हालत क्या है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इसको ये भरेंगे कैसे? रेवेन्यू रिसीट्स इनकी कहां है? मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपकी विद्वता पर हमें अच्छा लगता है, आप बोलते हो, दूर खड़े हों तो अन्दर आते हैं, पर आपने इस बार बी.ई. के आधार पर सारी बात कह दी। इसीलिए यह आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि मंत्री महोदय को तो समझ में आएगा नहीं। 2019-20 की बी.ई. के अन्दर 1 लाख 64 हजार 4 करोड़ की आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कुल थी। आप आर.ई. में आये। इसीलिए मैं कह रहा था कि आर.ई. के आंकड़े के साथ, एक्चुअल आंकड़े के साथ आंख मिलाकर बात करो तब पता लगेगा कि राजस्थान आर्थिक रूप से किस स्थिति में पहुंच गया है। आप आर.ई. के अन्दर आये तब आपकी यह गिरकर एक लाख 56 हजार 715 करोड़, यानी 7 हजार 279 कम। यह हालत है। ये हालात इसलिए हैं कि आपका वित्तीय अनुशासन लचर है, राजस्थान के खजाने में सेंध लगाने के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए जगह-जगह माफिया खड़े हो गये हैं, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार कम करते जा रहे हो, आप कंसोलिडेटेड फण्ड से अनुमति ले रहे हो दो हजार करोड़ से ज्यादा की। पर आपने हमेशा आज तक जो यह आंकड़ों की बाजीगरी की है न, उससे कर क्या रहे हो आप? आप पूंजीगत खाते की प्राप्तियों को पहले बढ़ाते हो, आपका घर का राज है? आज पीएफ का पैसा पड़ा है, दूसरा है और आपने एक आंकड़ा दे दिया। फिर सब्जबाग दिखाये.... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, प्लीज, बीच में नहीं बोलें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप भी लिख लो, माननीय सदस्य। मैं इस पर ज्यादा लम्बा समय नहीं लेना चाह रहा था....

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): अब यह आंकड़ा मैं आपको भी बता दूं कि 2019-20 में पूंजी खाते से प्राप्तियों के लिए जो कहा वह था, मैं आर.ई. की बात कर रहा हूं, 68 हजार 135 करोड़ 52 लाख और पूंजी खाते में व्यय आप बी.ई. में लेकर आये, 40 हजार 72 करोड़ 31 लाख और इसका सरप्लस 28 हजार करोड़ करके इसको पूरा कर दिया। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर ये सारी बातें अगर मैं कहना चाहूं तो निश्चित तौर पर सरकार की कलई खुल जाएगी और एफआरबीएम एक्ट अगर नहीं होता तो ये आंकड़े भी हमें नहीं मिलते। यह तो आपका आउटकम बजट है, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप आउटकम बजट को जरूर पढ़ो। क्या हालात हैं राजस्थान की हुकुमत की, वित्तीय व्यवस्था की और उसके अन्दर, मैं कहता हूं कि मुझे एतराज इस बात का है कि यह जीएसटी के झटकों वाला यह शेर जोड़ा तो जोड़ा किसने। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को बताओ आप कि यह जांच का विषय है। मैं समझता हूं, पूरा सदन सहमत होगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य। विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं हो।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): 000

**श्री सभापति**: रफीक जी, विराजिये। माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, इस जीएसटी में झटका सरकार खुद खा रही है, हिचकोले खा रही है एसजीएसटी में। बी.ई. में करते हैं 29 हजार करोड़ की, आर.ई. में आते हैं आपके 35 हजार 605 करोड़....

**श्री सभापति**: आप थके हुए कैसे लग रहे हो आज?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कहां जा रहे हो, आप बोलो तो इनको बताना तो सही। मैं एक बात बताऊं आपको और फिर मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं पर आपकी हालत भी दूसरी हो गई। ये सत्ता में बैठे लोग आपकी कद्र जब आप चुनकर आते हो तभी करते हैं और जब आप इस पूरे आर्बिट से बाहर जाते हो, ऐसा विद्वान व्यक्ति जिसकी सेवाएं यह पार्टी कहीं ले सकती थी, आपको विस्मृत कर जाते हैं ये लोग, भूल जाते हैं आपको लोग। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपके लिए आज एक शेर ढूंढकर लाया हूं और वह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

'वो करीब तो बहुत हैं, मगर कुछ दूरियों के साथ,

हम दोनों जी तो रहे हैं, पर मजबूरियों के साथ।'

इन मजबूरियों को, मैं इसलिए कह रहा हूं इन मजबूरियों का बंधन तोड़ दो। इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था में, यह सरकार जिस जगह जा रही है। मेरा दावा है आप सड़क नहीं बना पाओगे, आप हास्पिटल नहीं खोल पाओगे, स्कूल नहीं खोल पाओगे और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने सवालों के माध्यम से अपनी सारी बात कह दी। मैं चाहूंगा कि आपका यह एप्रोप्रिएशन बिल, ब्रूटल मैजोरिटी है। आप हमें डिवीजन देंगे नहीं, यह पारित हो जाएगी, पर यह विनियोग विधेयक राजस्थान की जर्जर वित्तीय व्यवस्था का, वित्तीय अनुशासन का और राजस्थान के अंदर आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। राजस्थान के अन्दर रोज जो ये बदलते हो, गुड्डा-गुड्डी के खेल की तरह, आज वित्त सचिव इसको, आज वित्तीय सचिव उसको, ये उसका परिणाम है। ए, बी, सी, डी पता नहीं और इसलिए मुझे तो आखिर वो ही मिलेगा, तिकड़म से बने हुए अर्थशास्त्री। इसलिए सभापति महोदय, मुझ पर कोई आरोप नहीं लग जाए, इसलिए ये बात कहते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विनियोग विधेयक पर बात कहने का मौका दिया। अभी माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता का उद्बोधन हम सभी सुन रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने इनको जो उपाधि दी थी, तिकड़म से बने अर्थशास्त्री, उसको देने

(श्री संयम लोढ़ा)

का एक मात्र कारण था। जब इनकी पार्टी सरकार में आती है तो इनके अर्थशास्त्र के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं करती और इनके पूरे अर्थशास्त्र का ज्ञान जब इनकी पार्टी सत्ता में होती है भीतर ही धरा रह जाता है।

इस ज्ञान से, अगर पिछले पांच साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाभान्वित किया होता तो आज राजस्थान इस कर्ज के हाल में खड़ा नहीं होता। आपने कर्ज के अमाउंट का जिक्र किया तो आप यह भी बता देते कि जब आप सरकार छोड़कर गये तो राजस्थान कितने परसेंट की आउटस्टेंडिंग पर खड़ा था। क्या आज आउटस्टेंडिंग परसेंट उससे ज्यादा हो गया? आप के वक्त जिस आउटस्टेंडिंग परसेंटेज पर छोड़कर गये थे, उससे तो कुछ कम ही परसेंटेज पर खड़ा है। जिस आन टैक्स रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं तो, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के हाल इतने भी खराब नहीं है, आन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान का, देश के 18 राज्यों से बेहतर है। यह सही है कि अशोक गहलोत 2008 से 2013 में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट आपको देकर गये थे। आप 2013 से 2018 के बीच में उसको राजस्व घाटे के रसातल में पहुंचा गये। आज जो आप ये कर्ज का भारी भरकम आंकड़ा गिना रहे हों, इसके लिए एक मात्र अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, तो लंदन में बैठी हुई वसुन्धरा राजे सिंधिया जिम्मेदार हैं। जो अब भी इस सदन में आकर के अपने कृत्यों की स्वीकारोक्ति करने के बजाय, ट्वीट से आगे एक कदम नहीं बढ़ पा रही।

माननीय सदस्य, आप कह रहे है डिस्इंवेस्टमेंट। कौन थे जिसने राजस्थान में सरकारी हास्पिटल को प्राइवेट में दिया था? कौन थे, आप ही थे या कोई और था? वो कौन थे, जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट में देना चाह रहे थे? ये तो राजस्थान के छात्र, नौजवान और कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पर आकर खड़े हो गये तो आपको बैक आउट होना पड़ा। ये जीएसएस ठेके पर देने का काम किसने शुरू किया था? आज इस सरकार को सुना रहे हो। ये सारे काम आप ही करके गये हैं। पांच साल अपनी सरकार को खबरदार किया होता तो ये 0.5 परसेंट के माइनस वोट से राज से बाहर आपको नहीं जाना पड़ता।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां कोई आलोचना के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। ये हालात हैं, ये हम सब जानते हैं और आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं। लेकिन, हालात में सुधार कैसे लाया जाए, उस पर विचार करने की जरूरत है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2019-20 का जो बजट पेश किया, संशोधित अनुमान में उसमें कटौती हुई है और बहुत-सी ऐसी योजनाएं हैं। भारत सरकार का पैसा आ गया, आपने अकाउंट में ले लिया, पीडी अकाउंट में डाल दिया और पेमेंट स्टाप कर दिया, यह भी हकीकत है। लेकिन, इस हालात से राजस्थान को बाहर कैसे निकाला जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यह विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिए सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। आप भूमि आबंटन करते हैं सोसायटियां, राजस्व विभाग भी करता है, स्वायत्त शासन विभाग भी करता है, नगरीय विकास विभाग भी करता है। विगत इतने सालों में जितने भी भूमि आबंटन आपने किये हैं। आपने कभी यह देखने की कोशिश की है कि जिन शर्तों के आधार पर आपने भूमि आबंटन की है, उन शर्तों की पालना हुई है या नहीं हुई है? आपने जमीन दी हास्पिटल के लिए, क्या आज भी उसका उपयोग उसी परपज से हो रहा है या जिस परपेज से आपने जमीन दी थी, उसका कामर्शियल यूज होना शुरू हो गया? क्या आपके अधिकारियों ने कभी देखने की चेष्टा की? आपने जमीन दी धर्मशाला के लिए, चाहे राजस्व विभाग हो या आप हो, क्या आपने कभी देखने की चेष्टा की कि वहां पर दुकानें बन गई हैं? आपने जमीन दी कालेज के लिए, क्या आपने देखने की चेष्टा की कि वहां काम्पलैक्स खड़े हो गये? आपने जमीनें दीं 50-50 बीघा बेशकीमती 2008 में, इसी सदन के अंदर, जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पहली बार बिल आया था। मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को आगाह किया था, वसुन्धरा जी को कि ये मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी आसन पर भी नहीं हैं, वे भी इसी सदन में ही थे। क्या हश्र हुआ, करोड़ रुपयों की भूमि आपने रियायती दर पर यूनिवर्सिटीज को दी, अन्दर कामर्शियल कंस्ट्रक्शन हो गये, दुकानें बन गईं, कैफेटेरिया बन गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अब आप उन दुकानों को हटा नहीं सकते, अब उस कैफेटेरिया को भी नहीं हटा सकते, आप उस काम्पलैक्स को भी नहीं हटा सकते, लेकिन कम से कम आपकी शर्तों का उल्लंघन हुआ है, उसके आधार पर पैसे तो वसूल कर सकते हो। आप दोगुना पैनल्टी लगाइये, तीन गुना पैनल्टी लगाइये, करोड़ों रुपया राजस्थान को प्राप्त होगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

शिक्षा मंत्री जी, मैं तो बोलना नहीं चाहता आप खरीद नहीं कर पा रहे हो, पैसे नहीं हैं आपके पास, पर 12 महीने आपने चिंतन करने का काम नहीं किया कि पैसा कहां से लाया जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी जेडीए बिना अनुमति बिल्डिंग्स बना रही है। आपके प्रवर्तन अधिकारी मिले हुए हैं। जेडीए से प्लान अप्रूव नहीं है, दो मंजिल बन गई, तीन मंजिल बन गई, ऊपर पैन्ट हाउस बन गये। आप हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते तो पैसा तो वसूल करो। सरकार के खाते में पैसा तो लाओ, आप तोड़ तो सकते ही नहीं। आप तो जयपुर शहर में जो आपकी जमीनें हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके, उनको कब्जे ले लो, तो वह भी राजस्थान की जनता पर एक बड़ी कृपा होगी। सचिवालय के इर्द-गिर्द की चारों तरफ की अरबों रुपये की भूमि पर, आपकी भूमि पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। लेकिन, आपका समन्वय नहीं है, आपकी इच्छाशक्ति नहीं है। आप वह पैसा वसूल नहीं करना चाहते, सरकार के खजाने में लाना नहीं चाहते या वोट के डर से उन लोगों को हटाना नहीं चाहते।

माननीय सभापति महोदय, सरकारी स्कूलें पहले गांव के बीचोंबीच में अनेक स्कूलें हुईं। आप कई कस्बे देख लो, शहर देख लो, वे आज अनुपयोगी हो गई, जा नहीं सकते, क्योंकि इतना विस्तार हो गया, गाड़ी नहीं जा सकती, बंद पड़ी है, अरबों रुपये की भूमि, अरबों रुपये की, खाली मेरे होमटाउन में, मैं बताऊं आपको तो शिक्षा विभाग की अनुपयोगी भूमि की कीमत होगी, सौ करोड़ रुपया, मेरे अकेले होमटाउन में। ऐसा का ऐसा सिरोही में मैं कह सकता हूं, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, अनुपयोगी पड़ी हुई भूमि की कीमत होगी, 100 करोड़ रुपये। राजस्थान में हजारों करोड़ रुपये की भूमि अनुपयोगी पड़ी हुई है। आपका कोई समन्वय नहीं है। आपको तो यह भी पता नहीं है कि आपकी भूमि है कहां, कोई देखने वाला है। एक-दो साल के लिए आप शिक्षा अधिकारी लगाते हो, वह अपना इधर-उधर का निरीक्षण करके चल पड़ता है। आप चिह्नित कीजिए, आज जो हालात आपको देखने पड़ रहे हैं न, 12 महीने के अंदर आप उससे बाहर आ जाएंगे और राजस्थान फिर विकसित राज्य की तरफ आगे चल पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कोटा माननीय संसदीय कार्य मंत्री का क्षेत्र है। रीको के अंदर डेढ़ सौ

(श्री संयम लोढ़ा)

हास्टल बन गये, कोचिंग सेन्टर बन गये, सरकार के खजाने में फूटी कौड़ी आई, सरकार के खजाने में पांच पैसे आये। आपकी ही सरकार थी, आप ही मंत्री होते थे। उसी वक्त ये सारे हास्टल बने, कोचिंग सेन्टर बने, आपने कृपा की अच्छा किया, कोटा एक विकसित क्षेत्र के रूप में डवलप हुआ। पूरे देश के लोग आने लगे, बच्चे आने लगे, सरकार के खजाने में क्या आया? यहीं पर ये विश्वकर्मा जयपुर का वेयर हाउसिंग का सेन्टर बन गया, इनकी सरकार में सरकार के खाते में पांच पैसा आया? मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि आप हटा नहीं सकते, आप निर्णय करिए कि हम दुगुना पैसा लेंगे और इनको रैगुलराइज करते हैं। हम तीन गुना पैसा लेंगे और इनको रैगुलराइज करते हैं। कम से कम पैसा तो आता, वह तो आदमी आपके उपयोग कर ही रहा है। आपकी जमीन का उपयोग कर रहा है और, माननीय सभापति महोदय, आप यह बार-बार रीको के भरोसे छोड़ देते हैं। रीको यह कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। वह इसके लिए काम्पीटेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। उसका काम यह कोचिंग सेंटर बनाने का नहीं है। उसका काम है इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करने का। यह नगरीय विकास के माध्यम से आप ही को निर्णय करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान देवभूमि है। इस देवस्थान विभाग की कितनी जमीन है इस देवस्थान विभाग को खुद को पता नहीं है कि उसकी भूमि कितनी है। उसकी भूमि पर कालोनियां कट गईं। उसकी भूमि पर कालेज बन गए। उसकी भूमि पर काम्प्लैक्स बन गए। लोग पैसा कमा रहे हैं। माइनिंग हो रही है उसकी भूमि पर। मंत्री जी पहले रहे हुए कह रहे हैं लेकिन सरकार के खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है और किसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके विभागों का आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। देखने की फुर्सत नहीं है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी, सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आप अपनी भूमि का सर्वे करवाइए और पता करिए, इस पर खर्चा करिए और आप से नहीं हो सकता तो प्राइवेट आदमी को काम दीजिए, जिससे यह सारा पता लगा सके और उसका उपयोग राजस्थान की जनता के हित में हो सके।

माननीय सभापति महोदय, देश के अनेक राज्यों के अंदर देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है। कोई जाकर कभी देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में

(श्री संयम लोढ़ा)

आपकी प्रोपर्टी है। गुजरात में आपकी प्रोपर्टी है। महाराष्ट्र में आपकी प्रोपर्टी है। दिल्ली में आपकी प्रोपर्टी है। लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। दुकानें बनाकर रह रहे हैं। कोई जाकर के यह पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे बैठे हो? उत्तराखंड में है। यह अरबों रुपये की सम्पत्ति हमारे ध्यान नहीं देने के कारण और आप नयी पालिसी लीज की क्यों नहीं लेकर आते? किराएदारी की नयी पालिसी इसमें क्यों नहीं लेकर आते देवस्थान के अंदर? आपका करोड़ों रुपयों का तो किराए ही कोई नहीं देता। एन्क्रोचमेंट करके बैठे हैं, वह तो अलग है। अवैध निर्माण किए हुए हैं, वह भी अलग है। खाली देवस्थान मंत्री जी के खुद के भरतपुर में 3 करोड़ रुपये की तो रेंटल इनकम ही बाकी है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, इनके अपने शहर के अंदर तीन करोड़ रुपये बाकी है और दो सौ-ढाई सौ तो इनके अपने शहर के अंदर देवस्थान की प्रोपर्टी पर एन्क्रोचमेंट है। आप स्वयं देवस्थान के मंत्री रहे हुए हैं। कौन ध्यान देगा? मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि यह सरकार इस पर ध्यान दे जिससे आने वाले वक्त में लोगों की हम इच्छाएं पूरी कर सकें, अपेक्षाएं पूरी कर सकें।

अब माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और है डीएमएफटी, करोड़ों रुपया आता है इस फंड में, मिनरल फंड में पड़ा है। मेरे अपने सिरोही जिले के अंदर 97 करोड़ रुपये पड़े हैं। (व्यवधान) राजसमंद की माननीय सदस्या कह रही हैं कि 400 करोड़ रुपये उनके यहां पड़े हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर कितना पैसा डीएमएफटी फंड में पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया शांत रहें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप कोई इस बारे में निर्णय तो करिए और आपने 99 में इस पर रोक लगा दी जनवरी में 2019 के अंदर ही कि हम स्वीकृतियों पर रोक लगाते हैं, उसके बाद भी 4 जिलों में स्वीकृतियां जारी हो गईं। कैसे हो गई? मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, मुख्य मंत्री जी के साथ बैठिये और यह करोड़ों रुपये जो पड़े हुए हैं इनका सही तरीके से उपयोग और उस पर विचार करिए और माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी सुझाव मैं और देना चाहता हूं। सचिन पायलट साहब कारपोरेट मिनिस्टर थे एक्ट लाए थे और कंपनीज पर समाज सेवा की एक जिम्मेदारी डाली थी सीएसआर के नाम से। इस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? राजस्थान में भी

(श्री संयम लोढ़ा)

इतने बड़े-बड़े उद्योग हैं। अरबों रुपया उनका सीएसआर का है, कोई आपका चैक है? कोई आपका इस पर ध्यान है? इंडस्ट्री तो यहीं लगी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, मर्जी आए तब खुद के एनजीओ बना दिए, उनको पैसे दे देते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, इतना पैसा एक नंबर में देते हैं, दो नंबर में इतना पैसा लेते हैं। मैं सुझाव दूंगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की सदारत में इस संबंध में एक कमेटी बनाइये जिससे सीएसआर के पैसे का जो मकसद था, भारत सरकार के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी का कि यह सामाजिक जिम्मेदारी इन कंपनियों पर डाली जानी चाहिए उसके अनुरूप पैसे का उपयोग हो सके। आपने मुझे यह बात कहने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): वी वांट डिवीजन।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): आप देखिए, सभापति महोदय, सरकार अल्पमत में है। फाइनेंस बिल पास हो रहा है। सरकार गिर सकती है। आप लॉबी क्लीयर करवाइए। सभापति महोदय, यह मजाक बना रखा है इन्होंने। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): ...(व्यवधान) फाइनेंस बिल है। मजाक है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप भी जानते हैं, माननीय नेता महोदय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): लॉबी क्लीयर करवाइए आप। यह तरीका है इनका। गेट बंद कराइए आप। गेट बंद कराओ, सभापति महोदय। गेट बंद कराओ इनका। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

(श्री सभापति)

जाइए, अपने-अपने स्थानों पर जाइए। प्लीज। श्री नारायण बेनीवाल।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गिन लो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) मेघवाल साहब हमारे साथ हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पधारिये अपने स्थानों पर। प्लीज, ऐसे नहीं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। अपने-अपने स्थानों पर पधारिए। काफी लोग बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य। विराजिये अपने-अपने स्थानों पर जाइए। प्लीज, सहयोग करें। अपने-अपने स्थानों पर पधारिए। मैं बात करता हूं। आप अपने स्थानों पर पधारिये। प्लीज। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। (व्यवधान) आसन पर जाइए। बाद में करूंगा न बात।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्लीज, सहयोग करें। अपने आसन पर जाइए।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): बैठ जाओ। (व्यवधान) आप की संख्या ही नहीं है, बेवजह हंगामा करने से क्या होगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अपने आसन पर जाइए न। काफी लोग बोलने वाले हैं। जाइए-जाइए।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): ...(व्यवधान) चिल्लाने से क्या होगा? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: पधारिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास** (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, सदन का टाइम खराब कर रहे हैं ये लोग। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: काफी लोग बोलने वाले हैं।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, काफी लोग बोलने वाले हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, काफी लोग बोलने वाले हैं, 30-35 लोग बोलने वाले हैं।

**श्रीमती ममता भूपेश** (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सभापति महोदय, यह सदन का अमूल्य समय खराब कर रहे हैं।

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। (व्यवधान)

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) आप चाहो तो गिना लो, इनसे दुगने हैं, इनसे दुगने हैं, गिना लो। (व्यवधान) ये मुट्ठीभर लोग हैं।

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए। अपने स्थानों पर जाइए। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): आपको डिवीजन देना पड़ेगा और अगर आप नहीं देते हैं तो वाकआउट करते हैं।

**श्री सभापति**: यह आपकी मर्जी है। आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते। प्लीज, सहयोग करें।

## बहिर्गमन

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)**

विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, कुल मिलाकर ये 28 आदमी हैं, आप इनकी गिनती करवा लो, 28 हैं और इधर देख लो 56 आदमी बैठे हुए हैं। ये सिर्फ 28 लोग हैं ...(व्यवधान) और उसमें भी कैलाश जी मेघवाल हमारे साथ हैं।

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। विराजिए प्लीज। प्लीज सहयोग करें।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मेरे द्वारा निम्नांकित मांगों के कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के बाबत जो बात कही गई है, इन 25 मांगों के बाबत मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री सभापति**: अनाउंसमेंट हैं आपका। मंत्री महोदय, अनाउंसमेंट। ... (व्यवधान) पारित तो हो गई।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पारित हो गई?

**श्री सभापति**: हां।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद साहब।

**श्री सभापति**: श्री शान्ती कुमार धारीवाल, अनाउंसमेंट।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, आपका बहुत्बहुत धन्यवाद आपने गिनती कर ली, वह कुल मिला कर 28 ही थे और यहां देख लो आप। (व्यवधान) इक्का दुक्का आदमी ही कोई बाहर हो तो हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए, विराजिए।

## शासकीय वक्तव्य

## सिविल लाइंस स्थित मैरिज गार्डन (राजस्थान पत्रिका परिसर) में पुलिस प्रवेश की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मेरे द्वारा 24.2.2020 को विधान सभा के सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान पत्रिका के मामले में जांच पुलिस आयुक्त, जयपुर से उच्चतर पुलिस अधिकारी के द्वारा करवाई जायेगी। मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त जांच के विषय में विभागीय अधिकारियों के साथ मेरी चर्चा हुई है और चर्चा के उपरांत जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता की दृष्टि से मैं यह उचित समझता हूं कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई जांच को पुलिस अधिकारियों के बजाय किसी अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा करवाई जाए, मैं यह घोषणा करता हूं क्योंकि पुलिस से जांच करवाएंगे तो कई तरह के आरोप लग जाएंगे कि यह उसको बचा रहा है, यह उसको बचा रहा है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा करवाएंगे तो बात साफ आ जायेगी।

**श्री सभापति**: श्री नारायण बेनीवाल।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह बता दें कि संभागीय आयुक्त से करवायेंगे या किससे करवायेंगे? बता दीजिए।

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संभागीय आयुक्त से करवा लेंगे। वह भी बहुत बड़ा अधिकारी होता है, पूरे डिवीजन का अधिकारी होता है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हां, संभागीय आयुक्त से करवा दीजिए।

**श्री सभापति**: करवा लेंगे अपने हिसाब से। श्री नारायण बेनीवाल।

## आय व्ययक

## आय व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आय व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर चर्चा में भाग लेने का मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए दिल से आभार। सभापति महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मुख्य मंत्री जी ने....

**श्री शान्ती कुमार धारीवाल** (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, देख लो 12 हैं यह, 12 से 13वां नहीं है। यह देख लो, 12 गिन लो आप। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया शांत रहें, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): 000

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): 000

**श्री सभापति**: आप बिजली के बटन की तरह इस्तेमाल मत होइए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपका बटन आन करेंगे तो आप आन हो जाएंगे, आफ करेंगे तो आप आफ हो जाएंगे। नहीं, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज बोलने दें उनको। बिजली के बटन हैं क्या आप, आप बिजली के बटन हैं क्या? संसदीय कार्य मंत्री आन करेंगे आप आन हो जाएंगे और आफ करेंगे तो आफ हो जाएंगे। (व्यवधान) नहीं, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए आप, माननीय सदस्य विराजिए। 30-32 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, कल भी कुछ लोग बाकी रह गये थे। आसन अकेला कुछ नहीं कर पायेगा। आप सब लोग सहयोग करेंगे, माननीय सदस्य तैयारी करके अपने घर से आते हैं और शाम को पता लगता है कि बोल नहीं पाये। कल नारायण बेनीवाल जी नहीं बोल पाये, उनको भी पीड़ा हुई, मुझे भी अच्छा

(श्री सभापति)

नहीं लगा। मेहरबानी करके आपको जो समय दिया गया है, समय पर अपनी बात रखें और सारगर्भित बात रखें ताकि सदन के समय का सदुपयोग हो और बीच में इंटरवीन नहीं करें। श्री नारायण बेनीवाल।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, आय व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने वित्तीय प्रबंधन, प्रशासकीय कौशल और सूझबूझ को दर्शाने के बजाय केन्द्र सरकार और पूर्ववर्ती राज्य सरकार को कोसने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी। वह अपना विजन तय कर पाने में असफल रहे हैं। नकारात्मक मानसिकता से प्रस्तुत यह बजट राज्य के विकास को उचित दिशा नहीं दे पायेगा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट की एक और खासियत यही है कि इसमें नई प्रभावशाली योजनाएं लाने की बजाय पूर्व की योजनाओं को नया नाम देकर राज्य को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। सभापति महोदय, वित्तीय संसाधनों के बिना बजट घोषणाओं का अम्बार लगा दिया गया है। ज्यादातर घोषणाएं पिछले बजट वाली ही हैं। आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस नीति नजर नहीं आती। रेगिस्तान के विकास के लिए अकाल निवारण या जल कुबेर जैसे अच्छी योजनाओं को अगर लागू किया जाता तो केन्द्र सरकार या विश्व बैंक से धन मिल सकता था। सभापति महोदय, यदि हमें एक स्वस्थ, सुखी, विकसित राजस्थान का निर्माण करना है तो सबसे पहले इस सदन और सरकार को नैतिक रूप से मजबूत बनाना होगा तथा अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्य के आउटपुट का विश्लेषण भी आवश्यक रूप से करना होगा। वार्षिक बजट वर्षभर का विजन डाकूमेंट होना चाहिये न कि जोड़-तोड़कर बनाया हुआ आंकड़ों का भ्रमजाल ताकि गलत व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सके। हर वर्ष बजट का 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च होना, हमारे वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। सरकार ने जनता को किसी भी प्रकार की कोई सीधी आर्थिक सहायता नहीं दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण के बिन्दु संख्या 6 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोट भी किया है कि मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता का यह कथन 'मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं।' माननीय सभापति महोदय, यह बात गांधी जी ने 50-

(श्री नारायण बेनीवाल)

60 साल पहले कही होगी, अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बजट भाषण में यह लिखना चाहिये था कि मेरी यह प्रबल कामना है कि मैं किसी की आंखों में आंसू न आने दूं। इस बजट का पूरा सारांश जब मैंने पढ़ा, तब मुझे हिन्दी फिल्म का एक सीन याद आया। जिसमें हीरो पहले बंद कमरे में किसी को मारता है और फिर जनता के सामने कमर में रिवाल्वर लगाकर बाहर लाता है और यह कहता है कि सबके सामने हंसो। हमारे सत्ता पक्ष के जो अधिकतर विधायकगण बैठे हैं, उनको भी अपने क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की कोई ऐसी सौगत नहीं मिली लेकिन चूंकि यह तंत्र की मजबूरी भी है कि सबको हां में हां मिलानी पड़ेगी। नावां से आने वाले माननीय उप सचेतक महोदय, मेरे सीनियर यहां विराजमान हैं। इस बार के बजट में नागौर को फिर 'ना गौर' किया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि नागौर से सत्ता पक्ष के 6 विधायक चुनकर आये हैं तो कोई न कोई बड़ी योजना नागौर के लिए आयेगी लेकिन नागौर इस बार भी इस बजट में 'ना गौर' ही रहा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब मुख्य मंत्री 27 तारीख को सदन में अपना पक्ष रखें तो नागौर में ऐसी दो-चार योजनाएं जरूर आनी चाहिए, उसके लिए हमें अपेक्षाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले जो बिंदु संख्या-9 है- सम्पूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है और इस परिवार के लिए मैं, सात संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकताएं बनाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दो दिन से पूरे सदन की कार्यवाही को देख रहा हूं। सिरोही और पाली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी कहीं कि हमें बजट बनाने से पहले यह तय करना है कि इस प्रदेश में रेवेन्यू कहां से आएगा। आज इस प्रदेश में जो स्पष्ट खनन नीति का अभाव है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू खनन से मिल सकता था। अभी स्वायत्त शासन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। स्वायत्त शासन विभाग के पास, एक तरफ तो हर व्यक्ति और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह पीड़ा जरूर जाहिर की कि हमारे 10 हजार 362 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने काट लिए। अब आप 10 हजार 362 करोड़ रुपये की बात क्यों कर रहे हो? आपके पास इतना बड़ा संसाधन है कि यदि आप ईमानदारी से चाहें और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप एक लाख करोड़ से ज्यादा की आय इस प्रदेश में ले सकते है। पिछले पांच-छह साल से खनन नीति पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बजरी माफिया ने हजारों-करोड़ों रुपये, प्रशासनिक

(श्री नारायण बेनीवाल)

अधिकारियों और सत्ता में बड़े पदों पर बैठे लोगों को दिये, यदि वह पैसा कहीं न कहीं सरकारी खजाने में आता तो आज हमारा बजट भी घाटे का बजट नहीं होकर फायदे का बजट होता।

मानननीय सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान की बात इस बजट भाषण में कही गयी है। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि नीरोगी राजस्थान के अंदर यदि हमने संकल्प लिया है तो जनसंख्या नियंत्रण का संकल्प पत्र हमें सबसे पहले इस सदन में लाना चाहिए था क्योंकि संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या पर काबू पाये बिना सीमित संसाधनों से हमें विकास कार्यों में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा, आधारभूत ढांचा, चाहे वह प्राथमिक हैल्थ सैंटर हो, सीएचसी हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, आज सब जगह पर आधारभूत ढांचे का अभाव है। उनके अंदर एएनएम, जीएनएम, डाक्टर और विशेषकर विशेषज्ञ डाक्टरों की बहुत बड़ी कमी इस प्रदेश में है। नीरोगी राजस्थान, हालांकि अच्छा शब्द है और कन्सेप्ट भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ठोस कार्य योजना बना कर हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारा प्रदेश नीरोगी प्रदेश कैसे बने? इसके अलावा, जो परम्परागत चिकित्सा विधियां हैं, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी पर पहले सदन से वक्तव्य भी आया था, उसके लिए भी ठोस कार्ययोजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा निःशुल्क दवाओं की जो योजना है, उसके लिए आप लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसके अंदर जो फार्मासिस्टों के पद हैं, उसको लेकर बड़ी विचित्र स्थिति है। आप इसका कैडर तय करके इन लोगों को भी आप परमानेंट करें।

इसके बाद नशा मुक्ति, यदि नीरोगी राजस्थान बनाना है तो हमें नशा मुक्ति प्रदेश बनाने के लिए पहल करनी होगी। एक तरफ नशा मुक्ति के संकल्प की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब का कारोबार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे सदन के जो सदस्य थे, जिन्होंने शराबबंदी के आंदोलन में अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, उनके नाम पर एक कालेज और विश्वविद्यालय का नाम भी रखा, लेकिन उनको असली श्रद्धांजलि तब होती, जब आप इस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करते। माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से यह अपील भी करूंगा कि इस प्रदेश में शराबबंदी और जो सारे नशे हैं, उन

(श्री नारायण बेनीवाल)

पर रोक लगाकर एक जन जागरण अभियान चलाना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम रोक तो लगा देते हैं, लेकिन माफिया पनप जाते हैं, वह भी आम आदमी के लिए हित का सौदा नहीं होता। ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बनाएं।

मैं 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान की बहुत बड़ी महती आवश्यकता समझाता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा नीरोगी राजस्थान के लिए बायो मेडिकल वेस्ट पर ठोस कार्य योजना का बहुत बड़ा अभाव है। बायो मेडिकल वेस्ट पर कोई ठोस कार्य योजना बनाएं।

खेलों का बजट कम देना, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जब स्वस्थ शरीर होगा तब स्वस्थ मन होगा। स्वस्थ शरीर के लिए हमें खेल की प्रतिभाओं को आगे लाना पड़ेगा। खेल पर जो बजट कम किया है, उसको बढ़ाने का निवेदन भी मैं आपसे करूंगा।

इसके अलावा, हमारे क्षेत्र में जो पांचला, सीदा के अंदर जो सीएचसी की घोषणा 2013 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी, लेकिन अभी मापदंड के अनुसार शुरू नहीं हुई उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा। एक सीएचसी और दो पीएचसी तथा हमारे क्षेत्र में दस उप स्वास्थ्य केन्द्रों की अलग से सूची मैं माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूंगा।

दूसरा संकल्प-सम्पन्न किसान। माननीय सभापति महोदय, अगर किसान को वास्तव में सम्पन्न बनाना है। जब लोग खड़े होते हैं तो 95 प्रतिशत लोग यही कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं व्यथा यह है कि हम जब किसान के नाम पर चुनकर आते हैं और हमें आवाज उठाने की आवश्यकता होती है, तब हमें कहीं न कहीं कमी विशेष रूप से नजर आती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करूंगा कि अगर किसान को सम्पन्न बनाना है तो इस व्यवस्था को कृषि प्रधान नहीं बनाकर हमें कृषक प्रधान व्यवस्था बनानी होगी। जिस हिसाब से हम सैन्य क्षेत्र में सैनिक का सम्मान करते हैं, उसी तरह इस कृषि प्रधान देश में कृषक के प्रति सम्मान यदि हम प्रकट करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें विकास की एक ललक जागेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जिसकी सब दल मांग भी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं कोई ठोस कार्य योजना की बात करूंगा। उसके अलावा यदि किसान को सम्पन्न बनाना है तो

(श्री नारायण बेनीवाल)

सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य और दूसरा उन्नत बीज, हालांकि इसके अंदर 8 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 12 लाख क्विंटल बीजों के वितरण की बात सरकार ने कही है। माननीय सभापति महोदय, बीजों के साथ-साथ जो नकली बीज आ रहे हैं। सरकारी माध्यम से मिनिकिट और बीज किसानों को दिये जा रहे हैं, उसके अंदर नकली बीजों का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्री जी ऐसी योजनाओं की पूरी मानिटरिंग करके किसान को उन्नत बीज मिले, तब जाकर सम्पन्न किसान की बात चरितार्थ होगी। इसके अलावा सिंचाई का उचित प्रबंध, अभी सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बातें कहीं कि बाढ़ के समय में पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। उस पानी को अच्छे डैम बनाकर रोकें। नागौर सहित ऐसे बहुत सारे जिले हैं, जहां सिंचाई के पानी की माकूल व्यवस्था कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें ठोस कार्य योजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

असली पेस्टिसाइड और उचित विपणन- सरकार यह ध्यान दे कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले-एमएसपी, समर्थन मूल्य पर जो खरीद योजना चलती है। माननीय सहकारिता मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि इसकी प्रभावी मानिटरिंग की जरूरत है और इसका जब भंडारण होता है, उसमें करोड़ों रुपये व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे कभी नागौर का मूंग गंगानगर जा रहा है, कभी जोधपुर जा रहा है, कभी भरतपुर जा रहा है और कभी भरतपुर वाले का नागौर आ रहा है। इसके अंदर कोई ठोस कार्य योजना भंडारण को लेकर बने, ताकि सरकारी पैसे का सदुपयोग हो। इसके अलावा, फसली बीमा, जिसकी मांग हम सब लोग करते हैं। हालांकि, केन्द्र की विषय-वस्तु है, लेकिन इसकी मानिटरिंग का सारा जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके अंदर जो अधिसूचनाएं जारी होती हैं, वे समय पर नहीं हो पाती हैं। कई जो अऋणी लोग होते हैं, वे अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सकते, इसके ऊपर भी प्रभावी मानिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय सहकारिता मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो जो सहकारी संस्थाएं हैं, वे चुनाव के लिए बहुत समय से बाट जोह रही हैं और बड़ी उम्मीद है चूंकि आप किसान परिवार से आये हैं तो सहकारी संस्थाओं के चुनाव आपको कराने चाहिए। 25 को-आपरेटिव बैंक और 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं, वे लगभग घाटे की ओर अग्रसर हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि आप उनके सारे आंकड़े भी उठाकर देख लीजिए, जब-जब उस बैंक में चुने हुए

(श्री नारायण बेनीवाल)

प्रतिनिधि रहे हैं, तब-तब वह बैंक फायदे में रही है और जब भी प्रशासक लगा तो घाटे में क्यों गयी? इसलिए सहकारिता संस्थाओं का चुनाव कराने की मैं महती आवश्यकता समझता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जैविक खेती की बात तो सब करते हैं, लेकिन गोवंश नहीं बच रहा है। उसके लिए कोई कार्य योजना सरकार नहीं बना रही है। इस पूरे प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं का इतना जमावड़ा लग गया है कि आये दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोगों की फसलें खराब हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तीन साल से कम के बछड़ों के परिवहन पर सरकार ने जो रोक लगायी है, ऐसे मामले न्यायालयों में भी लंबित हैं। इस पर ठोस कार्य योजना बनाकर नागौरी नस्ल के जो बैल, जो कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये के बिकते थे, उसके ऊपर कोई ठोस कार्य योजना बना कर तीन साल से कम के बछड़ों के परिवहन पर रोक हटे ताकि किसान का वापस गायों को पालना शुरू हो और मेलों का जो स्वरूप था, वह भी वापस लौटाएं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए व अन्य अधिग्रहण में। अभी जैसे भारत माला का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें किसानों को कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान जब अपनी जमीन ही सरकार को किसी कार्य के लिए दे देगा तो अपना पेट कहां से पालेगा? इसलिए उसको उचित मुआवजा मिले और ऐसी योजनाओं के अंदर रोजगार के साधन उस परिवार को उपलब्ध हो, ऐसी ठोस कार्य योजना की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। इसके अलावा, नयी कैनाल व्यवस्था और सेम की समस्या, अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मेरी हां में हां मिला रहे हैं। मेरे ससुराल बड़ोपल में जब मैं जाता हूं तो 1975 से हजारों नहीं, लाखों बीघा जमीन जलमग्न हो गयी, सरकार को इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए कि किसान के पास यदि जमीन ही नहीं बची तो अपना पेट कहां से पालेगा, ऐसी व्यवस्था हमें बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, अग्रिम भंडारण, अभी कल ही सहकारिता मंत्री जी बता रहे थे कि डीएपी और यूरिया का हमने अग्रिम भंडारण किया है। मैं भी सहकारी तंत्र से चुन कर आया हूं। मुझे पता है कि अग्रिम भंडारण की बहुत बड़ी बातें सरकार करती है लेकिन वह यूरिया और डीएपी खराब हो जाता है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

किसान के किसी काम का नहीं रहता तब वह सहकारी संस्थाओं में पहुंचता है। इसलिए अग्रिम भंडारण की व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ी मानिटरिंग की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके सबके खाते सहकारी बैंकों के अंदर खुलें। जो प्राइवेट बैंक हैं, उनके अंदर ये भू-अधिग्रहण या जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, करोड़ों-अरबों रुपये उनके पड़े हैं, ये सब खाते सहकारी बैंकों में खुलवाने का मैं निवेदन करूंगा। इसके अलावा, डीजल पर जो वैट है, उसके अंदर सरकार जरूर छूट दे। कृषक कल्याण कोष की जो आपने घोषणा की है, इसकी मानिटरिंग और कृषक साथी योजना के अंदर जो दो लाख रुपये किसान की मौत पर मिलते हैं, उसको बढ़ा कर दस लाख रुपये किया जाए, यह मैं सरकार से मांग करूंगा। केसीसी के ऋणों में प्रति बीघा सहकारी बैंकों से असिंचित भूमि के लिए दस हजार और सिंचित भूमि के लिए कम से कम बीस हजार रुपये सरकार ऋण दे, तब जाकर किसान की हालत को सुधारने की जो बात कर रहे हैं, उस पर खरा उतरेंगे।

माननीय सभापति महोदय, चौथा संकल्प- सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, आजीविका के समुचित साधन और सुअवसर उपलब्ध करवाना और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता, यह इसके अंदर विजन होना चाहिए। संविदाकर्मियों का नियमितीकरण, आप देख रहे हैं अभी सदन चल रहा है तो संविदाकर्मी लोग बहुत पैसा खर्च करके यहां शहर में, हम जो माननीय विधायक यहां बैठे हैं, सभी के घरों के बाहर खड़े रहते हैं, विधान सभा के बाहर भी धरने-प्रदर्शन का प्रयास करते हैं। जो जवान है, उसकी ऊर्जा को हम सड़कों पर खर्च कर देंगे तो उनका आउटपुट हम कैसे लेंगे? अत: ऐसी कोई ठोस नीति बने। एक लाख नौकरियों का जो वादा था, उसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ता था, ये सब चीजें हैं जो कहीं न कहीं युवाओं को विचलित करती हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन पर त्वरित कोई कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि सक्षम मजदूर के लिए श्रम एवं रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप चाहे रोजगार डायरी, श्रम मजदूर डायरी की बात करें, बहुत बड़ेबड़े प्रकरण हनुमानगढ़, गंगानगर और कई जिलों के अखबारों

(श्री नारायण बेनीवाल)

के मुख पृष्ठ पर छपे हैं। इसके अंदर प्रभावी मानिटिरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूं। सिलिकोसिस पर कोई ठोस कार्य योजना बने और डीएमएफटी के अलावा सरकार इसके अंदर पैसा दे। जो डीएमएफटी का पैसा आ रहा है, वह सारा का सारा पैसा नागौर जैसे जिले में पांच-पांच लाख रुपये जो सिलिकोसिस के अंदर दे रहे हैं, उसके अंदर चला जा रहा है। आधारभूत सुविधाएं सड़क, शिक्षा वगैरह जो हैं, उस पर डीएमएफटी का पैसा खर्च नहीं हो रहा है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): सर, दो मिनट। शिक्षा का परिधान-आरटीई का क्या हश्र हुआ, इस पर हमें गौर करने की बहुत आवश्यकता है। अभी हम 10 हजार करोड़ काटने की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़ी विडम्बना की बात है कि पिछले 6 साल के अंदर इस प्रदेश में 26 हजार स्कूल बंद हो गईं जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपये भी हम मानें तो 26 अरब का बहुत बड़ा नुकसान सरकारी राजकोष में हुआ है। राइट टू एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, ऐसी नीतियां लेकर आएं ताकि शिक्षा का तंत्र भी सुधरे और सरकारी धन का अपव्यय भी नहीं हो। इसके अलावा, जो नये संकाय खोले हैं, उनमें सारे पद खाली पड़े हैं। विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों में लैब नहीं है, पुस्तकालय नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक ब्लाक में स्वामी विवेकानंद के नाम से स्कूल खोलने की सरकार जो मंशा रखती है तो यह भी सब जगह खुलवाएं। इसके अलावा, महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की और कौशल विकास योजना, इन पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छठा संकल्प- पानी, बिजली व सड़कों का मान, पानी के लिए नहरी परियोजनाएं बहुत शिथिल हैं। 2015-16 में नागौर नहरी योजनाएं पूरी होनी चाहिए थीं, वह पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बने। प्रत्येक व्यक्ति के घर तक नल, अभी माननीय प्रधान मंत्री जी भी यह बात कर रहे हैं, हम सब लोगों को मिलकर, ईमानदारी से, यह सोचकर नहीं कि पहले विपक्ष ने यह गलती की तो हम भी यह गलती करेंगे, इस सब चीज से ऊपर उठकर आम आदमी को न्याय कैसे मिले, उसको सुविधाएं कैसे मिले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): सर, दो ही मिनट। वाटर ट्रीटमेंट सुचारु हो। नहरों के अंदर पेस्टीसाइड और बहुत गंदा पानी आ रहा है तो इसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना बने। पिछली सरकार ने रूफ टाप हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लागू किया था, वह सब जगह बंद पड़े हैं। बहुत बड़ा सरकारी धन भी वहां लग चुका है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। आर.ओ. व डी-फ्लोराइजेशन सेंटर के नाम पर एनजीओ ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इसके लिए भी निवेदन आपसे करूंगा। जल प्रदाय योजना, पूर्व में जो जनता जल योजना वगैरह हैं, यह तो सब सदस्यों की सामूहिक समस्या है कि जनता जल योजना के कार्मिकों को आप नियमित कराएं। जो ट्यूबवैल फेल हो गये हैं, उनके अगेंस्ट में नये ट्यूबवैल खुदवाएं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली मंत्री अभी नहीं बैठे हैं। बिजली के अंदर कंपनियों में बहुत बड़े घाटे की बात कही जा रही है। बिजली कंपनियां घाटे में हैं लेकिन इसकी तह तक हमें जाना पड़ेगा। बिजली खरीद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। बिजली का जो मैटेरियल खरीदा जा रहा है, उसमें बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसलिए बिजली व्यवस्था खराब हो रही है। इसके ऊपर कोई ठोस कार्ययोजना बनाकर सोचना चाहिए।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): सर, दो ही मिनट। हो ही गया।

**श्री सभापति**: दो-दो मिनट करते हुए आपने आठ मिनट ले लिए।

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): बिजली के बिल के अंदर पहले जो सब्सिडी दी जाती थी और अब डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो वह भी बिल के अंदर ही समायोजन हो और जीएसएस के ठेके वगैरह को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सड़कों का मान माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी के झगड़े के अंदर हम 198 विधायक पिस रहे हैं। आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से कि हमें सड़कें भी दी जाएं। अभी ग्राम विकास पथ के नाम से जो योजना आई है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर गांव के अंदर पहले ही पक्की सड़कें बनी हुई हैं, पक्के खरंजे बने हुए हैं, सीसी ब्लाक लगे हुए हैं। उनको तोड़कर आप नये बनाएंगे तो यह धन का बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। इससे बढ़िया तो हम सबको मिसिंग

(श्री नारायण बेनीवाल)

लिंक सड़कें दी जाएं और कम से कम 40 किलोमीटर, हमारा क्षेत्र 150 किलोमीटर लंबा है, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करूंगा और कौशल एवं तकनीक प्रधान...

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री ज्ञानचंद पारख

**श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): इसके अंदर डवलपमेंट के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ईमित्र पुलिस योजना इसका अच्छा रेस्पोंस जाना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र की तंदुरुस्ती तथा भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करवाने का संकल्प पत्र भी सरकार को लाना चाहिए। सभापति महोदय, आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री ज्ञानचंद पारख।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): माननीय सभापति महोदय, जब से इस सदन में बजट पेश हुआ है, पूरे प्रदेश में निराशा का वातावरण है। कई उम्मीदें थीं सरकार से लोगों की परंतु सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हम तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे हमारी सरकार नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, उनको मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। करेंगे क्या? केन्द्र सरकार को कोसेंगे। माननीय प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र मोदी को गालियां बोलेंगे क्योंकि गालियों का क्रम इस देश में चालू हो गया। कैसी-कैसी गालियां हमारे देश के प्रधान मंत्री को देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बोली हैं? पूरा देश शर्मिंदा होता है।

**श्री सभापति**: आप पहले वक्ता हैं। क्यों आप यहां से वहां, वहां से यहां जा रहे हैं। सीधे बजट पर आइए।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आप मुझे टोके नहीं। उससे बढ़कर एक बात और कह दी कि प्रदेश नहीं देश की जनता डंडे मारेगी। आप काम नहीं करेंगे तो अपने बारे में भी सोच लेना। क्या-क्या टिप्पणियां कीं? प्रधान मंत्री के तो कोई आगे-पीछे नहीं है, देश नहीं संभलेगा तो झोली-डंडा उठाकर वह चल देंगे परंतु जिसके आगे-पीछे है, एक पार्टी नहीं संभली। नरेन्द्र मोदी तो कहीं भी भगने वाले नहीं हैं। सबको पता है कि लोक सभा चुनाव की हार के बाद कैसे भाग छूटे नेता? एक महीने तक समझाने में

(श्री ज्ञानचंद पारख)

लग गये, तब भी उनको समझ में नहीं आयी। दूसरे पर कमेंट करना बहुत आसान काम है। जब खुद पर बीतती है तो जवाब देते बनता नहीं।

**(14.00 बजे)**

बजट के पैरा नंबर 3 में ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात कह दी कि हमारी संघीय व्यवस्था में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर होती है। हमारे खुद के भी बहुत सारे संसाधन हैं। हम प्रयास करें तो हमारी आय व वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास नहीं, मात्र केन्द्र को कोसना। माननीय सभापति जी, आपको मालूम है मुख्य मंत्री जी छात्र जीवन से ही जादू की कला जानते हैं। जैसा जादू के बारे में पता है, सिर्फ नज़रों का भ्रम, हकीकत में कुछ नहीं होता। यह बजट भी मात्र नजरों का भ्रम...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, मैं आपको बार-बार टोक रहा हूं, आपका बोलने का मौका है, यह अच्छी परम्परा नहीं है। आप नये-नये आए हैं इसलिए कुछ सीख लीजिए। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। बैठे-बैठे मत बोलिए, नम्बर आए, तब अपनी बात गंभीरता से कहिए।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): यह बजट भी नज़रों का भ्रम ही साबित होगा। सभापति महोदय, आप तो खुद गवाह हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो 12 मिनट बाद ही उनका गला सूखने लग गया था, क्योंकि उनको पता है कि देने को कुछ नहीं है। पूरे बजट भाषण के दौरान उनको चार बार पानी पीना पड़ा। मैं भी इस सदन में बैठकर यह 22वां बजट पेश होते हुए देख रहा हूं। पहली बार देखा है कि इतनी कम बार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज़ थपथपाई, ऐसा पहली बार हुआ है। थपथपाई भी कब, जब कहीं न कही केन्द्र पर कटाक्ष किया गया, कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार में कोई कमी निकाली गई, तब। सदन में घोषणा को लेकर मेज़ें थपथपाने का काम इस बार इतना कम हमने पहली बार देखा है।

सभापति महोदय, जनता का नेचर तो आप जानते ही हो, कि राजस्थान की जनता कैसी है। 1998 में 154 सीटों के साथ राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी थी। बाद में 2003 के चुनाव में क्या हालत

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हुई, मात्र 53 पर सिमट गए थे। जब 2008 में चुनाव हुए सीटें कम होने के बाद भी आप सत्ता में तो आ गए थे, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा, हमने ऐसा बुरा काम नहीं किया कि हमको इस तरह हराए, पर कुछ अंतर रह गया। 2008 में भी 95 सीटों के साथ कांग्रेस वापस सत्ता में आई। 2013 की दुर्गति तो आपको पता ही है, 21 सीटों पर आकर कांग्रेस सिमट गई थी, अगर दो सीटें कम आतीं तो प्रतिपक्ष नेता का दर्जा भी आपकी पार्टी को नहीं मिल पाता। जब 2023 के चुनाव आएंगे 53 और 21, थोड़ा अनुपात निकाल देना, अगर इसी तरह से बजट पेश किया, विकास कार्यों में अरुचि दिखाई, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लोक सभा में आपकी जो हालत हुई है वही आने वाले विधान सभा चुनाव में होगी।

बजट में इतने बड़े-बड़े संकल्प, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाले हो। सात संकल्प बताए। आपकी अपनी घोषणाओं के बारे में तो आप थोड़ा चिंतन मंथन कर लो। घोषणाएं बड़ी-बड़ी और जब आदेश जारी होते हैं तो किस तरह आपकी कैंची चलती है, यह कुछ नमूने मैं आपको दिखा रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी जोधपुर में इंडस्ट्री को संकट से बचाने के लिए घोषणा करते हैं कि प्रदूषण की समस्या के निजात में जो भी व्यक्ति कोई ईटीपी लगाएगा तो सरकार उसको दो करोड़ तक की सब्सिडी अनुदान देगी, यह मुख्य मंत्री जी घोषणा अख़बार में आई है, जिसकी वीडियो क्लिपिंग भी मेरे पास है। एमएसएमई स्कीम में जब आदेश जारी होते हैं तो वह दो करोड़ से एक करोड़ पर आ जाते हैं, उसमें भी शर्त, मशीनरी की लागत के बिल का 20 परसेंट तक, दोनों में जो भी कम होगा, वह देंगे। मतलब 30-40 लाख से ज्यादा किसी को मिलने वाला नहीं है, आप प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे करेंगे।

एक बड़ी घोषणा के बारे में, सदन में कई बार चर्चा चली, विधान सभा चुनाव के पहले सत्ता पाने के लिए आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपने खुद ने, सबसे बड़ी घोषणा की थी कि हम किसानों का सम्पूर्ण कृषि कर्जा माफ कर देंगे, कहने को घोषणा कोई और, बाद में क्रियान्विति क्या? सहकारी या भूमि विकास से जुड़े काश्तकारों तक आपने सीमित कर दिया। बाकी नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी आपने केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने का काम किया कि हम केन्द्र सरकार के पास गए थे, हमने उनसे मांग की, पर वहां से हमको कुछ नहीं मिला तो कौन-सी आपने घोषणा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

केन्द्र सरकार या प्रधान मंत्री से पूछकर की थी भाई? अपने बूते करते तो मान लेते।

आपने शिक्षित बेरोज़गारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। लगभग 12 लाख शिक्षित बेरोज़गारों का आपके रोजगार कार्यालय में पंजीयन है। कितनों को दिया, मात्र 11 प्रतिशत। कहते कुछ हैं और करते हैं नाममात्र का।

माननीय सभापति महोदय, घोषणा की गई थी प्रदेश में जो भी गौशालाएं हैं, आपके मन में गायों के प्रति कहां प्रेम पैदा हो गया? इतना प्रेम पैदा हो गया कि आपने जोश में आकर घोषणा कर दी कि हम गोशालाओं को 9 महीने का अनुदान देंगे। आप मात्र 6 महीने का अनुदान दे रहे हैं। यहां भी आपने कटौती कर दी, आप अपनी घोषणा से पीछे हट गए।

आपने घोषणा की बालिकाओं को कालेज तक नि:शुल्क शिक्षा सरकारी खर्च पर। आपके जो भी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं, कालेज हैं, कोई दो-चार विषय छोड़ दीजिए जो सरकारी खर्च पर चल रहे हैं, ज्यादातर सीनियर सैकण्डरी स्कूल या कालेज में जो प्रमुख विषय हैं, आज की आवश्यकता है, सारे के सारे सैल्फ फाइनेंस में पढ़वाए जा रहे हैं। उसके लिए बच्ची को शिक्षा के लिए जितना खर्चा आता है उससे भी ज्यादा राशि देनी पड़ती है। वाकई आपकी मंशा घोषणा पूरी करने की है तो सरकारी बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल या कालेज हैं, उनमें जितने भी सैल्फ फाइनेस के विषय हैं, वह सारे सरकारी खर्च पर करवा देंगे तो आपके माध्यम से बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री जी की घोषणा थी कि मेडिकल कालेज से संबंधित अस्पतालों में हम एंजियोग्राफी फ्री करवाएंगे, अभी कहीं भी फ्री चालू नहीं हुई है। नीरोगी राजस्थान की जिस दिन डिबेट थी, उस दिन भी मैंने याद दिलाया था, पर आज भी सरकारी अस्पतालों में एंजियोग्राफी का पूरा शुल्क लिया जाता है। पहले जितना लिया जाता था बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा लिया जा रहा है, उसको कम नहीं किया गया।

आपने यह भी घोषणा की थी मेडिकल कालेज से संबंधित जितने भी जिला अस्पताल हैं वहां हम सीटी स्कैन नि:शुल्क करेंगे। पुरानी 6 मेडिकल कालेज में तो आपने आदेश कर दिए, पर 8 कालेज और हैं, वहां अभी तक आपके आदेश नहीं पहुंचे हैं, जबकि आपकी घोषणा कई दिनों पहले पहुंच गई, तो वहां भी वह आदेश करवा दो।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, आपने किसानों से भी वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 7-8 घंटे बिजली देंगे, परन्तु 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है, आपको भी मालूम होगा, अपने क्षेत्र के किसानों से पूछ लेना, 4 या 5 घंटे बिजली मिल रही है वह भी अनियमित रूप से। वह भी पूरी नहीं मिल रही है।

शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूर्ववर्ती सरकार ने जितने भी विद्यालय बंद कर दिए हैं, हम उनकी समीक्षा करवाएंगे और बंद विद्यालयों को पुन: चालू कर देंगे। पिछला एक सत्र निकल गया, आपकी सूची आगे नहीं बढ़ी और नया सत्र आने वाला है। मैंने भी लिखकर दिया है और विभाग की ओर से भी वहां पत्र भेजा गया है कि यहां छात्र हैं, बिल्डिंग है, गलत बंद हो गई, इसको चालू करिए, पर एक साल बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, सरकार को काम करना है तो कोई न कोई पैसा सरकार के खाते में होना बहुत जरूरी है, सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो चाहे किसी पार्टी की सत्ता हो, ज्यादा काम करवा नहीं सकती। पर हमारी आय कैसे बढ़ेगी, इस पूरे बजट में, इसके लिए हमने कोई चर्चा नहीं की, न सदन के सदस्यों को कोई इस बात का विश्वास, भरोसा दिलवाया कि हम इस-इस माध्यम से अर्जित करेंगे और आपकी जो उम्मीदें हैं, आपको जो काम हैं हम वे काम पूरे करके आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे, ऐसा एक भी इस पूरी बुक में कहीं भी नहीं है।

आपको अपनी आय बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के लिए कुछ न कुछ विशेष पैकेज लाना होगा। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो आपकी रेवेन्यू बढ़ नहीं सकती। आजादी के समय राजस्थान में 17 मिलें थीं और आज मात्र एक बची है, 16 मिलें बंद हो गईं, क्यों हो बंद हो गई, कारण ढूंढो। गुजरात इंडस्ट्री को लेकर जितना आगे बढ़ा है हम उसके सामने कहीं टिकते नहीं। हम राजस्थान में भी गुजरात की तरह इंडस्ट्री को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास करो। अगर इंडस्ट्री बढ़ गई, हो सकता है पाल्यूशन हो, उसके समाधान के लिए भी आप कोई न कोई काम करो पर इंडस्ट्री के लिए यदि सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया तो आय बढ़ेगी नहीं और रोजगार जो हमारा सबसे बड़ा संकट है, कितनी ही सरकारी नौकरियां आप दे दोगे, हमने भी दे दी, उसके बाद में उतने के उतने बेरोजगार, बेरोजगार तो बढ़ रहे हैं तो यह

(श्री ज्ञानचंद पारख)

इंडस्ट्री आपके रोजगार के भी काफी बड़े अवसर पैदा कर देगी इसलिए इंडस्ट्री के लिए विशेष तौर से मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा, उनके मन में इंडस्ट्री को लेकर बहुत दर्द भी है और जिस जोधपुर से वे आते हैं, उनको खुद को पता है कि जोधपुर में इंडस्ट्री की कितनी संभावनाएं हैं। कोई पैकेज देना पड़े तो पैकेज देकर भी, कोई सुविधा देनी पड़े तो सुविधा देकर भी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री राजस्थान की धरती पर लग जाएं, वह काम सरकार को करना होगा।

यह हमारा राजस्थान है, इसको प्रकृति ने बहुत सारी कलाएं दी हैं बहुत सारी। यहां पर्यटन की भी बहुत बड़ी संभावना है। मेरे अपने जिले पाली का जवाई बांध का जो पीछे वाला इलाका है, जहां बीजापुर सेणा आते हैं, आज की तारीख में हिन्दुस्तान में यदि पर्यटन के लिए पर्यटक सबसे ज्यादा आकर्षित हैं तो उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, वहां हजारों की संख्या में लैपर्ड हो गए और वहां देखने के लिए अभी सचिन तेंदुलकर भी आए थे, बीच में सैफ अली खान आकर गया था।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो भी ऐतिहासिक स्थान हैं, जो हमारे प्रकृति के द्वारा दिए गये सुंदर स्थान हैं, पर हमारी सोच कभी पर्यटन को विकसित करने की रही ही नहीं, आपके इस पूरे बजट डाक्यूमेंट में। कहीं पर्यटन को बढ़ावा देना है और हमारा इतिहास भी कितना गौरवशाली रहा है, हमारे गौरवशाली इतिहास को देखने को भी बहुत सारे पर्यटक राजस्थान में आना चाहते हैं, हम अगर पर्यटकों को आकर्षित कर दें तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है। उदयपुर का महाराणा प्रताप गौरव स्थल, वह सरकार का नहीं है, आर.एस.एस. ने बनवाया पर जब से वह बना है, उसके बाद में वहां देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है उस महाराणा प्रताप गौरव स्थल को देखने के लिए, तो हम ऐसे स्थान भी विकसित करें।

अभी जो मेरे से पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे रॉयल्टी को लेकर, अब रॉयल्टी में कितनी चोरियां होती हैं, सबको पता है। हमारा यह जो भ्रष्टाचार है, यह हमारी अर्थव्यवस्था को खा रहा है। प्रकृति ने हमको खनिज भी बहुत दिया, रॉयल्टी भी बहुत आ सकती है, अगर हम भ्रष्टाचार पर थोड़ा लगाम लगा दें तो रायल्टी के माध्यम से भी हमारी बहुत इनकम हो सकती है और हमारी सम्पत्तियां जो नाकारा हैं, जहां चले जाओ वहां सरकारी सम्पत्ति

(श्री ज्ञानचंद पारख)

नाकारा, खंडहर बनी पड़ी है, कोई काम की नहीं, आगे भविष्य में उनके लिए कोई प्लानिंग भी नहीं है, तो ऐसी सम्पत्तियों को भी चिन्हित करके अगर हम बेचेंगे तो भी सरकार का खजाना काफी हद तक कर्ज के बोझ से कम हो सकता है, वरना यह आपका कर्जा बढ़ता रहेगा और राजस्थान की जनता विकास को लेकर तरसती रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, अब आपका संकल्प है नीरोगी राजस्थान, इस पर चर्चा पहले ही हो गई। यह नि:शुल्क दवा, यह तो बहुत पुराना मैटर हो गया, यह नया मैटर थोड़े ही है, यह 8 साल पहले प्रदेश की धरती पर आ गया और उसके बाद में तो एक विधान सभा चुनाव हो गया, उस नि:शुल्क दवा की हवा कैसे निकली, यह आपको पता है न, 21 सीटों पर आ गए थे, तो मेहरबानी करके इससे कुछ आगे बढ़ो, नि:शुल्क दवा तो पहले से चल रही है, उसके बाद में तो उससे बहुत बड़ी योजना भामाशाह आ गई। हम आयुष्मान भारत योजना से अपने आप को जोड़ने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार पैसा देगी, आपके मद का पैसा बचेगा पर कहीं प्रधान मंत्री पापुलर नहीं हो जाएं, प्रधान मंत्री की वाहवाही नहीं हो जाए, हम उससे भी बच रहे हैं। इसलिए आप कुछ आगे बढ़ो, नीरोगी राजस्थान हम भी चाहते हैं, पर कहने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा।

सम्पन्न किसान, केन्द्र सरकार भी चिंतित, राज्य सरकार भी चिंतित, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। वाकई में किसानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। माननीय मंत्री महोदय आपसे आग्रह करूंगा, विशेष तौर से फसल बीमा को लेकर, यह हमारे किसान अशिक्षित हैं, भोले भाले हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका जो नुकसान हुआ है, उसके विरुद्ध में उनकी क्लेम राशि कितनी बनती है। आप सरकार से एक आदेश कराओ कि बीमा कंपनी तो आकलन करें, उसके साथ-साथ हमारा अपना विभाग भी आकलन करें तो हमारे किसानों को जो वाकई में नुकसान हुआ है, उतना का उतना उनको क्लेम मिल जाएगा, वरना बीमा कंपनी क्लेम काटने में काफी कुछ बेईमानी करती है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): मेरा बाकी है, मैंने देख लिया था।

एक आग्रह और आपसे रहेगा कि जब आप 1200 करोड़ की प्रीमियम

(श्री ज्ञानचंद पारख)

फसल बीमा के लिए आप राज्य मद से देते हैं, तो बीमा कंपनी पर आपका भी प्रभावी अंकुश होना बहुत जरूरी है। बीमा कंपनी बेलगाम है, केन्द्र सरकार के तो नियंत्रण में है लेकिन आपके नियंत्रण में नहीं रही। जितनी राशि केन्द्र सरकार देती है, उतनी ही राशि आप देते हो, किसान आपका है, विशेष तौर से आपका है। आप किसानों को लेकर बहुत चिंतित हो, मैंने खुद ने महसूस किया है और मैं तो गवाह हूं कि जब भी मैंने कोई बात कही तो आपने किसान के हित में कार्यवाही करके उसको पैसा दिलवाया है। तो इसका नियंत्रण आपके पास भी केन्द्र सरकार के समान रहे, उसके लिए भी आप कोई न कोई बात करें, ताकि किसानों को उनके हक का पैसा मिल सके। क्योंकि मेरा समय हो रहा है इसलिए मैं अंतिम बात कह दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह छठा संकल्प है न 'पानी बिजली सड़कों का मान' यह आप पूरा बजट डाकूमेंट उठाकर देख लो, पहली बार हुआ है कि सदन के एक भी सदस्य को चाहे कोई क्षतिग्रस्त, नोन पैचेबल सड़कें हैं, उनकी नवीनीकरण की राशि मिली हो या मिसिंग लिंक की मिली हो। पिछली बार आपने विकास पथ दिया था। पिछली सरकार ने प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए, कुछ न कुछ मिसिंग लिंक के लिए और ग्रामीण गौरव पथ के लिए तो एक अभियान चलाकर जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उन सारे ग्राम पंचायत मुख्यालयों में तीन चरणों में ग्रामीण गौरव पथ देकर सारे गांवों में सीमेंट की शानदार सड़कें बनवा दीं और आपने ग्रामीण विकास पथ के नाम पर एक पंचायत समिति में मात्र एक सड़क वह भी 80 लाख की, उससे ज्यादा नहीं, वह भी अभी धरातल पर नहीं आई है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): हां, बस एक मिनट में। मैं लास्ट कह रहा हूं, मैं खुद ही कम हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा, जैसा अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री की आपसी लड़ाई में जो सड़कों की दुर्दशा या ग्रामीण विकास की दुर्दशा, थोड़ा आप बैठ कर दोनों को बैठा दो, समझौता करवा दो, यहां पर हमको सड़कों का पैसा मिल जाए और राजस्थान के गांव सड़कों की दृष्टि से कुछ और सुदृढ़ हो जाएं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

लास्ट बात है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान मंत्री जी को जिन्होंने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक की जो पुरानी ऐसी सड़कें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनी थीं, उन सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए या उनकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, जब प्रधान मंत्री हमारे राजस्थान की सड़कों को लेकर इतने चिंतित हैं, 30 से लेकर 50 किलोमीटर एक विधान सभा में दे सकते हैं तो मेरी राज्य सरकार से मांग रहेगी कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे, यहां के ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा मिल जाए, अपने बजट से भी कम से कम 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक और 25 किलोमीटर नवीनीकरण की घोषणा हमारे मुख्य मंत्री जब वापस बजट में रिप्लाई करें, उस समय दे दें।

यह बजट बिल्कुल निराशाजनक है, बिल्कुल निराशाजनक, इससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो पहले ही कहा न हम तो बच जाएंगे, हम तो पल्ला झाड़ लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री रूपाराम।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2020-21 पर चर्चा हो रही है। इस पर मुझे भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, 20 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2020-21 का बजट पेश किया। बजट पेश करते समय उस वक्त की क्या स्थिति है, सबको ध्यान में रखते हुए, उस वक्त पिछली सरकार ने, राज्य में जो कर्जे की आवश्यकता थी, कर्जा लिया। उसमें से, जब कांग्रेस अभी सरकार में आई थी, 3,10,000 करोड़ कर्जा अभी बाकी था। भारत सरकार को जिस अनुपात में पैसा देना था, उसमें भी राशि सवा दस करोड़ करीब कम प्राप्त हुई थी। जो 2013 के इलेक्शन हुए थे, अलग-अलग विभाग के बजट प्रावधान के अलावा जो कार्यादेश दिये थे, एग्रीमेंट हुए और काम शुरू हो गये थे, उसकी देनदारियां भी लगभग 13 हजार करोड़ बाकी थीं।

उसके अलावा, भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, 2013 से 2018 तक राज्य में भा.ज.पा. का राज था। शायद उस वक्त भी केन्द्र और

(श्री रूपाराम)

राज्य के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। बाद में कांग्रेस का राज आया, लेकिन वहां भा.ज.पा. का ही रहा, तो विभिन्न योजनाओं में जो राशि स्टेट को मिलती थी, कोई 80:20 था, 70:30 था, 60:40 था, कई योजनाओं में भारत सरकार द्वारा रेशो कम कर दिया गया, स्टेट का शेयर बढ़ा दिया गया, उस वजह से स्टेट की जो आय होनी है, रेवेन्यू आना है, वह कम हुआ। पिछले 2013 से 2018 तक जिस-जिस सैक्टर में राजस्व क्या बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कोई दृढ़ नीति लाने का काम भी जिस स्पीड से होना चाहिए, 2013 से 2018 तक में नहीं हुआ।

विभिन्न विभागों में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विकसित किया जाना था, वह भी 2013 से 2018 में, पहला एक-डेढ़ साल तो 2008 से 2013 तक कांग्रेस का राज था, क्या हुआ, नहीं हुआ, जांचों में ही समय खराब किया और परिणाम यह निकला कि एक-डेढ़ साल जांच कराने के बाद में उसी परियोजना को चालू रखा गया, तो टोटेलिटी में राजस्व कैसे बढ़े, एक निरन्तरता जब बनी नहीं रहती है, तो राज आते ही कोई हाथ में जादू नहीं है कि राजस्व भी बढ़ा लें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुरंत डवलप कर लें। 2013 से 2018 तक रेवेन्यू को बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने की गति धीमी रही और राजस्व नहीं बढ़ने से आनुपातिक रूप से, जो पिछले कई वर्षों से उससे अधिक राज्य सरकार पर बोझ बढ़ा, 3,10,000 करोड़ का जो कर्ज हुआ, पिछले कई वर्षों में देखा जाए तो यह बहुत ही अत्यधिक है।

राजस्थान में पिछले 72 वर्ष का जो राज प्रजातंत्र के बाद किया जा रहा है, लगभग 10 बार में 52 वर्ष कांग्रेस ने किया और 5 बार में 20 वर्ष, अलग-अलग मुख्य मंत्रियों के रहते भा.ज.पा. ने किया। स्टेट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप हुआ है, अभी बजट की चर्चा पर हमारी तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ हमने किया और उधर से कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं किया। चाहे बांध है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप्ड है, जिससे विस्तार करके आगे बेनिफिशरी को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, तो 20 और 52 वर्ष की तुलना में देखें तो उस रेशो में बहुत अच्छे अनुपात में कम्पेयर किया जाए तो कांग्रेस के राज में जनहित में काम अधिक हुए हैं।

जहां तक पब्लिक का राज़ी या नाराज होने का है, वह भी अगर आप

(श्री रूपाराम)

52 वर्ष में देखें तो 2013 को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को जनता ने बहुत ढंग से चाहा। कई बार तो 50 प्रतिशत मत से भी अधिक मत मिले 2013 को छोड़कर। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, 20 फरवरी को जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, जो संसाधन उपलब्ध थे, राजस्व की प्राप्तियां क्या होनी हैं, और भारत सरकार के पिछले ट्रेंड को देखते हुए क्या प्राप्तियां होनी हैं, पिछले कई वर्षों तक भा.ज.पा. सरकार ने भी कोशिश की, 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार ने भी बहुत कोशिश की।

मैं भी राजस्थान सरकार के एक विभाग में एक अधिकारी था। वाटर सैक्टर के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से एक नोट बना करके भारत सरकार को गया था। वह प्रोसेस में होने को था, जिसके अन्दर पेयजल की जो यहां भूमिगत, सरफेस सोर्स और जो यहां की विकृति है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, और पापुलेशन की डेन्सिटी कम है, उस हिसाब से यहां पहाड़ी क्षेत्र में विशेष क्षेत्र को देखते हुए जो 80:20 के रूप में मिलता है, अपने भी कई सैक्टर्स में उसी अनुपात में मिलना चाहिए लेकिन उसकी पर्स्युएंस भी 2013 से 2018 में नहीं हुई। उसका भी अभी तक हुआ नहीं है। अभी जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, फिर 90:10 का पेयजल के सैक्टर में कहा, तो उसमें भी विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जाता है कि अपने यहीं से जनरेट करें। अपने यहां से जनरेट करना कोई गलत नहीं है लेकिन वहां अपना हक है। राजस्थान, भारत का एक अंग है। अन्य राज्यों की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अपना राज्य आये तो अपने को पर्सेंटेज अधिक क्यों देना है, उसका भी, मेरे ख्याल से एक भी सदस्य महोदय द्वारा यह नहीं कहा गया कि यह मांग सही है, हम भी कहेंगे तो रिर्सोसेज हैं, भारत सरकार से पैसा लेना या यहां रेवेन्यू बढ़ाना, उसी से ही अपन राज्य की, जहां आज की तारीख में अपन खड़े हैं, और कहां ले जाना है, उसके ज़रिये आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 वर्ष पहले मुख्य मंत्री रहते हुए, कांग्रेस ने जो 52 वर्ष राज किया, उसमें उन्होंने किया, तो अभी 2019-20 एक शुरुआत थी, इलेक्शन ईयर था, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो बजट में घोषणाएं की थीं, उनमें अभी व्यय कम हुआ है, एक्सपेंडीचर नहीं हुआ, फिजिकल वर्क नहीं हुए। किसी का भी राज रहा हो, पहले तीन तिमाही में,

(श्री रूपाराम)

दिसम्बर तक का अभी एक्सपेंडीचर या फिजिकल वर्क्स की मोनिटरिंग हुई और जो आंकड़े हैं, पहले तीन तिमाही में प्रगति वास्तव में 50 या 60 प्रतिशत, ऐसे ही आती है, कई जगह 40 प्रतिशत भी आती है। लास्ट का, जो जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, उसमें अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति होती है। तो पिछले बजट की जो भी घोषणाएं हैं, वह 31 मार्च, 2020 तक काफी पूर्ण हो जाएंगी।

आगे के लिए बजट 2020-21 में सात संकल्प लेकर और अलग-अलग जो घोषणाएं की हैं, सभी सदस्यों ने एक-एक सैक्टर में विस्तार से बात की है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। खेलों के बारे में कुछ-एक सदस्यों ने जरूर थोड़ा सा कहा कि ठीक किया है। मैं भी खेलों से जुड़ा हुआ हूं। इंडिया में राजस्थान स्तर पर भी कई खेलों में अध्यक्ष भी रहा हूं या एकाध में हूं। आज पूरे राजस्थान में प्रतिदिन का भत्ता राजकीय प्रतियोगिताओं में 300 रुपये से 600 हुआ है, यह 600 कहीं नहीं है। पहले हरियाणा, पंजाब हम से आगे थे। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हजार रुपये हुआ। ओलम्पिक्स, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स के अन्दर जो इनामी राशि घोषित की है, वह भी किसी भी राज्य में इतनी व्यवस्था नहीं है, अधिक की है। इससे अपने राजस्थान की जो सात करोड़ की आबादी है, इसमें यहां का वातावरण है, लोगों की फिजिक्स है, खेलों में काफी आगे बढ़ेंगे।

पानी के लिए मैं भारत सरकार को यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान ऐसा राज्य है कि अपना जो भूमिगत पानी था, करोड़ों वर्षों से जो भूमि के अंदर था, वह पानी ड्राअल हो गया है, अधिक ड्राअल हो गया, पानी कम है तो पूरे राजस्थान को चाहे चंबल नदी हो, नर्मदा हो, इंदिरा गांधी नहर हो, बीसलपुर बांध हो, जवाई बांध हो या उदयपुर डिवीजन, भरतपुर डिवीजन और कोटा डिवीजन के छोटे-छोटे लोकल डैम्स हों, उन पर लेने के लिए अभी भी कई गांव और शहर ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं तो पेयजल को सतही स्रोतों पर लेने के लिए अभी कई स्टेट्स हैं जो सतही स्रोत पर कवर हैं, उनको सिर्फ घरेलू कनेक्शन चाहिए, राजस्थान उसमें से नहीं है। अभी कई जगह पर पानी खारा हो गया है, क्वांटिटी कम हो गयी है तो पहले उनको पानी पहुंचाएं फिर घरेलू कनेक्शन हो। साथ-साथ दोनों चलें तो अपने को अधिक पैसा मिलना चाहिए था।

भारत सरकार ने जो प्रावधान किया है, आज एक डेट तो तय कर ली

(श्री रूपाराम)

कि वर्ष इतने तक हम पूरा कर लेंगे। राजस्थान को अगर जो पहले से सरफेस स्रोत से जुड़े हुए नहीं हैं और प्लस घरेलू कनेक्शन दें यदि यह पूरे करें तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है तो वह कैसे होगा, यह समझ में नहीं आती है लेकिन सबने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की प्रशंसा की, यहां पर जो कुछ भी किया।

एक समय ऐसा था, मैं भी गांव से आता हूं। बाड़मेर में बाढ़ आई थी, लोगों को चिकनगुनिया हो गया था, हम लोग भी वहां पर किसी संस्था के थ्रू गये थे तो कई लोग ऐसे थे कि जो चिकनगुनिया की दवाई लो, तीन-चार हजार रुपये लगते हैं, उसके बाद में छह महीने तक उनके गोड़ों में दर्द होता है। मजदूरी करने जाओ मत, डाक्टर कहता है कि रेस्ट करो, रेस्ट करे तो वह कमाकर कैसे खाए? ऐसी स्थितियां थीं और जब 2008 में बजट में नि:शुल्क दवाइयों की घोषणा की गयी, जांचों की की गयी। 2013 में कांग्रेस की सरकार नहीं आई, भाजपा ने खिल्ली उड़ाई और रेवड़ियां बांटने की कई बातें कहीं लेकिन जिस बीमार को सहायता मिली थी, उनके आश्रितों को पूछो, उनसे पूछो कि उन्हें कितनी रिलीफ मिली है।

इसी बजट में नीरोगी राजस्थान के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया परंतु इसमें जो 2013 की व्यवस्थाएं थीं, उनको बीच में पांच वर्ष तक ढंग से लागू नहीं किया गया और अब उसको पूर्णतया लागू करके उसको बढ़ावा दिया गया। चाहे दवाइयों की संख्या हो, चाहे रोग है, जिसके अंदर ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): चाहे कैंसर, किडनी, लिवर का हो, जांच का हो तो सबमें बढ़ाया तो यह जो बजट पेश किया गया है, स्टेट की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, संसाधनों को देखते हुए और राजस्व कैसे बढ़ाएंगे वह भी आने वाले तीन-साढ़े तीन वर्ष में सबको पता लगेगा, उसके लिए भी नई नीतियां लायी गयी हैं, लायी जा रही है और प्रक्रियाधीन भी हैं।

सरकार के हम लोग भी अंग हैं, मैं भी एक अंग हूं। मैं जैसलमेर जिले के लिए कुछ कहना चाहूंगा। जैसलमेर जिला जिसका क्षेत्रफल करीब 39 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के 9 जिलों की 43 ग्राम पंचायतों, विधान सभा क्षेत्र के बराबर है तो मेरा यह निवेदन है कि जो भी फैसिलिटीज,

(श्री रूपाराम)

आधारभूत सुविधाएं दी जाएं, वहां पर पापुलेशन की डेन्सिटी कम है, लेकिन रेगिस्तानी एरिया को देखते हुए उस रेशो के अंदर चाहे स्कूल हों, चाहे हैल्थ का हो, पानी का हो, सड़क का हो, उस रेशो में जिले का अधिक ध्यान रखा जाए।

अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि सरकार ने यह घोषणा की कि हमने जो स्कूलें बंद की थीं, वह चालू करेंगे, वह नहीं हुई हैं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। सरकार ने आते ही निर्देश दिये, जिलों से रिपोर्ट आई और वास्तव में ऐसा हुआ कि एक-डेढ़ किलोमीटर में थी, वह ही हमने मर्ज की है। मेरे जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में एक हमीरों की बस्ती है, चालीस किलोमीटर नजदीक में न कोई गांव है और न कोई ढाणी है, स्कूल का तो कोई अता-पता ही नहीं है, उसको भी बंद कर दी थी। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी करीब एक हजार स्कूलें पुन: मर्ज से मुक्त होकर खुल गयी हैं, उसमें 85 स्कूल जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र की हैं। अब 85 स्कूलें बंद कर दीं और जो नोर्म्स में नहीं आती थीं, उनके जो नोर्म्स बनाये गये थे, उसमें नहीं आती थीं तो इससे बुरा क्या हो सकता है?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री रूपाराम** (जैसलमेर): मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो बजट पेश किया गया है सैक्टरवाइज, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री सुरेन्द सिंह राठौड़।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में सात संकल्प लिए हैं। प्राथमिकताएं तय की हैं, उसमें पहला संकल्प यह है- नीरोगी राजस्थान। पहला सुख नीरोगी काया और अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक अपने भाषण में यह बता रहे थे कि 2008 से 2013 की सरकार में किस तरह नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ की गयी थी।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, 2013 से 2018 तक हमारी सरकार ने जो भामाशाह योजना लागू की, उस योजना में गरीबों को 30 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक फ्री इलाज होता था। वह केवल सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि कुछ चिह्नित प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका इलाज होता था, लेकिन जब से यह सरकार आई है, इन्होंने यह नहीं सोचा कि हम कोई योजना लाने से पहले, सबसे पहले यह काम इस सरकार में आने के बाद इस राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ कुठाराघात किया और भामाशाह योजना को बंद किया। एक साल से वह बीमार लोग आपको बद्दुआ दे रहे थे, और आज आप इस बजट में पहला सुख नीरोगी काया की बात कर रहे हो और उनकी बद्दुआ का पहला परिणाम यह आया है कि पंचायत चुनाव में उन्होंने आपको निपटा दिया है।

अब आप इस बजट में, इसमें अब कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री थोड़ा जादूगरी तो जानते ही हैं, उसकी तो हम भी प्रशंसा करते हैं। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना, केन्द्र सरकार की योजना को मिलाकर थोड़ी सी जादूगरी कर अपनी सरकार को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए यह मैसेज देने का प्रयास किया है, लेकिन राजस्थान की जनता यह जानती है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कौन लेकर आया है। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक सबको यह पता है कि यह योजना श्री नरेन्द्र भाई मोदी, भारत के प्रधान मंत्री ने लागू की है। आपने यहां पर नि:शुल्क दवा योजना भी वापस लागू की है, लेकिन चाहे सब सैंटर्स देख लो, पी.एच.सीज. देख लो, सी.एच.सीज. देख लो, जिला अस्पतालों को देख लो, हमारे राजसमन्द जिले में आज की तारीख में 60 प्रतिशत पोस्ट्स इन पर खाली पड़ी हुई हैं। कौन आपकी वह निशुल्क दवाई जाकर देगा? इस नि:शुल्क दवाई के बारे में, पहले 2008 से 2013 के बीच भी आप यह दवाइयां देते थे, उस समय गांवों में चौपाल पर एक मजाक बन गयी थी कि गांव का कोई आदमी आता था, दस-दस लोग लाइन में लगते थे, उस सैंटर के ऊपर जब वह मरीज कहता था कि मेरे सिर दर्द हो रहा है तो दो तरह की गोली उसको देते थे, जब दूसरे का नम्बर आता था तो उसको भी वही दो तरह की गोली देते थे, जब तीसरा कहता था कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे दस्त है तो वही गोलियों के पैकेट पकड़ा दिये जाते थे और जब कोई बहस करता था तो वहां ए.एन.एम., कम्पाउंडर और डाक्टर्स यह कहते थे कि तुम्हारी सरकार जो दवाई

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

भेजती है, वह दवाई हम देते हैं, थोड़ा गर्म पानी कर लेना और दो गोली ज्यादा खाकर सो जाना। इन फ्री दवाइयों की गांवों में यह हालत हुई, इसलिए हमारी वसुन्धराजी की सरकार ने भामाशाह योजना लाकर लोगों की मदद करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा संकल्प, सम्पन्न किसान। हमारी सरकार ने सहकारी समितियों का 50 हजार तक का कर्जा माफ किया था। हर सहकारी समिति के वहां शिविर लगे थे। हम स्वयं उन शिविरों में गये हैं। 50 हजार कर्जे के बाहर तो प्रमाण-पत्र दिये हैं और साथ में उसको 50 हजार तक का नया लोन भी दिया है। यह पहली सरकार थी जो कर्जा भी माफ करती है और उसी दिन, उसी शिविर में आगे के लिए लोन की भी स्वीकृति प्रदान करती है।

आपकी सरकार आयी। जब 2013 के चुनाव हो रहे थे तो मेवाड़ की धरा पर सागवाड़ा की भूमि पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल को लाया गया। एक तरफ वर्तमान मुख्य मंत्री विराज रहे थे और दूसरी तरफ वर्तमान उप-मुख्य मंत्री विराज रहे थे और वहां यह घोषणा करवायी गयी और गिनती गिनवाई एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दस होते ही मंच पर सब नेता तालियां बजा रहे थे। सब किसानों का कर्जा दस दिन में सम्पूर्ण हम माफ कर देंगे। कई गांवों में किसान थे, जिनके ट्रैक्टर पर भी लोन थे। दो लाख, चार लाख, पांच लाख तक के लोन थे, उन्होंने देखा कि वसुन्धराजी की सरकार ने तो 50 हजार तक का कर्जा माफ किया, यह तो दो-दो लाख का कर्जा माफ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह कहा कि पाइंट फाइव परसेंट मत आपको ज्यादा मिले और आपकी अल्पमत सरकार यह आयी है और आज उन ट्रैक्टरों के पीछे बैंक की गाड़ियां दौड़ रही हैं। पुलिस की गाड़ियां उनको पकड़ रही हैं और ट्रैक्टर सीज हो रहे हैं। किसान आपकी तरफ देख रहा है। उन्हीं किसानों ने इन पंचायत के चुनावों में आपको निपटाया है।

माननीय सभापति महोदय, यहां तीसरा संकल्प है - महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण। महिलाओं के साथ इन पन्द्रह महीनों में क्या हालात हुए राजस्थान के? कई माननीय सदस्यों ने यहां प्रश्न के द्वारा और अन्य माध्यमों से कई बातें यहां उठायी हैं। हालात आपके सामने हैं। इसमें बाल कल्याण भी बताया गया है, वृद्ध कल्याण भी बताया गया है। मैं वृद्ध कल्याण के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन यह निवेदन करना चाहूंगा कि पन्द्रह

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

महीनों में आपकी सरकार के अंदर जो माननीय वरिष्ठ विधायक हैं, जो वृद्ध विधायक हैं, जब उनके चेहरे हम उधर से देखते हैं तो उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि सरकार में उन वृद्ध लोगों के क्या हाल हैं? माननीय सदस्य भी सुरक्षित नहीं हैं। उनको भी कोई मान-सम्मान नहीं मिल रहा है। इस सरकार में यदि डिविजन आये तो आप डिविजन करवाओ, यह वरिष्ठ माननीय विधायक इस सरकार को बता देंगे कि हम कितने दु:खी हैं। लेकिन आप टालना चाहते हो डिविजन आये तब।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, यहां चौथा संकल्प है - सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान। इस राजस्थान के युवाओं ने देखा, आपने 2019 के बजट में घोषणा की है कि 3 हजार रुपये छात्र को और 3,500 रुपये छात्राओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि आप कहीं स्कूटी लेकर जाओ तो पैट्रोल के लिए मां-बाप की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब यह गहलोतजी की सरकार आ गयी है। आप बैंक में जाओगे तो महीना होते ही आपका भत्ता खाते में पहुंच जाएगा और आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन वह युवा इतने आक्रोश में आ गये और इन युवाओं ने भी पंचायती राज के चुनाव में आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर आपको सावधान किया कि अब भी संभलो, नहीं संभलते हो तो ठीक है, आपकी सरकार है, मर्जी आये जो करते रहो आप। दो बजट तो आ गये हैं, दो और रख दोगे। पांचवें बजट में कोई सुनता है नहीं। फिर इधर आ जाओगे।

माननीय सभापति महोदय, पांचवां संकल्प है - शिक्षा का परिधान। शिक्षा मंत्री यहां अभी बिराजे हुए नहीं हैं। जब यहां इस तरफ बिराजते थे, तब शिक्षा मंत्री बहुत जोस्शोर से बोलते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा मंत्री को क्या हो गया है। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। 22 हजार स्कूलें जब मर्ज हुईं तो उन्होंने बहुत आवाज उठायी और जब हमने देखा टीवी. पर कि शिक्षा विभाग डोटासरा साहब को मिला है तो हमने भी भाषण दिये थे कि वह स्कूलें बंद हो गयीं, लेकिन अब तो गोविन्द सिंह डोटासरा जी आ गये हैं, लोग देख रहे थे, डोटासरा साहब आये हैं और उन 22 हजार स्कूलों को खोल देंगे। लेकिन उनके तो हालात यह हैं कि 2019 में 50 प्राइमरी स्कूलें दीं, उसमें से उन्होंने केवल दो खोलीं। एक खुद की विधान सभा क्षेत्र में और दूसरी बांसवाड़ा में। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग कैसे चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, शांत रहें।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, यह तो आप जानते ही हो और जब भी आप मुझे पुकारोगे, उसके पहले टाइम होते ही मैं बैठ जाऊंगा। अनुशासन में रहता हूं और कोई दूसरा बीच में बोलेगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

**श्री सभापति**: आपकी सेहत देखकर वैसे ही कोई नहीं बोलेगा। नीरोगी काया का पूरा फायदा आपने ही लिया है।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): अब शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, नीरोगी काया का जो स्लोगन है न, उसका पूरा फायदा आपने ही लिया है।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, सब तरफ स्कूलें समान खोलेंगे। उनको यह पता ही नहीं कि राजसमंद जिले में चार विधान सभा क्षेत्र हैं। इन्होंने 15 स्कूलें क्रमोन्नत कीं, माननीय सभापति महोदय, वह भीम और नाथद्वारा में की हैं। कुंभलगढ़ और राजसमंद विधान सभा क्षेत्र, राजसमंद जिले में नहीं हैं क्या? इससे पता चलता है कि आपकी मंशा क्या है? आपकी मर्जी आये जो करते रहो। लेकिन धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि यह जो आप भेदभाव कर रहे हो, यह भेदभाव मत करो। सरकार आपकी है, कुंभलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आप पता कर लेना कि किस बूथ पर आप जीते हो। मैं कह रहा हूं 242 में से 42 बूथ पर आप भी जीते हो। वहां तो स्कूल खोल देते और फिर मंत्रीजी वहां आकर फीता काट देते। मैं भी वहां पर एक साफा लेकर खड़ा रहता और उनको एक साफा बंधवा देता। आप भेदभाव मत करो, जनता देख रही है। जब अखबारों में छपा था कि इन दो विधान सभा क्षेत्रों में 15 स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं तो उसी समय सोशल मीडिया पर चल गया। अब शिक्षा मंत्रीजी को समझ में आ गया तो आगे ध्यान में रखेंगे और नहीं रखेंगे तो उनकी इच्छा पर है।

माननीय सभापति महोदय, छठा संकल्प है - पानी, बिजली और सड़कों का मान। पानी की यह हालत है, माननीय सभापति महोदय, राजसमंद जिले में डीएमएफटी का पैसा पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर का है, जहां सबसे ज्यादा पैसा आता है। 2017-18 में हम चारों विधायक भाजपा के थे। राजस्थान में पैसा खर्च करने में हमारा जिला पहले नंबर पर आया। हमने वहां 160 सड़कें 2017-18 में कुंभलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बनवायी थीं और एक-एक विधायक ने बनवायी थी।

**श्री सभापति**: सारा पीएचईडी विभाग आपके पास ही था तब तो।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): पीएचईडी का तो अब बोलूंगा, अभी मैं सड़कों पर बोल रहा हूं। यह तो सड़कों का उदाहरण बता रहा हूं आपको। सरकार के सामने आने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप यह हमारा पैसा सही लगवा दो। आपका बजट बच जाएगा।

पानी पर भी मेरी विधान सभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना है बेडच का नाका, उसका शिलान्यास हुआ था। जब गहलोत साहब की पहली सरकार थी। उस समय शिलान्यास हुआ और आपने भी उस समय प्रयास किया, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं आई, जिससे वह कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। 2003 से 2008 में हमारी सरकार आई, उस समय मैं सरकार में मंत्री भी था, हमने भी प्रयास किया, लेकिन वह एनओसी नहीं आने की वजह से नहीं हो पाया। अब जब 2017 में एनओसी आ गई, तो 2018 में डीएमएफटी योजना में 25 करोड़ रुपये इस बेड़च का नाका के लिए स्वीकृत कर दिये गये थे। उस समय यह प्रावधान था कि एक करोड़ से ऊपर की योजना होगी तो चीफ सैक्रेटरी की कमेटी में जाएगी, चीफ सैक्रेटरी ने उसको एप्रूव भी कर दिया पर तब तक चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। 15 महीने में यह सरकार उस महत्वपूर्ण पेयजल योजना के लिए केवल वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं कर पायी है। यह हाल है आपके पीएचईडी के।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): मैंने तो कहा कि आप नहीं बताओगे तो भी बैठ जाऊंगा मैं।

**श्री सभापति**: नहीं, दो मिनट बाद।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): ठीक है, धन्यवाद आपको। सड़कों के बारे में यहां गत बजट में आपने घोषणा की, गौरव पथ आपको पसन्द नहीं आया। जब हमारी सरकार थी, भाटी साहब, आप भी हमारे साथ विधायक थे, आपके गौरव पथ मिले या नहीं मिले? मुझे अच्छी तरह से याद है, जब आप मुख्य मंत्री से मिल रहे थे कि ये-ये गौरव पथ बाकी हैं तो मुख्य मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया था कि हम इनको मंजूर कर देंगे। कोई भेदभाव नहीं किया। तीन साल के तीन चरण में राजस्थान की 9 हजार पंचायतों में गौरव पथ बनाये। आज गांव के लोग अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

दुर्भाग्य है कि इस सरकार के नम्बर टू, उप मुख्य मंत्री के पास यह डिपार्टमेंट और 2019 में एक घोषणा हुई थी, गौरव पथ हमें पसन्द नहीं है, हम तो विकास पथ बनाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप विकास पथ बनाओ। लेकिन कहां बनाओगे? एक पंचायत समिति ब्लाक पर एक। उसके भी अभी तक टेंडर नहीं हुए। मैं तो कहना चाहता हूं कि इन दोनों का झगड़ा अब आप ही मिटा सकते हो। आप इस पर निर्णय करवाओ कि सरकार एकमुखी होकर चले। क्यों जनता के साथ यह धोखा हो रहा है? उप मुख्य मंत्री जी के पास दो विभाग हैं, पंचायती राज विभाग और पीडब्ल्यूडी, दोनों विभाग 15 महीने से ठप पड़े हुए हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): अन्त में, मैं एक मांग रखकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, जब पूर्व में आपकी सरकार थी तो आपने, गहलोत साहब ने भी घोषणा की थी कि राजसमन्द झील में माही डैम का ओवर-फ्लो पानी लेकर आएंगे और 5 करोड़ का आपने बजट भी दिया था लेकिन वह योजना सफल नहीं हुई। हमारी सरकार में भी प्रयास हुआ लेकिन हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि राजसमन्द झील में माही डैम का ओवर-फ्लो लाने के लिए आप योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजें। हम भाग्यशाली हैं कि राजस्थान के ही गजेन्द्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं, हमारी सांसद महोदया इसमें प्रयास कर केन्द्र सरकार से इस योजना को मंजूर कराने का प्रयास करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सरकार से यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार तक भिजवा दें।

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री सुरेन्द सिंह राठौड़** (कुम्भलगढ़): मैं अन्त में कहूंगा कि यह बजट निराशाजनक है, किसी को भी इससे आशा नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

**श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): सर, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

**श्री सभापति**: विराजिये। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सदस्य, आप दुरुस्त कर लो, दो नहीं एक हजार खुल गईं।

**श्री सभापति**: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

**श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (बसेड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे 2020-21 के बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 2020-21 का बजट पेश किया है, वह सभी वर्गों के लिए, किसान, महिला, युवा, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क और सात संकल्प के साथ पेश किया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी भी जब बजट पर बात करते हैं तो उनका धर्म है कि उनको नेगेटिव बोलना ही होता है, लेकिन यह नहीं जानते कि जो मुफ्त दवा योजना थी उसको पूरे हिन्दुस्तान में सराहा गया और उसकी इतनी सराहना हुई, जिसकी कोई सीमा नहीं क्योंकि एक गरीब और साधारण आदमी, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उस वक्त चिकित्सा जांचें, दवा मिल जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। आज उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़कर जो नीरोगी राजस्थान के लिए काम किया जा रहा है, यह जन कल्याणकारी कार्य कोई बिरला ही कर सकता है और इसमें हमारे जो जन-नायक अशोक जी गहलोत की सोच है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। आज राजस्थान के एसएमएस में हार्ट ट्रांसप्लांट के कितने बड़े केसेज हुए हैं, कितने अग्रणी कार्य किये हैं, यह सब आप जानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिस तरह का कार्य सरकार ने घोषणाओं का किया है, मेरा क्षेत्र भी बसेड़ी है और डांग क्षेत्र से आता हूं तो वहां भी हमारे हास्पिटल में कुछ बैड बढ़ा दिये जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी।

कृषि के क्षेत्र में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2020-21 में 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व बजट में भी मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि विद्यालय खोला, जो ऐसी जगह खोला जहां बिल्कुल ही ग्रामीण, डांग और शिक्षा की बहुत जरूरत थी। उस जगह पर खोलने के साथ-साथ मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उसके तुरन्त बाद 3 महीने के भीतर ही वहां पर क्लासेज चालू कर दीं और क्लासेज चालू करने के बाद में आज वहां पर 60 बच्चों का अध्ययन हो रहा है और कृषि विद्यालय कार्यरत है।

महोदय, किसानों के हित में एक जो नया फैसला लिया गया है कि एडवांस में 2 लाख टन यूरिया और 1 लाख टन डीएपी भण्डारण हेतु सरकार

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

ने 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि जब खेती की बहुत मारामारी होती है, उस वक्त डीएपी और यूरिया के लिए मारामारी होती है जिससे वह परेशान होता है। उसके लिए एडवांस में यह प्रावधान किया है, यह बहुत ही अच्छी सोच है और सरकार को मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, बिजली के क्षेत्र में भी चार वर्षों में 2 हजार नवीन जीएसएस के गठन की बात कही है, वह अति महत्वपूर्ण है। इससे हमारे राजस्थान में जो वंचित क्षेत्र हैं, उनको उसका फायदा मिलेगा।

एससी, एसटी युवाओं के लिए भी 25 हजार रुपये का जो ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है, वह बहुत ही सराहनीय है। बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए जो 100 करोड़ रुपये का नेहरू बाल संरक्षण कोष स्थापित करने की बात की है, वह भी बहुत हितकारी है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार खादी पर 50 परसेंट की छूट की इससे खादी वाले लोगों को तो बहुत फायदा मिला ही मिला, इसके साथ-साथ, हमारे जो लोग खादी के वस्त्र पहनते हैं, उन लोगों ने 4 की जगह 10-10 ड्रेसें बनवा लीं जिससे बहुत फायदा मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो 150वीं जयन्ती है, उस अवसर पर खादी प्लाजा के लिए 10 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, वह हमारे सबके लिए धन्यवाद की बात है।

महोदय, मैं पंचायती राज की बात करूं तो इसमें हमारा जो डांग क्षेत्र है, उसके लिए इस बजट में सरमथुरा को पंचायत समिति बनाया उससे उस क्षेत्र में वाहवाही लूटी जा रही है और सरकार के प्रति इतना लोग धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा, 47 और भी पंचायतें बनाई हैं वे भी बहुत हितकारी हैं।

जहां तक पर्यटन की बात है, महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लेक पैलेस सिलीसेढ़, झूमर बावड़ी, गोकुल और होटल पुष्कर सरोवर के लिए 4 करोड़ रुपये की जिस तरह की घोषणा की गई है, उसमें मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस कड़ी में कुछ और भी स्टेशनों को जोड़ा जाए क्योंकि राजस्थान पर्यटन का अति महत्वपूर्ण स्थान है और यहां देश-विदेश से इतने लोग आते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रणथम्भौर की बात करें तो

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

रणथम्भौर में इतने पर्यटक आते हैं कि सीजन के टाइम में संख्या में पूरे राजस्थान का नाम आगे बढ़ता है।

**(15.00 बजे)**

सभापति महोदय, मैं शिक्षा के मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय और 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोलने का जो प्रावधान किया है, यह सरकार की शिक्षा के प्रति सही नीति है। पिछली सरकार ने जो स्कूल बंद कर दिये थे, उसमें भी इस सरकार ने विद्यालय चालू करने के लिए कई फैसले लिए हैं। उसके लिए भी इनको साधुवाद देता हूं, सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, जहां तक पेयजल की बात आती है, उसमें 8794 करोड़ एवं 51 लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत भी धौलपुर को चयनित किया है। उसके लिए भी मैं हमारी धौलपुर की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, बिजली के क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह का प्रावधान फर्स्ट फेज में रात और दिन देने का किया है, यह बहुत ही सराहनीय वर्क है। रात को हमेशा किसानों को परेशानी होती है। टर्म के आधार पर होगा तो पता चल जाएगा कि इस टर्म में बिजली यहां मिलेगी और सैकण्ड में यहां मिलेगी, तो वह प्रिपेयर होकर के ठीक से पानी दे सकेंगे। उससे किसान का बहुत भला होने वाला है।

सभापति महोदय, सरकार ने 287 जीएसएस स्टेशन खोलने के लिए भी प्रावधान रखा है। मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सात संकल्प सरकार के द्वारा पेश किए हैं, उन सातों संकल्पों में मुख्य मंत्री जी ने सभी को फायदा देने के लिए, सभी के हितों के लिए काम करने के लिए जो बजट पेश किया है, उसकी सराहना करते हुए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा में 200 सदस्य चुनकर के आते हैं। प्रत्येक विधान सभा के लगभग 2 लाख मतदाता इनके भाग्य का फैसला करते हैं। विधायकों का जो समूह बहुमत के रूप में होता है वह सत्ता के रूप में काम करता है। यह

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

सत्ता कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किया हुआ एक कार्य है, जिसके लिए हमें आगे बढ़ने का काम मिलता है। सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कार्यकर्ता के मान-सम्मान और क्षेत्र के विकास पर हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, जब से देश आजाद हुआ है, तब से केन्द्र सरकार का और राज्य सरकारों का बजट आता है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि पक्ष के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और विपक्ष के लोग उसकी बुराई करते हैं। मेरा इसमें यह मानना है कि चाहे हम पक्ष में बैठें या विपक्ष में बैठें, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जो चीज जनहित की नहीं है, उनके लिए विपक्ष में बैठे लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि सरकार को समय-समय पर सुझाव दें।

सभापति महोदय, बजट का प्रावधान वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। अब तक बहुत सारे बजट आ गए। अभी तक ऐसा कोई बजट नहीं आया जो एक ही बजट में 200 के 200 विधायकों और 7 करोड़ जनता की मांगों को पूरा कर सके।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): यह सत्ता न तो स्थायी है और न ही हमारा जीवन चिरस्थायी है। हम सबको 7 करोड़ जनता की जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। जब बजट की बात आती है तो हर साल हम बजट का इंतजार करते हैं। बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, जो आने वाले वर्ष में विकास के नए आयाम पैदा करती हैं। इस बजट पर मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा,

**'आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होतीं,**
**दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती।**
**अगर मिल जाता हर बजट में सब कुछ**
**तो अगले बजट की इंतजार न होती'।**

इन विषम परिस्थितियों में राजस्थान के गांधीवादी, लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हर व्यक्ति को जीवन में एक काम ऐसा जरूर

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

करना चाहिए जिससे कि वह सत्ता में रहे या न रहे, उसके बाद भी लोग याद कर सकें। आंदोलनों में शामिल होने के बाद, आंदोलन की बातें जनता के हृदय पर चिरस्थाई रूप से छप जाती हैं। मैं उसी कड़ी में कहना चाहता हूं कि सत्य की खोज में गौतम बुद्ध जी निकले थे। उनको लोग सत्य की खोज के लिए याद करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन से देश को आजाद कराया। इस कार्य के लिए गांधी जी को याद करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना की और हमें ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिक को जीने का अधिकार मिला। मैं बाबा साहेब के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा,

**'हमारे यह सिर का सम्मान, तेरे संविधान से मिला है,**
**हमारे चेहरे की यह मुस्कान, तेरे संविधान से मिली है,**
**औरों को जो मिला है, वह उनके नसीब से मिला है,**
**हमें तो जो मिला है भारतीयों को, तेरे संविधान से मिला है'।**

देश आजाद हुआ। देशी रियासतों के रूप में भारत का खंड-खंड हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह काम सौंपा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण का काम किया। इस काम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है।

सभापति महोदय, एपीजे कलाम साहब जैसे महान व्यक्तित्व का भारत के रामेश्वरम की धरती पर जन्म हुआ जिन्होंने भारत को मिसाइल देने का काम किया। मिसाइल मैन के रूप में आगे आने वाली सदियों तक एपीजे कलाम साहब को याद किया जाएगा। महिला शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले को याद किया जाएगा।

इतना ही नहीं, विश्व धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो में जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे, उसमें पहले तो उनको समय नहीं दिया जा रहा था लेकिन जब समय देने की बात आई और जब उन्होंने शून्य पर अपनी बात शुरुआत की तो वह लंबे समय तक बोलते रहे। इस विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नाम रोशन किया। इसके कारण से स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया जाता है। जब अख़बार में, अमेरिकन मीडिया में खबर छपी तो स्वामी विवेकानंद जी को साइक्लोनिक हिन्दू के नाम से लिखा गया।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

सभापति महोदय, संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा को शामिल करने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसके लिए अटल बिहारी जी को भी याद किया जाएगा। सूचना का अधिकार डा. मनमोहन सिंह जी ने दिया। इस अधिकार के लिए डा. मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं इसी कड़ी में एक व्यक्तित्व का नाम और जोड़ना चाहता हूं। पिछली बार जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मैं भारत सरकार के भारतीय राजस्व विभाग में अधिकारी के रूप में काम कर रहा था। कई बार जब मैं गांव आता तो देखता कि गरीब मां उसके बच्चे को दिखाने के लिए तरसती रहती थी। अपनी जेब की तरफ देखती थी, लेकिन उस गरीब मां के बच्चे की चिंता आदरणीय अशोक जी गहलोत ने की। उन्होंने मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना चालू की।

सभापति महोदय, देश में बहुत सारे प्रदेश हैं बहुत सारी सरकारें चलती हैं, केन्द्र सरकार अपनी तरह से काम कर रही है, राज्य सरकारें अपनी तरह से काम करती हैं। उस गरीब की मां और उसके बच्चे का इलाज कराने का काम पहली बार अशोक गहलोत जी ने किया। इस तरह से इन महान व्यक्तित्वों में एक और नाम अशोक गहलोत जी का मैं जोड़ना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने इस तरह से काम किया कि,

**'चल ए नजीर इस तरह से कारवां के साथ,**

**कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले'।**

चाहे तू सत्ता में रहे या नहीं रहे, 2013 से 2018 तक वे सत्ता में रहे या न रहे लेकिन इस दास्तां को लोग आज भी याद करते हैं। मैं इस बात के लिए थोड़ी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा कि हमारे सुरेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब कह रहे थे कि एक गोली का, जब भाजपा की सरकार होती है या कांग्रेस की सरकार होती है तो कम्पाउण्डर वही होते हैं, गोली भी वही रहती है लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि वह गोली असर नहीं करती और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वह गोली असर नहीं करती है। आखिर वह एक ही कम्पनी से तो गोली आ रही है। जनहित का तो मुद्दा ही है इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे माननीय सदस्यों से कि हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उस

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

कार्यकर्ता ने विधायक के रूप में भेजा है, इसलिए सकारात्मक चर्चा पर यदि हम ध्यान देंगे तो हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का विकास सम्भव हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में गांव, गरीब, व्यापारी मजदूर की चिंता की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ, मेडिकल कालेज जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से खुलने की बात चल रही है, स्वीकृति भी शायद जारी हो गयी है, मैं दोनों सरकारों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, महुवा में एडीजे कोर्ट गहलोत सरकार ने खोला है, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। किसानों को दो चरणों में बिजली देने की बात है, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी से, इसे 2023 तक नहीं ले जाकर किसानों को अगले साल से ही पूरे राजस्थान को दो चरणों में दिन में बिजली देने की बात करें तो यह बहुत अच्छा साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले दौसा से दिल्ली-मुम्बई, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं लालसोट से, हम सबको एक ऐसी सौगात मिली है कि जयपुर और दिल्ली की जब यात्रा होगी तो दौसा होकर ही आएंगे, जाएंगे। दौसा से डेढ़ -दो घण्टे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, यह हमारे लिए दिल्ली और मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे बन रहा है, हम उन सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे दूसरी बार महुवा विधान सभा क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाकर भेजा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जनता का आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से,

**"वक्त बदला, मौसम बदला और बदली तस्वीर,**
**महुवा विधान सभा क्षेत्र के लोगों को बधाई,**
**गुण्डाराज को खतम करके,**
**वोट के दम पर बदल दी मेरी तस्वीर,**
**बदल दी मेरी तस्वीर।"**

आज मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों ने थ्री फेज के कनेक्शन ले रखे हैं, पानी बहुत डीप में चला गया है, उनका बिल ज्यादा आता है इसलिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसानों की बात को ध्यान रखते हुए पांच केवीए का सिंगल फेज का कनेक्शन दिया जाए ताकि उनकी सिंचाई का काम ढंग से हो सके।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए उसे समुचित उपाय करने चाहिये। साथ ही महुवा में आर्मी में बहुत लोग नौकरी करते हैं अत वहां पर कैंटीन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। विधायक कोष को गोशाला में लगाने का भी प्रावधान होना चाहिये।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): माननीय सभापति महोदय, युवाओं के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी उद्योग हैं उनमें अस्सी प्रतिशत राजस्थान के युवाओं को ही रोजगार दिया जाए। बसवा में राणा सांगा का जो स्मारक है उसे बनाने की कृपा करें तो बहुत मेहरबानी होगी। संविदा कर्मियों को भी अगर स्थायी किया जाए और उन पर विचार करे सरकार तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ईसरदा डैम जिससे हमारे पूरे दौसा जिले को पानी की व्यवस्था होनी है, लालसोट, सिकराय, दौसा, बांदीकुई और महुवा, इसका काम जल्दी शुरू करके पूरे जिले को पानी दिया जाए तो बहुत बेहतर सुविधा होगी। हिंगोटा और रसीदपुर, दोनों गांवों में विज्ञान संकाय खोलने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। महुवा में एक एडिशनल एसपी के आफिस के लिए अभी कार्यवाही चल रही है, जिस तरह की वहां की अपराधों की स्थिति है, उसके अनुसार यह आफिस जल्दी खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी हमें एमएलए क्वार्टर खाली करने के लिए एक चिट्ठी दी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, न तो विधायक हैं, न वो मंत्री हैं, उसके बाद भी आपने ऐसे लोगों को बड़े-बड़े बंगले दे रखे हैं। आप समझ रहे होंगे इन सब चीजों को, उन बंगलों को खाली कराइये। हम विधायक तो एक मिनट में खाली कर देंगे, पहले उनको तो खाली करा लीजिये।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): बस, समाप्त कर रहा हूं, सर।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो राज्य सभा में हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, किसी का नाम नहीं लेंगे, समाप्त करें।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): नाम नहीं लूंगा साहब।

**श्री सभापति**: श्री धर्मनारायण जोशी।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): नाम नहीं लूंगा, साहब।

**श्री सभापति**: समाप्त करो आप, बात हो गई आपकी। (व्यवधान) आपकी बाकी की जो प्रोब्लम है सदन के बाहर के बारे में, वह आप अध्यक्ष महोदय को बताएं।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): एक मिनट, सर। धर्मनारायणजी, एक मिनट।

मैं यह कहना चाहता हूं साहब कि भारत के किसी भी कोने में अगर हैलीपेड बनाया जाएगा तो उसकी राजस्थान सरकार, भारत सरकार और विमानपत्तन विभाग से परमिशन ली जाती है खसरा नम्बर 765 और खसरा नम्बर 815 में माननीय सांसद महोदय ने अवैध रूप से हैलीपेड बना रखे हैं दूसरे की जमीन पर, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) के बारे में अंकित नहीं होगा।

**श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महुवा): 000

**श्री सभापति**: विराजिये। श्री धर्मनारायण जोशी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): माननीय सभापति महोदय, रिकार्ड से वे सारी चीजें ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: कह दिया, अंकित नहीं होगा, कह दिया।

**डा. महेश जोशी** (सरकारी मुख्य सचेतक): किसी का नाम नहीं लिया।

**श्री सभापति**: यह अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): तो फिर डिबेट चालू कर दो। मुख्य सचेतक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप अच्छा मानते हैं न, चलो शुरू कर दो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्लीज।

**डा. महेश जोशी** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय सभापति महोदय, बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तीसरा दिन हो गया, बजट पर चर्चा हो रही है। मैं मन से बहुत दुखी हूं जिस प्रकार से राजनीति और क्षेत्रीयता को लेकर लामबंद हो रहे हैं।

**श्री सभापति**: पांच वर्ष काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रसन्न रहिये और पांच वर्ष तक निकालिए, इतने ज्यादा दु:खी मत होइये। (व्यवधान)

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): हमारे मेवाड़ के साथ में अन्याय किया है, माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू यहीं से कर लेता हूं। केवल मात्र विधान सभा के अध्यक्ष सीपी साहब थे इसलिए सड़क के लिए 40 करोड़ रुपये दिये हैं, मेवाड़ को कुछ भी नहीं दिया। मैं यहीं से शुरू करता हूं। उदयपुर के लिए 50 करोड़ की पिछले साल घोषणा की शहर के लिए, एक रुपया नहीं दिया। गत बजट की बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस केवल नारे देती है। इन्दिरा गांधी आयी है, नई रोशनी लायी है। कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ, 54 साल से जो पार्टी राज्य में राज कर रही है, 54 साल हो गये और भारतीय जनता पार्टी का राज केवल 20 साल रहा, माननीय अशोक गहलोत साहब के लिए कहना चाहता हूं, तुलसीदासजी ने कहा है कि "मुखिया मुख सो चाहिये, खान में एक, सकल अन्न पालन करे, तुलसी सहित विवेक।" ऐसा मुखिया चाहिये हमारे समाज को यहां।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, गत बजट भाषण 10 जुलाई, 2019 के कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

बिन्दु संख्या 17 में एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की थी, वापस घोषणा हो गयी है, साल भर में कुछ नहीं हुआ। बिन्दु संख्या 21 में प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दीशाला स्थापित करने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिन्दु संख्या 32 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, साल भर से काम बंद पड़े हैं, नये काम स्वीकृत होना तो दूर, अधूरे काम भी पूरे नहीं हुए। बिन्दु संख्या 92 में उदयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपये दिये, कुछ नहीं मिला, कोई समाधान नहीं। बिन्दु संख्या 119 में बेणेश्वर धाम, हमारे मेवाड़ का प्रसिद्ध धाम है वागड़ का, हाई लेवल पुल की डीपीआर के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान था, कुछ नहीं हुआ। बिन्दु संख्या 131 में 18 भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण की घोषणा की, कुछ

(श्री धर्मनारायण जोशी)

नहीं हुआ। मेरे मावली क्षेत्र में भी कालेज का भवन बनना था, कुछ भी नहीं हुआ। बिन्दु संख्या 158 में पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये जाएंगे, माननीय सभापति महोदय, वह स्वागत कक्ष हम विधायकों को डीजी, आईजी, सब कह रहे हैं कि आप पैसे दो, मैंने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात-सात लाख रुपये दो थानों के लिए स्वागत कक्ष के लिए दिये, कुछ भी नहीं हुआ। बिन्दु संख्या 187 में हमारे परिवहन मंत्री और माननीय उप मुख्य मंत्री, विधान सभा चुनाव के पहले रोडवेज वालों की हड़ताल चल रही थी, आप वहां गये थे, आपने कहा कि आप हड़ताल समाप्त कर दीजिये। आज भी रो रहे हैं वह कर्मचारी। संविदा वालों के लिए आपने कहा था कि इनको परमानेंट करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। पिछली बार बजट में महात्मा गांधी के सात बिन्दु दिये थे, ...(व्यवधान) उनका आज नाम नहीं है। श्रम विहीन सम्पत्ति, विवेकहीन भोग विलास, चरित्रहीन शिक्षा, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, त्याग विहीन पूजा, सिद्धांत विहीन राजनीति, कुछ भी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर पिछले कई वर्षों से पानी का अभाव है। बागोलिया डैम के लिए डीपीआर बनी है, सर्वे हो गया है। माननीय सभापति महोदय, सरकार से मेरा निवेदन है कि डीपीआर बन गयी है, आप पैसा नहीं दे सकते हैं, आप एक रिपोर्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भिजवाएं, मेरी माननीय केन्द्रीय मंत्री से बात हुई है, वे हमें पैसा देने के लिए तैयार हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने संकल्प लिया- 'पहला सुख, नीरोगी काया'। मैं तो कोटा के अस्पताल के उन बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी कृपा से गहलोत साहब के मन में सद्‌बुद्धि आयी। तब जाकर वे नीरोगी राजस्थान का संकल्प ला रहे हैं। आज मेडिकल की स्थिति क्या है? हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में दस दिन पहले एक फोटो आयी थी। एक मां की डिलीवरी थी और खाट पर उसे ले जाया जा रहा था। अब मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खोलें आप, फ्री में दवाएं दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं 2008 से कि फ्री दवाएं दे रहे हैं, मान लिया कि आपने दवाएं दे दीं, 54 साल आपने राज किया, हमने तो 20 साल राज किया, जो भी काम किया, आपने किया, हम मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप पहले जन्मे हैं और हम बाद में आये हैं।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। इस बजट के प्रस्तुतीकरण के समय आज तीन दिन से लोगों के भाषण सुन रहा हूं। एक भी सदस्य ने राजस्थान के निर्माता मोहन लाल सुखाड़िया का नाम नहीं लिया, एक भी सदस्य ने हमारे दलित मुख्य मंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का नाम नहीं लिया। जिसने वागड़ का उद्धार कर दिया, आज वागड़ जनजाति के आदमी को रोटी खाने को मिली है, हरिदेव जोशी के कारण मिली है, उनका कहीं नाम नहीं है। केवल गहलोत साहब की गाथा गा रहे हैं। आप सब जानते हैं यह।

गहलोत साहब तो ऐसे अधिकारियों के घोड़े पर सवार हैं, जिसकी लगाम कमजोर है। वे गिरेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है। अधिकारी कंट्रोल में नहीं हैं। मैं मेडिकल पर निवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय ये कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं- आईसीयू में सीलन, छतों के फर्श उखड़े, हर मरीज को इन्फेक्शन तय, 250 रुपये का स्विच बदलने के लिए दो डाक्टर लड़ते रहे और जल गयी मासूम, अस्पताल में घूमते चूहे, श्वान, खुले में फेंक रहे बायो वेस्ट, दलालों पर नहीं लग रही लगाम, जरूरतमंदों को बेचा शुद्ध रक्त, मरीजों से कान्ट्रास्ट मंगाया, पूरा लगाया भी नहीं, बचाया और बेच दिया, एक माह में 90 लाख रुपये का दवा घोटाला।

माननीय सभापति महोदय, हमने जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा की, जयपुर में उसकी आवश्यकता नहीं है, आठ क्लीनिक खोले हैं, एक साल हो गया, आप जयपुर में करें। आप शहर में करें, उसका विरोध नहीं है, परंतु गांव के कोटड़ा के आदिवासी क्षेत्र में जो स्थिति बनी है, आप पहले वहां डाक्टरों की व्यवस्था करें। मेरे मावली क्षेत्र में 40 पशु चिकित्सालय खुले हुए हैं। 15 कर्मचारी डाक्टर तो हैं ही नहीं। अब 15 कर्मचारी 40 क्लीनिकों को कैसे चलाएंगे? जनाना अस्पताल के वेटिंग हाल का तीन मंत्रियों ने एक महीने पहले उद्घाटन किया था, वेटिंग हाल पर ताला। मैं यह जयपुर की स्थिति बता रहा हूं। स्ट्रेचर्स माल ढुलाई के काम में आ रही हैं। यह स्ट्रेचर्स की दशा है। माल ढो रहे हैं इन पर। माननीय सभापति महोदय, बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, तब जाकर हमारी सरकार चेती है। ये कुछ नमूने मैंने आपको दिये।

दूसरा, किसान का आपने संकल्प लिया है। हमारे यहां ऐसा कहते थे- उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। ऐसा पुराने लोग कहते थे।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आज की स्थिति क्या बनी है? सारा उलटा हो गया। आज चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। हम बाजरे के बीज के लिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। बाजरे का बीज बाहर से आता है, बाजरे का बीज हम मंगवा रहे हैं। ऐसी स्थिति किसानों की बन गयी है और सरकार क्या कर रही है? बीस-पच्चीस साल पहले आपकी सरकार थी। सरकार आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को मुर्गी पालन और बकरी पालन करा रही थी, क्यों भला? आदिवासी बच्चा जो कि आठवीं पास है, उसे आप लाइसेंस दीजिए, उसे कहें कि वह टैक्सी खरीदे। उसे बिना ब्याज के लोन दें। मुर्गी पालन में क्या होगा? मुझे माफ करें, वह अधिकारी शाम को जाएगा और कहेगा कि आपका लोन हो गया, दस मुर्गियां आ गयीं, एक मुर्गी वहीं समाप्त हो जाएगी। सरकार की क्या स्थिति है? केवल नारों से सरकार नहीं चलती है। माननीय सभापति महोदय, आज आपने बच्चों की स्कूली शिक्षा की बात की। मुझे बहुत दुख है। शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। मेरा उनसे बहुत ज्यादा सम्पर्क नहीं रहा है। राजस्थान में दो प्राइमरी स्कूल खोले हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हरीश जी मीना बैठे हैं, उन दोनों की एफआईआर, कितने सीनियर हैं, हम तो वर्षों से आपको सुनते थे कि आप जैसे बड़े मंत्री हैं। पीछे माननीय उनियारा वाले विधायक बैठे हैं। अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। आज आपकी सरकार की क्या स्थिति है? लॉ एण्ड आर्डर की यह स्थिति है?

**श्री सभापति**: आप मेरी तरफ इधर देखिए। माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ देखकर बात करें।

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): 35 हजार स्कूलों में आठ माह से सुबह 9 बजे सैनेटरी नैपकिन, यह वसुन्धरा जी की देन थी। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की जो स्थिति है, आपने कहा कि इन्होंने 22 हजार स्कूल बंद कर दिये। हमारी सरकार के आते ही बटन दबाकर स्कूल चालू हो जाएंगे। जो खराब बात है, उसकी आलोचना करें। स्कूल बंद हो गये, हमने उसकी समीक्षा की। (व्यवधान) श्रीमान बीच में न बोलें। आप प्लीज बीच में न बोलें।

**श्री सभापति**: आप अपना डायरेक्शन मेरी तरफ रखें, फिर कोई नहीं बोलेगा बीच में।

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): आपने 22 हजार स्कूल बंद कर दिये। खूब गालियां दे रहे हैं। वर्षों से यह बात कह रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराज जाएं आप। आप खोल देते, नहीं खोले, कोई चिंता की बात नहीं।

**श्री सभापति**: आप डायरेक्शन बदल लीजिए इधर की तरफ।

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): आप सदन में यह तो कह ही सकते थे, हम समीक्षा कर रहे हैं उसकी। शिक्षा मंत्री जी ने एक हजार स्कूल खोलने की घोषणा की, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद अगर लगेगा, हमने भी खोले थे, स्कूल बंद करने के बाद 1900 स्कूल वापस खोले, क्योंकि वे गलत बंद हो गये, क्योंकि काम तो अधिकारी करते हैं न। माननीय सभापति महोदय, आप समीक्षा करते। आज मुझे लगता है कि आप पांच हजार स्कूल भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि वहां बच्चे नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 25 हजार स्कूलों में बिजली नहीं है। यह अख़बार राजस्थान पत्रिका कह रहा है। गरीब बच्चों की किताबों की खरीद के कागज में कालिख। यह राजस्थान पत्रिका कह रहा है। शिक्षा विभाग में एक लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियां सिर्फ 34 हजार पर ही होंगी, 35 हजार स्कूलों में पेयजल नहीं है, 12 हजार स्कूलों में शौचालय नहीं और शौचालय है तो पानी की व्यवस्था नहीं। यह है राजस्थान की स्थिति।

यहां पर्यटन मंत्री विराजमान थे। गुजरात में अमिताभ बच्चन को आगे किया- जिसने कच्छ नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। राजस्थान तो पर्यटन की धरोहर है। संसार में राजस्थान प्रसिद्ध है। श्री भैरोंसिंह शेखावत जी ने मेवाड़ काम्प्लैक्स चालू किया, उसे आपने बंद कर दिया। आप मेवाड़ में धार्मिक सर्किट चालू करें, आपकी आय बढ़ेगी। मैंने अख़बार में पढ़ा, जो स्टेच्यू आफ यूनिटी बनी है गुजरात में सरदार पटेल की, आज ताजमहल से ज्यादा उसकी इनकम हो रही है। आप सर्किट चालू करिए। आप पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से आय होगी, कोई रोक नहीं सकता है।

माननीय सभापति महोदय, 1966 में उदयपुर में एक योजना बनी थी, सुखाड़ियाजी का सपना। सुखाड़िया जी का सपना था कि उदयपुर को पानी मिले। योजना यह बनी थी कि 2000 तक उदयपुर की पानी की सप्लाई को पूरा किया जाएगा। आज 2020 चल रहा है। दो चरण हुए, तीसरा चरण बाकी

(श्री धर्मनारायण जोशी)

है। सरकार के पास पैसा नहीं है। हम क्या विकास की बात करें? ऐसी स्थिति में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लीकेज को कम करें। सरकार की आय को बढ़ाएं। जब सरकार की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम विकास के काम कर सकेंगे। एक और निवेदन करना चाहता हूं, टीचर ट्रेनिंग कैम्प के लिए एक हजार बायोमैट्रिक मशीनें खरीदी थीं, वे सब गायब हो गयीं। जेलों में जैमर खराब, डोर मैटल डिटेक्टर्स भी नहीं।

आज राजस्थान में शिक्षा के 19 कालेज भवनविहीन हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शिक्षा की स्थिति यह है। माननीय अशोक जी गहलोत का भी एक स्टेटमेंट निवेदन करता हूं- घूसखोरी में राजस्थान पुलिस देश में नम्बर वन। माननीय अशोक जी गहलोत 05.09.2019 को भाषण देते हैं, एसपी कान्फ्रेंस में वे कहते हैं- अफसर जूनियर से पैसे लेता है। वह भी जेब से नहीं देता, जनता से वसूलता है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): माननीय सभापति महोदय, 11 लाख भेज रहा हूं, मुझे यहां ही थाना अधिकारी रहने दो। यह अखबार की कटिंग है, यह राजस्थान सरकार की स्थिति है। सैंट्रल जेल में दो माह में चौथी बार बैरक में मिले मोबाइल, जेलों की सुरक्षा में 20 करोड़ के जैमर बने खिलौने, 10 थाना प्रभारियों ने नहीं माना सी.एम. और डी.जी.पी. का आदेश, यह हमारे लॉ एंड आर्डर की स्थिति है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बजट खोखला है, राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है,

**'लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,**

**तुम झूठ को सच लिख दो, यह बजट भी तुम्हारा है'**

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

**श्री सभापति**: श्री हरीश चन्द्र मीना।

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय जो आपने मुझे बजट अनुमान 2020-21 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं मैं आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिया था।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

शायद धर्मनारायण जी मेरे जैसे ही पहली बार विधायक बने हैं और कटारिया जी हमारे वरिष्ठतम यहां विराजमान हैं, मैं दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धर्मनारायण जी ने कहा कि राजस्थान में करीब 54 साल कांग्रेस का राज रहा और 20 साल बी.जे.पी. का रहा। धर्मनारायण जी, यह राज रजवाड़ों के होते थे, अब प्रजातंत्र है, आपको 20 साल सेवा करने का मौका दिया और कांग्रेस को 54 साल सेवा करने का मौका दिया और मैं आशा करता हूं कि आप इसको इसी भावना से लेंगे। अब राज किसी का न होगा, राज तो जनता का ही रहेगा, यह प्रजातंत्र है।

सर, सर्वप्रथम मैं इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए अपनी एक कार्ययोजना पेश की है और जिसके मुख्य सात संकल्प हैं जिस पर यह कार्ययोजना आधारित रहेगी। पहला - नीरोगी काया, दूसरा - सम्पन्न किसान, तीसरा–महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, चौथा - सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, पांचवां संकल्प–शिक्षा का परिधान, छठा संकल्प - पानी, बिजली व सड़कों का मान और सातवां एवं अंतिम संकल्प - कौशल व तकनीक प्रधान। सर, इन चीजों को अपन देखेंगे तो एक आम आदमी की, गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, युवा की, व्यापारी के जीवन के हर पहलू को टच किया गया है और इनको अगर इसी भांति लागू किया जाए तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश का सम्पूर्ण विकास होगा।

सर, इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला संकल्प नीरोगी राजस्थान या नीरोगी काया, सर, नीरोगी काया हो, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है और सरकार की यह सोच बहुत ही सकारात्मक है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, पर जिस तरह से खुले आम जर्दे का, गुटखे का, तंबाकू और शराब की बिक्री हो रही है तो काया नीरोगी रहना, उस पर थोड़ा-सा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं आशा करता हूं कि इसको भी ध्यान में रखें। नीरोगी काया का संकल्प बहुत ही अच्छा है। यह देश के हित में है, समाज के हित में है, प्रदेश के हित में है पर जब खुले रूप से इन चीजों का सेवन होगा, आज हर शहर में नशे का चाहे स्मैक का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, सर, जो तरह-तरह के नशे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, जयपुर शहर में भी खुले रूप में बिक रहे हैं तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है और इस सरकार के इस

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

संकल्प को पूरा करने में बाधक बने हुए हैं तो मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जरा इसका ध्यान रखें अन्यथा उनको अपनी मंजिल हासिल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी।

सर, दूसरा नीरोगी काया के लिए आपको चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। जैसा मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे साथियों ने बताया कि हमें अस्पतालों में सुविधाएं देनी पड़ेगी। सर, पहले तो बिल्डिंग्स की स्थिति देखें, उसमें सुधार की आवश्यकता है, उनकी मेंटेनेंस के लिए हमने कितना बजट उपलब्ध कराया, उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इतने हास्पिटल हैं, प्रत्येक हास्पिटल के हिसाब से, प्रत्येक यूनिट के हिसाब से कितना पैसा दिया, उसका रखरखाव कौन करेगा, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। सर, इसी तरह से अगर हास्पिटल, बिल्डिंग अच्छी हो, स्टाफ का क्या होगा? कितने पद स्वीकृत हैं, क्या उतने आपके पास डाक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है या और जो पैरामेडिकल या क्लास फोर्थ हैं, उतने हैं या नहीं हैं? उसके अभाव में हास्पिटल कितना भी अच्छा हो, पूरी सेवा नहीं दे पाएगा।

सर, अंत में, डाक्टर्स की सेवाएं, ज्यादातर डाक्टर्स हैं यह देखने में आते हैं, ईवन आप जयपुर में भी देखें, एस.एम.एस. में भी देखें, ये अपने अस्पताल में सेवा कम देते हैं घरों पर ज्यादा दे रहे हैं और घरों पर जो सेवा देते हैं, उसकी एक फीस होती है। मैं मानता हूं कि सरकार के रूल्स ये परमिट करते हैं पर फिर भी सरकार को इस पर कोई व्यवस्था देनी चाहिए ताकि गरीब आदमी कम से कम पैसा खर्च करके अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवा सके, अपना स्वास्थ्य लाभ कर सके।

चिकित्सा शिक्षा, सर, यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। मैंने जितना पढ़ा, देखा, कुछ लोगों से सुना, राजस्थान की जो आबादी है कुल आबादी का 40 परसेंट अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग है। सर, एक भी मेडिकल कालेज में मैंने कोई प्रिंसिपल इस वर्ग का नहीं सुना। क्या हम मान लें कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या इसके पात्र ही नहीं हैं। सर, कुछ ऐसा लगे कि प्रजातंत्र है। मैं धर्मनारायण जी को आग्रह करूंगा कि आप राज नहीं कर रहे हो सेवा कर रहे हो और सेवा जब ही सार्थक होगी तब जिसकी सेवा कर रहे हो, उसको आप इसमें भागीदार बनाओ,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से ही थोपते रहो। जनता की भागीदारी होगी तो प्रजातंत्र सफल होगा, वह लाभदायक होगा। ऐसा मेरा मानना है।

सर, चिकित्सा शिक्षा में तरह-तरह की गड़बड़ होती है, मैं जानता हूं कैसे तो परीक्षा पास की जाती है, कैसे पी.जी. में एडमिशन दिया जाता है और कैसे रिजल्ट सेमेस्टर विदहोल्ड कर लेते हैं, उसको आगे किस-किस कारणों से पास किया जाता है तो हमारे बच्चों का शोषण होता है, उन पर मानसिक तनाव रहता है तो सम्पूर्ण शिक्षा के लिए हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसमें जो भी कमियां हैं, उनको दूर करें।

सर, जैसे मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। मेरे दो सब-डिवीजन हैं, एक देवली और एक उनियारा। सर, उनियारा जो जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है, उस अस्पताल में मोर्चरी नहीं है, अब कोई लाश को रखना होता है, चाहे उसका कल पोस्टमार्टम होगा किसी कारण से, उसको टोंक मोर्चरी लाया जाता है वहां से 40 किलोमीटर दूर, तो वह लाश ही नहीं जाती, परिजन को भी जाना पड़ता है। वहां जाकर उनके रहने की क्या व्यवस्था है और अगले दिन उस लाश को यहां लाना पड़ता है क्योंकि पोस्टमार्टम यहां होगा, तो इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इन चीजों को देखें, कम से कम उनियारा में आप एक मोर्चरी स्थापित कर दें ताकि लोगों को अनावश्यक नुकसान नहीं हो।

सर, इसी तरह से, ब्लड बैंक, जहां-जहां यह सेवा है, अब मेरा देवली नेशनल हाईवे पर है, वहां 4 जिले जुड़ते हैं टोंक, अजमेर, जहाजपुर भीलवाड़ा का और बूंदी। सर, खून के लिए या तो आदमी कोटा भागता है या टोंक भागता है जो सौ किलोमीटर दूर है। यह जो आधारभूत चीजें हैं, इनकी व्यवस्था करें तो मैं मानता हूं कि नीरोगी राजस्थान का जो सपना है वह साकार हो सकेगा।

सर, एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

**श्री सभापति**: स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): स्वास्थ्य तो, सर, हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब ठीक हैं, राजेंद्र जी बैठे हुए हैं इनके रहते हुए कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, महेश जी से सलाह ले लेंगे और कोई कमी रह जाएगी तो।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के बच्चे थे, इनके लिए जो यह प्रावधान किया है, सिर्फ 8 लाख रुपये की जो सीमा रखी है एवं और जो चीजों को हटाया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके अभाव में बच्चों को समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, किसी को कहीं एडमिशन के लिए जाना था, इसका जो सरलीकरण किया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ ही, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए बोर्ड का जो गठन किया है, यह भी बहुत अच्छा कदम है। इन लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, उसका परीक्षण किया जा सकेगा और सरकार को यह बोर्ड सकारात्मक सुझाव देगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

सर, इसके साथ-साथ, आप यह देखिये कि जो हमारे युवा हैं, बहुत सारे हमारे युवा हैं जो बी.ए., एम.ए. या उससे भी आगे की डिग्री पास हैं, उनको रोजगार मिल नहीं रहा, इन युवाओं को किसी रूप में सरकार की तरफ से सहायता मिले चाहे, चाहे उसको बेरोजगारी भत्ता कह दें, आप उसको स्टाइपेंड कह दें। ये बच्चे योग्य बच्चे हैं, पढ़े-लिखे बच्चे हैं, नौकरियों की कमी है, राजस्थान में उद्योग नहीं है, कृषि चौपट हो चुकी है तो यह बच्चे क्या करेंगे और ऐसे बेरोजगार या जो हमारे शिक्षित युवा हैं, उनके रहते हुए राजस्थान कैसे तरक्की करेगा? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार जो भी मानदेय दें, भत्ता दें, जिस रूप में भी दें, उनकी किसी न किसी रूप से सहायता करनी चाहिए। यह हमारे युवाओं के साथ न्याय होगा, उचित होगा।

सर, इसी तरह से, बहुत सारे संविदाकर्मी हैं, सब शिक्षित हैं, योग्य हैं, लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। इस समस्या से पूरा राजस्थान पीड़ित है, हमारे पास भी लोग आते हैं, ज्ञापन देते हैं, इनको किस तरह से नियमित किया जाए, इसका क्या समाधान किया जाए, पक्ष-विपक्ष दोनों बैठ करके जो भी इनके हित में हो, कोई चीज गलत नहीं हो पर जो इतने लंबे समय से हमारे प्रदेश की एक पीड़ा है, इसका बैठकर समाधान कर लेना चाहिए, उचित समय आ गया। लोगों में आक्रोश भड़क रहा है, तरह-तरह की बातें आती हैं, सड़कों पर आते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हम लोगों को उसमें

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

जाना पड़ता है। इसके लिए मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि शिक्षित युवा बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए।

सर, इसी तरह से, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। भर्तियां कोर्ट कचहरी में अटकी हुई हैं। उसके बावजूद क्या हो रहा है। उसका एक बड़ा पहलू है कि जिन वर्गों के लिए आप कहते हो, इनके लिए आरक्षण है, एससी, एसटी, ओबीसी, सरकारी नौकरियों में इनके लिए आरक्षण है। सर, आरक्षण सिर्फ कागज पर है। हर पद पर बैकलाग है, आप भर्ती नहीं कर रहे हो। अब बताइये, दुनिया को तो आप दिखाते हो कि इतने पद आरक्षित हैं, इतने परसेंट, कहां हैं वे पद तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि एक अभियान चलाकर, अभियान के रूप में जिनका भी बैकलाग है, जिस भी वर्ग का है, अभियान के रूप में पहले, वे भर्ती करें, फिर नई नौकरी शुरू करें।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): सर, कोई काम की बात पर आते हैं तो आप दो मिनट की बात करते हो। सर, आदेश तो आपका ही चलेगा। ऐसे ही मेरे कांस्टीट्यूएंसी में बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों पर भी हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा, इस देश के नागरिक हैं। अगर, वे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हिन्दुस्तान पिछड़ जाएगा, उनको भी हमें विकास की दौड़ में साथ रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मदरसा पैरा टीचर्स, ये लम्बे से नियमित नहीं हुए। इनको नियमित किया जाए, ये योग्य हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार जैसे भी करे। सर, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएं और जो मदरसे बने हुए हैं। ये शिक्षा देते हैं, ज्ञान की, विज्ञान की, कम्प्यूटर की शिक्षा देते हैं। इनके आधुनीकरण के लिए भी सरकार को कोई बजट देना चाहिए। इसमें हमारे युवा जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, इसका ध्यान रखें।

सर, युवा खेल के बारे में नारा मैंने देखा ''फिट राजस्थान, हिट राजस्थान''। ओलम्पिक में जो गोल्ड मैडल लेकर आएगा उसको तीन करोड़ देंगे, सिल्वर मैडल लाएगा उसको दो करोड़ देंगे, ब्राज वाले को। सर, मुझे बताइये वह ओलम्पिक में कब पहुंचेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज स्कूल लेवल पर खेलों की क्या व्यवस्था है, एक भी स्कूल में स्टेडियम नहीं है। वह

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

स्कूल में खेलेगा नहीं, यूनिवर्सिटी में खेलेगा नहीं, कालेज में खेलेगा नहीं, तो फिर ओलम्पिक में कैसे जाएगा। सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया हर गवर्नमेंट हायर सैकण्डरी स्कूल में कम से कम एक खेल मैदान हो, खेल स्टेडियम हो, ताकि हमारी प्रतिभा जो है गांव की, वह निखरे और आगे बढ़े और सरकार की योजना का लाभ ले। यह मेरा सरकार से आग्रह है। सर, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में दो कालेज हैं, स्कूल तो छोड़ दीजिए, एक देवली में सरकारी कालेज है, एक उनियारा में सरकारी कालेज है। खेल मंत्री से लगी हुई कांस्टीट्यूएंसी है तो कम से कम वहां तो स्टेडियम बनवा दें। सर, आपसे भी मैं आशा करूंगा, आप उनको आदेश देंगे कि कम से कम पड़ौसी का ध्यान रखें, देवली में तो खेल स्टेडियम बनाएं।

सर, अंत में शिक्षा विभाग की मेरी बात है। सर, शिक्षा में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। देश के मुकाबले में और महिला शिक्षा में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 4 गर्ल्स स्कूल हैं, जो दसवीं तक हैं। मैंने मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है। आपके मार्फत भी मेरी आवाज उन तक पहुंचाएं कम से कम उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वाले के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। वे जो दसवीं तक स्कूल हैं, उनको बारहवीं तक कर दें अन्यथा क्या हो रहा है, उसके अभाव में वे मां-बाप दूर तो अपनी बच्चियों को भेजते नहीं है। बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, तरह-तरह की शंकाएं हैं। वे बच्चियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो चार गर्ल्स स्कूलें हैं, उनको दसवीं से बारहवीं तक क्रमोन्नत करें।

सर, एक लास्ट टूरिज्म के विकास के लिए राजस्थान में प्रचुर संभावना है पूरे प्रदेश में। राजस्थान पूरी दुनिया में टूरिज्म हब के रूप में जाना जाता है। देश विदेश के लाखों टूरिस्ट हमारे यहां आते हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में प्राचीन काल का एक स्थान है, जिसका महाभारत से जुड़ाव है हाथी भाटा, अवशेष वहाँ है, मूर्तियां वहां हैं, सब कुछ वहां हैं, उसके विकास के लिए भारत सरकार ने तो उसको ले लिया, आर्कोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, उसको मेंटेन कर रही है पर उसके विकास के लिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि हाथी भाटा का भी विकास करें ताकि वह भी हमारे टूरिज्म सर्किट में आ जाए, वहां साथ ही सवाई माधोपुर की रणथम्भौर सैंक्चुअरी लगी हुई है,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

उसके साथ है। जो टूरिस्ट वहां जाएं इसका भी लाभ ले। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री राजकुमार रोत।

## सूचना

### प्रतापगढ़ में फरार सिपाही की तलाशी

**श्री राजकुमार रोत** (चौरासी): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने एक मिनट इंर्फोमेंशन पर बोलने का अवसर दिया। ये जो वर्तमान में घटना घटित हुई है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कल ही पुलिस विभाग के एक सिपाही ने, एसपी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसके संबंध में लैटर लिखकर वह फरार हो चुका है दोनों अपने मोबाइल छोड़कर और पूरा परिवार अभी सदमे में हैं। कई सामाजिक संगठनों द्वारा, कई कर्मचारी संगठनों द्वारा भी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा टीम बनाकर वह आदमी कहां है, उसकी तलाशी की जाए, कोई ऐसी अनहोनी घटना न हो, इसके लिए प्रयास किये जाएं और जल्दी से जल्दी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। उन पर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: विराजिए। श्री रामकेश मीणा।

## आय व्ययक

### आय व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद विवाद

**श्री रामकेश** (गंगापुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने बजट अनुमान 2020-21 पर बोलने का मौका दिया। बजट सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकता दर्शाता है। यह बजट किसानों के लिए, पशुपालक, छात्र, युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों और सिविल सोसायटी के हित में एक समावेशी बजट है।

सभापति महोदय, देश में संघीय व्यवस्था है और किसी भी राज्य का बजट केन्द्र की नीतियों से प्रभावित होता है और भारत सरकार में अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने 2016 में एकाएक जो नोटबंदी का निर्णय लिया। उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उद्योग धन्धे, आयात-निर्यात, रीयल एस्टेट एवं समस्त कारोबार नोटबंदी के कारण जबर्दस्त प्रभावित हुआ। देश में

(श्री रामकेश)

आर्थिक मंदी चरम सीमा पर है और इसी का परिणाम है कि भारत सरकार का भी राजस्व कम हो रहा है और भारत सरकार ने राजस्थान प्रदेश का भी लगभग 10 हजार करोड़ कम करके देने का निर्णय किया है।

मैं यह मानता हूं कि भारत सरकार के पास कई तरह के साधन होते हैं। अगर भारत सरकार के पास कोई वित्तीय असुविधा है तो विश्व बैंक के मार्फत, आईएमएफ के मार्फत, एडीबी से विकास दर के अनुमानों को कम करके और भारत सरकार किसी भी रूप में अपने पैसे की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन राज्यों के पास ऐसे कोई साधन नहीं होते हैं। राज्यों को अपने स्तर पर राजस्व इकट्ठा करना होता है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी जब पूरे देश में आर्थिक मंदी है, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सुविधा दस हजार करोड़ कम होने के बाद भी, एक शानदार बजट राजस्थान में प्रस्तुत किया है। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आर्थिक मैनेजमेंट के रूप में 2008 से 2013 के बीच में उन्होंने शानदार मैनेजमेंट किया और इसी तरीके से अब भी दूसरे बजट में उन्होंने बहुत अच्छे प्रावधान इस बजट के मार्फत किए हैं। सभापति महोदय, राजस्व कम होने के बाद में भी हमारे सामाजिक सरोकार की जो सुविधाएं हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनमें पर्याप्त बजट का प्रावधान इस बजट में किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 14,533 करोड़ रुपये का प्रावधान करके चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने एक सफल प्रयास करने की कोशिश की है कि लोगों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, जनता क्लिनिक यह सारी की सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के मार्फत राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके।

मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि नि:शुल्क दवा योजना और अन्य योजनाओं की न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा हुई है। पूरे भारतवर्ष में इन योजनाओं को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। इन सबके बावजूद हमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में और भी बहुत ज्यादा जागरूक रहकर के लोगों की सेवा करने की आवश्यकता है। यही एक ऐसा सैक्टर है, जिसमें आम जनता का सरोकार रहता है। आम जनता जो गरीब जनता है, उसको बहुत ज्यादा सरकार की जरूरत होती है। प्राइवेट हास्पिटलों में जनता का जबर्दस्त शोषण

(श्री रामकेश)

होता है और उस शोषण से मुक्ति दिलाने का आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने काम किया। पिछले कार्यकाल में और इस बार भी उनका जो प्रयास है कि सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और आम जनता को लूट से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में जो राजकीय अस्पताल है, उसको क्रमोन्नत करने की पिछले बजट में घोषणा की थी। मैं सरकार से मांग करूंगा, मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारा गंगापुर क्षेत्र सवाई माधोपुर से बहुत दूरी पर है और वहां पर हास्पिटल को क्रमोन्नत करके उसको जिला अस्पताल घोषित किया जाए, जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिल सके। हमारे दूसरा वजीरपुर जो कस्बा है, उसमें भी हमारे हास्पिटल को क्रमोन्नत करके और वहां पर बैड बढ़ाए जाएं।

सभापति जी, बजट की जो दूसरी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की कृषक कल्याण कोष की, इसमें 1000 करोड़ की घोषणा उन्होंने की थी कृषक कल्याण कोष के लिए, उसको भी दिसम्बर, 2019 में स्थापित कर दिया। कृषि विभाग के लिए भी कुल 3,420 करोड़ रुपये का शानदार प्रावधान करके हमारे किसानों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। वर्षा जल से संग्रहित हमारे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 12,500 फार्म पोंड का लक्ष्य रखा है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे सवाई माधोपुर जिले में, क्योंकि पूरा का पूरा पथरीला एरिया है, फार्म पोन्ड ही एक ऐसा साधन है जिससे किसान अपने सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकता है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि फार्म पोंड के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये का इस बजट में जो प्रावधान किया है, उसको बढ़ा करके अच्छी राशि की जाए तो किसानों को इससे लाभ होगा। सोलर पंप, उन्नत बीज भंडारण के क्षेत्र में और नजदीक मंडी का जो कंसेप्ट इस बजट में रखा है, सरकारी बैंकों के द्वारा जो 22 लाख से अधिक किसानों को 8700 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण देकर किसानों को संबल प्रदान किया, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, महिला, बाल और वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में भी एक शानदार कंसेप्ट, एक शानदार अवधारणा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय एवं कन्वर्जन के लिए कामन प्लेटफार्म ए-3 एप विकसित किया है, इससे भी क्षेत्र में समन्वय बढ़ेगा और संगठित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इसका काम हो सकेगा।

(श्री रामकेश)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए भी 8,500 करोड़ रुपये का प्रावधान करके और समाज के कमजोर तबकों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। एसटी/एससी, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को भी राशि ढाई हजार से तीन हजार रुपये करनी चाहिए। इससे भी इन वर्गों के छात्रों को सुविधा मिल सकेगी।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, 2 मिनट में समाप्त करें।

**श्री रामकेश** (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन और सिंचित क्षेत्र विकास के लिए मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी, जिसको इस बजट में सरकार के द्वारा टाप प्रायोरिटी में रखने का आश्वासन दिया है, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सभापति जी, पूर्वी राजस्थान उद्योग विहीन है, पूर्वी राजस्थान में एकमात्र उद्योग जो सीमेंट फैक्ट्री का था, उसका भी नामोनिशान मिट गया है। टाइगर के नाम पर, घड़ियाल के नाम पर वहां पर लोगों को उजाड़ दिया। उद्योग-धंधे बिल्कुल नहीं है और केवल और केवल अगर कोई साधन है तो वह खेती का साधन है। सिंचाई की परियोजना, बहुत पहले इंदिरा लिफ्ट योजना का हम लोग जब बचपन में थे तो नाम सुनते थे, वह इंदिरा लिफ्ट योजना भी खतम हो चुकी है और अब यह ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट आया है, मैं मेरे भाजपा के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का यहां पर अजमेर में आश्वासन दिया है और लगातार आश्वासन दे रहे हैं, भाजपा के साथियों को भी, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट अगर यह घोषित होता है तो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को इससे फायदा होगा और किसान को संबल मिलेगा। चंबल में व्यर्थ में बहुत पानी बहता रहता है। इस बार डेढ़दो महीने व्यर्थ में पानी बहकर समुद्र में गया। अगर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम होता है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वी राजस्थान की काया पलट हो सकती है। हमारा जो पांचना का क्षेत्र है, वह पांचना भी 2006 से बंद है, मैंने पहले भी विधान सभा में यह मांग उठाई थी। सभापति महोदय, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किन कारणों से 2006 में जब एक बार बांध बंद हो गया, भर गया और लगातार उसमें पानी फ्लो हो करके नदी में बहता रहता है, लेकिन उसको नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा है। किस कारण से नहरों में नहीं छूट रहा है पानी? इसका सरकार को जवाब देना

(श्री रामकेश)

चाहिए और सरकार से, मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बांध जिस परपज से, जो कमांड एरिया के किसानों के लिए बांध बना है, जिनकी जमीन अवाप्त हो करके और जिनके खेतों में नहरें निकाली हैं, उनके खेतों को बर्बाद होने से बचाना सरकार का दायित्व है। सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया और अब भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को संकल्प के साथ में सरकार आगे बढ़ाए, जिससे हमारे पूर्वी राजस्थान के किसानों का भला हो सके। धन्यवाद जय हिन्द।

**श्री सभापति**: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

**(16.00 बजे)**

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जब 20 फरवरी, 2020 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट 2020-21 सदन में प्रस्तुत किया और बजट भाषण के बाद, सदन स्थगित होने के बाद, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद लोगों ने मेरे से प्रतिक्रिया मांगी कि साहब अपने क्षेत्र को इस बजट में क्या मिला। मैंने उनसे कहा कि क्या लेकर आये थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आये थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे एक बार पुन: बड़ी निराशा हुई जब 2019 के बजट के बाद जब 2020 में बजट प्रस्तुत किया गया तो एक भी चीज मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के लिए इस बजट में राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दी गई। पिछले बजट और इस बजट में मात्र एक फर्क है, 2019 के बजट में अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र में बदलकर बजट में शामिल किया था और इस बजट में यह नये सात संकल्प लेकर आये हैं। क्या सरकार यह मानती है कि जो नये संकल्प यह लेकर आये हैं वह पुराने बजट के समय इन्होंने नहीं किये थे? क्या युवा, किसान का भला इन्होंने पहले नहीं किया था जो इस बार इस संकल्प को इन्होंने बजट में जोड़ा?

सबसे पहले मैं सरकार द्वारा लिये गये पहले संकल्प नीरोगी राजस्थान की बात करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये के नीरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष की घोषणा की है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार कहती है कि इस कोष का अधिकतर पैसा प्रचार प्रसार पर, परिचर्चा पर व गोष्ठियों पर खर्च करेंगे।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

प्रचार-प्रसार किसका, परिचर्चा किससे और गोष्ठियां किसकी? क्या सरकार आम जन के पैसे का दुरुपयोग स्वयं के प्रचार-प्रसार पर, स्वयं से गोष्ठियों पर और स्वयं की ही परिचर्चा पर खर्च करना चाहती है? मैं आपके माध्यम से जब निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार को खुद को यह नहीं पता कि नीरोगी राजस्थान पर कब और कैसे काम करेंगे तो इस योजना को इतनी जल्दी लागू करने की जरूरत कहां थी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के गरीब लोगों के पैसे की बर्बादी आप इस तरीके से नहीं करें। आपका यह पैसा उनके और भी कहीं काम आ सकता था।

आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट के पैरा नंबर 14 में सरकार द्वारा चालू की गई निःशुल्क दवाई योजना और निःशुल्क जांच योजनाओं की तारीफ की, पर आज इन योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र के धरातल पर क्या हाल है, यह हम सब को पता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी द्वारा चालू की गई भामाशाह योजना की भी तारीफ करते जिसकी पूरे विश्व ने सराहना की। इस योजना की वजह से आज प्रदेश में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ और साथ ही साथ उनकी जमीन जायदाद बिकने से भी बची, पर आप बड़ाई कैसे करते, क्योंकि यह योजना आपके माध्यम से चालू नहीं की गई। बड़ाई करना तो दूर, आपने इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचने से भी रोका, जिससे आमजन और गरीब आदमी को बहुत अधिक परेशानी हुई।

आदरणीय सभापति महोदय, इस बजट के पैरा नंबर 16 में सरकार ने निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी और लीवर की दवाइयों को शामिल करने की बात कही। क्या सरकार ने कभी यह सोचा कि प्रदेश में बीमारियां क्यों अपने पैर पसार रही हैं? क्या सरकार ने कभी ऐसा सोचा कि हम इन बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, उस पर कदम उठाने की बात सोची? एक तरफ तो आप बात करते हैं, प्रिवेंशन की, कि हम बीमारियों को कैसे रोकें और दूसरी तरफ आप बात करते हैं निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत और दवाइयों को बढ़ाने की।

आदरणीय सभापति महोदय, आज पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व प्रदूषण को लेकर चिंतित है पर मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि राजस्थान सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अभी आई एक

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 बड़े शहरों में दो शहर राजस्थान के शामिल हैं, एक भिवाड़ी और दूसरा जोधपुर। जोधपुर से माननीय मुख्य मंत्री खुद आते हैं, फिर भी बड़ी निराशा है कि इस बजट में प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। भिवाड़ी अलवर जिले में आता है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के नजदीक लगता है, दिल्ली से नजदीक लगता है। बार-बार सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के आदेशों के बाद भी अगर हम प्रदूषण को नहीं रोक पा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। अच्छा होता आप कोई ऐसी योजना बनाते जिससे आने वाले समय में हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकें और इससे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बाहर ला सकें, तो ज्यादा अच्छा होता। सभापति महोदय, इसी में आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के औद्योगिक क्षेत्र नीमराना, शाहजहांपुर, गिलोठ की बात करना चाहूंगा, जहां पर अनेकों इकाइयां लगी हुई हैं और अधिकतर वायु प्रदूषण के साथ-साथ जमीन के पानी को भी दूषित करने का काम जोर शोर से कर रही हैं। आदरणीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा उदाहरण शाहजहांपुर के नजदीक स्थित किंगफिशर बीयर फैक्ट्री का है, जो पानी के दोहन के साथ-साथ कचरा वहां निकलता है, उसे आसपास के खेतों में छोड़कर आसपास के किसानों के खेतों को बर्बाद करने का काम कर रही है और साथ ही साथ जमीन के पानी को भी दूषित करने का काम कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय, जिसे देखकर भी सरकार अनदेखा कर रही है। क्या सरकार इसी तरह नीरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का विचार रखती है?

आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने चौथे संकल्प के रूप में सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान की बात की है। सरकार राज्य में ऊर्जावान युवाओं की और मेहनतकश मजदूरों की बात करती है। पैरा 68 में सरकार कहती है कि हम जिले में, प्रदेश में और ब्लाक स्तर पर खेलों का आयोजन कर, फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का संकल्प लेकर आये हैं। क्या सरकार ओलम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स और कामनवैल्थ गेम्स के विजेताओं की राशि बढ़ाकर फिट राजस्थान और हिट राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का सपना देखती है? अच्छा होता आप कोई ऐसी योजना लेकर आते जिससे गांवों में रहने वाले किसान के बेटे और शहर में रहने वाले युवाओं को अपनी

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

खेल प्रतिभा निखारने का मौका मिलता। बजट में ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाते जिससे वह प्रतिभा आगे निकलकर आती और जिससे आगे जाकर वह इन खेलों में पदक लेकर आते और हमें भी खुशी होती जब प्रदेश का बेटा, प्रदेश का युवा पदक लेकर आये और सरकार उसे अपनी तरफ से बजट में राशि प्रदान करे। जब प्रतिभाएं निकलेंगी ही नहीं तो मैडल कौन जीत कर लायेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 74 पर सरकार औद्योगिक विकास की बात करती है, औद्योगिक विकास को गति देने की बात करती है, नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात करती है। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में अभी जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनका हाल देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहां पर जितने भी उद्योग हैं, वह यहां से और आगे दूसरे प्रदेशों में जाने की योजना बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप पहले पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की कमियों को दूर करें जिससे देश में प्रदेश की एक अच्छी छवि बने और ज्यादा उद्योग यहां पर स्थापित कर सकें, जिससे यहां उद्योग स्थापित होने के बाद प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल सके। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो यहां उद्योग लगे हुए हैं, आपने कोई भी ऐसी पालिसी नहीं बनाई कि यहां के युवा को, यहां के किसान के बेटे को उस कंपनी में नौकरी मिल सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब बजट रिप्लाई दें तो एक ऐसी नई योजना की घोषणा करें जिससे जो राजस्थान में उद्योग लगे हुए हैं, उनमें आसपास के प्रदेशों की तरह कम से कम 70-75 प्रतिशत यहां के लोकल बेटे को, लोकल भाई को उन कंपनियों में नौकरी मिल सके और वह अपना जीवनयापन कर सकें।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा युवाओं की मांग पर राजस्थान के युवाओं की जरूरत को देखते हुए राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर उद्योगों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का काम सरकार करे।

आदरणीय सभापति महोदय, पांचवें संकल्प में सरकार शिक्षा का परिधान का संकल्प लेकर आती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे इस सदन में आये एक वर्ष से भी अधिक हो गया। मैं पिछले एक साल से

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मुण्डावर में राजकीय महाविद्यालय की फाइल को लगातार परस्यु कर रहा हूं, पर आज तक वह फाइल कलेक्टर साहब के पास जमीन आबंटन के लिए पैंडिंग पड़ी हुई है। जब एक कालेज की फाइल एक-एक साल से कलेक्टर महोदय के पास जमीन आबंटन के लिए पैंडिंग पड़ी रहती है तो क्या आप इस तरह से क्षेत्र की जनता को शिक्षा का अधिकार देने का सपना देखते हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी बजट रिप्लाई दें तो सरकार अगर इतनी ही ज्यादा संवेदनशील है तो उससे पहले उस फाइल को क्लीयर करवाने का काम करें और मुण्डावर में राजकीय महाविद्यालय की जमीन आबंटन करने का काम करें।

आदरणीय सभापति महोदय, 6ठे संकल्प के रूप में सरकार पानी, बिजली और सड़कों का मान की बात करती है। सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार ने हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का संकल्प लिया है और उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का है और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का है। आदरणीय सभापति महोदय, आज आदमी की सबसे बड़ी जरूरत शुद्ध पेयजल की है। अगर मैं अलवर जिले की बात करूं और विशेष तौर से मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की, आज हालात यह हैं कि 1500-1500 फीट नीचे तक पानी चला गया और 1500 फीट बोर होने के बाद भी वहां पानी नहीं मिलता। फिर सरकार कहती है कि हम केन्द्र सरकार से मांग करेंगे, उनको अनुरोध करेंगे कि इस हिस्से को बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाए। मैं कहता हूं कि अगर आप प्रदेश की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं करवा सकते ..

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): आप प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करवा सकते तो आप नीरोगी राजस्थान के संकल्प को कैसे पूरा करेंगे? मनुष्य शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा पानी का है, अगर हम शुद्ध पेयजल ही उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो नीरोगी राजस्थान के संकल्प को कैसे पूरा करेंगे? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहें आप बाकी योजनाएं बेशक छोड़ दें, सबसे पहले आप हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की बात करें और बजट में जो आपका 50 प्रतिशत हिस्सा है, उसको आप पूरा करने का काम करें।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

आदरणीय सभापति महोदय, प्रदेश में जो बिजली के हालात बने हुए हैं, वे यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से छानी नहीं हैं। कोई खुले मन से बोल देता है, कोई दबे मन से उसकी बात कर लेता है, पर जो हालात आज बने हुए हैं, वे किसी से भी छानी नहीं हैं। लाइनमैन, ए.ईएन, जे.ईएन. को टारगेट देकर उनसे वीसीआर भरवायी जाती है। गरीब जनता व गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अगर वह वीसीआर नहीं भरता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। उसकी डीपी उतार ली जाती है, बाकी अन्य जो ताकतवर लोग हैं, उनको अनदेखा कर दिया जाता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जो भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, उसी तर्ज पर अगर सरकार बिजली विभाग के अंदर भी कार्यवाही करती है तो उससे भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। अगर सड़क की बात करें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय से 30 से अधिक सड़कों के निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। एक वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी आज भी सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं होना, आपके द्वारा दिये गये संकल्प को पूरा करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आदरणीय सभापति महोदय, सातवें संकल्प के अंदर सरकार कौशल व तकनीक प्रधान की बात करती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेरे पिताजी स्वर्गीय धर्मपाल जी चौधरी की अनुशंसा पर सरकार ने सुखामेड़ी गांव के अंदर एक आई.टी.आई. खोली, उस आई.टी.आई. का भवन पूरी तरह से तैयार है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर): सर, दो मिनट। उसके बिजली के कनेक्शन की फाइल, उसका डिमांड नोट भरवा दिया गया है। छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज आई.टी.आई. का बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है। क्या इसी तरीके से सरकार युवाओं को शिक्षा का परिधान के साथ-साथ कौशल व तकनीक प्रधान के संकल्प को पूरा करेगी? यह मात्र दो विषय, एक कालेज और आई.टी.आई. के मैंने आपके सामने रखे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे अनेकों विषय हैं, जो बताना चाहता हूं, पर आप समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं उनकी बाद में चर्चा करूंगा।

आपने पैरा 199 में सीनियर सीजे एवं एसीजेएम कोर्ट खोलने की बात

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

की। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी नजर उन विधान सभा क्षेत्रों पर तो डाली, लेकिन आप उन विधान सभा क्षेत्रों पर भी डालें, जहां से भाजपा के उम्मीदवार जीतकर इस सदन में पहुंचते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के नीमराणा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जहां पर 3200 से भी अधिक केस हैं, जिसमें 1100 से अधिक फौजदारी के मुकदमे हैं। उपखण्ड के तहत तीन थाने माण्डन, शाहजहांपुर और नीमराणा आने के बाद भी आज तक सीजेएम और जेएम कोर्ट के लिए अन्य जरूरी मापदंड पूरे करने के बाद भी सरकार का ध्यान उस पर नहीं पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट पर अपना जवाब दें तो इस बात को ध्यान में रखें कि नीमराणा में भी सीजे और जेएम कोर्ट खोलने की घोषणा कर जनता को लाभ पहुंचाने का काम करें। आदरणीय सभापति महोदय, दो दिन पहले बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि आदरणीय मुख्य मंत्री ने पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को अपना मानकर सभी विधान सभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ दिया है। मैं पूरे प्रदेश की तो बात नहीं करता, पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप पुनः एक बार बजट को पढ़ें। केवल मात्र दो विधान सभा क्षेत्रों को छोड़कर, अलवर जिले के किसी भी विधान सभा क्षेत्र में अगर सरकार ने कुछ दिया है तो वह आप आगे लेकर आएं। अंत में, इस बजट में कहना चाहूंगा:-

इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है,
तो ये खूबसूरत जिंदगी भी एक जंग हो जाती है।

आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

**श्रीमती कृष्णा पूनियॉ** (सादुलपुर): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे 2020-21 बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, वृद्धजन हो या बालगोपाल हो, हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला बजट पेश किया है। ऐसे समय में जब राजस्थान को विगत सरकार द्वारा दिये गये वित्तीय संकट की मार हो या फिर केन्द्र का सौतेला व्यवहार हो, माननीय मुख्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

महोदय ने सात संकल्पों के माध्यम से प्रदेश की अवाम को तकलीफों से राहत देने वाला बजट पेश किया है। सम्माननीय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नीरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। आपके पिछले कार्यकाल में चलायी गयी नि:शुल्क दवा योजना हो, नि:शुल्क जांच योजना हो, विपक्ष के लिए चाहे वे रेवड़ियां हैं, पर गरीब अवाम के लिए उसने संजीवनी बूटी का काम किया। ठीक उसी तरीके से नीरोगी राजस्थान बनाने के लिए नीरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष, जनता क्लीनिक, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सम्माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से प्रदेश के खिलाड़ियों का मान-सम्मान बढ़ाया गया, प्रदेश के खिलाड़ियों में एक खुशी की लहर है और मैं यहां पर तारीफ भी करना चाहूंगी, क्योंकि जो राज्य स्तर के खेल हुए, उन खेलों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से 'खेलो इण्डिया' में भी भारी पदक जीते और अब उसी की भावना पर इस योजना को बढ़ावा देने के लिए खेलों को ब्लाक स्तर पर ले जाया जा रहा है। मेरा मानना है कि हिट राजस्थान, फिट राजस्थान और नीरोगी राजस्थान के सपने को साकार करेंगे, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

साथ में, मैं कृषि के ऊपर जरूर कहना चाहूंगी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार की है। विशेष तौर पर यहां का जो किसान है, बड़ा मेहनतकश है, विभिन्न परिस्थितियों में भी रहकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। इसमें कृषक कल्याण कोष, भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा, यूरिया एवं डीएपी का अग्रिम भंडारण, उन्नत बीज के उत्पादन को बढ़ाना और खजूर की खेती के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए उसके ऊपर भी काम करना, जिसमें 12 जिलों को जो चिह्नित किया गया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं, लेकिन साथ-साथ मैं चूरू जिले का भी जरूर जिक्र करना चाहूंगी और विशेष तौर पर सादुलपुर का, जहां से मैं जीत कर आती हूं। जहां पर खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर है और ऐसे में जीवनयापन काफी कठिन है। जैसे कि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, अभी चने की फसल काफी अच्छी रही। लेकिन तीन-चार दिन हवा तेजी से चली तो फसल को काफी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में खासकर सादुलपुर के किसानों की तरफ विशेषकर ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर कोई उद्योग-धंधा भी नहीं है, कोई रोजगार

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

नहीं है। ऐसे में वहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने सिद्धमुख कैनाल जो कि खासकर सिद्धमुख एरिया के लिए चलायी थी, उसके लिए भी मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि आज तक वहां के किसानों का उसका पानी नहीं मिल पाया है तो यह विडम्बना है। हम लोग बोर्डर एरिया पर रहते हैं।

महिलाएं जब हरियाणा से शादी कराकर राजस्थान में आती हैं, एक ऐसे प्रदेश से जहां पर पानी की कमी नहीं हो और यहां पर पीने के पानी की कमी हो तो हमेशा शिकायत करती हैं। इसलिए मैं जरूर इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के लिए भी सरकार की सराहना करती हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है, जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास है, इसमें जिस तरीके से सरकार ने 'नो बैग डे' को शामिल करने की बात कही है, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आएगा। विशेष तौर पर हम देखते हैं कि 'नो बैग डे' के ऊपर जिस तरीके से शहरों में या प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक और टीचर्स की जो मीटिंग रहती है, अपने बच्चे की गतिविधियों पर जो विचार किया जाता है या उस पर ध्यान दिया जाता है तो उससे काफी बदलाव आएगा। स्कूल जाने वाले 6 से 18 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या विशाल है। यदि हमारे बच्चों को वास्तविक दुनिया का आत्म विश्वास के साथ सामना करने की शिक्षा दी जाती है तो वे हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो अभिभावक हैं, वे अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। 'नो बैग डे' का जो प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं तारीफ करना चाहती हूं।

पेयजल के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि पानी, बिजली व सड़कों का मान, मैंने विशेष तौर पर पहले भी अंकित किया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की ज्यादा महिलाएं हरियाणा क्षेत्र से आती हैं। मैं खुद भी हरियाणा से हूं। हमारी हर घर तक पानी पहुंचाने की जो योजना है तो मैं कहना चाहूंगी कि इस योजना को विशेष तौर से चूरू जिले में जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शिकायत करती हैं कि सिर पर पानी ढोते-ढोते बाल उड़ गये हैं। महिलाओं की इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। लेकिन यहां

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

पर जो विपक्ष के साथी हैं, 3 दिन से यह बहस चल रही है। मैं सुन रही थी। बड़ा अचरज हुआ कि एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि हम तो विपक्ष में हैं, पल्ला झाड़ लेंगे। आप सदन में पल्ला झाड़ने के लिए नहीं आये हैं और बड़े गुरूर के साथ कहा कि हम 25 सदस्य चुनकर लोक सभा में गये हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आपने पल्ला झाड़ने की बात कही है और 25 सदस्य जीतने की बात कही। एक तरफ जब आपने राजस्थान पर 3 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ा और 13 हजार करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों के भुगतान का भार आपने छोड़ा, साथ में 2019-20 के अंतरिम बजट में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 46 हजार 411 करोड़, 8 लाख रुपये देने की अनुमानित राशि को घटाकर 36 हजार 49 करोड़ 14 लाख रुपये किया तो पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं। पच्चीस के पच्चीस सांसदों को राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पर भेजा है। जब केन्द्र की सरकार आपके राजस्थान के साथ, जहां पर हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, कर देने के अंदर और हमारी हिस्सेदारी है, उसको काटा जाता है तो उन 25 सांसदों से इस प्रदेश की जनता सवाल करेगी। खासकर जब बाड़मेर रिफाइनरी जैसी बात आती है, विगत सरकार में आप बैठे थे, केन्द्र में भी आपकी सरकार थी, उसको आपने कितना बढ़ावा देने का काम किया। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि पिछली सरकार के दौरान स्वीकृत स्कूल के लिए भूमि आबंटन की बात की, आपकी सरकार में आप नहीं करवा पाए थे तो यह आपके सोचने की बात है कि आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हमें इस सदन के अंदर जनता की आवाज को मजबूत बनाने और उनका निस्तारण करने के लिए भेजा गया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला यह बजट दिया है। आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति जो हमारी है, केन्द्र सरकार भी हमारे से क्योंकि कांग्रेस की सरकार सत्ता में होने के कारण जिस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है, माननीय सदस्यों से इतना कहना चाहूंगी, सदस्य काफी हैं बोलने वाले लेकिन आप अपने उन 25 सांसदों से कहें कि जल ही जीवन की बात अगर रखी है या इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात जो रखी गई है, उसमें सहयोग किया जाए कि जो राशि हमारे प्रदेश के हिस्से की काटी गई है, वह हमें मिलनी चाहिए। उन्हें पुरज़ोर तरीके से इस बात को संसद में रखना चाहिए। मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

देती हूं। विशेष तौर से आग्रह करना चाहती हूं कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के प्रति, पेयजल आपूर्ति और खेती का पानी जो हमें हमारे हिस्से का मिलना चाहिए था, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के लिए दो लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

'वो कोई और चिराग होते हैं, जो हवाओं से बुझ जाते हैं,

हमने तो आगे बढ़ने का हुनर भी तूफ़ानों से सीखा है।

धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री कन्हैया लाल चौधरी।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): सभापति महोदय, बजट 2020-21 आय-व्ययक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सात संकल्पों के साथ इस बजट को पेश किया है। सबसे पहले बोला है कि 'नीरोगी राजस्थान'। पिछले 5 साल से पूरे भारत के अंदर हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'आयुष्मान भारत' योजना चालू कर रखी है। इसमें सबसे पीछे 'नीरोगी राजस्थान' करने में रख रही है तो हमारी राजस्थान की सरकार है, जिन्होंने अभी तक इसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया। हमें बहुत उम्मीद थी कि राजस्थान वास्तव में बहुत नीरोगी हो जाएगा, जब इन्होंने एक घोषणा की थी, एक कमेटी बनाई थी, राजस्थान में शराब मुक्ति के लिए। अगर यह वास्तव में 'नीरोगी राजस्थान' बनाने का संकल्प लेते तो वह शराबबंदी वाली योजना लेकर आते। इस बजट के अंदर यह घोषणा होती। पूरे राजस्थान को, जनता को यह उम्मीद थी कि यह घोषणा होगी तब वास्तव में राजस्थान 'नीरोगी राजस्थान' की तरफ जाता। आज भामाशाह योजना से जितने भी मरीज आते हैं, उनको तकलीफ हो रही है। पूरे राजस्थान को 'नीरोगी राजस्थान' बनाने की बात करते हैं। एएनएम के पूरे पद खाली पड़े हुए हैं, जीएनएम के पद खाली पड़े हैं। गांवों के अंदर हर पीएचसी के अंदर डाक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। मुझको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से पूरा राजस्थान नीरोगी होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो हाईवे निकलते हैं। वहां पर ट्रोमा अस्पताल की बहुत आवश्यकता है। अगर वहां पर बैड 75 से बढ़ाकर 100 कर

(श्री कन्हैया लाल)

दिये जाएं और लगभग दो-तीन सीएचसी, पीएचसी खोल दी जाएं तो जरूर वहां पर लोगों को सहायता मिलेगी।

इसके साथ-साथ, इन्होंने दूसरा संकल्प लिया है, सम्पन्न किसान का। अगर इस बजट के अंदर देखते हैं, चूंकि पूरे राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा कमी है। पूरा राजस्थान मूल रूप से कृषि पर आधारित है। पानी को बढ़ावा देने के लिए बूंद-बूंद इर्रिगेशन, फार्म पौण्ड वगैरह हैं, इन पर अगर और ज्यादा सब्सिडी बढ़ाते, और ज्यादा बजट रखते तो जरूर पानी की कमी दूर होती और किसान सम्पन्न होता। इसके साथ-साथ, आधुनिक खेती के लिए ग्रीन हाउस, आर्गेनिक खेती, बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर एक्स्ट्रा प्रावधान करते तो जरूर किसान सम्पन्न होते। पहले जो मिलता था, उससे भी कम इस बजट के अंदर दिया है तो किस तरह से किसान सम्पन्न होगा? मेरे समझ में नहीं आता।

तीसरा संकल्प इन्होंने लिया है, इस बजट की एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टोडारायसिंह कृषि मंडी, गौण कृषि मंडी थी, उसको पूर्ण कृषि मंडी का दर्जा देने की इन्होंने बजट में घोषणा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में एक भी घोषणा नहीं हुई थी। यह घोषणा होने के बाद में वहां के कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर लगाए, बैनर लगाए। जब मैंने उनको बताया कि 2 जून, 2017 को ही गजट नोटिफिकेशन में गौण कृषि मंडी को कृषि मंडी में दे दिया गया था तो किस तरह से आप लगा रहे हैं? जब उनको गजट नोटिफिकेशन की कापी दी तो पता लगा कि हमें कुछ भी नहीं मिला। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने किस तरह से गुमराह करके बजट के अंदर इसको जुड़वाया और मंडी जिसका 2017 के अंदर गजट नोटिफिकेशन हुआ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से रखा जाए। इतना ही कर देंगे तो मान लेंगे कि बहुत कुछ उस मंडी को दे दिया।

सहकारिता की बात करते हैं। एमएसपी के अंदर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह समर्थन मूल्य किसानों के लिए बढ़ाया। पिछले कांग्रेस राज के अंदर किसी भी जिंस का दस रुपये से लेकर पचास रुपये से ज्यादा का किसी का भी समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान मंत्री जी को जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कम से कम पचास रुपये, ज्यादा से

(श्री कन्हैया लाल)

ज्यादा एक हजार रुपये तक पर-ईयर समर्थन मूल्य बढ़ाया और उनको खरीदने का भी प्रावधान किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो पहले हर किसान से 25 क्विंटल माल खरीदती थी, इसको अगर 50 क्विंटल तक कृषि मंडी में सहकारिता के माध्यम से खरीदे, किसान का पूरा माल खरीदे और उसको उचित मूल्य मिले तो किसान की आमदनी जरूर बढ़ेगी। कर्ज माफी की बात की। अगर किसानों को सहकारिता का लोन समय पर दे देते तो किसान इंश्योरेंस समय पर करता। कम से कम उसको क्लेम तो मिलता। मार्च तक किसान उम्मीद करता रहा कि हमारा कर्ज माफ होगा, सभी बैंकों का कर्ज माफ होगा, वह जमा नहीं करा पाया। उसके ओवरड्यू होने की वजह से तीस हजार, चालीस हजार, पचास-पचास हजार तो हर किसान को अलग से पैनल्टी के रूप में भुगतना पड़ा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन की बात करते हैं। आज गांवों के अंदर जाकर देखें तो लगभग 1000 से 1200 पोस्ट तो पशुपालन के डाक्टर्स की कमी है, बिल्डिंग्स नहीं हैं। इनको बढ़ाने का प्रावधान करते तो बहुत अच्छा होता।

चौथा संकल्प इन्होंने लिया है, सक्षम मजदूर-छात्र-युवा-जवान। बेरोजगारों को रोजगार देने की पिछले बजट में बात की थी। आज तक किसी भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया है। इसके साथ-साथ, यह घोषणा की कि जो भी ओलम्पिक का पदक जीतकर आएगा, उसको तीन करोड़ रुपये देंगे। पदक कहां से जीतेगा, जब तक आप खेलने की कोई सुविधा नहीं बढ़ाएंगे, कोई स्टेडियम नहीं बढ़ाएंगे, न कोई खेल मैदान को विकसित करेंगे तब तक वह बच्चा कहां खेलेगा, कहां पदक जीतकर लाएगा। यह तो वही बात हो गई कि 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी'। बस घोषणा करने में क्या बिगड़ता है? आपने कर दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे टोडारायसिंह और मालपुरा में दो गवर्नमेंट कालेज हैं। अगर उन दोनों जगह पर आप खेल स्टेडियम बना देते हैं तो काफी बच्चे खेल कर आगे जा सकते हैं। इसके साथ-साथ, इसमें कहा है कि सक्षम मजदूर, अभी सुबह भी मेरा प्रश्न था कि जो पिछली सरकार ने श्रमिकों के हित के लिए हर काम के लिए एक परसेंट लेबर सैस काटते हैं, 8 हजार करोड़ से भी ज्यादा इसका बजट है, जमा है, मजदूरों को 55 हजार शादी के लिए मिलते हैं, उसको पढ़ने के पैसे मिलते हैं, कोई डैथ हो जाए तो उसके लिए मिलते हैं, वह बजट भी टाइम पर, समय पर नहीं दिला पा रहे हैं तो किस तरह से मजदूर सक्षम

(श्री कन्हैयालाल)

होगा? किस तरह से उसको रोजगार मिलेगा? मेरी यह समझ में नहीं आता है। यह बजट में एक तरह से छलावा है।

शिक्षा की बात करते हैं। आज शिक्षा के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर, सभी जगह स्कूल क्रमोन्नत होगी, जहां पर 12वीं स्कूल चल रही है, वहां पर 5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं, रमसा से भी आते हैं तो गिनती के एक-दो कमरे आते हैं। अगर कक्षा कक्षों की व्यवस्था करते तो बच्चे सारे अलग-अलग क्लासवाइज बैठते तो उनका भी काम होता। इसके साथ-साथ पदों की बात करें तो विशेषकर दसवीं क्लास के अंदर विज्ञान और गणित के लगभग 60 से 70 परसेंट पद हर स्कूल के अंदर खाली हैं। जब गणित और विज्ञान ही हम प्रोपर ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो किस तरह से शिक्षा में बच्चों की कमजोरी दूर करेंगे। जल्दी से जल्दी पद भरने की आप कोशिश करेंगे तो शिक्षा में कुछ होगा।

पिछली सरकार ने टोडारायसिंह में गवर्नमेंट कालेज खोला था, सात करोड़ रुपये की बिल्डिंग भी बन गई, सब कुछ हो गया। मैंने मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री व माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि वहां कालेज के बच्चे नीचे दरी पर बैठते हैं। साइंस कालेज है, लैब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैंने बार-बार लिखा। मैंने यह भी कहा था कि आप ही उद्घाटन कर दो, सात करोड़ रुपये से बिल्डिंग तैयार है। मैंने निवेदन भी किया कि उद्घाटन के बहाने आप वहां आएंगे तो 10-20 लाख, 50 लाख रुपये मिलेंगे तो कम से कम उसकी सुविधा तो मिलेगी। आप यह करेंगे तो बहु त अच्छा रहेगा।

इसके साथ-साथ पंचायत राज की बात करते हैं। पंचायती राज में हम गांवों के विकास की बात करते हैं। गांवों में यह स्थिति है कि 3 से 4 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है, सारे पद खाली पड़े हैं।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): आप पदों की बात कर रहे हो, यहां तो मंत्रिमण्डल खाली है।

**श्री सभापति**: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, इनकी सीट दिखवाइये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): एक कैबिनेट मिनिस्टर तो रहें न साहब।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) :यह पहली बार हो रहा है।

**श्री सभापति**: सब बैठे हैं, आप चिंता मत करो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

**श्री सभापति**: विराजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। (व्यवधान) बहुत से लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। विराजिए।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**डा. सुभाष गर्ग** (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सभापति महोदय, यहां तीन-तीन मंत्री मौजूद हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: प्लीज, आप विराजिए। (व्यवधान) आप विराजिए तो सही, आसन पैरों पर है।

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): तीन-तीन मंत्री बैठे हैं, इनको दिख नहीं रहे हैं क्या?

**श्री सभापति**: प्लीज, आप विराजिए। बहुत से नये माननीय सदस्यों को बोलना है। आपकी इस चर्चा के चक्कर में बहुत से लोग नहीं बोल पाएंगे, कल भी नहीं बोल पाए थे। मेहरबानी करके उनको बोलने दे। माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। माननीय उप सचेतक महोदय, माननीय सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनको कहें कि एक दो लोग तो यहां बैठें। दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त कीजिए। (व्यवधान) विराजिए।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति**: अलाउ नहीं करूंगा, विराजिए। यह आपकी गलत परम्परा है। विराजिए। (व्यवधान) उप नेता महोदय, आप इन दो सदस्यों की सीट दिखवाओ, क्या प्राब्लम है, यह एक मिनट भी चुप नहीं बैठते।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (सूरतगढ़): 000

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): सभापति महोदय, सरकार ने छठा संकल्प पानी, बिजली व सड़क का किया।

**श्री सभापति**: अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): सभापति महोदय, पिछली सरकार में हर साल, हर विधायक को सौ हैण्ड पम्प लगाने की परमीशन होती थी, आज हम एक हैण्ड पम्प नहीं लगा पा रहे हैं। पानी की यह स्थिति है। मेंटीनेंस की बात करें तो जे.ईएन, ए.ईएन, एक्स.ईएन के पद नहीं है, हैण्ड पम्प मिस्त्री के पद भी नहीं है। आने वाली गर्मी कैसे निकालेंगे? आप घर-घर नल कनेक्शन की बात कर रहे हैं अगर मेंटीनेंस के ही आदमी नहीं हैं तो किस तरह पानी पहुंचाएंगे।

रोड की भी ऐसी ही स्थिति है। सब लोगों को उम्मीद थी, विशेषकर टोंक ज़िले में तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि उप मुख्य मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, पड़ौसी हैं, हमें तो खूब मिलेगा, लेकिन एक रुपये का भी रोड का काम नहीं मिला, कोई मिसिंग लिंक नहीं मिली। विकास पथ में भी अभी सुरेन्द्र सिंह जी बता रहे थे एक विकास पथ, दो साल में 80 लाख रुपये का, उसके टेंडर अब हो रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा? पुरानी रोड है, उनकी मेंटीनेंस के लिए पैसा नहीं है। काम चल रहा है तो पूरा बजट नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है।

इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने लगभग साठ करोड़ रुपये डिग्गी के विकास के लिए दिए थे। आज 24 करोड़ के बाद एक रुपये का बजट नहीं दे रहे। सिंचाई की बात करें....

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): दो मिनट....

**श्री सभापति**: विराजिए, बहुत हो गया।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): राजस्थान कैनाल की बात थी। उसके तहत विशेषकर बीसलपुर बांध में ओवरफ्लो पानी डालने की बात थी। पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मैं कहना चाहता हूं कि बीसलपुर बांध से इस बार भी लगभग 100 टीएमसी से ज्यादा पानी बहकर निकल गया।

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): टोडीसागर में पानी डालने का तीसरे चरण में अगर यहां से प्रपोजल बनाकर 220 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार में भेज देते तो वहां से सैंक्शन की पूरी उम्मीद है। यह बजट दिया है.....

**श्री सभापति**: विराजिए। श्री मदन प्रजापत।

**श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): एक तरह से राजस्थान की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, 20 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। तारीख भी 20, साल भी 20 और बजट पेश किया 21, माननीय सभापति महोदय, सामने से एक बात हो रही थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी और पायलट साहब में आपसी राजीनामा करवा दिया जाए। उनसे पूछना चाहता हूं पहले घर में जाकर, घर वाला निस्तारण कर दें, हमारा तो अपने आप हो गया। हमारे बीच कोई बात नहीं है। आपकी वास्तविकता है, उसकी ओर देखें।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, फिर बार-बार आप दो मिनट-दो मिनट करेंगे।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): आप मुझे पहले कह दीजिए कि दस मिनट हैं या दो मिनट हैं, मैं बोल दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज विरासत में 3 लाख 10 हजार करोड़ का कर्ज मिला। इन्होंने झूठे शिलान्यास और उद्घाटन करके 13 हजार करोड़ रुपये के वर्क आर्डर दे दिए। मैं सुन रहा था, जो तीन-तीन, चार-चार बार मंत्री रहे, कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। अभी सवा साल हुआ है। आप चार-चार बार मंत्री बने, आप वास्तव में मंत्री थे या कटारिया जी की तरह सिर्फ नाम के मंत्री थे। अगर आप मंत्री थे तो बार-बार यह आवाज नहीं उठती कि कुछ नहीं हुआ। सवा साल में क्या बिगड़ गया। पहले तो कह रहे थे सब कुछ हुआ। माननीय सभापति महोदय, 20 फरवरी, 2020 गुरुवार को इस सदन में

(श्री मदन प्रजापत)

लोकप्रिय मुख्य मंत्री, ग़रीबों के मसीहा, किसान, युवा एवं महिलाओं के हितैषी, दलित वर्ग शुभचिन्तक,

**(16.38 बजे)**

**(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)**

हर प्राणी के दिल की पीड़ा जानने वाले मुख्य मंत्री, माननीय अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। खुशहाल राजस्थान बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें बिजली, पानी, सड़क, युवा, शिक्षा सहित सभी सैक्टरों पर फोकस किया है। अपराधियों, मिलावटखोरों, माफियाओं पर लगाम लगाने का काम किया है, इसको जनता की सरकार कहते हैं। आपकी तरह पोपाबाई का राज नहीं, वास्तव में जन हितैषी सरकार किसी को कहते हैं तो आज की वर्तमान सरकार को कहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जन सेवा की भावना, जन कल्याण के तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने सात संकल्प लिए। वह जनता की पीड़ा जानते हैं। नीरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर छात्र, युवा जवान, शिक्षा का परिधान, बिजली, पानी, सड़कों का मान, आज की वर्तमान केन्द्र की अर्थव्यवस्था डूबती हुई कमजोरी के बावजूद भी शानदार बजट पेश करके यह साबित कर दिया कि जन हितैषी में कोई फैसला ले सकते हैं तो क्रांतिकारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ले सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, 53 हजार नई नौकरियां देने का फैसला किया। दो करोड़ नौकरियों की तरह झूठा फैसला नहीं। युवाओं के हित का मामला हो, चाहे कर्मचारियों के डीए का मामला हो, शानदार फैसला किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात सुन रहा था कि दिल्ली में सरकार बन जाती तो इनका ज़मीर जिंदा रह जाता। इनको वोट नहीं दिए, ज़मीर मर गया। पानी, बिजली में ज़मीर बेच दिया। आपको वोट देते हैं तो ज़मीर जिंदा, आपके खिलाफ वोट पड़ें तो इसका मतलब ज़मीर मर गया। इस तरह की बातें जो मैं सुन रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष कमजोर है या मजबूत है, यह तो विधान सभा के पूर्व माननीय अध्यक्ष, कैलाशजी मेघवाल ने प्रमाणित कर दिया। इनकी आपसी लड़ाई के कारण विपक्ष की हालत वास्तव

(श्री मदन प्रजापत)

में कमजोर है। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, ताकि यह लोकतंत्र मजबूत होता रहे। यह मेरे कहने की जरूरत नहीं, माननीय वरिष्ठ नेता, पूर्व विधान सभा अध्यक्षजी ने यह बात कही है।

आज मुझे पुरानी बात याद आई तो मुझे हंसी आ गई। ताजमहल को तोड़ने की बातें करने वाले ताजमहल का स्मृति चिन्ह पेश कर रहे थे। हम यह चाहते हैं, यह प्रेम का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है। हम तो यही चाहते हैं, हमें खुशी हुई। लेकिन तोड़ने की बातें करने वाले आज यूपी. के मुख्य मंत्रीजी, जब मैंने टेलीविजन पर फोटो देखा तो मुझे लगा कि इनकी करनी और कथनी में कितना अन्तर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों की कहावत है कि रेस वाले घोड़े और शादी वाले घोड़े में अन्तर होता है। आज वर्तमान विपक्ष के जो नेता हैं, ये रेस वाले घोड़े के बजाय शादी वाले घोड़े हैं, क्योंकि रेस वाले घोड़े छह महीने पहले अपने आप आ जाएंगे। ये तो शादी वाले घोड़े हैं, छह महीने पहले अपने आप, जो वास्तविक हैं, वे आने वाले हैं। पहले भी चार सालों के बाद में आये। अब आने वाले समय में भी वे आयेंगे।

मुझे उस बात का दुःख हुआ कि हिन्दुस्तान में गुजरात माडल पेश किया गया। अगर गुजरात का वास्तविक विकास का माडल होता तो यह गरीब की झोंपड़ी के आगे बड़ी-बड़ी दीवारें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गुजरात माडल होता तो उस गरीब को आवास मिलता, उस गरीब को फ्लैट मिलता। आपने आवास देने के बजाय गरीबों की झोंपड़ी के आगे, अमरीका के राष्ट्रपतिजी आये, बड़ी-बड़ी दीवारें कर दीं, ताकि उनको हवा-पानी भी नहीं मिल सके। यह गुजरात का इनका विकास माडल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है, पहले भी आये, आज भी आये। जब नेहरूजी और इन्दिरा गांधीजी के समय आये, उस समय भी ताजमहल और जो अपनी विरासत है, चाहे लाल किला है, चाहे हैदराबाद हाउस है, मुझे आज भी अन्तर नहीं दिखा। उस समय भी वही और आज भी ताजमहल और लाल किला हिन्दुस्तान की शान को बढ़ा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान अर्थशास्त्री देश के पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने जब ओबामा जी के समय परमाणु समझौता किया तो कई आरोप लगाये, भयंकर विरोध हुआ। आज वही बातें, वे ही कर रहे हैं। मनमोहन सिंहजी के अनुभव के कारण ही आज हिन्दुस्तान मजबूत हुआ है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गांधी का देश है। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे नेहरूजी हों, चाहे बाबा साहब हों, आज इनके पास अगर महापुरुष होते तो आप वीर सावरकर, दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ट्रम्प साहब को बता देते। आप उनका वर्णन करते। आज गांधी आश्रम जाकर यह साबित हो गया कि यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी ओर नेहरू की विरासत है। आपके पास में बताने के लिए कोई महापुरुष नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी और भी कई बातें आयीं। महंगाई से आज देश में हालत खराब हो रही है। इस महंगाई के कारण आज वर्तमान स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि मैं याद दिलाना चाहता हूं, वह मंत्री स्मृति ईरानी कहां हैं, कहां हैं बैलगाडियां, कहां हैं गैस की टंकियां। आज गरीब के वजूद में, गरीब के हाथ में वह गैस नहीं रही, टंकी के इतने भाव बढ़ गये। आज इतनी महंगाई आसमान छू रही है, देश में महंगाई की हालत खराब है और वे चुप हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मदनजी, मदनजी।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि देश की आजादी के बाद में, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा-लिखा है, अगर वोट लेने में शर्म नहीं आती है तो उनके खड़े होने के अधिकार को लोकतंत्र में कोई छीन नहीं सकता। इन्होंने वापस जो फैसला किया है, मैं धन्यवाद देता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज कई असत्य बातें करना, आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता क्लीनिक का फैसला गरीब हित में लेकर यह साबित कर दिया कि वास्तव में गरीब की पीड़ा कोई जानता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी जानते हैं। इनकी तरह 15 लाख के झूठे वादे नहीं किये, अच्छे दिन के झूठे वादे, काला धन, महंगाई, नई-नई कई बातें, समय कम है, इसमें नहीं जाते हुए, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज मां गंगा याद कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी तरह दो करोड़ नौकरियों के झूठे वादे के बजाय 55 हजार नौकरियां देकर यह साबित कर दिया कि युवा की पीड़ा कोई जानता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी जानते हैं।

आज ये झूठे क्यों फर्ज की बातें करते हैं। आज नंदी शाला खोलकर लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने साबित कर दिया कि गऊ की पीड़ा

(श्री मदन प्रजापत)

और गऊ के हित में अगर कोई क्रांतिकारी फैसला ले सकता है, उनका नाम अशोक गहलोतजी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चाहे गरीब के लिए दवा हो, गरीब के लिए फ्री जांच हो, चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, चाहे बेरोजगारों के लिए भत्ता हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी का फैसला हो, पहले भी माननीय लोकप्रिय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी और सोनिया गांधीजी के नेतृत्व में 73 हजार करोड़ का किसानों का कर्जा माफ हुआ। आज भी माननीय गहलोत साहब ने किसान हित में फैसला लेकर यह साबित कर दिया कि किसान की पीड़ा कोई जान सकता है, वह कांग्रेस सरकार और मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी जान सकते हैं। चाहे किसानों के हित में दिन में बिजली का फैसला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह फैसला मैं सुन रहा था तो दिल में यह सुकून महसूस हुआ कि किसान को, अन्नदाता को रात में क्या-क्या कठिनाइयां महसूस होती हैं। दिन का फैसला लेने के लिए यह जो मन में भाव आये और मुख्य मंत्रीजी ने, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, चाहे गरीब हों, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए फैसला लेकर जो सौगात दी है, आज वह अशोक गहलोतजी ने दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं लोकिप्रय मुख्य मंत्रीजी को कि मिलावट के खात्मे के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आज की ताजा जरूरत है, समय की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, मिलावट के मामले में यह क्रांतिकारी फैसला है, इसमें पूरा सदन एकजुट होकर, सभी मिलकर सहयोग करें, ताकि जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात को पूरा करते हुए, मिलावट के मामले में, और अवैध बजरी के जो माफिया पनप रहे हैं, वास्तव में मजबूरी भी है कि बजरी के बिना काम भी नहीं चल सकता और बजरी में लीज आबंटन नहीं होने के कारण ये अवैध माफिया पनप रहे हैं। अवैध माफिया को रोकना भी जरूरी है, मिलावटखोरों के ऊपर लगाम कसनी जरूरी है। इनके लिए कोई न कोई निर्णय करना जरूरी है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी और पोषाहार मामले में तो इतनी बदनामी होती है, यह कोई नई बात नहीं है। चाहे सरकार इधर की रहे, चाहे इधर की रहे, इनमें खुले आम ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी मांग करता हूं। +++ के नाम से लाइट घोटाला, बार-बार सदन में मांग उठ रही है। मैं मांग करता हूं कि नगरपालिकाओं में बिजली घोटाले की जांच हो। इनके अलावा भामाशाह योजना और खाद्य सुरक्षा योजना में जो फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ न कुछ फैसला करना अति जरूरी है।

**श्री अध्यक्ष**: धन्यवाद।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: हो गया, हो गया। बस, धन्यवाद। (व्यवधान) धन्यवाद।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): मेरी चालीस सालों से मांग है ...(व्यवधान) बालोतरा जिला बने, नहीं तो ए.डी.एम. आफिस तो इसी जवाब में, जिला बने तब तक ए.डी.एम. आफिस की घोषणा, और चाहे कालेज हो, पानी हो और रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए, बात आती है प्रोटोकाल में एम.एल.ए. को ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त करें, समाप्त करें। श्री बलजीत यादव। हो गया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): 000

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। बैठें, प्लीज। श्री बलजीत यादव।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): 000

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृदि्ध

**श्री महेन्द्र चौधरी** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्षजी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: सदन की सहमति है?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

# आय-व्ययक

## आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद विवाद

**श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोतजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को इस बजट में राहत देने का प्रयास किया। उन्होंने किसानों की परेशानियों को समझा और यह निश्चय किया कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। उसके लिए मैं उनका बार-बार आभार व्यक्त करता हूं।

मैं आभार इस बात के लिए भी राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो एक्सीडेंट हो जाते थे कहीं पर भी और किसी गरीब का एक्सीडेंट हो गया या किसी बाहर दूसरे स्टेट के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और पास में कोई प्राइवेट हास्पिटल में ले जाकर उसको भर्ती तो करवा देता है लेकिन बिना पैसे दिये प्राइवेट हास्पिटल वाले उसका इलाज नहीं करते थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह निश्चय किया कि वह बाध्य होंगे उनका इलाज करने के लिए, यह बहुत ही प्रशंसा की बात है

माननीय मुख्य मंत्रीजी की मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज वाली जो योजना है, उसको पूरे देश में सराहा जा रहा है। अभी उन्होंने हार्ट, सांस और दूसरी गुर्दा जैसी बीमारियों को भी जोड़ा है, इसमें एड किया कि उनका इलाज भी मुफ्त में किया जाएगा। दवाओं की संख्याओं को भी बढ़ाया, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री बलजीत यादव)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खिलाड़ियों के लिए, जो विजेता खिलाड़ी हैं, उनकी पुरस्कार राशि में जो वृद्धि की है, उसके लिए भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। बेरोजगारी भत्ता देने का निश्चय किया, कर्मचारियों का पांच परसेंट डी.ए. बढ़ाया और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए स्कूल खोलने, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का जो निर्णय लिया, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। 53 हजार जो भर्तियां निकालीं, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और 876 नई बसें जो खरीदने का निर्णय लिया, उसके लिए भी मैं राजस्थान की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

राजस्थान की सरकार का आभार इस बात के लिए भी व्यक्त करता हूं कि परिवहन विभाग जो भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो कुछ महकमों में होता है, उसमें परिवहन विभाग भी है। उसमें सवा करोड़ रुपये पकड़कर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को साबित किया तो इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से मैं अपना एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो यह भ्रष्टाचारी पकड़े हैं, सवा करोड़ रुपये पकड़े हैं, यह सवा करोड़ रुपये ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्षों से चलते आ रहे हैं। जो यह सरगना बता रहे हैं, वह मोटरसाइकिल पर चलता था कुछ वर्षों पहले और अब वह ऑडी गाड़ी में चलता है। उसके घर में दो-दो ऑडी गाड़ियां हैं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उसने अर्जित कर रखी है, जो भ्रष्टाचार से कमाई हुई है। उसके लिए मैं सरकार को लिखित में भी दूंगा और मैं बताऊंगा भी, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की सरकार ऐसी सम्पत्ति जो भ्रष्टाचार से अर्जित की गयी है, वह जनता की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई है, उस सम्पत्ति को जब्त करके जनता को सौंपेगी।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और सुझाव राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। संविदाकर्मी जो वर्षों से काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, जैसे पंचायत सहायक है, वह पहले पंचायत में थे, अब उनको स्कूल में लगा दिया तो पूरे टाइम वह काम करते हैं और वेतन उनको मात्र छह हजार रुपये ही दिया जाता है। इसी प्रकार बहुत से सरकारी

(श्री बलजीत यादव)

विभागों में संविदाकर्मी काम कर रहे हैं। यह मांग मैंने पहले भी उठाई थी, वह संविदाकर्मी इस आशा में इतने कम वेतन में काम कर रहे हैं कि सरकार उनको स्थाई जॉब देगी। इसलिए सरकार से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि या तो उनको स्थाई किया जाए या उनको स्पष्ट यह बता दिया जाना चाहिए था। जब उनको अपाइंट किया गया, कांट्रेक्ट के ऊपर इसलिए मैं यह आशा रखता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को भी स्थाई करेगी।

दूसरा, मैं बताना चाहता हूं होमगार्ड के लिए, होमगार्ड को एक महीने ड्यूटी दी जाती है और दूसरे महीने उनको घर पर भेज दिया जाता है और जो व्यक्ति किसी अधिकारी को, कमांडेंट को पांच-सात हजार रुपये दे देता है, उसकी ड्यूटी कंटीन्यू लगायी जाती है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कमांडेंट को पैसे दे दिये तो उसको ड्यूटी कंटीन्यू मिलेगी। तीन-तीन विभागों में कंटीन्यू ड्यूटी करते हुए पाये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आर.टी.आई. के जरिए उदयपुर की एक जानकारी मेरे को मिली है तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसा जो इनके साथ इन्जस्टिस हो रहा है, उसको रोका जाए और सभी जो होमगार्ड हैं उनको 30 दिन या कंटीन्यू 12 महीने उनकी सेवाएं ली जाएं।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारों के द्वारा भर्तियां निकाली जाती हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, भर्ती निकलती है और भर्ती निकलने के बाद पहली बात तो यह होती है कि भर्ती निकलेगी, जैसे कोई भर्ती निकली हुई है 2018 में और अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। ऐसे ही एक भर्ती निकालते हैं तो तीन से चार साल तक तो रिजल्ट ही नहीं आता है और फिर और भर्तियां निकलती रहती हैं। गांव का बच्चा यहां पर आता है तो एक कमरा उसको चार हजार रुपये में कम से कम किराये पर लेना पड़ता है और उसका खाने का और ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा मिलाओ तो कम से कम दस हजार रुपये एक युवा के खर्च होते हैं और कोचिंग की फीस वह अलग से देता है। अब एक भर्ती आपने निकाल दी, जैसे आर.ए.एस. की निकाल दी, आर.पी.एस.सी. ने भर्ती निकाल दी और भर्ती तो निकाल दी 2018 में और उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है। अब वह विद्यार्थी पहले आर.ए.एस. की तैयारी करके एग्जाम दे देता है और फिर दूसरी भर्ती निकलती

(श्री बलजीत यादव)

है, फिर दूसरी कोचिंग करता है, फिर उसकी तैयारी में लगा रहता है। फिर तीसरी भर्ती निकलती है तो उसमें लगा रहता है। फिर चौथी निकलती है तो उसमें लगा रहता है तो हर साल जो आदमी इतनी महंगी-महंगी कोचिंग में फीस देता है, दस हजार रुपये महीने के देता है, वह गरीब किसान का बेटा किस तरह से पढ़े और गरीब किसान जो यह चाहता है कि मेरा बेटा पढ़-लिखकर सक्सेस हो और वह अपने पैरों पर खड़ा हो तो वह कितने दिन तक गरीब किसान लड़े, उस गरीबी से, उस मजबूरी से, वह कितने दिन वेट करे? अब उसका एक एग्जाम में सलेक्शन हो जाएगा तो फिर दूसरे का रिजल्ट आएगा। फिर यदि दूसरे में भी सलेक्शन हो गया तो फिर तीसरे का रिजल्ट आएगा। फिर तीसरे में भी सलेक्शन हो गया तो अब उसको नौकरी एक ही करनी है, लेकिन उसका शोषण चार साल तक कर लिया गया। इसलिए मैं यह मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से, हर सरकारें यह बात करती हैं कि हम इनको यह कर देंगे, हम इनको असुविधा नहीं होने देंगे तो आर.पी.एस.सी. है, वह अपना कैलेण्डर जारी करे। जैसे यू.पी.एस.सी. की भी तो भर्तियां होती हैं तो आर.पी.एस.सी. क्यों नहीं कर सकती है? वह अपना कैलेण्डर जारी करे कि इस डेट को हम यह एग्जाम करेंगे और इस डेट तक हम इसका रिजल्ट दे देंगे, इस डेट को अपाइंटमेंट दे देंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास वैकेंसीज नहीं हैं तो फिर सरकारें विद्यार्थियों को छलावे में क्यों रखती हैं? वह बता दे कि हां, दो साल तक हम एक भी भर्ती नहीं निकालेंगे लेकिन निकालें तो फिर कमिटमेंट होना चाहिए कि कोई भर्ती निकाली तो उसको कहें कि जनवरी में निकली है, दिसम्बर तक आपको अपाइंटमेंट देंगे तो वह आदमी एक साल के लिए कहीं से कर्जा लाकर, किसान, मजदूर अपने बेटे को पढ़ाएगा और उसका सलेक्शन होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है।

हर सरकार यह कहती है, इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि देखिये, जो युवा है, मुझे नहीं पता, सबको पता लगता है या नहीं लगता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कई साथी लोग कहते हैं कि सारा दर्द बलजीत यादव ही लेकर घूम रहा है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी अगर उन स्टूडेंट्स से बात करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी परेशानी में वह है। एक-एक रुपये के लिए मोहताज व्यक्ति कर्जा लेकर आता है, हाई ब्याज के ऊपर पैसा लेकर आता है और हर मां-बाप यह चाहता है कि बच्चा एक नम्बर से रह गया, वह

(श्री बलजीत यादव)

दूसरे साल कोचिंग करवाता है कि अबकी बार सलेक्शन हो जाएगा। उस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है, वह यह सोचता है कि बेटे को घर नहीं बैठाऊं इसलिए दूसरी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसका फार्म भरवाता है, उसकी कोचिंग करवाता है। कोचिंग सेंटर है, वह सवा-सवा लाख रुपये एक-एक साल के ले लेते हैं। सवा लाख रुपये रहने खाने के खर्च हो गये। अब सवा-सवा लाख, कुल ढाई-ढाई लाख रुपये कोई आदमी एक साल के दे और फिर दूसरे साल के दे और फिर तीसरे साल के दे, चौथे साल के दे तो फिर कहां से किसान लाये? खेती में कोई इनकम हो नहीं रही है, पानी खतम हो गया, बिजली पूरी नहीं मिलती है और पानी सूखता जा रहा है। एक बार ट्यूबवैल कराता है तो पानी सूख जाता है तो उसको दो साल बाद वापस ट्यूबवैल करवाना पड़ता है, उसको नीचे करवाओ, वह सूख गया, फिर होता है तो फिर दो साल बाद करवाना पड़ता है तो मैंने पिछली बार भी इस सदन में इस बात को रखा था कि एक बार इन और चीजों से बजट चाहे एक बार आप बंद कर दो और सब चीजों पर, चाहे कम दे दो भले ही लेकिन एक बार जो यहां कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश है, उस किसान को पानी की व्यवस्था की जाए।

सर, हमारे वहां पर यमुना बारिश के दिनों में ओवर-फ्लो बहती है, वहां का पानी लाया जा सकता है, डैम बनाकर डाला जा सकता है, उससे वाटर लेवल भी ठीक हो जाएगा और सिंचाई नहर के जरिए भी पानी दिया जा सकता है। इसी प्रकार से, चम्बल नदी है, वह खतरे के निशान से ऊपर बहती है। उस वक्त वह पानी हमारे स्टेट से चला जाता है, उस पानी को रोका जाए, इस बार भी जैसे कितनी बही है तो वह पानी किसान के काम आ सकता है। इसलिए मैं राजस्थान की जो लोक कल्याणकारी सरकार है, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी हैं, उनसे मैं यह मांग करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें कि किसान की स्थिति सुदृढ़ करने के बारे में उन्होंने सोचा है लेकिन मैं यह और चाहता हूं कि और ज्यादा किसान के फेवर में सोचने की जरूरत है। मुझे यह आशा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी किसान की यह जो समस्या है, पानी की और बिजली की इस बारे में और सोचेंगे क्योंकि जो सब्सिडी मिलती थी 833 रुपया, वह सब्सिडी अभी किसान को नहीं मिल रही है। मैं यह आशा रखता हूं कि वह सब्सिडी पुनः चालू होगी, उसको मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें बताना चाहता हूं। मेरे वहां पर गण्डाला है, वह उप तहसील बनाने के सारे मापदंड पूरे करता है।

(श्री बलजीत यादव)

30 हजार से ज्यादा आबादी है, चालीस गांव आस-पास के जुड़े हुए हैं इसलिए उसको उप तहसील बनाया जाए। नीमराना, हमारे यहां पर तीन थाने लगते हैं, साढ़े तीन हजार के लगभग मुकदमे पैंडिंग हैं, वहां पर सिविल न्यायालय की स्थापना हो। मांढन है मेरा, वह बहुत दूर से कृषि उपज मंडी है, वहां पर कृषि मंडी बनाई जाए।

बहरोड जो मिड-वे है, वह मिड-वे प्रोफिट में था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको जानबूझकर और कुछ लोग उस मिड-वे की जमीन को बेचना चाहते थे प्रोपर्टी डीलर को इसलिए उसको जानबूझकर चूंकि, यह मेरे क्षेत्र का है तो मैं जानता हूं कि जानबूझकर उसको घाटे में डाला गया कि इसको घाटे में लाओ और घाटे में लाकर इसको बेचें। फिर प्रोपर्टी मार्केट में मंदी आ गयी तो वह बिक नहीं पाया इसलिए वह बंद पड़ा है। मैं आशा रखता हूं कि सरकार उसको वापस चालू करेगी जिससे कि जो दिल्ली-जयपुर के बीच यहां जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी पैसेंजर जाते हैं, उन सबको सुविधा मिलेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**(17.00 बजे)**

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में ही अपनी बात खतम कर रहा हूं। अभी जो वीडियो कोच बसें चलती हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको अब ढाबों और होटलों पर रोका जाता है कि कुछ पैसा रोडवेज को दिया जाएगा और वहां पर ऐसी लूट होती है कि एक थर्ड क्लास चाय मिलेगी, उसके वह आपसे 40 रुपये मांग लेगा, कोई ब्रेड का पैकेट लेगा तो उसके मनचाहे पैसे मांग लेगा, कोई आपने बिस्किट का पैकेट ले लिया तो बिस्किट के आपसे 50 रुपये मांग ले, 100 रुपये मांग ले, इसलिए सरकार मिड-वे को चालू करे, ताकि यह लूट बंद हो और जनता को अच्छी सुविधा मिल सके, पैसेंजर को अच्छी सुविधा मिल सके, यह मैं मांग करता हूं। आशा है हमारी मांगें राजस्थान की सरकार पूरी करेंगी। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: पूराराम चौधरी।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बजट 2020-21 पर बोलने की अनुमति चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सात संकल्प, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिए हैं, पिछला जो 2019-20 का बजट था, उसमें संकल्प तो नहीं लिए थे, मगर उन्होंने कहा कि हम सड़कें बनाएंगे। आज तक एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी राजस्थान में। हमारे जालौर जिले में बिलकुल नहीं बनी।

(श्री पूराराम चौधरी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से केवल दो-तीन बिन्दुओं पर बोलना चाहूंगा। 'पहला सुख नीरोगी काया' बिलकुल सत्य बात है, पर हमारी नीरोगी काया कहां से होगी? दूसरा संकल्प है किसान का, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय जवाहर लाल जी नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री माननीय पटेल साहब ने नेहरूजी को यह कहा था कि हमारे किसानों के लिए यदि भारत को सम्पन्न करना है तो नदी से नदी को जोड़ दो ताकि यह जो सारा भारत है, उससे जल्दी सम्पन्न हो जाता। चार मुख्य सड़कें हैं - दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चैन्नई, इनको जोड़ दो ताकि आवागमन की व्यवस्था सही हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के लिए एक संत ने 100 वर्ष पहले कहा था कि पैसे से पानी मिलेगा। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि पानी पैसे से थोड़े ही बिक सकता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सब जगह नीरोगी काया और किसान सम्पन्न, किसान सम्पन्न तब होगा, जब इस देश के अंदर, यह राजनीति छोड़कर पांच बरस इनकी सरकार आयी, पांच बरस दूसरी सरकार आयी। पहले बीजेपी की रही, फिर कांग्रेस की रही, इससे कोई लेना-देना नहीं। इसी तरह यदि हम करते रहे तो एक दिन वह समय आ जाएगा कि दूसरा वर्ल्ड वार हुआ था, तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिए होगा। दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो आजाद हिन्द फौज के हमारे जो सैनिक थे माननीय सुभाष चन्द्र जी बोस, जर्मनी में जब वह पहुंचे, जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध हार गया था। विश्व का जो सबसे बड़ा हिटलर था, बहुत बड़ा तानाशाही था, लेकिन उस तानाशाह ने सुभाष चन्द्र बोस के सामने माफी मांगी थी कि मिस्टर बोस, आई एम वैरी सारी। इंडिया इज गुड कंट्री। उन्होंने एक बात और कही थी कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। इसलिए भारत के अंदर बहुत सारी नदियां बहती हैं, आप नदी से नदी जोड़ दो ताकि कम-से-कम किसान सम्पन्न हो और हमको और हमारे बच्चों को कहीं से पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय वह आया जब भारत के प्रधान मंत्री शास्त्रीजी थे तो उन्होंने कहा था कि हम हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू सोमवार को व्रत कर लें और मुसलमान भाई शुक्रवार को एक दिन के लिए रोजा रख लें ताकि हमें अनाज बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।

(श्री पूराराम चौधरी)

आज नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी में क्या हुआ, क्या लेना-देना है? नोटबंदी इसलिए करनी पड़ी कि आपको तो पता है, आप विद्वान हैं। जब पी.वी. नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधान मंत्री थे और मनमोहन सिंहजी अर्थशास्त्री थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं और कोई बुराई नहीं करता हूं। लेकिन भारत की करेंसी को तीन बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा था। नोटबंदी इसलिए करनी पड़ी कि जो हमारा पेपर आता था, वह इंग्लैण्ड से आता था और उसी के आधार पर जितने भी पेपर आते थे, वह कहीं न कहीं बीच में चोरी हो जाते थे और आधे पेपर इंडिया में आ जाते और आधे पाकिस्तान चले जाते। इसलिए यह नोटबंदी करनी आवश्यक थी। क्योंकि नुकसान हुआ, किसानों को नहीं हुआ, व्यापारियों को हो गया, इसमें कोई दोराय नहीं है। यह हुआ है नुकसान।

अध्यक्ष महोदय, आज देश के लिए सबसे बड़े संकल्प की जरूरत है तो पानी के लिए लेना चाहिए। आगे पानी की समस्या आएगी, यह हकीकत बात है। दूसरा संकल्प है मुख्य मंत्रीजी का बजट में पानी, बिजली और सड़कें। पानी यदि हमको राजस्थान में लाना है तो जो माही बेसिन योजना बनी थी 1996 में, एक समझौता हुआ 1984 में खोसला आयोग का, उसी के आधार 1994 में समझौता हो गया और गुजरात के कडाणा बांध में पानी चला गया। सेही बांध में उसका पानी डालकर जवाई पुनर्भरण योजना, जो पूर्व में 6 हजार करोड़ की जालौर, पाली और सिरोही जिलों के लिए स्वीकृत की थी ताकि हमारे जो बांध हैं, वह उस पानी से भर जाएं ताकि किसानों के लिए पीने का पानी और सिंचाई की व्यवस्था हो सके। आज आपने इसके बारे में कहा है कि हम घर-घर में, भारत सरकार की योजना भी है और राजस्थान सरकार की 50 प्रतिशत हिस्सा राशि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पानी पर ज्यादा बोल रहा हूं कि अगर आपके पानी के सोर्सेज ही नहीं होंगे तो नल लगाओगे कहां पर?

**(17.07 बजे)**

**(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)**

जब आपके पास है ही नहीं। हम एम एल ए फण्ड से पैसा तो दे देते हैं, टंकी भी बनवा देते हैं, पर टंकी बनाने के लिए पानी कहां से जाएगा। हमारे पास सोर्सेज ही नहीं है। मैं अब जालौर जिले के ऊपर ही आ रहा हूं, पूरे

(श्री पूराराम चौधरी)

राजस्थान की बात नहीं करता। जालौर जिले के अंदर जो पिछली सरकार में 6 हजार करोड़ की जवाई परियोजना थी, माननीय सभापति महोदय, जालौर जिले के आज हमारे एक भी एम एल ए नहीं आये, वह कोई प्रोग्राम में गये हैं, जालौर जिले की जवाई परियोजना में पानी डालकर माही का पानी जो व्यर्थ जा रहा है, उस व्यर्थ पानी को हम एक जगह इकट्ठा करके, यदि जवाई बांध में जवाई से सूकड़ी और सिंदरा में चला जाए तो पीने के पानी की सुविधा हो जाएगी। जैसे ही बरसात ज्यादा होगी तो उन नदियों में पानी बहेगा और जल स्तर अपने आप ऊपर आ जाएगा। यह अति-आवश्यक है। आज इन्होंने योजना तो बना दी कि हम घर-घर में नल देंगे, पर पानी तो है ही नहीं। पिछली जो नर्मदा की योजना थी, इसमें तीन परियोजना एफ.आर., ई.आर. और डी.आर., ई.आर. प्रोजेक्ट में अलग से पिछली सरकार में 39 करोड़ का भीनमाल शहर के लिए बजट आबंटन हुआ था। लेकिन जैसे ही सरकार गयी, इस बजट में भी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि वहां की जनता को पानी पिलाएंगे। आज भीनमाल शहर की आबादी करीब एक लाख के ऊपर है और 25 हजार लोग ऐवरी-डे, चाहे वह किसान हो...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): अभी-अभी शुरू ही किया है।

**श्री सभापति**: दो मिनट तक मौलिक रहेंगे, उसके बाद फिर ...(व्यवधान)

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आपको पता है, आप और हम तो कमेटी में एक ही साथ रहे हैं।

**श्री सभापति**: बहुत पुराने साथी हैं अपन।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और बोलता भी कम ही हूं, लेकिन मैं पाइंट-टू-पाइंट बोलता हूं ताकि सदन के अंदर मामला उठे। बाकी तो रोज मैं 295 में बोल दूंगा कि एक हमारी भैंस गुम गयी, परन्तु यह बोलने की जगह नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी भीनमाल के अंदर आ रहा हूं। जवाई पुनर्भरण योजना पूरे जालौर जिले की है, ई.आर., एफ.आर., डी.आर. यह पूरे जालौर जिले का है, लेकिन भीनमाल में जो ईआर प्रोजेक्ट की एक अलग से स्कीम सैंक्शन हुई थी उसकी वित्तीय व्यवस्था नहीं हो सकी, माननीय

(श्री पूराराम चौधरी)

मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं, वित्त मंत्री वे ही हैं इसलिए इसी बजट के अंदर इसकी घोषणा करें कि हम कम से कम भीनमाल शहर के लिए तो पानी पिला सकें।

चिकित्सा मंत्री जी विराजमान नहीं हैं। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो पहला सुख नीरोगी काया है क्योंकि इस बार हमारे उधर टिड्डी आई थी और देखते-देखते पूरी फसल को निगल गई थी, मैं देख रहा हूं सुबह आठ बजे ही और जैसे ही वहां से एक जगह से टिड्डी उड़ाई, मेरे ज्यादा खेत थे, फसल सारी खाकर और आगे बढ़ गई, हमारे गांव में क्योंकि दूसरे गांव से तो उड़ा दी लेकिन तीसरे गांव में गई तो मेरा खुद का गांव उसमें आ गया, पूरा चौपट करके आगे के गांव में और निकल गई। इसलिए मेरा चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि अभी 25-30 साल से बागोड़ा अभी नई पंचायत समिति बनी है, वहां पी.एच.सी. है उसकी जगह एक सी.एच.सी. खोली जाए।

उसी जगह जो सबसे ज्यादा सब्जी और किसानों की फसल पकती है वो बागोड़ा क्षेत्र में है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है, वहां एक सब्जी मंडी और एक कृषि मंडी खोली जाए। आज पानी की परिस्थिति यह हो गई है कि यदि पानी के ऊपर और बिजली के ऊपर हमने फोकस नहीं दिया तो हम खुद एक न एक दिन फोकस हो जाएंगे। परिस्थिति बड़ी खराब है इसलिए आप पहले पानी के ऊपर एक ही काम करो, आपको नल लगाने की जरूरत नहीं, आप नल लगाकर करोगे क्या? जब आपके पास और हमारे पास पानी के सोर्सेज नहीं रहेंगे तो नल लगाकर क्या करोगे? माननीय मंत्री महोदय जी विराज रहे हैं, नल मत बनाओ, आप तो जालौर जिले में कम से कम नर्मदा का पानी दे दो और नल हमारे काट दो, बाद में देना। हम अपने आप नल लगा देंगे।

**श्री सभापति**: आप मंत्री महोदय के कक्ष में मिलें मंत्री महोदय से, समाप्त करें।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): नर्मदा का पानी है ईआर, एफआर और डीआर प्रोजेक्ट दे दो और कुछ ट्यूबवैल दे दो, आपने ट्यूबवैल दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी खिलाफत कर रहा हूं, आपने दिए भी हैं इसलिए आपको धन्यवाद भी देता हूं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, अंत में इस बजट में, वास्तव में वे कहते थे न कि दो शंख थे, एक सही था और एक गलत था। मैं 2 मिनट में खतम करूंगा, लंबी कहानी है। शंख वाला मामला है इसलिए कह रहा हूं कि गांव में दो-दो पुजारी रहते थे। एक पुजारी की डैथ हो गई तो पुजारिन गरीब हो गई और उसके बच्चे अनाथ हो गये, अनाथ ही हो गये। वो शिवजी की पुजारन थी, उसका पति शिवजी का पुजारी था और उसने शिव जी के पास में मांगा कि मुझे कुछ दे दो तो उन्होंने कहा कि, हे पुजारन तुझे एक शंख दे रहा हूं पर तुझे संतुष्टि हो उतना ही मांगना। पुजारन खुश हो गई, उसको दस-बीस रुपये की जरूरत होती थी वही मांगती थी। लेकिन जब पड़ौसन को पता लगा कि इसके बच्चे मेरे चोरी करके लेकर जाते थे, यह आज सम्पन्न कैसे हो गया? उसकी नीयत खराब हो गई और वह शंख लेकर चली गई। फिर वो पुजारन शिवजी के पास गई।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं।

**श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): मैं एक मिनट में खतम करता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

दूसरा शंख लेकर आये, शिव जी ने कहा यह तो थोथा शंख है, बोले मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। उसने कहा जो मांगेगा दूंगी, तो उसने कहा कि 50 हजार मांग, बोले लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, करोड़ दस करोड़ पर आ गई। पड़ौसन को पता लगा कि यह तो अलग शंख है, यह तो कोई अलग ही शंख है, असली शंख नहीं ले करके वह थोथा शंख लेकर चली गई इसलिए जो सरकार देने वाली थी वह तो चली गई, अब माननीय गहलोत साहब से निवेदन है, आप भी थोड़ा निवेदन करना कि कुछ बजट दे दें। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**श्री सभापति**: श्री रामप्रसाद।

**श्री रामप्रसाद** (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है उसमें खासतौर से नीरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया है, उसमें खासतौर से हमारे हास्पिटलों में या तो डाक्टर्स नहीं हैं या डाक्टर्स हैं तो अपनी खुद की प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं इसलिए जिस तरह से विद्यालयों में अध्यापक ट्यूशन करते हैं तो उस पर प्रतिबंध है तो सरकारी हास्पिटल के डाक्टर जो

(श्री रामप्रसाद)

प्राइवेट क्लिनिक खोलकर कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह हमारा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है।

शिक्षा में जो नो बैग डे घोषित किया है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार लेकिन नो बैग डे जो शनिवार को है, उसमें शिड्यूल्ड एरिया में संस्कृति, इतिहास और अनुसूचित क्षेत्र में जो पांचवीं अनुसूची है, उसकी जानकारी दी जाए।

अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हम उस इलाके से आए हैं, जहां अनुसूचित जनजाति, एस.सी. और गरीब लोगों की जो दुकानें हैं, उसमें क्या माल है, यह खासतौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी दुकानों के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं या बिल्डिंग वर्क्स करते हैं, जो भी करते हैं, जो उनकी छोटी-मोटी जमीनें हैं, उसमें जो पैदा करते हैं तो पैदा होते ही उसमें कितनी मेहनत पड़ती है, क्या नहीं पड़ता है वह काश्तकार जानता है लेकिन उसको तुरंत बाजार में ले जाकर बेचना पड़ता है और उस वक्त उसकी जो कीमत तय करते हैं, सभापति महोदय, वह कीमत हमारी चाहे मजदूरी हो, उसकी दुकान में जो सामान है उसकी कीमत कोई और तय करता है। जो मजदूर है, उसको रोजगार गारंटी के अंदर भी यदि आपके 200 रुपये मिनिमम वेजेज है, फिर भी वहां 200 रुपये नहीं दिये जाते हैं, वहां उसको 100 रुपये मिलेंगे। जब 100 रुपये मिलेंगे तो यदि वहां यह स्थिति है तो जहां बाजार में या कहीं भी काम करेगा, क्योंकि उसका ज्यादातर समय मजदूरी में और किसानी करता है, उसमें निकलता है तो वहां उसको जो मजदूरी मिलती है, वह सामने वाला तय करता है और जो अनाज पैदा करता है उसका भाव व्यापारी तय करता है, तो मैं मुख्य मंत्री महोदय को सदन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी जो दुकानें हैं, उनके अंदर मजदूरी और मेहनत करके जो अनाज पैदा करता है, उसकी कीमत कोई और करता है, तो उस इलाके में जब कीमत ही कोई और करता है तो हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। इसलिए खास तौर से मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे पीडब्ल्यू.डी. में जो वर्क चार्ज होते हैं, उन वर्क चार्ज का भी दिन का कम से कम 900 या 1000 रुपया होता है और हमारी मजदूरी कोई और तय कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं

(श्री रामप्रसाद)

कि कम से कम 700-800 रुपये मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए, तभी जाकर उनकी हालत में परिवर्तन हो सकता है, उनके परिवार का गुजारा हो सकता है, बाकी किसी सूरत में संभव नहीं है। सभापति महोदय, खासतौर से यह हमारा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमारे पांचवीं अनुसूची के अंदर जो उसमें बोला गया है कि अक्षरश: लागू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टी.ए.सी. को गुलाम बना रखा है। आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि टी.ए.सी. जनजाति सलाहकार परिषद को गुलामी से मुक्त करो। उस शिड्यूल्ड एरिये में आदिवासियों का कैसे विकास हो, उनमें आर्थिक रूप से कैसे बदलाव आए, यह आप देखें।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पांचवीं अनुसूची अक्षरशः लागू है। हमारे जो बेरोजगार हैं, वह पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अगर लगेंगे तो बेरोजगारी खतम होगी। 1969 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, रामकृपाल बनाम बिहार सरकार, समता जजमेंट, 1997, ऐसे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उन फैसलों पर हमारी टीएसी ने आज तक विचार ही नहीं किया है। आज तक शिड्यूल्ड एरिये में उस पर कुछ सोचा नहीं गया है।

**श्री सभापति**: 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री रामप्रसाद** (सागवाड़ा): सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जो टीएसी है, उसको मुक्त करें। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, इनको शिड्यूल्ड एरिये में पूरी तरह से लागू किया जाए।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जो ओलंपिक में खेलेगा और मैडल लेगा, उसके लिए 75 लाख से 3 करोड़ की राशि बढ़ा दी गई है। हमारे इलाके में लिम्बाराम है, उसको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। उसको अनेकों पदक भी मिल चुके हैं। ऐसे लिम्बाराम को आज दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वह इलाज के लिए तरस रहा है। इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, इनको सुधारा जाए।

सभापति महोदय, शिड्यूल्ड एरिया में 1913 के अंदर मानगढ़ कांड हुआ। वहां पर निहत्थे आदिवासियों पर गोलियां चलाई गईं। 1500 से ऊपर आदिवासियों को वहां मारा गया। उनका उस वक्त गुनाह इतना ही था कि

(श्री रामप्रसाद)

हमारा विकास कैसे हो। हमारा जो शोषण हो रहा है, उसको रोका जाए। उसके लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। आज तक पुस्तकों में, इतिहास में यह कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। हम उस संबंध में यह कहना चाहते हैं कि जो मानगढ़ कांड हुआ, वह क्यों हुआ? आदिवासियों की मांग क्या थी? खास तौर से उनकी मांग भील प्रदेश की थी। यह पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची को लागू करने की मांग थी। उस समय हमारे जो गुरू गोविंद थे, वे संत थे।

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करें।

**श्री रामप्रसाद** (सागवाड़ा): उन्होंने एक ही बात कही थी। वह ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। अनपढ़ थे। पांचवीं अनुसूची आदि के बारे में भी नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि ऊंच की नीच होगी और नीच की ऊंच होगी। यह उनकी थीम थी। हम यह समझते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची पर विशेष रूप से ध्यान देकर के उस इलाके के लिए काम करेंगे। यही कहकर के अपनी बात को खतम करता हूं। जय जोहार।

**श्री सभापति**: श्री पुखराज।

**श्री पुखराज** (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने बजट 2020-21 की चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदय ने ट्रोमा सेंटर और नगरपालिका बनाने की घोषणा की, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो नगरपालिका बनाने की घोषणा की है, इसकी तीसरी बार घोषणा हुई है। मैं चाहूंगा कि इस बार नगरपालिका के संबंध में जो भी कार्यवाही करनी है, उस पर त्वरित कार्यवाही कर इसे धरातल पर उतारें। तत्काल इसको पूरा करें।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 7 संकल्पों के साथ में बजट रखा है। उसमें सबसे पहला संकल्प नीरोगी राजस्थान का है। इसके संबंध में ज्यादा लंबी बात नहीं कहकर के मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे भोपालगढ़ में सीएचसी हास्पिटल है। उसके संबंध में मैंने 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में प्रश्न लगाकर पूछा था कि वह 30 बैड की है या 100 बैड की

(श्री पुखराज)

संचालित है? उसका मंत्री जी ने उस वक्त जो जवाब दिया, वह यह था कि भोपालगढ़ में 100 बैड की सीएचसी संचालित हैं, जबकि अभी भी वहां 30 बैड की ही सीएचसी संचालित हो रही है। जो भी संसाधन और स्टाफ हैं, वह भी 30 बैड की कैपेसिटी के हिसाब से ही लगा रखे हैं। आज भी उस सीएचसी में 7 डाक्टर हैं, 4 नर्सिंग स्टाफ हैं। जो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोला हुआ है, उसकी बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है। वहां 6 डाक्टर्स की पोस्टें हैं, वह 6 की 6 ही खाली हैं।

सभापति महोदय, एक तरफ तो हम नीरोगी राजस्थान की कल्पना करते हैं। यह सरकार का विजन है कि नीरोगी राजस्थान बनाएं। दूसरी तरफ जो सीएचसी, पीएचसी और सब सैंटर्स हैं, उसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में और भोपालगढ़ हास्पिटल में जो भी पोस्टें डाक्टर्स और नर्सिंग की खाली हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरें ताकि सरकार की जो नीरोगी राजस्थान की कल्पना है, वह धरातल पर आ सके।

सभापति महोदय, दूसरा संकल्प है, सम्पन्न किसान। सम्पन्न किसान की हम जो बात करते हैं, जैसा मेरे से पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने भी कहा कि जो किसान प्रधान स्टेट हैं, देश हैं, वहां जब तक किसान प्रधान मानते हुए विकास की परिकल्पना नहीं करेंगे, तब तक किसानों की सम्पन्नता की बात करना बेकार है। किसानों को सम्पन्न करने के लिए किसानों की फसलों को उचित दाम मिले। किसानों की सम्पूर्ण फसल की खरीददारी होनी चाहिए। तभी जाकर के किसान सम्पन्न होगा।

सभापति महोदय, किसानों के लिए लाइट की बात की गई है। इसमें 1 लाख 21 हजार कृषि कनेक्शन देने की बात कही गई है। जोधपुर डिस्काम के जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के 10 जिले आते हैं। उन जिलों में जो अनुसूचित जनजाति के परिवार रहते हैं, उनको किसी भी तरह की लाइट की सुविधा या छूट नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र की तर्ज पर जोधपुर डिस्काम के दोनों संभागों में अनुसूचित जनजाति के जो किसान हैं, उनको कृषि कनेक्शन दिए जाएं ताकि वह किसान भी सम्पन्न हो सकें। वह भी विकास की गति में आगे बढ़ सकें।

(श्री पुखराज)

दूसरा जो लाइट के लिए है, सरकार ने सबसे बड़ी किसानों के लिए बात की, दो ब्लाक में सप्लाई देने की बात है, उसके लिए नये जीएसएस बनाने की बात कही है लेकिन दो ब्लाक में सप्लाई देने के लिए नये जीएसएस के साथ में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग जो जीएसएस हैं उनमे एडिशनल ट्रांसफार्मर रखना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से और मंत्रीजी से कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो विशेषकर कृषि बैल्ट का है, वहां तुरंत स्कीम बनाकर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की भी व्यवस्था करें ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता की बिजली की सप्लाई मिल सके और दो ब्लाक में बिजली दिन में देने का सरकार का जो सपना है वह भी पूरा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, अगला जो संकल्प है, महिला, बाल, वृद्ध कल्याण, इसमें विशेषकर जितने भी समाज कल्याण छात्रावास हैं, चाहे एससी, एसटी के हों चाहे अल्पसंख्यकों के हों, उनमें जो छात्र रह रहे हैं, उनका मैस भत्ता आपने इसमें 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया है, मैं समझता हूं कि अभी भी यह काफी कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि छात्रावासों में जो छात्र रह रहे हैं, आप कभी उन हास्टलों में जाकर निरीक्षण करें, देखें तो आपको व्यवस्था का पता चल जाएगा कि इन 2000 और 2500 रुपये में क्या मिलता है और क्या होता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस मैस भत्ते को भी बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अगला जो संकल्प है, शिक्षा का परिधान। शिक्षा परिधान के अंदर बजट में बहुत सारी बातें कही गयी हैं, नये कालेज खोलने की बात कही गयी है, नये संकाय बढ़ाने की बात कही गयी लेकिन मैं मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। हमारे यहां एकमात्र ग्रामीण सरकारी बीएड कालेज है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री पुखराज** (भोपालगढ़): एकमात्र सरकारी बीएड कालेज है, जो बंद होने के कगार पर है। पिछले दो साल से उसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि अभी वह बंद हो रहा है। बंद सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसमें सरकार ने किसी तरह के संसाधन और बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, विशेषकर शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना

(श्री पुखराज)

चाहूंगा कि ये जो घोषणाएं अपन नये कालेजों की कर रहे हैं, अगर संसाधन और स्टाफ अवेलेबल नहीं हैं तो ये घोषणाएं करनी बेकार हैं, उन विद्यार्थियों के साथ में एक तरह से धोखा है जो पिछले दो साल से उस कालेज में पढ़ रहे हैं। दूसरा सरकारी कालेज मेरे विधान सभा क्षेत्र में बावड़ी में है। वह आज भी एक प्राइमरी स्कूल के एक रूम में चल रहा है। न वहां स्टाफ है, न भवन है, न किसी तरह का वहां कोई संसाधन है। हमने बार-बार उसकी जमीन के लिए, मैंने अधिकारियों, जिलाधीश और जेडीए कार्यालय में सम्पर्क किया लेकिन अभी तक वह पत्रावली पिछले डेढ़ साल से जेडीए में पड़ी है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री पुखराज** (भोपालगढ़): तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की क्या इच्छाशक्ति है? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अगर काम करना चाहती है तो खाली घोषणाओं से नहीं होगा, उसके साथ में काम भी करें, जमीन भी अवेलेबल कराएं, संसाधन भी अवेलेबल कराएं, स्टाफ भी अवेलेबल कराएं, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्रीमती जाहिदा खान।

**श्री पुखराज** (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) धन्यवाद।

**श्रीमती जाहिदा खान** (कामां): माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2020-21 के समर्थन में आपने जो मुझे अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने आमजन के कल्याण के संकल्प के साथ गठित सरकार का शानदार दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और सरकार की मंशा राज्य के आमजन को राहत देते हुए राज्य के सम्पूर्ण विकास की है और इसी दिशा में किसी भी प्रकार का नया कर का बोझ राज्य की जनता पर सरकार ने नहीं डाला है तथा बजट में बिना कोई कर लगाये राज्य के सीमित वित्तीय साधनों के साथ सम्पूर्ण विकास की कल्पना के साथ बजट सदन में रखा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का शुक्रिया अदा करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सात

(श्रीमती जाहिदा खान)

संकल्पों को बजट में शामिल किया है, जिसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है और सभी वर्गों को राहत देने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने नीरोगी राजस्थान योजना लागू की है, यह योजना स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाकर स्वस्थ राजस्थान की अवधारणा को पूरा करेगी। इसके साथ ही मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कैंसर एवं लीवर जैसे गम्भीर रोगों की दवाओं को शामिल करके इसकी संख्या 709 कर दी गयी हैं जो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है।

माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जब तक भारत का किसान सम्पन्न नहीं होगा तब तक देश के खुशहाल होने की कल्पना नहीं कर सकते। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि किसानों को पूर्ण संरक्षण देते हुए पूर्व में अपने किये गये वायदे के अनुसार सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी इसी दिशा में लिया गया एक बहुत बड़ा कदम था। वर्तमान बजट में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गयी है। इसके साथ ही राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य बना है, जिसने कृषि क्षेत्र में सोलर पम्प का इस्तेमाल किया है। ''खेती में जान तो सशक्त किसान'' की सोच रखते हुए कृषि लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आय में वृद्धि हेतु ड्रिप एण्ड स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, कुओं व नलकूपों के जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में 12,500 तालाबों का निर्माण किया जाएगा, जिससे बरसात के पानी को संरक्षण करके जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। सिंचाई के क्षेत्र में भी पूरी कोशिश की गयी है जिससे किसान को जरूरत का पूरा पानी मिल पाये और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के पंचायती राज को मजबूती देने के लिए पंचायत समिति एवं पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। इसमें 57 नयी पंचायत समितियां एवं 1456 नयी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। यह पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है जिसकी मांग लम्बे समय से चली आ रही थी। नयी बनायी गई ग्राम पंचायतों

(श्रीमती जाहिदा खान)

एवं पंचायत समितियों के लिए सरकारी भवन विभिन्न योजनाओं से बनाये जाएंगे।

जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तर पर खोले हैं जिससे गरीब के बच्चे को कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे बहुत ही कामयाब हुए हैं इसी को देखते हुए 134 ब्लाकों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले गये हैं, शेष 167 ब्लाक पर जल्द ही ऐसे विद्यालय खोल दिये जाएंगे। यह बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे ही राजस्थान के सारे ही ब्लाक्स पर हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित होंगे। राइट टू एजुकेशन को सही तरीके से प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

सबसे बड़ी बात जो इस बजट में उन्होंने की, बच्चों के लिए नो बैग डे रखा गया है क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने इतना ज्यादा किताबों के वज़न से दाब दिया है कि उनकी क्षमताएं, उनकी प्रतिभाएं उसी में दब कर रह गयी हैं बस्ते के बोझ में। बच्चों के लिए इन्होंने जो घोषणा की है उससे उनका विकास होगा और उनका इन्टरक्शन भी बढ़ेगा, जब माता-पिता आएंगे कि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के लिए उससे इसमें बहुत फायदा होगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर से सम्बन्धित सही जानकारी व शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षक कैडर बनाया जाएगा। कम्प्यूटर की योग्यता रखने वाले युवकों को लगाया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिल सकेगा। विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी ई-कान्सेप्ट बैंक्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें विशिष्ट विषयों के विशेषज्ञों के लैक्चर्स को रिकार्ड करके रखा जाएगा, जिससे कभी भी विद्यार्थी उन्हें फ्यूचर में यूज कर सकें और जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाया जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चों को इससे पढ़ाई करने में बहुत आसानी रहेगी।

सभापति जी, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं पर कोई काम नहीं किया, इसलिए पिछले पांच वर्षों में उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। वर्तमान बजट में जयपुर में सौ बैड का माइनोरिटी बायज हास्टल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दूरदराज से बच्चे यहां आकर के कोचिंग ले सकें और पढ़ सकें, क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस चीज का एहसास किया है कि कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश

(श्रीमती जाहिदा खान)

तब तक नहीं बढ़ सकता, जब तक वहां की अवाम शिक्षित नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अपने पिछले बजट में तकरीबन पचास कालेज खोले थे जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

मेरे और एक दूसरे इलाके में उन्होंने बायज एण्ड गर्ल्स माइनोरिटी रेजीडेंशल हास्टल दिया है। यह भी बहुत स्वागत योग्य है। वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए पांच करोड़ की आर्थिक मदद दी गयी है, जिससे पूरे राजस्थान की वक्फ सम्पत्तियों का रख रखाव हो सकेगा। मुख्य मंत्री जी ने सड़क सुरक्षा पुरस्कार योजना भी शुरू की है, जिससे कि जिन जिलों में कम एक्सीडेंट होंगे, उनमें पहले जिले को पच्चीस लाख, दूसरे को पंद्रह लाख और तीसरे नम्बर पर आने पर दस लाख रुपये दिये जाएंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि शायद एक्सीडेंट्स कम होंगे।

सभापति जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे इलाके कामां में माइनोरिटी रेजीडेंशल बायज एण्ड गर्ल्स स्कूल दिये हैं। पहाड़ी वाली कृषि उपज मण्डी को इंडिपेंडेंट बढ़ाया है और इर्रिगेशन में डिस्ट्रीब्यूटरीज को जो पक्का करने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि उसे जितना मिलता है, उसे यह उम्मीद होती है कि उसे और ज्यादा मिले। मैं आपके मार्फत चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी जो कुछ और मांगें हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दें। गुड़गांवा कैनाल का सीकरी बांध तक विस्तार, जिससे कि सीकरी के मेवात तक हमारा जो पानी है, वह पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरीज से पहुंच सके। केपी ड्रेन की अगर खुदायी हो जाए तो पूरे ही कामां विधान सभा क्षेत्र को पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसान को बहुत आसानी रहेगी।

हमारे यहां रोजगार की कमी है। हमारे यहां पढ़ाई-लिखाई भी कम है, लेकिन हमारा इलाका चूंकि कृषि प्रधान है और वहां कृषक ज्यादा हैं तो वे लोग गाय-भैंस ज्यादा रखते हैं। अगर सरस चिलिंग प्लांट मेरे इलाके में खोल दिया जाए तो वहां के लोगों की आय भी बढ़ेगी और उनके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। मेवात में टैक्निकल एजुकेशन की बहुत कमी है। सीएम साहब ने दो कालेज तो मेरे इलाके में खोल दिये, लेकिन मैं कहना चाहूंगी नर्सिंग और फार्मेसी कालेज या बीएड कालेज हमारे यहां खुल जाएं तो बच्चों को पढ़ने के लिए सौ किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वे लोग वहीं पर

(श्रीमती जाहिदा खान)

पढ़ सकेंगे। साथ ही, जो नर्सिंग स्टाफ के लोग ग्रामीण इलाके में नहीं रहते और अपना ट्रांसफर करा जाते हैं, वे बच्चे वहां रहकर पढ़ने लगेंगे।

राज्य विद्यालय में उर्दू पैरा टीचर की नियुक्ति हो। मदरसा पैरा टीचर्स का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी की नजर से यह कैसे रह गया, नहीं तो उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मदरसा पैरा टीचर्स का मानदेय बढ़ाकर इन्हें परमानेंट किया जाए। इन्हें बहुत कम मानदेय मिल रहा है, जिसमें इनका जीवनयापन नहीं हो सकता। पहाड़ी उप खण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। 33 केवीए के जीएसएस के निर्माण कराये जाएं। नांगल, नौगांवा, आड़दुका, पथराली, खेड़ानौबाद, छपरा, क्षतिग्रस्त लाइनों को बदला जाए।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मुझे बड़ा दु:ख है कि हमारे इलाके में जो सीएम साहब ने 2011 में दो कालेज दिये थे, बीजेपी सरकार ने राज में आते ही सबसे पहले उन्हें बंद करने का काम किया। किसी भी सरकार को कम से कम पढ़ाई का हक नहीं छीनना चाहिए किसी इलाके से। न ही मेरे इलाके में कोई डवलपमेंट हुआ। मेरे बारह जीएसएस तक उन्होंने कैंसिल किये थे। मैं आपके मार्फत यही चाहूंगी कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी मेरी इन मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वीकृत कराएं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

**श्री सभापति**: श्री सुरेश टाक।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने राज्य का 2020-21 का जो बजट पेश किया है, वह समग्र है, संतुलित है और आकर्षक होने के साथ-साथ एक महत्त्वाकांक्षी बजट भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने इस बजट के क्रियान्वयन की चुनौती भी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इस चुनौती को वे आसानी से पार करेंगे। इस बजट को उन्होंने सात संकल्पों के साथ प्रस्तुत किया है जो कि साफ दर्शाता है कि बहुत बड़ी इच्छाशक्ति और जनकल्याण की भावना को मन में रखते हुए उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है।

इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सात संकल्पों के साथ यह बजट करीब-करीब सभी क्षेत्रों को कवर करता है, जिनके पूरे होने से राज्य की

(श्री सुरेश टाक)

उन्नति को पंख लगने हैं। यह बजट एक संतुलित बजट है। इसमें बाल विकास, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सभी पर कवरेज के आधार पर संतुलन को प्राथमिकता दी गयी है। इस बजट में कई नवाचार किये गये हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेंगे। इस बजट पर बात करने से पहले, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे बहुत निर्दलीय साथी यहां हैं हम लोग निर्दलीय जीतकर यहां आये हैं और हमसे जनता को अपेक्षा भी बहुत ज्यादा हैं। जनता दोनों दलों से जीतकर आने वाले लोगों से ज्यादा अपेक्षा निर्दलीयों से करती है, क्योंकि वह दलों को छोड़कर हमें वोट करती है और हमें वोट करने के बाद उसके मन में रहता है कि अच्छी तरह से हमारे काम होंगे, उनकी स्पीड बढ़ेगी और ज्यादा अच्छा विकास होगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो 13 निर्दलीय यहां जीतकर आये हैं, वे आपकी सरकार को आज समर्थन दे रहे हैं और आपके विश्वास पर सरकार के साथ खड़े हैं। मैं यह चाहूंगा कि बजट में कम से कम हमारे विधान सभा क्षेत्र का नाम आये और हमारी जनता को यह एहसास हो कि उन्होंने जो कदम उठाया है, वह एक सार्थक कदम है। किशनगढ़ या अन्य विधान सभा क्षेत्र, जहां-जहां से भी लोग जीतकर आये हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात मिले।

मैं आपको बता दूं, 20 तारीख को जब बजट पेश किया गया था, 21 तारीख को जो समाचार पत्र आये थे, उनमें बड़ी-बड़ी खबरें छपीं- बजट में किशनगढ़ का कहीं नाम नहीं, शहरवासियों को किया निराश। मैं चाहूंगा कि जब संशोधित बजट आये तो कम से कम यह निराशा जो आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों में है, यह नहीं रहे और उन लोगों को जवाब मिले, जो ये बातें करते हैं कि सरकार को समर्थन देने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, उन्हें इसका जवाब मिले। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमारी इस बात पर गौर करेंगे और मुझे, मेरे साथी निर्दलीय विधायकों और हमारी जनता को कहीं न कहीं कोई बड़ी सौगात देकर कृतार्थ करेंगे।

मैं सरकार के बजट पर सीधा-सीधा आता हूं। साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी जोड़ना चाहूंगा। नीरोगी राजस्थान अपने आप में एक बड़ा संकल्प है। पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नि:शुल्क दवा

(श्री सुरेश टाक)

योजना और अब नि:शुल्क जांच योजना जो पेश की है, अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और उस कदम की सराहना पूरे भारत में है, सभी जगह इसकी सराहना है। लगातार इस बात पर फोकस भी है कि वे इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे हिन्दू धर्म में सीधी-सीधी बात है कि हम किसी चीज की सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं और यह बात कहते हैं कि हमें यह काम करना है। नीरोगी राजस्थान का यह संकल्प भी उसी दिशा में है।

आज जो सात संकल्पों के साथ यह बजट पेश किया गया है, कहीं न कहीं इच्छाशक्ति को मजबूत करता है। मुख्य मंत्री की भावना राजस्थान के सभी लोगों को फायदा पहुंचाने की है। जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसे भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, शायद यही वजह है कि उन्होंने ये सात संकल्प लिए हैं। उसमें नीरोगी राजस्थान के तहत मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा- मानव संसाधन और संसाधन दो अलग-अलग चीजें हैं, जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। नीरोगी राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत है मानव संसाधन की। जहां डाक्टर्स की कमी है, वहां उस कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाए। जहां डाक्टर्स नहीं हैं, वहां नीरोगी कैसे रहा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टरों की भर्ती पर जल्दी कार्यवाही हो और सभी सीएचसी-पीएचसी को जहां जितने स्टाफ की आवश्यकता है, वह उन्हें मिले।

बहुत सारे सक्षम लोग हैं, सक्षम विधान सभा क्षेत्र हैं, जहां बहुत सारे भामाशाह रहते हैं, मानव संसाधन हम नहीं दे सकते, लेकिन संसाधनों की व्यवस्था हम कर सकते हैं। यह मैं बता रहा हूं। मैं आपको मेरे किशनगढ़ क्षेत्र का एक उदाहरण दे रहा हूं। एक छोटा-सा कार्यक्रम था, मानव संसाधन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने एक घंटे में साढ़े तीन करोड़ रुपये लोगों से अर्जित किये और मेरे अस्पताल को सुसज्जित करने का एक सार्थक प्रयास किया जिसमें छोटी-मोटी मशीनें भी हैं, बहुत सारे वार्ड बनाने का काम भी है, अस्पताल के नये बैड लगाने का भी है, गद्दे भी हैं, पर्दे भी हैं, बैडशीट भी बदलने का है और मेरे वहां अस्पताल में रोज नई बैडशीट चैंज होगी। यह भी हमने एक संकल्प लिया है कि सात दिन सात कलर की बैडशीट हो। हमें सरकार से यह अपेक्षा है कि हमारे अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए और जो अन्य स्टाफ है उसकी भी पूर्ति की जाए।

'शुद्ध के लिए युद्ध' अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है जो

(श्री सुरेश टाक)

मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और राजस्थान में मिलावटखोरी को बन्द करने के लिए एक बड़ा कदम होगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एक बात का और धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना में आपने अजमेर को लिया, इसके लिए पूरे अजमेर जिले की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। राजस्थान में दो महाविद्यालय लिए और उनमें से एक अजमेर को मिला, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी वहां इनोग्रेशंस थे और उनमें उन्होंने दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक एक्स-रे सी.आर. सिस्टम मशीन की घोषणा की थी। मैं यह भी चाहूंगा कि खण्डाच, जहां पर आर.के. मार्बल पार्टी परिवार का गांव है और वे वहां अस्पताल बनाकर देने को तैयार हैं तथा खाली घोषणा सरकार को करनी है, स्टाफ की नियुक्ति करनी है। बाकी सारे संसाधन वे उपलब्ध कराएंगे, बिल्डिंग वे उपलब्ध कराएंगे तो ऐसी जगह पर जरूर होना चाहिए जहां पर संसाधन देने के लिए भामाशाह तैयार खड़े हैं। जो एक्स-रे सीआर सिस्टम हमारे वाई.एन. अस्पताल में नहीं है, उसकी जो घोषणा की थी, उसके लिए मैं चाहूंगा कि इस संशोधित बजट में यह घोषणा हो जाए ताकि मेरे अस्पताल को यह सुविधा मिले।

साथ ही, शिक्षा में जो मुख्य मंत्री महोदय ने काम किया है, जो घोषणा की है मैं इसको एक नई व्याख्या देना चाहूंगा। यह ट्रिपल एस (SSS) विजन आपने दिखाया है जिसमें तीन एस के साथ पहला स्कूल, दूसरा स्किल और तीसरा स्टार्ट-अप, इन तीनों पर आपने फोकस किया है। स्कूलों में आपने 200 स्कूल में अतिरिक्त संकाय और 300 स्कूलों में अतिरिक्त विषय खोलने का जो संकल्प किया है, यह अपने आपमें एक सराहनीय बात है और यह सभी को समानता से मिले। यह चर्चा के बाद सबको वितरित किये जाएं जिससे सभी स्कूलों में इस बात का फायदा हो।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां बालिका के प्राथमिक स्कूल हैं, उनको उच्च प्राथमिक किया जाए, जहां उच्च प्राथमिक हैं, उनको माध्यमिक किया जाए और जहां माध्यमिक

(श्री सुरेश टाक)

बालिका स्कूल हैं, उनको उच्च माध्यमिक किया जाए। गांवों में एक धारणा है और बच्चियों को पढ़ाने के लिए मां-बाप दूर नहीं भेजते जिसकी वजह से हमारी बेटियां अशिक्षित रह जाती हैं, कम पढ़ी-लिखी रह जाती हैं जबकि बच्चियों को पढ़ने की बहुत लालसा होती है, पर स्कूल उपलब्ध नहीं होने से वे गांव छोड़कर दूसरे गांव में नहीं जा सकतीं। मैं यह चाहूंगा कि जब स्कूल क्रमोन्नत हों तो बालिका स्कूलों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले और हमारी साक्षरता बढ़े।

स्किल में आपने आरएसएलडीसी और स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से जो 40 सैक्टर्स में 10 हजार स्टूडेंट्स की स्किल को निखारने का जो प्रोग्राम बनाया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि यह एक बड़ा नवाचार है। स्टार्ट-अप में स्टार्ट-अप प्लेटफार्म के लिए i-Start एंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ाने के लिए 75 संस्थाओं के साथ टाई-अप किया है, यह भी एक बड़ा कदम है। इससे हमारे जो भी एमएनआईटी, जयपुर, जोधपुर, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने आइडियाज और अपने बिजनस मॉडल को बेहतर तरीके से पेश करने का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं हमारे आईटी सैक्टर को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

'नो बैग डे' अपने आपमें एक बहुत बड़ा नवाचार है। सेटरडे के दिन बच्चों को स्कूल में बिना बैग के जाना है और उनको बहुत सारे नवाचार, जो आज तक वे नहीं कर पाये, चाहे वे खेलकूद में हैं, चाहे वे डिबेट में हैं, चाहे और किसी काम में है, अपने माता-पिता के साथ जाने में उनको बहुत अच्छा महसूस होगा और माता-पिता को भी अपने बच्चों का स्किल देखने का मौका मिलेगा कि हमारा बच्चा किस तरह जा रहा है। उसमें क्या कमी है, हम उसको क्या नया दे सकते हैं। स्कूल का शिक्षक, अभिभावक और बच्चा साथ बैठेंगे तो बहुत सारी नई चीजें निकलेंगी और शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा नया आयाम स्थापित होगा। यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको क्रमोन्नत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। मैंने दे रखा है, लिखित में दिया हुआ है, मेरा समय कम है इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा लेकिन जितना भी लिखकर दिया है और डिमाण्ड में जो आएगा उसको आप लेने का प्रयास करें।

(श्री सुरेश टाक)

इसके साथ ही, ऊर्जा मंत्री जी यहां विराज रहे हैं, मैं फिर एक बार आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैंने अभी पर्ची के माध्यम से एक क्वेश्चन लगाया था और एक निवेदन किया था, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। यह बहुत जरूरी बात है कि राज्य में जनरल और ओबीसी श्रेणी के जो किसान हैं, उनको कृषि का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। 31.1.2012 के बाद अब तक, यानी आठ सालों में उन लोगों को कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और अगर आप आठ साल का नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम पांच साल, 2018 तक के जो आवेदन हैं उनको तो कम से कम रैगुलराइज करें ताकि जनरल और ओबीसी श्रेणी के जो किसान हैं, उनको भी बिजली मिले तथा वे भी अपने खेतों में सिंचाई करके अपनी फसल ले सकें। मैं यह मानता हूं कि जहां कुए खुद गये हैं वहां सिंचाई हो रही है और सिंचाई हो रही है तो कहीं न कहीं बिजली चोरी हो रही है। अगर आप इस ओर कदम बढाएंगे तो निश्चित रूप से बिजली की चोरी भी कम होगी और उनको सुविधाजनक बिजली प्राप्त होगी। इसके अलावा, सरकार के प्रति भी यह सकारात्मक मैसेज जाएगा कि आपने सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा फोकस करें और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात से अवगत कराएं कि इस बार कम से कम 2018 तक के जो आवेदन किये हुए किसान हैं उनको बिजली मिले।

जो दिन में बिजली देने का आपने इस बजट में प्रावधान किया है, इसकी मैं बहुत-बहुत सराहना करता हूं। राज्य के सारे किसान इस बात से खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अजमेर इसके प्रथम चरण में आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारे विधान सभा क्षेत्र के जो किसान हैं वे भी दिन में बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इसकी जल्दी से जल्दी मानिटरिंग हो और निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही भी होगी, मैं ऐसा मानता हूं।

पीएचईडी को बहुत बड़ा बजट मिला है। पीएचईडी मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी यहीं विराज रहे हैं। जितनी भी योजनाएं जो विभाग द्वारा यहां आयी हुई हैं, कम से कम उनका क्रियान्वयन हो जाए। जितनी भी डिमाण्ड्स आयी हुई हैं उनका क्रियान्वयन हो जाए ताकि लोगों को पानी मिले। शुद्ध जल देने की आपकी योजना है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): बस सर, दो मिनट में कर रहा हूं। सड़क के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सड़क पर 6 हजार 808 करोड़ का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है। अभी पिछली सरकार के वक्त में जो सड़कें स्वीकृत की गई थीं वे नाट स्टार्टेड में हैं तो सबसे पहले उन नाट स्टार्टेड सड़कों को लेना जरूरी है क्योंकि वे ज्यादा टूटी हुई सड़कें हैं और इसीलिए उनको लिया गया था तो पहली प्राथमिकता उन नाट स्टार्टेड सड़कों को स्टार्ट करके करनी चाहिए कि जो नाट स्टार्टेड सड़कें हैं उनको बनाया जाए ताकि लोगों को यह महसूस हो कि हमारी जो सड़कें स्वीकृत हो गई थीं उनको सरकार बनाने जा रही है।

घायलों के इलाज के लिए जो आपने निजी अस्पतालों को बाध्य किया है, यह एक बहुत बड़ा कदम है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): बिल्कुल सर, कर रहा हूं। किशनगढ़ में पुराने रेलवे स्टेशन पर आर.यू.बी. के लिए मेरी बहुत लगातार मांग रही है और पिछले 13 महीनों से मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं। यह बहुत बड़ी समस्या है किशनगढ़ की जनता के लिए। मेरा शहर दो भागों में बंट गया है क्योंकि पुराना रेलवे स्टेशन टूटने के बाद नया रेलवे स्टेशन बन गया और पुराने रेलवे स्टेशन पर जो फुट ओवरब्रिज था...

**श्री सभापति**: कनक्लूड करें माननीय सदस्य।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): एक मिनट में खतम कर रहा हूं। जो फुट ओवरब्रिज था वह हटा दिया गया। मेरी 35 परसेंट आबादी स्टेशन के उस पार रह गई तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बार संशोधित बजट में आर.यू.बी. की घोषणा करें। सारी कार्यवाही हो रखी है, केवल तीन करोड़ रुपये रेलवे को ट्रांसफर करने हैं और मेरा आर.यू.बी. बन जाएगा जिससे मेरी किशनगढ़ की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है ट्रैफिक और आवागमन से। बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, हर स्तर पर इसके निदान की आवश्यकता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य। बाकी की कोई बात है तो आप मंत्री महोदय से मिल लें।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): सर, दस मिनट तो आप देंगे, मेरे दस मिनट नहीं हुए हैं।

**श्री सभापति**: दस मिनट कहां, आप तो ज्यादा बोल लिए। ऐसे नहीं होता।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): नौजवानों की जिस ताकत पर हम गर्व करते हैं वह आज नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा है। इस युवा शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हमें बहुत सारी चीजें विकसित करनी पड़ेंगी। आपने 53 हजार पदों पर जो भर्ती करने का किया है, यह निश्चित रूप से उस ओर एक बड़ा कदम है। यह भर्ती अनिवार्य रूप से हो, इस तरह की मोनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। उद्योग के लिए आपने स्टाम्प ड्यूटी बन्द की है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): एमएसएमई की जो बीमार यूनिट्स हैं, उनको इससे बड़ी राहत मिलेगी। आपसे मेरा एक निवेदन है कि किशनगढ़ में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, टैक्सटाइल पार्क है।

**श्री सभापति**: श्री सुखराम विश्नोई। विराजिये अब।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): एक बात और कह रहा हूं सर। टैक्सटाइल पार्क के लिए मैं विशेष तौर से निवेदन करूंगा। श्रम विभाग के मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किशनगढ़ में श्रम निरीक्षक कार्यालय है उसे श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में क्रमोन्नत कर दें। जिले से सबसे ज्यादा मजदूर किशनगढ़ में हैं। हमें इसके लिए अजमेर जाना पड़ता है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप यह घोषणा जरूर करवाएंगे कि किशनगढ़ में श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय क्रमोन्नत हो जाए ताकि हमारे जो मजदूर हैं उनको वहां तक नहीं जाना पड़े।

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): सर, पूरी बात कर लूं, एक सैकण्ड में कर लेता हूं।

**श्री सभापति**: अब बाकी कोई बात हो तो मंत्री महोदय से उनके कक्ष में जाकर आप मिल लें। ऐसे कौनसे हाथों-हाथ ही वे आर्डर निकाल कर दे रहे हैं।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): मैं मिल लूंगा। एक लास्ट बात है। मैं टैक्सटाइल के लिए बिजली दरों की बात कहना चाहूंगा कि टैक्सटाइल में हमारे राजस्थान की विद्युत दरें सबसे अधिक हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, को-आपरेट करें, आप मुझे सहयोग करें।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): उन बिजली दरों को कम करने के लिए प्रयास करें। सर, दस मिनट में बात ही नहीं कह सकते पूरी।

**श्री सभापति**: सभी आपकी तरह से खड़े रहेंगे तो पूरा होगा ही नहीं। प्लीज, सहयोग करें। श्री सुखराम विश्नोई।

**श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): धन्यवाद, सर।

**श्री सभापति**: श्री सुखराम विश्नोई।

**(18.00 बजे)**

# शासकीय वक्तव्य

## लूणकरणसर में हिरणों के शिकार को लेकर हुए आंदोलन व रेंजर के निलम्बन आदेश में बार-बार परिवर्तन

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, दिनांक 22-23 जनवरी, 2020 की रात्रि को रेंज लूणकरणसर में ग्राम शोदोलाई में घटित हिरणों के शिकार प्रकरण में वन विभाग द्वारा प्रकरण संख्या 49/24 दिनांक 23.01.2020 को दर्ज किया जाकर वन विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से दो मुलाज़िमों श्री रोशन खां पुत्र श्री यासीन खां एवं श्री लालू खां पुत्र श्री मंजूर खां निवासी शोदोलाई को दिनांक 24.01.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। तत्पश्चात्, तीन अभियुक्तों को और गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अभियुक्तों की निशानदेही से शोदोलाई ग्राम में पुराने कुएं से वहां 6 हिरणों के शव बरामद किये, जिनका पोस्टमार्टम करवाया गया है एवं जब्त सामग्री एवं सबूतों के नमूने एफएसएल को जांच हेतु भिजवाये गये हैं।

इसी बीच जीव रक्षा संस्थान, बीकानेर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जांच में विलम्ब किये जाने के कारण वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों की निलम्बन की मांग पर धरना शुरू किया गया। दिनांक 25.01.2020 को प्रकरण में श्री मनरूप सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, लूणकरणसर से जांच हटाकर श्री इकबाल सिंह, सहायक वन संरक्षक को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया तथा मनरूप सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी को दिनांक 02.02.2020 को निलम्बित कर दिया गया। वन विभाग के जांच अधिकारियों की लापरवाही की

(श्री सुखराम विश्नोई)

जांच किये जाने हेतु श्री जय प्रकाश, आईएफएस, वन संरक्षक, बीकानेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच में किसी कर्मचारी-अधिकारी को दोषी नहीं माना गया। जिस पर पुन: संभागीय वन मुख्य संरक्षक, बीकानेर ने मनरूप सिंह को बहाल कर दिया। उसके पश्चात् पुन: 18.02.2020 को मौके की स्थिति को देखने के बाद में वन प्रेमियों की रिपोर्ट के आधार पर मनरूप सिंह की जांच को विथड्रा कर लिया गया। बाकी सीसीएफ, बीकानेर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों नहीं आपने हालात को काबू किया। जो जांच की जय प्रकाश ने, मोनिटरिंग सही नहीं की, उन तमाम बातों को लेकर उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

**श्री सभापति**: विराजिए, विराजिए एक मिनट।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): मेरा ही था। माननीय सभापति जी, 22-23 जनवरी की दरमियानी रात को लूणकरणसर में जो हिरण शिकार की घटना हुई। उसके संबंध में मेरा स्थगन था। उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। इसके अगले ही दिन जीव प्रेमियों का, आम जनता का लूणकरणसर में धरना शुरू हुआ। 26 जनवरी को सीसीएफ और डीएफओ धरनास्थल पर गये और वहां वार्ताकारों को, जीव प्रेमियों को यह आश्वस्त करके आये कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। वार्ताकारों, जीवप्रेमियों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि इतने बड़े स्केल पर शिकार हुआ तो निश्चित तौर पर वन अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह सम्भव नहीं है। यह लगातार कई अर्से से जारी है।

28 जनवरी को, मैं स्वयं और माननीय विधायक लूणकरणसर आदरणीय सुमित जी, हमारे पूर्व विधायक खाजूवाला और हमारे जिला अध्यक्ष ताराचन्द जी, हम सब लोग धरनास्थल पर गये। उस दिन माननीय सीसीएफ साहब और डीएफओ वहां पधारे और इस बात पर पुन: चर्चा हुई कि मिलीभगत करने वाले अधिकारी को निलम्बित किया जाए तो उन्होंने अक्षमता जाहिर करते हुए कहा कि हम इसमें सक्षम नहीं हैं। हम इसको निलम्बित नहीं कर सकते। उसके बाद जब वार्ता विफल हो गई। एक तारीख को, वे लोग जो आठ दिनों से धरने पर बैठे थे। वे जीव प्रेमी जिनकी भावना उद्वेलित थी, सरकार उस पर सुनवाई नहीं करती, सीसीएफ उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर

(श्री बिहारीलाल)

रहा था तो वे लोग जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो वे एक तारीख को लूणकरणसर से ठण्डी रात में पैदल रवाना होते हैं, हजारों लोग पैदल रवाना होते हैं, जीवों की रक्षार्थ जिनकी भावना है, 36 बिरादरी के लोग, एक तारीख की रात पैदल रवाना होते हैं और 75 किलोमीटर की दूरी बीकानेर तक की, जो 48 घंटे में पूरी होती है। वह दूरी आक्रोशित नौजवान 12 घंटे में पूरी करते हैं। जब 2 तारीख को कलेक्टर सुबह 10 बजे कार्यालय में आते, उससे पहले पूरे धरनार्थी लूणकरणसर से पैदल चलकर बीकानेर आ जाते हैं। जब कलेक्टर की उपस्थिति में वार्ता होती है। एक तारीख से पहले सीसीएफ दुबारा कहता है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि हमने हमारी जांच पूरी कर ली है और इसमें हमारा वन अधिकारी कहीं दोषी नहीं है। वह एक तारीख को अपने आप में क्लीन चिट दे देता है और 2 तारीख को जब कलेक्टर की मध्यस्थता में दुबारा वार्ताकारों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ बात होती है तो सीसीएफ अपने अधिकारी को निलम्बित करने की कार्यवाही करता है। उसका मुख्यालय बीकानेर करता है तो वह जब पहले दिन कह रहा है, हमारी जांच पूरी हो गई, दोषी नहीं है तो इसका मतलब वे जीव रक्षा प्रेमियों के सब्र के पैमाने के छलकने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद 2 तारीख को यह सस्पैंशन होता है और 7 तारीख को जो वार्ताकारों के सामने कलेक्टर के सामने तय हुआ, 7 तारीख को कलेक्टर, एडीएम (प्रशासन) बीकानेर की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक कमेटी बनाता है जिसमें एक प्रशिक्षु आईएएस है, अभिषेक सुराणा, एक एसएचओ लूणकरणसर है एक जीव रक्षा के पदाधिकारी मोखराम है, एक एडवोकेट विनोद है। इन लोगों की कमेटी बनती है और कलेक्टर 15 दिन का समय देता है कि यह कमेटी 15 दिन में अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट देगी। उसके बाद आगे का निर्णय होगा।

7 तारीख को यह कमेटी बनती है तो 15 दिन 22 तारीख को होते हैं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन 18 तारीख को ही, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक हाफ, वह पोप की तरह आदेश जारी करता है और 18 तारीख को निलम्बित वन अधिकारी को पुन: बहाल करके, उसका कार्यस्थल कोलायत कर दिया जाता है। यह बात 18 तारीख की है। 18 तारीख को जब यह आदेश आता है तो 19 तारीख को मैं एक स्थगन लगाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मुझे उस पर बोलने की व्यवस्था तो नहीं देते,

(श्री बिहारीलाल)

लेकिन जब सदन में इस पर चर्चा हो जाती है तब वन विभाग के कान खड़े होते हैं, अधिकारियों के हाथ पैर फूलते हैं और 19 तारीख को जब स्थगन लगा तो 20 तारीख को जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह अपने 18 के आदेश को विथड्रा कर लेता है, प्रशासनिक आधार बताते हुए विथड्रा कर लेता है।

माननीय सभापति महोदय, 18 तारीख को एक और बड़ी बात होती है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा का प्रतिनिधिमण्डल माननीय वन मंत्री जी के नेतृत्व में मुख्य मंत्री जी को आमंत्रित करने जाता है कि 23 तारीख को मुकाम, नोखा मेरी विधान सभा में गुरु जम्बेश्वर भगवान का बहुत बड़ा मेला है। माननीय मुख्य मंत्री जी को निमंत्रित करते हैं। मुख्य मंत्री जी उसमें आने की हां भरते हैं और यह फैसला 18 को उसी दिन आता है, 19 को स्थगन लगता है, 20 को अपने फैसले को विथड्रा करते हैं। ये मुख्य प्रधान वन संरक्षक, अब मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि इसमें कितने अगंभीर, कितने लापरवाह, संभाग स्तर के अधिकारी हैं सीसीएफ महोदय, जो 10 दिन तक तो वहां जनता की भावना के पैमाने को छलकने का इंतजार करते हैं, जीव रक्षा की लोगों की भावना का बांध टूटने का इंतजार करते हैं और कलेक्टर की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करते, स्वयं घोषित तरीके से यहां होफ को भेज देते हैं और वह पोप की तरह आदेश जारी कर देता है और फिर आदेश को विथड्रा करता है। जब 23 तारीख को मुख्य मंत्री जी मुकाम, नोखा पधारे थे तो 10 लाख लोगों की उपस्थिति हुई थी मेले में। उन 10 लाख लोगों की जीव रक्षा के प्रति भावना है और पर्यावरण के प्रति भावना है, जो पैदा होते ही घूंटी के साथ उस समाज को मिलती है। उन लोगों की भावना के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया और अपने आदेश को वापस ले लिया। उस समाज के लोगों ने, लाखों लोगों ने, जो एक सरकार के प्रति, विभाग के लापरवाह अधिकारियों के प्रति एक संदेश दिया, वे उद्वेलित हुए, वह परिणति कहां तक हो सकती थी।

मुख्य मंत्री जी, हमारी महासभा, हमारे पैरेंटल बाडी के मेहमान थे। उनकी सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। हम स्थानीय प्रतिनिधि हैं, महासभा की जिम्मेदारी है कि मेला साढ़े पांच सौ वर्षों से सफल आयोजित होता जा रहा है, लाखों लोगों की उपस्थिति में उसमें कितनी बड़ी अव्यवस्था हो सकती थी। महासभा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, माननीय वन

(श्री बिहारीलाल)
मंत्री जी, जो इसी परम्परा से आते हैं। वे सबसे बड़े रक्षक हैं, बेजुबान की आवाज, हमसे ज्यादा यदि कोई बनता है तो माननीय मंत्री जी बनते हैं। उनको अंधेरे में रखकर कर्मचारी कार्यवाही करता है। आज माननीय मंत्री जी जवाब में कहते हैं कि सिर्फ नोटिस दे दिया गया है सीसीएफ को। क्यों नोटिस दे दिया गया सीसीएफ को? सीसीएफ को तुरन्त बीकानेर संभाग से हटाइये, उसको निलम्बित करिए और मुख्य मंत्री जी की चिंता, सभापति महोदय, आपको है या नहीं है। वे हमारे मेहमान थे, हमको चिंता होनी चाहिए, लेकिन हमें आपसे भी ज्यादा अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, जिन्होंने मेहमान के तौर पर मुख्य मंत्री जी को बुलाया, उसकी प्रतिष्ठा की चिंता है, जीव रक्षा प्रेमियों की भावना की चिंता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करिए।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): स्थानीय प्रतिनिधि के नाते मुझे मेरी चिंता है। इसलिए मैं आपसे, सभापति महोदय, आग्रह करता हूं कि मुख्य वन अधिकारी जो संभाग पर बैठता है सीसीएफ और डीएफओ उनकी जिम्मेदारी तय करें। उन दोनों अधिकारियों को वहां से निलम्बित करें और एक नजीर पेश करें राजस्थान में लाखों लोगों ने मुख्य मंत्री जी से मांग की..

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, ये जो जीव रक्षा के नियम बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना हुआ है। यह बिना दांत और नाखून का कानून है। इन बेजुबानों की हत्या पर मुलजिम अगले दिन छूट जाता है और ऐसा ही एक प्रकरण और महाजन थाने में दर्ज हो रखा है 18/20, उस पर भी कार्यवाही की जाए।

**श्री सभापति**: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री बिहारीलाल** (नोखा): मुलजिमों को दुबारा गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर शिकार होते हैं तो यह सप्लाई कहां होता है। उनको भी चिन्हित करके जिम्मेदारी तय की जाए और माननीय मंत्री जी आज सात संकल्प की बात करते हैं। ये संकल्प मुख्य मंत्री जी को सुखराम जी ने ही दिये होंगे। सात सुखों की बात करते हैं, निश्चित तौर पर आज सदन में आपके मार्फत उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सुमित गोदारा** (लूणकरणसर): सभापति जी, यह लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र का है...

**श्री सभापति**: विराजिए। अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए आप।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्य की पूरी बात कहने के बाद कोई लंबी बात बची नहीं है। मैं चंद समय में ही अपनी बात को पूरी करूंगा। मंत्री महोदय, आप एक बात बताएं मुझे, घटना 22 जनवरी की है और घटना में आपने दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद इसी घटना के आधार पर आपका सीसीएफ एक रैंजर को सस्पैंड करता है 2 तारीख को और फिर, सभापति महोदय, मुख्य बात यह है कि जो सीसीएफ रैंजर को सस्पैंड कर रहा है, वो ही सीसीएफ वापस रिकमंड कर रहा है कि सस्पैंशन गलत कर दिया, इसको बहाल करो और इनका जो होफ है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वे 18 फरवरी को उसको वापस बहाल कर देते हैं और उसके बाद वही होफ किसकी रिपोर्ट के आधार पर वापस उस आर्डर को विदड्रा करता है? सवाल इस बात का है। खेल नहीं है यह, यह कानून चल रहा है, कानून का राज है। एक अधिकारी को एक बार आप दोषी मानते हो, वही जांच करने वाला वापस कहता है कि यह दोषी नहीं है, आप वापस उसको बहाल करते हो। आपका होफ उसको वापस बहाल करता है। वही होफ उस आर्डर को वापस विदड्रा करता है और अब आप यह कह रहे हो कि उसको नोटिस देकर छोड़ दिया गया, मैं समझता हूं कि कानून का मजाक मत करो आप। आप इस प्रकार की नजीर मत रखो कि लोग यह कहें कि यह फुटबाल बनी हुई है मर्जी आए जिस को सस्पैंड करोगे, 1-2 नहीं, यह 40 बेजुबान हिरण हैं और यह सारी बात इसलिए हुई है, अगर उस दिन मुकाम के मेले पर मुख्य मंत्री जी के जाने का कार्यक्रम नहीं होता तो यह भ्रष्ट अधिकारी उसको बचा लेते। इस सीसीएफ को आप जब तक निलम्बित नहीं करोगे, तब तक यह न्याय नहीं होगा। आप निलम्बन करने की घोषणा करो।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, जयप्रकाश को जांच दी गई और जांच में जो बयान लेने चाहिए थे, वह नहीं लेकर के सीधी ही रिपोर्ट भेज दी गई जिस पर उसने ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): मेरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि जो सीसीएफ है, उसने न तो सही तरीके से उसको टैकल किया हड़ताल को, और न केस को किया इसलिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जैसे ही उसका जवाब आता है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे।

**श्री सभापति**: कृपया शांत रहें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपने सारा घटनाक्रम सुना है। आप स्वयं इस आसन पर विराजमान हो। आपकी आत्मा इस विषय पर क्या कहती है, वही आज हम निर्णय मान लेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, आप जिस आसन पर बैठे हैं, यह पहली बार है, हम अपनी पूरी बात को यहीं खतम करते हैं। एक शब्द हम में से कोई नहीं बोलेगा पर क्या यह नजीर नहीं रहेगी, सभापति महोदय, अब आप फैसला करो। अगर इसी प्रकार यह सरकारी अधिकारी करते रहेंगे, आपने निलम्बन किया, किसकी अभिशंसा पर किया? उसको सिर्फ नोटिस दे रहे हो। फिर कह रहे हो कि वह लापरवाह है। यह मजाक मत करो आप। आप फैसला कर दो, सभापति महोदय, हम विदड्रा कर लेंगे।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): सभापति महोदय, कमेटी बनाई है, जांच होगी और जांच के बाद में जो उसका जवाब आएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। (व्यवधान) सस्पैंड किया है न मनरूप सिंह को। पहले तो सस्पैंड किया है।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सस्पैंशन कोई दंड नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये। यह गलत परंपरा है। विराजिये आप लोग। आपके नेता बोल रहे हैं।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, मौके का जो अधिकारी था उसको सस्पैंड किया है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, सस्पैंशन कोई दंड नहीं है।

**श्री सभापति**: विराजिये। आपके नेता बोल रहे हैं, इतना तो लिहाज करिए आप। जब चाहें, तब खड़े हो जाएंगे।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, सस्पैंशन कोई दंड नहीं है, सस्पैंशन के बाद भी व्यक्ति को सुना जाता है, उसके बाद उसकी आगे कार्रवाई होती है। यह जिद करके आप इस सदन को इतना कमजोर कर दोगे कि फिर यह अधिकारी कभी भी और किसी की भी बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कृपा करके इस सदन की गरिमा और हम सब की गरिमा और इस सदन में उठे हुए विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए अधिकारी को, सस्पैंशन से उसकी जान नहीं जा रही है। उसके बाद भी उसको सुनने का अधिकार है, उसको बताने का अधिकार है, उसको अपना केस प्लीड करने का अधिकार है। सस्पैंशन दंड नहीं है, केवल और केवल उसको एक मौका देकर, आप सुनकर के फिर जो कार्रवाई आपको करनी है, वह करो लेकिन पहले बचाने का मतलब इस सदन का कोई महत्व नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है आपके मन में।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): सभापति महोदय, जो मौके का अधिकारी था मनरूप सिंह, उसको सस्पैंड कर दिया। उसको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जवाब आने के बाद क्या उसकी लापरवाही है, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: किन परिस्थितियों में सस्पैंड किया उसको? माननीय मंत्री महोदय, सस्पैंशन किन परिस्थितियों में किया गया और किया गया तो वापस रिवोक कैसे हुआ?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): वापस किया इसीलिए उसको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उसका जवाब आ जाएगा किस तरह से जांच हुई उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर उसने लापरवाही बरती है तो निश्चित रूप से उसको सस्पैंड करेंगे।

**श्री सभापति**: ड्यूरिंग सस्पैंशन जवाब नहीं आ सकता था क्या उसका?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): जवाब तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता।

**श्री सभापति**: सस्पैंशन के दौरान भी तो उसका जवाब आ सकता था?

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): नोटिस दे दिया है, वह जवाब दे रहा है, जवाब आने के बाद में स्थिति देखेंगे, उसने क्या लापरवाही बरती, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

**श्री सभापति**: आप तो स्वयं उसी परंपरा से हैं और निश्चित रूप से पूरा सदन इस बात से चिंतित है कि इस तरह से यदि जीव हत्या होगी तो

(श्री सभापति)

चिंता का विषय निश्चित रूप से ही है और माननीय जो नेता महोदय हैं, इनकी भी चिंता वाजिब है। जब सस्पैंशन हुआ तो या तो उसी वक्त आप उसको नोटिस देते, उसके बाद सस्पैंशन करते। आपने सीधा सस्पैंशन किया और फिर सस्पैंशन वापस ले लिया।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, मौके का जो अधिकारी था मनरूप सिंह, उसको सस्पैंड कर दिया है। यह जो बात कर रहे हैं सीसीएफ की जो बीकानेर बैठता है उसकी। उसने जांच सही टैकल नहीं की इसलिए उसको कारण बताओ नोटिस दिया गया है सीसीएफ को। जवाब आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी सीसीएफ के खिलाफ। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): सभापति महोदय, वह सीसीएफ जो एक बार कहता है कि यह अधिकारी दोषी है, इसको सस्पैंड करो, वही सीसीएफ कहता है, जिसकी रिकमंडेशन पर होफ उसको वापस बहाल करता है और फिर होफ वापस उसी सीसीएफ के कहने पर विदड्रा करता है।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): तभी तो कारण बताओ नोटिस दिया है उसको।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): यह मजाक है, वह सीसीएफ है या क्या है?

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री सुखराम विश्नोई** (राज्य मंत्री, वन): ...(व्यवधान) कारण बताओ नोटिस दिया है उस सीसीएफ को। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये। चर्चा समाप्त। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब मैं स्वयं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं जब स्वयं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं स्वयं उनको डायरेक्शन देने की...। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। चर्चा समाप्त। मैं स्वयं बात कर रहा हूं। आपने ठान लिया है कि आपको यही करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया आपने। नहीं, अब नहीं होगा। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही आपको तो वैल में आना था। नहीं, अब अलाउ नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपका आज का एजेंडा यही है कि आपको यहीं आना है। मैं जब स्वयं बात कर रहा हूं, मैं स्वयं मंत्री

(श्री सभापति)

महोदय को निर्देश देने की सोच रहा हूं, उससे पहले आपको तो वैल में आना है। यह नहीं चलेगा। माननीय नेता महोदय, मैं स्वयं मंत्री से बात कर रहा हूं, उससे पहले ही आप वैल में आकर के खड़े हो गए हो, यह नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। चर्चा समाप्त। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। श्री जोराराम कुमावत। माननीय नेता महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनिये आप। आप अपनी सीटों पर जाइये। विराजिये। एक मिनट मैं बोल लूं। मैंने स्वयं इस मामले को गंभीर समझा। मैं स्वयं जीव हत्या का विरोधी हूं और मुझे पीड़ा होती है इस बात से कि कहीं कोई जीव हत्या हुई है। आपने मुझे बताया, मैंने स्वयं संज्ञान लिया और माननीय मंत्री महोदय से मैं अपनी बात कह रहा हूं, उससे पहले ही आज का कोई आपका एजेंडा हो कि आपको यहां वैल में आना है, यह मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं यह। आपने स्वयं ने देखा, मैं स्वयं बात कर रहा हूं माननीय मंत्री से कि कैसे हो गया, अगर हो गया तो वापस रिवोक क्यों किया। मैं स्वयं पूछ रहा हूं। आपको इतना भी धीरज नहीं था कि मंत्री जब मुझे जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं, उससे पहले ही आपके सारे साथी लोग यहां वैल में आकर खड़े हो गए। फिर सैंक्टिटी क्या है इसकी। माननीय नेता महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को निर्देश देता हूं कि स्वयं आप माननीय नेता महोदय से मिलकर के उनको पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे और चर्चा समाप्त।

## बहिर्गमन

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं। आपने जिन भावों से इस विषय को कहा है, इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सही बात है लेकिन हमें इस बात की पीड़ा है कि इतना गंभीर विषय होते हुए भी, इस सदन में इतनी देर तक चर्चा करने के बाद भी अगर वह निर्णायक दौर पर नहीं जाता है तो सदन का महत्व खतम होता है। मैं और मेरा दल इसके विरोध में वाकआउट करते हैं, अगर नहीं करते हैं सस्पैंड तो।

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री सभापति**: श्री जोराराम कुमावत। श्री अभिनेश महर्षि। श्री शंकर सिंह रावत। श्री प्रताप लाल मीणा।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: जब बहिर्गमन कर लिया तो बोल कहां से रहे हैं आप?

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): मैं बोल रहा हूं न।

**श्री सभापति**: जब बहिर्गमन कर रहे हैं तो बोल कहां से रहे हैं आप? (व्यवधान)

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डा. महेश जोशी** (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है कि बहिर्गमन को भी कैंसिल कर स्थगित कर दिया हो। यह सदन की नई-नई परम्परा डाल रहे हैं। सत्ता पक्ष आपसे संरक्षण चाहता है, आप इनको कृपा करके रोकें। यह माननीय सदस्य बाहर चले गये, आपकी कृपा है कि यह दुबारा बोल रहे हैं और इस बात को यह समझ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बलवान पूनियां** (भादरा): यह कटारिया जी और राजेन्द्र जी के साथ नहीं, वसुन्धरा जी के साथ हैं।

**श्री सभापति**: आप बोलिए, बोलिए।

## आय व्ययक

## आय व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद विवाद

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, निश्चित रूप से इस बजट में समाज के किसी वर्ग का मुख्य मंत्री जी ने ध्यान नहीं रखा, चाहे वह महिला हो, किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, इसमें कुछ भी विशेष नहीं दिया है। कुल मिलाकर सरकार का यह सात संकल्प वाला बजट पिछले बजट की पुनरावृत्ति, केन्द्र सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर वाहवाही लूटने का पुलिंदा है। यह बजट आंकड़ों का मायाजाल व कागजी बजट है। इससे राजस्थान का और राजस्थान के लोगों का भला होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे सुमेरपुर के संबंध में बात करना चाहूंगा। वर्ष 2019-20 के बजट में जो घोषणाएं हुई थीं, वह एक भी घोषणा मेरे सुमेरपुर क्षेत्र में लागू नहीं हुई जिसमें पंचायत समिति स्तर पर गोशाला खोलने का था। सुमेरपुर क्षेत्र में तीन पंचायत समितियां हैं, लेकिन एक भी

(श्री जोराराम कुमावत)

गोशाला तीन पंचायत समितियों में अभी तक नहीं खुली। पंचायत हैड क्वार्टर पर पशु चिकित्सालय खोलने का सरकार का वादा था लेकिन 65 पंचायतों में एक भी पंचायत हैड क्वार्टर पर पशु चिकित्सालय नहीं खुला है। बजट घोषणा 2019 में जनता क्लिनिक शहरी क्षेत्र में खोलने का सरकार का वादा था। मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सुमेरपुर और तखतगढ़ दो शहर हैं, उसमें एक भी जनता क्लिनिक नहीं खुली है। पिछली बजट घोषणा में 50 प्राथमिक विद्यालय, 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय व 500 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की घोषणा थी लेकिन सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ है और एक भी विद्यालय नहीं खुला है। बजट घोषणा 2019 में नये सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी खोलने व क्रमोन्नत करने की घोषणा भी थी लेकिन एक भी पीएचसी, सीएचसी या सब सेंटर क्रमोन्नत नहीं हुआ है और न ही नये खुले हैं। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण सेवा में एक भी बस चालू नहीं हुई है जबकि पिछली बजट घोषणा में यह सरकार ने वादा किया था, यह तो रहा 2019 का।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी सरकार ने सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की है। सुमेरपुर क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना है, जवाई पुनर्भरण योजना, जो पूरे पाली जिले के पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में काम आती है, वह घोषणा भी इस बजट घोषणा में नहीं की है। सेई बांध की सुरंग चौड़ी करने की 92 करोड़ की योजना है। सेई बांध से पानी जवाई बांध में आता है, उस योजना की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। सुमेरपुर में खेल स्टेडियम खोलना, सुमेरपुर में डीटीओ आफिस खोलना, सुमेरपुर क्षेत्र के तखतगढ़ कस्बे में उप तहसील खोलना, तखतगढ़ में बालिका महाविद्यालय खोलना, सुमेरपुर शहर में सीवरेज सैकण्ड फेज को स्वीकृत कराना, सुमेरपुर व साण्डेराव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेंटर की स्थापना करना, सुमेरपुर शहर में ट्रैफिक की नफरी बढ़ाना, बस स्टैंड पर स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करना, नेशनल हाईवे ढोला व गुंदोज में पुलिस थाने खुलवाना, इनकी भी हम लोगों ने मुख्य मंत्री जी से मांग की थी लेकिन सुमेरपुर के लिए बजट घोषणा में एक भी नहीं दी है। निश्चित रूप से यह बजट जनता के हित का नहीं है।

मुख्य मंत्री जी ने बजट में सात संकल्प पेश किये हैं, पहला संकल्प है नीरोगी राजस्थान। नीरोगी राजस्थान की मुख्य मंत्री जी की सोच तो अच्छी है लेकिन इसकी परिकल्पना कैसे साकार होगी। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि

(श्री जोराराम कुमावत)

पहला सुख नीरोगी काया। लेकिन नीरोगी राजस्थान की परिकल्पना कैसे साकार होगी, आजकल बीमारियां बढ़ गई हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एड्स, किडनी, लीवर, पथरी, कई तरह के बुखार, मौसमी बीमारियां, बच्चों व महिलाओं की अनेक बीमारियां, इन बीमारियों का इलाज करने व मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए कलयुग के भगवान 'डाक्टर' की जरूरत होती है। हास्पिटलों में डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ के आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। नि:शुल्क दवा व नि:शुल्क जांच करने वाला भी हास्पिटलों में कोई नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 35 डाक्टरों के पद रिक्त हैं और लगभग 60 नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के रहते राजस्थान को नीरोगी बनाना दिन में सपने देखने जैसा है। हास्पिटलों में 108 व 104 गाड़ियां भी नाकारा पड़ी हैं, उन्हें भी ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आजकल राजस्थान भर में मिर्च मसाले, तेल, घी, मिठाई व कई खाद्य सामग्रियों में रोजाना मिलावट की शिकायत आती हैं। सैम्पल भरने वाले व सैम्पल पास करने वाले सभी भ्रष्टाचार की नदी में डूबे हुए हैं। मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने व जन जागृति अभियान चलाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद जल्दी से जल्दी भराएं। चाणोद में पीएचसी है व रूपावास में एक सब सैंटर है, जिनके भवन भामाशाह ने बना रखे हैं, उन दोनों पीएचसी व सीएचसी को क्रमोन्नत कराने की व्यवस्था कराएं।

मुख्य मंत्री जी का दूसरा संकल्प है, सम्पन्न किसान। भारत कृषि प्रधान देश है। आजादी के 70 साल बाद भी किसानों का जीवन स्तर वही का वही है। आज भी खेती घाटे का सौदा है। लोग खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी की कहावत उलटी हो गई है। राजस्थान में पानी की कमी, समय पर बरसात नहीं होना, महंगे खाद-बीज, महंगी मजदूरी के बाद उपज का सही दाम नहीं मिलना व सरकार द्वारा समय-समय पर उचित मदद नहीं मिलना किसानों को कमजोर करता है। सरकार ने 2019 के बजट में फसली ऋण हेतु 16 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था लेकिन 7,689 करोड़ के ही ऋण दिये गये। इस बार बजट में फसली ऋण हेतु 150 करोड़ का लक्ष्य, 50 हजार कृषि कनेक्शन, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति विकसित करने के लिए पूरे राजस्थान में सिर्फ 91 करोड़

(श्री जोराराम कुमावत)

का प्रावधान रखा है, यह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। टिड्डी दल से किसानों की लगभग 600 करोड़ की फसलों का नुकसान हुआ लेकिन सिर्फ 47 करोड़ 80 लाख रुपये का आदान-अनुदान किसानों को दिया गया, शेष वंचित किसानों को...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): 2019 में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का आदान-अनुदान हेतु इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। मैं पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेन्द्र मोदी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी एवं पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के 10 हजार व 50 हजार के कर्जे माफ किये। बारानी जमीनों की बिगोड़ी माफ की, प्राकृतिक आपदा में 50 प्रतिशत से 33 प्रतिशत खराबा पर मुआवजा, किसान सम्मान निधि के 6 हजार रुपये देने की घोषणा, मृदा कार्ड बनाना, जिन्सों के समर्थन मूल्य बढ़ाना, कृषि कुओं के बिजली के बिल माफ करना, किसानों की आय दोगुनी करने की अनेक योजनाएं बनायीं। आपकी सरकार किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने में आपकी पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा से भी मुकर गये। किसानों के बिजली बिल पुन: लागू कर किसानों के साथ धोखा किया।

मुख्य मंत्री जी का जो तीसरा संकल्प है, जो महिला, बाल एवं वृद्ध के कल्याण के संबंध में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम के बीच बेहतर समन्वय हेतु ऐप विकसित करने की बजट में घोषणा की है, जो हास्यास्पद है। ऐप तो सरकार आदेश निकाल कर भी कर सकती थी। महिला, वृद्धजन, एससी, एसटी के विकास व इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु बजट में कोई अच्छी योजना नहीं है। पूरे राजस्थान में 50 हजार युवाओं को ऋण आबंटित करने की घोषणा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। विद्यालयों में काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाली कुक-कम-हैल्पर महिलाओं का वेतन बढ़ाने हेतु इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हास्पिटलों में बच्चों की मौतें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं, बाल एवं वृद्धों का संकल्प कैसे पारित होगा, यह मुश्किल ही लगता है।

चौथा संकल्प- सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान- राज्य के ऊर्जावान युवाओं में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए ग्राम स्तर पर खेल मैदान

(श्री जोराराम कुमावत)

आबंटित कर विकसित करने व पंचायत समिति स्तर पर खेल आउटडोर/इनडोर स्टेडियम विकसित करने हेतु राज्य सरकार की निर्धारित योजना है।

**श्री सभापति**: कृपया समाप्त करें, कनक्लूड करें।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): सर, दो मिनट। इस योजना में खिलाड़ियों के लिए बजट का प्रावधान नहीं करना उनके साथ अन्याय है।

**श्री सभापति**: विराजिए। प्लीज सहयोग करें।

**श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): मैं बजट का विरोध करता हूं। यह बजट किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हित में नहीं है। निश्चित रूप से यह कागजी बजट है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री दानिश अबरार।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): मैं बजट 2020-21 जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा टेबल पर रखा गया, इसका स्वागत करता हूं। यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी जो बजट लाते हैं, वह पिछली बार के मुकाबले हर बार बढ़-चढ़कर लाते हैं। पिछली बार जो बजट आया, वह 2 लाख 24 हजार 828 करोड़ रुपये का और इस बार बजट 2 लाख 25 हजार 731 करोड़ रुपये का आया है। पिछली बार का बजट 57 पेज का था और 235 बिंदु थे और इस बार का बजट 64 पेज का है और 242 बिंदु हैं। फिर भी जाने क्यूं, जब से चर्चा चल रही है, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वे इसके कटाक्ष में लगे हैं। मैं हमारे बजट के लिए एक बात कहना चाहूंगा-

"मैं अभी कांच हूं तो चुभ रहा हूं

जिस दिन आईना बन जाऊंगा, उस दिन पूरी दुनिया को दिखाऊंगा।"

हमारे चूरू से आने वाले विधायक साहब, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं पढ़ रहा था कि राजनीतिक लक्ष्मण रेखा से दूर हटकर सदन में इस बजट पर चर्चा की जाए तो इस बजट के पारण होने में भी संदेह है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वे लक्ष्मण रेखा से बंधे हुए हैं, आपने ऐसा कहा था। मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि यहां कोई किसी से बंधा नहीं है। हम सब अपने-अपने विचारों से आजाद हैं। आपका पूरा भाषण सुनने के बाद एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने राजनैतिक जीवन में ग्रामीण विकास मंत्री रह लिए, आप पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री रह लिए, हैल्थ मिनिस्टर रह लिए, आज भी ईश्वर से कामना करता हूं कि यदि कभी दोबारा

(श्री दानिश अबरार)

आपकी सरकार आये तो आप वित्त मंत्री जरूर बनना, जिस हिसाब से आपने आंकड़े बताए। (व्यवधान) मैं कामना करता हूं कि भविष्य में कभी आये तो आप वित्त मंत्री जरूर बनना, बाकी सारे मंत्रालय तो आपने देख लिए। (व्यवधान) मंत्री तो तब बनेंगे, जब सरकार आयेगी।

**श्री सभापति**: कृपया शांत रहें, इनको भी बोलने दें।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में हमारी सरकार बजट 11 परसेंट बढ़ाकर लायी है। जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन और शहरी विकास में 20 परसेंट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 9 परसेंट, परिवाद में 13 परसेंट, सिंचाई में 16 परसेंट और कृषि के अंदर 13 परसेंट। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पावर सैक्टर एक्सपेंडीचर में जो पूरे देश का एवरेज 6.2 परसेंट है और हमारी सरकार ने 14.5 परसेंट रखा है, जबकि आपके शासित राज्य गुजरात में सिर्फ 6.4 परसेंट है। सर, यदि ग्रामीण विकास की बात करूं तो पूरे राष्ट्र का एवरेज 6.0 परसेंट, जबकि हमारी सरकार ने एक्सपेंडीचर 8.1 परसेंट रखा है, जबकि आपके शासित राज्य गुजरात का मात्र 3.4 परसेंट है। अगर मैं पेयजल और सेनिटेशन की बात करूं तो पूरे देश का 2.3 परसेंट है, जबकि हमारी सरकार ने 4.4 परसेंट रखा है जबकि आपके शासित राज्य हरियाणा का मात्र 3.5 परसेंट है। अगर हैल्थ एण्ड फैमिली की बात करूं तो पूरे देश का 3.5 परसेंट, हमारी सरकार ने 6.1 परसेंट रखा है, जबकि आपके शासित राज्य हरियाणा ने मात्र 4 परसेंट रखा है।

एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे चूरू से आने वाले विधायक साहब ने अपने भाषण में एक बहुत ही बढ़िया बात स्वीकारी थी और कही भी थी, अर्थव्यवस्था को लेकर। सर, यह कहा गया था कि पूरे बजट का अगर अध्ययन करें तो हमारे मुख्य मंत्री जी को चिंता केन्द्र सरकार की जीडीपी/जीएसडीपी के गिरने की है, राज्य सरकार की नहीं। यह बात सही भी है कि यही जीडीपी/जीएसडीपी है। यदि किसी राज्य और केन्द्र सरकार की वित्तीय सेहत को नापना हो तो निश्चित तौर पर उसमें प्रमुख पैमाना इंडीकेटर हमारी जीएसडीपी है, यह बात कही गयी थी और यह सत्य बात है। सर, इस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि जब आपने स्वीकार ही लिया है कि जीएसडीपी एक बहुत बड़ा इंडीकेटर होता है तो, सर, जब हमारी सेंटर में सरकार थी और

(श्री दानिश अबरार)

माननीय जी प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री थे तो हमारी जीएसडीपी 7 परसेंट होती थी। जब आपकी सरकार थी और वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थीं, तब जीएसडीपी 6 परसेंट होती थी। हाल में जो देश डगमगा रहा है, जो चिंता हो रही है, केन्द्र सरकार की जीएसडीपी है तो वह है मात्र 4.5 परसेंट। यह बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान की जीएसडीपी 11 परसेंट है। यह आंकड़ों का जाल है।

माननीय सभापति महोदय, इस बात से हटकर कुछ और। हमारे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जी बैठे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष आपका बजट 15 करोड़ रुपये बढ़ा है और 164 करोड़ रुपये हो गया है और जो हमारे सामने बैठे हैं, आपकी मानसिकता देखते हुए मुझे इस सदन में बैठकर बड़ा अजीब-सा लगता है। जब राठौड़ साहब ने बात कह दी।

**श्री सभापति**: क्या आपने पूरा भाषण राठौड़ साहब को ही समर्पित कर दिया?

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): सर, मैं उनसे बड़ा प्रेरित हूं क्योंकि वे बार-बार कहते हैं कि मैं 7वीं बार विधान सभा में आया हूं। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी बार आऊंगा, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। राठौड़ साहब ने अल्पसंख्यक की बात को लेकर कहा, जिसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी सरकार भी उलट हो गयी। आपने कहा कि लंबे समय से संविधान पर हमला करने का काम किसी न किसी उदम रूप से इस पार्टी के द्वारा किया जाता है। आजादी के बाद यह पहला मौका आया, जब इस सदन के अंदर एक ऐसे मसले पर चर्चा की गयी और आर्टिकल 11 में केन्द्र सूची में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के वैधानिक अधिकार में केन्द्र को कहा कि लोक सभा और राज्य सरकार में यह पारित होने के बाद कानून बन गया। इस सदन के अंदर हमने 25 जनवरी को चर्चा की और सत्तारूढ़ दल का संकल्प भी पारित किया, ऐसा आपने कहा। अब आप बताइये कि बिहार में तो आपकी सरकार है, बिहार में तो आपके समर्थन से सरकार है, अब वहां भी संकल्प पारित हो गया, अब क्या कहना चाहेंगे? अब प्रस्ताव पारित हो गया, अब आप क्या कहना चाहेंगे? यहां तो आप सब पर आरोप लगा दिया कि हमने सीएए के खिलाफ संकल्प दे दिया। बिहार में तो आपकी

(श्री दानिश अबरार)

सरकार है। बिहार में भी हो गया, बिहार छोड़ो, अभी मेरे समय के पांच मिनट बाकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली है, आज दिल्ली जल रही है। आप बताइये इसका कसूरवार कौन है?

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री सभापति**: मैं अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): ...(व्यवधान) मात्र एक फिट पर, ...(व्यवधान) एक बात, इसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो, किसी तरह देश डिवाइड होता रहे। मात्र एक बात, मात्र लक्ष्य कि किसी तरह इस देश का ध्रुवीकरण हो। किसी तरह से देश के वोट बंटते रहें। आज जैसे देश की राजधानी जल रही है, आप चाहते हैं, पूरा देश जले, ऐसा राजस्थान सरकार कभी नहीं होने देगी। आपको शर्म आनी चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आये हुए हैं और दिल्ली जल रही है। (व्यवधान)

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): 000

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री विट्ठल शंकर अवस्थी** (भीलवाड़ा): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य विराजिए। आपने तो बोल लिया और जो माननीय सदस्य बचे हुए हैं, जो बोलना चाहते हैं, आप उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं। गलत है ये।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000

**श्री सभापति**: आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): 000.

**श्री विट्ठल शंकर अवस्थी** (भीलवाड़ा): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): आज यह जो मेरे बोलने पर सदन में हो रहा है, यह चाहते हैं कि यह देश के अंदर हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजिए। इसी तरह से, यदि हाउस चलाना चाहते हैं तो मैं एडजोर्न करता हूं हाउस। यदि आप गंभीर हैं, आप दो-चार लोगों की तो स्थिति यह हो गई है कि हर बात में खड़े होकर इंटरवीन करना। अच्छी परम्परा नहीं है। पहली बार माननीय सदस्य

(श्री सभापति)

आए हैं। आप चौथी बार, पांचवीं बार आए हैं। कम से कम इतना तो लिहाज कीजिए। माननीय अवस्थी जी, किसी बात पर आप बोलेंगे नहीं, किसी सब्जैक्ट पर आप बोलेंगे नहीं, केवल उचक-उचक कर खड़े होने का यह कौन-सा तरीका है आपका? बैठिए आप, विराजिए। सारी परम्पराएं समाप्त कर दीं। यह क्या तरीका है आप लोगों का? आपके नेता सुन रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं, संसदीय परम्पराएं कुछ तो सीख लें। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, मैं जब तक यहां बैठा हूं मुझे इस तरह का वातावरण बिलकुल पसंद नहीं है। मैं आपसे और आपसे दोनों से कहता हूं कि बेवजह यहां पर उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है। जो भी माननीय सदस्य बचे हुए हैं, सब पहली बार आए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। पूरी तैयारी करते हैं। आपकी स्थिति यह है माननीय सदस्य बोले और बाहर। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप उनको बोलने नहीं देंगे। गलत है यह बात। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, विनम्र विनती करता हूं, कृपया जो बोलने वाले सदस्य हैं, उनको बोलने का मौका दें। प्लीज, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। माननीय सदस्य।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं मदरसा पैराटीचर्स की बात करना चाहूंगा।

**श्री सभापति**: आप भी इनवाइट मत कीजिए उनको। आप सिर्फ अपनी बात कहें।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): नहीं सर, बिलकुल नहीं कर रहा। मैं समझ गया। मदरसा पैराटीचर्स आज धरने पर बैठे हैं। मैं समझता हूं आज उनकी जो दुर्गति और दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उस दुर्गति और दुर्दशा के जिम्मेदार हम सदन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वे इधर के हों या इधर के हों। यह मदरसा पैराटीचर्स एक शिक्षित वर्ग है और वह वर्ग है जो बच्चों को राष्ट्र हित में चलने की दिशा और दशा बताता है। मैं समझता हूं कि इस सभागार में बैठे, सदन में बैठे सभी सदस्यों का दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उनका दर्द समझें। हम उनकी पीड़ा समझें और कम से कम उनके मानदेय और नियमितीकरण की बात करें। हमें यह करना है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा उन पैराटीचर्स को सदन के माध्यम से कि उन सबको भी और हम सब सदन में जितने लोग हैं, हमें हमारी मैं की भावना छोड़नी पड़ेगी। हम सबको मिलकर उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा, तभी जाकर उनका

(श्री दानिश अबरार)

मानदेय बढ़ पायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट वन विभाग पर बोलना चाहूंगा।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): सर, दो मिनट और लूंगा। वन विभाग के अंदर हमारा बजट 931 करोड़ था जो कम होकर 901 करोड़ रुपया रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट को उतना ही बढ़ाये रखा जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, माननीय वन मंत्री महोदय जिन्होंने पिछले बजट में घोषणा की थी कि वहां एक द्वार बनेगा, वहां जोगी महल का जीर्णोद्धार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया, उसका शिलान्यास और उद्घाटन हो और ईडीसी गाइड्स की भर्ती हो। साथ में, वन विभाग को लेकर, अब फिर से स्प्रिंग लग जाएगी लेकिन मुझे यह कहना जरूर है कि रणथम्भौर के अंदर पिछले दिनों अख़बार में खबर आई कि 26 बाघ पिछले इतिहास में आज तक गायब हो गये। आज 26 बाघ गायब होने की हम बात कर रहे हैं। आज बीजेपी की ही सांसद महोदया हैं, जिन्होंने सवाई माधोपुर में बाघों को लेकर बड़ी चिन्ता जाहिर की लेकिन यह जो 26 बाघ गायब हुए, ये 2010 से लेकर 2017 तक हुए जिसमें 2014 से लेकर 2017 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब टी-55, टी-70, टी-76, टी-22, टी-26, टी-43, टी-6, टी-78, टी-81, 82, 88, 79, 77, 90, 14 बाघ बीजेपी के राज के अंदर गायब हुए और ये 14 बाघ तब गायब हुए जब सवाई माधोपुर से विधायक कांग्रेस का नहीं था। सवाई माधोपुर से विधायक भाजपा का था तब चिन्ता नहीं हुई लेकिन आज चिन्ता बहुत ज्यादा हो रही है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): सर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सवाई माधोपुर के अंदर 33 करोड़ रुपये के बनास बांध की घोषणा की, 250 करोड़ रुपये मेडिकल कालेज की घोषणा की, 12 करोड़ की मलाराना डूंगर से सांखड़ा रोड की घोषणा की, अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास 2 करोड़ रुपये की घोषणा की, 1 करोड़ झूमर बावड़ी की

(श्री दानिश अबरार)

घोषणा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में शिक्षा वह चीज है, जो अपना खुद का धन होता है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री दानिश अबरार** (सवाई माधोपुर): सर, सिर्फ एक मिनट। सवाई माधोपुर कालेज के अंदर एमएससी की फैकल्टी नहीं है। मैं मांग करता हूं कि वहां एमएससी हो और मलाराना डूंगर में कालेज खुले। मैं अपनी बात एक शेर के साथ समाप्त करता हूं-

''सोचने से कहां मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर,

चलना भी जरूरी है, मंजिल पाने के लिए।''

बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती रमिला खडिया। श्री अभिनेश महर्षि।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): परिवर्तित बजट 2020-21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। अभी सदन के अंदर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर-शोर के साथ में बिहार की बात कर डाली और माननीय उपनेता प्रतिपक्ष के भाषण का उन्होंने उदाहरण दिया। आप सदन में रहकर सुना करो शांति से कि माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था? माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने सीएए की बात की थी और आप बिहार के अंदर एनआरसी के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। आप जरा यहां बैठकर सुनकर उसके ऊपर बात करने की कोशिश किया करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिनकी सरकार है, आप भूल गए 30 जनवरी का वह दिन, 28 मिनट का वीडियो बनाया था आपने, डीवाईएसपी का आपने वह वीडियो बनाया था कि किस तरह से अवैध खनन बजरी, उसके अंदर आपने वीडियो बनाया था, क्या हुआ उस वीडियो का? किस तरह से एसपी ने आपको बुलाकर के, पहले तो आपका टेलीफोन नहीं लिया एसपी ने, सत्ता पक्ष के विधायक को, हम लोगों के विधायक रहने के अंदर इस तरह का सोच करना पड़ रहा है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक की यह बात हो रही है, उसके बाद में किस तरह से फटकार लगाई थी, उस फटकार की खीझ आप यहां उतारना चाहते हैं। सरकार की बानगी की बात करूं मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी ने जब

(श्री अभिनेश महर्षि)

बजट भाषण शुरू किया तो हमारे नेता प्रतिपक्ष से पूछा उन्होंने कि मैं पानी पी लूं? अच्छा होता मुख्य मंत्री महोदय, यदि आप हमसे बजट पेश करने से पहले, विपक्ष के विधायकों से, माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछ लेते कि राजस्थान की जनता की आवाज क्या है? आप लोग बता दें तो उन मांगों को भी शामिल करते तो हमें अच्छा लगता है। आप पानी पी-पी करके राजस्थान की जनता को पानी पिलाने का काम मत कीजिए। आप लोग यदि पूछना चाहते हैं, यदि आपके दिल के अंदर इस राजस्थान की गरीब जनता के प्रति हमदर्दी हैं तो आप लोग पूछो हमसे, हम भी चुनकर आए हैं। ढ़ाई लाख वोटों के ऊपर प्रत्येक विधायक चुनकर राजस्थान की विधान सभा के अंदर 200 व्यक्ति आए हैं। कोई पहली बार आया है, कोई सातवीं बार भी आया है और कटारिया साहब आठवीं बार भी आए हैं। माननीय सवाई माधोपुर से आने वाले, मेरे भाषण की वो बदल गई, मैं कहना कुछ और चाहता था लेकिन आपकी बात को सुनकर बड़ा अजीब, मैं तो आपको बड़ा समझदार आदमी समझता था, मैं तो विद्वान समझता था कि हमारे गुरुजी के बेटे अच्छा प्रदर्शन करेंगे विधान सभा के अंदर। लेकिन अबरार साहब, माननीय विधायक महोदय, अभी आप कह रहे थे, जिन बातों के बारे में कह रहे थे, जिनका कोई सिर-पैर नहीं, ...(व्यवधान) उनको ही कर रहा हूं।

**श्री सभापति**: बीच में नहीं करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अब मंत्रियों से जब कोई प्रश्न पूछ लेते हैं और प्रश्न के अंदर मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनको ऐसा लगता है, मंत्री के प्रश्न का जवाब देते समय, उनके मन के ऊपर इस तरह की भावना आती है जैसे हमने उनकी व्यक्तिगत प्रोपर्टी में से कोई हिस्सा मांग लिया हो। जनता जनार्दन हैं, उसकी बात करने के लिए हम सदन में आए हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हम हमारे विधान सभा क्षेत्र के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम उन लोगों की भावनाओं पर खरा उतरने के लिए आए हैं तो क्या हम लोग आपसे सवाल भी पूछना बंद कर दें?

कई बड़े वाले मंत्री यहां से सारे के सारे चले गए, पहली बार मंत्री बने, अधिकार की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, कटारिया जी मुझे डाउट है, आप गृह मंत्री थे क्या? मुझे डाउट है, आपके उप

(श्री अभिनेश महर्षि)

मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी हैं क्या? यदि वह उप मुख्य मंत्री हैं तो पंचायती राज का कचरा करने में या तो उप मुख्य मंत्री जी की भूमिका है या उनके हाथ इस तरीके से बांध दिए गए हैं कि ग्रामीण विकास की भावना लेकर हम लोग सदन में आते हैं, उनकी भावना के अनुसार काम नहीं करने दिया जाता है।

झुंझुनूं से आने वाले सदस्य कह रहे थे, इतनी लाख किलोमीटर सड़क, उन्होंने यह कहा कि इतना सा बजट दिया है ऊंट के मुंह में जीरा। हमें तो यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि नागौर की घटना में, सरकार आपकी, जांच एजेंसी आपकी, आप कहते हो हमारा आईजी पहुंच गया, उसके बाद एक जांच कमेटी भेजी जाती है, जो रिपोर्ट आती है, वह माननीय उप मुख्य मंत्री जी सीधे इनके आलाकमान के पास भेजते हैं। आलाकमान के ट्वीट के बाद वहां जांच करने वाली एजेंसियां गई थीं, इसलिए आलाकमान को भेजा जाता है कि यह रिपोर्ट आई है। क्या आपको आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार पर से भरोसा उठ गया है?

सात संकल्प की बात कर रहे हैं। बजट के अंदर एक साल पहले भी घोषणाएं की थीं। आप ईमानदारी से छाती पर हाथ रखकर अपने आप से पूछ लेना, 40 परसेंट घोषणाओं को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर। डीजीपी पांच साल रहे, आपके शासन में ही वह डीजीपी थे। उनको मजबूर होकर धरना देने बैठना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आज उन्होंने अपने मन की भावना किन शब्दों में व्यक्त की, आप सब को सोचना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए। सात संकल्प, सात लोमहर्षक हृदय विदारक घटनाएं, इस राजस्थान का चेहरा कालिख से पोत दिया।

सरदारशहर की घटना याद करो, दलित के नाखून खींचकर पुलिस ने निकाल दिए। थानागाजी की घटना याद करो। रतनगढ़ में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जैसलमेर-बाड़मेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जैसलमेर-बाड़मेर, यह सात घटनाएं मैं सोचता हूं आपको शर्मसार करने के लिए काफी हैं। (व्यवधान) आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सभापति महोदय, संरक्षण चाहता हूं।

**श्री सभापति**: कोई नहीं बोल रहा, आप अपनी बात जारी रखें। कोई नहीं बोल रहा है।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): जब तक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक इस प्रदेश में न तो कोई उद्योग धंधे लगाने आएगा, न ही कोई पर्यटक आएगा। भरोसा दिलाना सरकार का काम है, सरकार लोगों को भरोसा दिलाए कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे। यह मेरे मन की पीड़ा नहीं है, यह आप सब लोगों के मन की पीड़ा भी आई है।

अभी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही। हम तो यह सोच रहे थे कि आप अनुशासन में बंधे हुए हो, लेकिन आपने स्वयं अपने मुखारबिंद से घोषणा की हम किसी के अंडर में नहीं आते, हम तो स्वतंत्र हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): हमें आज पता लगा। माननीय सभापति महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था करो जिससे हम लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। सभापति महोदय, बिल्ली के डर से कबूतर यदि आंख बंद करके बैठ जाएगा तो बिल्ली क्या करेगी, उस कबूतर को सोच लेना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से आंख मूंद कर जनता के सामने बैठ जाएंगे तो जनता आने वाले समय में आपके साथ क्या करेगी, आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

सिरोही वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वह भूल गए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसने दिया था। वह आरक्षण की बात कर रहे थे लेकिन भूल गए कि आरक्षण किसने दिया। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। अटल बिहारी जी वाजपेयी को याद करिए। सभापति महोदय, ओबीसी को आरक्षण, जाटों को आरक्षण, यदि किसी ने दिया था तो आपके सीकर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आप लोग आरक्षण की बात करते हो। आठ लाख के प्रावधान को हटाया, अच्छी बात है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। सरकार के ऊपर ब्यरोक्रेसी हावी है। उस ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की कोशिश कीजिए।

मैं कुछ बातें मेरे विधान सभा क्षेत्र की करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाई जाए। शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा है। संविदाकर्मियों को नियमित करो। रतनगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाने की कृपा कीजिए। छापर में अस्पताल में

(श्री अभिनेश महर्षि)

क्रमोन्नत, रतनगढ़ में इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोलें, रीको इंडस्ट्रियल एरिया में सिविल डिफेंस का कार्यालय खोला जाए। मिसिंग लिंक रोड अभी तक विधायकों को नहीं मिली हैं। दस महीने बाद इस बात के लिए सब विधायक हां भरेंगे, दस महीने बाद एमएलए लैड का पैसा खर्च करने की आपको परमीशन मिली थी, दस महीने तक सरकार ने रोके रखा था, यह हम जन प्रतिनिधियों पर कुठाराघात है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रतिवर्ष 20 किलोमीटर मिसिंग लिंक और 50 किलोमीटर प्रतिवर्ष रिपेयरिंग, री-कारपेटिंग का अधिकार दिया जाए।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी समय नहीं हुआ है। सुजानगढ़ ....

**श्री सभापति**: समाप्त करें। श्री अशोक खण्डार।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): मेगा हाईवे से जोड़ने वाली सड़क को वन विभाग से एनओसी दिलवाओ। राजलदेसर में गवर्नमेंट कालेज, भिवानी रामपुर में श्मशान भूमि में जाने का रास्ता, सम्पूर्ण कर्जा माफ।

**श्री सभापति**: समाप्त करें। माननीय सदस्य, विराजिए।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। फसल बीमा का क्लेम दिलवाया जाए। किसानों को आठ घंटे बिजली दी जाए। (व्यवधान) अशोक भाई, आप तो पुराने आदमी हो, मेरे साथी हो। पीड़ित किसानों के बिजली के बिल माफ करो, रतनगढ़ में कृषि उपज मण्डी यार्ड का निर्माण करवाया जाए, रतनगढ़ में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय खोला जाए, नंदीशाला खोलने की बात की थी, नंदीशाला नहीं खोली गई। गायों के लिए अनुदान होता था उसको आपने कर्मचारियों की तनख्वाह के अंदर खर्च कर दिया। आयुर्वेद की अनदेखी हो रही है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): सारे अस्पताल खाली पड़े हैं, पदों को भरिए।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): आयुर्वेद से तो देश की प्रतिष्ठा थी साहब। उस आयुर्वेद के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं बोला गया है। मैं

(श्री अभिनेश महर्षि)

आपसे यह कह रहा हूं कि जो पंचायती राज चुनाव नहीं करा सका, पंचायत राज को पंगु बना दिया..

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, मेरी आपको यह सलाह है आपकी जो गंभीर बातें थीं वह पहले नहीं रख सकते थे?

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): गंभीर बात है, यह पूरी की पूरी। खेल मैदान नहीं है, बच्चों को आप कहां से ओलम्पिक में भेजेंगे?

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा। अशोक खण्डार। विराजिए।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): 000

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

**श्री अशोक** (खण्डार): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): 000

**श्री सभापति**: विराजिए।

**श्री अशोक** (खण्डार): हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया है, पूरे प्रदेश में इसकी सराहना हो रही है।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): 000

**श्री सभापति**: विराजिए। अलाउ नहीं करूंगा। आप बोल लिए, बाकी को बोलने दीजिए। विराजिए। अलाउ नहीं करूंगा, आप विराजिए।

**श्री अभिनेश महर्षि** (रतनगढ़): 000

**श्री सभापति**: प्लीज विराजिए। सहयोग करें, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। कुछ परम्पराएं सीख लीजिए। माननीय सदस्य, यह आपके वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे पूछ लीजिए ...(व्यवधान) हमको भी सिखाया था यही।

**श्री अशोक** (खण्डार): बजट भाषण पर सबने अपने-अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस बजट की पूरे राजस्थान में सब सराहना कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा सबका साथ सबका विकास एक अवधारणा लेकर बजट पेश किया गया। किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का कल्याण कोष, महिलाओं के उत्थान के लिए एक हजार करोड़ की इंदिरा महिला शक्ति निधि, एक लाख युवाओं को एक हजार करोड़ रुपये के लोन उपलब्ध कराना, मुख्य

(श्री अशोक)

मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से राजस्थान में जन आधार योजना को विराट सफलता के लिए आयोजित करने का प्लान, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो संकल्प लेकर बजट पेश किया है, उसका मैं पुरजोर स्वागत करता हूं।

नीरोगी राजस्थान के लिए 100 करोड़ का बजट प्रबंधन करके नीरोगी राजस्थान की कल्पना की है, निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के युवाओं का, बालकों का, मातृशक्ति का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इसकी कल्पना करके यह कार्यक्रम हाथ में लिया है। मैं इसकी सफलता की अभी से कामना करता हूं।

**(19.00 बजे)**

हमारी सरकार ने पहले भी नि:शुल्क दवा योजना लागू की जिसकी पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सराहना की गई। हमारी सरकार के दुबारा आने के बाद में फिर नि:शुल्क दवा योजना का विस्तार किया गया, 700 से ज्यादा दवाइयां सरकारी दवाखानों में नि:शुल्क दी जा रही हैं। गम्भीर जांचों की भी नि:शुल्क योजना लागू की गई है। अब गांव का गरीब आदमी नि:शुल्क दवा योजना के माध्यम से, नि:शुल्क जांच योजना के माध्यम से अपना इलाज करा रहा है। और तो और गम्भीर बीमारियां, कैंसर की, हार्ट की, किडनी के इलाज के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है कि गरीबों का इलाज नि:शुल्क हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। 15 मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। सवाई माधोपुर को मेडिकल कालेज की सौगात दी गई, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। जयपुर में उच्च श्रेणी का राज्य का कैंसर संस्थान प्रारम्भ हो गया, इससे राजस्थान के कैंसर रोगियों को काफी लाभ मिलेगा।

नीरोगी राजस्थान में हमारी चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी, आयुर्वेद, फिजियोथैरेपी, एक्यूप्रेशर पद्धतियों को भी शामिल करके नीरोगी राजस्थान में इनको शामिल किया जाए ताकि इन पद्धतियों के माध्यम से भी राजस्थान में अन्य कई रोगों का इलाज हो सकता है।

किसानों की सम्पन्नता के लिए, किसानों के विकास के लिए एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई, जिसमें जल संग्रहण, भूमि सुधार, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम, पैदावार और उत्पादन बढ़ाने का काम, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, सोलर पम्पों की कृषि क्षेत्र में स्थापना करके किसानों के कल्याण का काम करेंगे।

(श्री अशोक)

उन्नत बीजों की उपलब्धता के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्पित है। 2020-21 में एक लाख टन डी.ए.पी., 2 लाख टन यूरिया की व्यवस्था की जाएगी। मुझे ध्यान आता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष भरपूर मात्रा में किसानों को डी.ए.पी. और यूरिया मिला। पिछली सरकार में डी.ए.पी. और यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता था। पुलिस कस्टडी में खाद मिलता था और कई बार तो लाठियां खानी पड़ती थीं, ब्लैक से खाद खरीदना पड़ता था परन्तु इस बार किसानों को सुगमता से खाद-बीज और यूरिया, डी.ए.पी. मिल रही है। किसानों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

इस बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नई 44 कृषि उपज विपणन मंडियां घोषित की हैं। खण्डार में भी कृषि उपज मण्डी खोलने की जो घोषणा की, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं।

सहकारिता के मामले में मेरा निवेदन है कि सहकारी संस्थाओं के द्वारा सहकारी बैंकों के किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। विपक्ष चाहे कितना भी कह ले, उन गांवों के गरीब किसानों का जो ऋण माफ हुआ, उनके दिल से दुआएं मिल रही हैं। अभी सहकारी फसली ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से 22 लाख से अधिक किसानों को 8,700 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं।

2020-21 में जी.एस.एस., के.वी.एस.एस. और उपभोक्ता भण्डारों में कुल 130 गोदाम बनाये जाएंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम छान में 5 एम.टी. का गोदाम बनाये जाने के लिए माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा।

महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इस संदर्भ में सरकार समुचित नवाचार कर ए-3 एप की तैयारी कर रही है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम., इन तीनों का बेहतर तालमेल होगा, इन पर प्रभावी नियंत्रण होगा। वे अच्छा काम कर पाएंगे और हमारे बच्चों के पोषाहार का पूरा ध्यान रख पाएंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

पोषाहार वितरण में प्रभावी देख रेख के लिए मेरा निवेदन है कि इस विभाग में कई शिकायतें लगातार मिलती जा रही हैं, पर प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके।

(श्री अशोक)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक और निवेदन है कि स्कूलों में दूध पिलाने की परम्परा जो पिछली सरकार ने चालू की थी, उसमें बहुत भारी धांधलियां हैं। इस दूध योजना से स्वास्थ्य कोई ठीक होने वाला नहीं है। आधा दूध डेयरियों का मिलता है और ऐसी डेयरियों से दूध लेते हैं कि वह दूध किसी काम का नहीं है। इसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती है। इसलिए इस योजना को बदलकर शीघ्र ही कोई ऐसी बिस्कुट ईजाद करके सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों में, स्कूलों में दूध की जगह पौष्टिक बिस्कुट का वितरण करे तो इसकी धांधली मिटेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा और बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान हो सकेगा।

सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से पिछली सरकार में करीब 34 लाख से ज्यादा पेंशन वृद्धजनों की, विधवाओं की, विकलांगों की हमने स्वीकृत की थी। काफी लोगों को उसका लाभ मिला परन्तु जैसे ही सरकार बदली, पिछली भा.ज.पा. सरकार ने काफी लोगों को केवल यह कहकर कि कांग्रेस की पिछली सरकार रेवड़ियां बांटकर चली गई, लाखों लोगों के नाम काटकर पेंशन बंद कर दी गई। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि एक बार फिर नये सिरे से अभियान चलाकर पेंशन को स्वीकृत करने के लिए गांव-गांव में, हर पंचायत मुख्यालय पर पिछली बार की भांति कैम्प लगाएं ताकि गांव के जो वंचित वृद्धजन रह गये हैं, विधवाएं रह गई हैं, विकलांग रह गये हैं, पालनहार के काम रह गये हैं, वे फिर नये तरीके से सामाजिक सरोकार में हमें करने का मौका मिले और जनता को इसका लाभ मिले।

हमारे एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक छात्रावासों में मैस भत्ता दो हजार से ढाई हजार बढ़ाया है, वह काफी अच्छा है। इससे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनका अच्छा भोजन होगा और उनकी देखरेख अच्छी होगी। सवाई माधोपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोलने की जो घोषणा की, उसका मैं स्वागत करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन का जो एलान किया है, उसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

सक्षम मजदूर, युवा, जवान के लिए, खेलों के प्रति जागरूकता लाकर 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' का जो लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है, यह काफी सराहनीय है। युवाओं में इसकी जागरूकता बढ़ेगी और प्रोत्साहन के

(श्री अशोक)

लिए अनेक आयोजन होंगे, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है।

ग्राम स्तरीय और ब्लाक स्तरीय खेलों के विकास के लिए खेल प्रतिभाओं के तराशने का जो काम होगा, आयोजन होंगे, उसके लिए एक नई सोच और नया प्रयास किया जाएगा। इसके लिए भी मैं सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं खेल मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि मेरा चौथ का बरवाड़ा उप खण्ड मुख्यालय है, वहां पर काफी खिलाड़ी हैं। वहां पर एक खेल स्टेडियम खोला जाए, ऐसा मेरा आग्रह है।

उद्योगों के विकास के लिए सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया है। अब वन स्टाप शाप प्रणाली से औद्योगिक विकास का संकल्प लेकर सरकार काम कर रही है, आगे भी करेगी और औद्योगिक विकास के ऊपर पूरा ध्यान देगी।

अभी हाल ही में पूरे देश में नोट बंदी और जी.एस.टी. के बाद में मंदी का माहौल बना, उद्योग धंधे चौपट हो गये, लाखों उद्योग बंद हो गये, हजारों लाखों युवा बेरोजगार हो गये। पूरे देश में मंदी का माहौल है, निराशा का माहौल है। उसकी किसी ने चर्चा नहीं की। केवल राजस्थान के बजट को कोस रहे हैं। देश के उस भामाशाह को, उन दोनों को नहीं कोस रहे जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हालत खराब कर दी। धंधे गये, माननीय सभापति महोदय, उद्योग-धंधे बंद होने के बाद में इतना अपराध बढ़ रहा है कि आपके जयपुर में सांगानेरी प्रिंट की फैक्ट्रियां बंद हो गईं, हजारों-लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये। हाल यह है कि वे क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल में नहीं लिया गया, अगर देश की मंदी को और महंगाई को कंट्रोल में नहीं लिया गया तो अपराध बढ़ेंगे। ये देखते रह जाएंगे। देश के अन्दर इनकी हालत भी खराब होने वाली है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के मामले में जमीन की 10 हैक्टेयर की जो बंदिश लगाई है, वह बहुत ज्यादा है। 10 हैक्टेयर में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसान इतने आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इसके लिए इस सीमा को कम करके दो एकड़ में प्रोसेसिंग यूनिट की स्वीकृति देने के लिए सरकार ध्यान दे।

खनिज के सम्बन्ध में, पूरे प्रदेश में बजरी के मामले में सबने चिंता

(श्री अशोक)

जाहिर की। अवैध बजरी खनन के माध्यम से पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं।

**श्री सभापति**: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री अशोक** (खण्डार): पांच मिनट, सभापति महोदय।

मेरा निवेदन है कि इसके मामले में कोई ठोस नीति बनाकर कानून में संशोधन करके कोई ऐसा तरीका निकालकर प्रदेश में बजरी उपलब्धता की जाए, ताकि प्रदेश में अपराध में कमी हो और सरकार को राजस्व का लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा को पुन: मजबूत बनाया गया। मेरा आग्रह है कि इसमें आगे अब पक्के निर्माण कार्यों को हाथ में लिया जाए। जैसे स्कूल की बाउण्ड्री है, श्मशान घाट की बाउण्ड्री है, गांव की नालियों के काम को हाथ में लेने की आवश्यकता है।

शनिवार को जो नो-बैग-डे की जो घोषणा की है, वह सराहनीय है। हमारे बालकों में नवाचार होंगे, पर्यावरण के प्रति, खेल-कूद के प्रति, संस्कृति के प्रति, नैतिक शिक्षा के प्रति इनमें हौसला बढ़ेगा, उनमें नई जागृति आयेगी, उनमें प्रतिभाएं तराशी जाएंगी, खेलों के माध्यम से एक हैप्पीनेस का माहौल रहेगा। निश्चित तौर पर यह भी एक नया नवाचार है। सरकार के लिए बहुत अच्छी, खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के छात्रों को उसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, परिवहन के मामले में मैं निवेदन करूं कि प्रदेश में काफी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबको चिंता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि परिवहन के जो दुर्घटना के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार ने सौ करोड़ का जो सड़क सुरक्षा कोष बनाया है, इसको प्रभावी रूप से काम में लिया जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि शनिवार को स्कूल में जो नो-बैग-डे घोषित किया है, वहां पर परिवहन के सम्बन्ध में जागरूकता लाने के लिए अभी से छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जाए। उनको अनुशासन के पाठ पढ़ाये जाएं। उनको सेलेब्रेशन में शामिल किया जाए। उनको खेलकूद, यातायात ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री अशोक** (खण्डार): दो मिनट, सर, मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

**श्री सभापति**: नहीं, समाप्त करें। अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें। समाप्त करें अपनी बात।

**श्री अशोक** (खण्डार): पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान पर्यटन के नाम से विख्यात है, मेरा जो खण्डार क्षेत्र है, वहां एक चम्बल क्रोकोडाइल सैंक्चुअरी है। माननीय सभापति महोदय, उसके लिए मेरा आग्रह है कि उसको विकसित करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय ध्यान दें।

जल संसाधन के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो लागू की जा रही है, यह योजना बनाई जा रही है, यह काफी सराहनीय है। 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। सवाई माधोपुर को इसमें शामिल करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। अभी हाल ही में ईसरदा में 1200 करोड़ रुपये का डैम बन रहा है।

**श्री सभापति**: श्री शंकर सिंह रावत।

**श्री अशोक** (खण्डार): उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। वन के संबंध में मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह से वनों के प्रति हमारी जागरूकता रहती है, उसी तरह से वन विभाग ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये-विराजिये। समाप्त करें।

**श्री अशोक** (खण्डार): एक मिनट, सर। वन विभाग के माध्यम से जो काम रणथम्भौर सैंक्चुअरी में हो रहे हैं, हमारी एक समस्या यह और हो रही है कि वहां पर टाइगर ज्यादा हो गये, टैरिटरी कम है तो टाइगर बाहर निकलते हैं और ग्रामीणों को जन हानि होती है और जो मुआवजा दिया जाता है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

**श्री अशोक** (खण्डार): 000

**श्री सभापति**: विराजिये।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट जो पेश किया है, इस बजट पर सबसे पहले पेज पर उन्होंने यह लिखा है कि-

(श्री शंकर सिंह रावत)

"नोटबंदी से बर्बादी पर वो बोलते नहीं,
जीएसटी के झटकों पर मुंह खोलते नहीं,
उनके आंकड़े ही दिखाते हैं उन्हें आईना,
वो फिर भी मुकर कर सच को तौलते नहीं।"

माननीय सभापति महोदय, यह जो चीजें लिखी हैं, इसकी बजाय तो यह लिखना चाहिए माननीय प्रधान मंत्रीजी के लिए कि इस देश का कलंक जो जिस प्रकार, 370 को हटाना, 35-ए को हटाना, राम मंदिर की समस्या हल होना, सी.ए.ए. लागू होना, कश्मीर में कोई झंडा फहरा नहीं सकता था, उस जगह पर आज तिरंगा घर-घर पर लहरा रहा है और पाकिस्तान को सुधारने का काम किसी ने किया है तो वह प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इन तारीखों की बात को कहीं न कहीं इस बजट के अंदर लिखते तो हमें भी अच्छा लगता और हम भी कोई तारीफ की बात करते। हमें कोई न कोई नेगेटिव बात लिखकर और देश को नीचा दिखाने की बात करते हैं, वह उचित नहीं है। इस प्रकार के शब्दों के अंदर यह लिखना चाहिए कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री ने यह अच्छाइयां की हैं। ठीक है, उनकी यह भावना है लेकिन उसमें अच्छाइयों को भी लिखना चाहिए।

मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से बजट के अंदर इन्होंने सबसे पहले सात संकल्प जो लगाये हैं, पहला संकल्प- नीरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीक प्रधान। माननीय सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान की बात करें तो जिस प्रकार आपने नीरोगी राजस्थान के अंदर अच्छा एक करके बजट के अंदर घोषणा और ऐसे संकल्प जो लेते हैं, मैं उस संकल्प के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो पीएच.सीज. खुले हुए हैं, सी.एच.सीज. खुले हुए हैं, अस्पताल हैं, उनके अंदर डाक्टर्स नहीं हैं, ए.एन.एम., जी.एन.एम. नहीं है, स्टाफ नहीं है, उन पदों को कम से कम भरने के लिए आप संकल्प लेते तो अच्छा लगता और सब मरीजों का इलाज होता। मैं किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा हूं, सब जगह पर यह हालत है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

हमारे ब्यावर के अंदर भी आज अमृतकौर अस्पताल हो, चाहे पी.एच.सी., जवाजा हो, सी.एच.सी., जवाजा हो, सी.एच.सी. टाड़गढ़ इन सभी के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं, आप भरने के लिए कष्ट करें। अमृतकौर अस्पताल, अब जैसे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आप चलाने की बात कर रहे हैं। शुद्ध के लिए, इंसान को स्वस्थ रखने के लिए खाने में, पीने में सब चीज की मिलावट आ रही है। आपके हर चीज, तेल के अंदर मिलावट आ रही है, दूध नकली आ रहा है, मावा नकली आ रहा है, केस आप पकड़ते हैं तो किसी को आज तक सज़ा हुई क्या? सज़ा देने की हिम्मत नहीं है। यह कहीं संकल्प लेते तो हमें अच्छा लगता कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर यह जो संकल्प लिया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, उसके लिए हम भी धन्यवाद देते।

आज जिस प्रकार से स्कूलों के अंदर पीने के पानी के लिए बात कर रहे हैं। पीने के पानी के लिए जो संकल्प ले रहे हैं, हमारे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर के बांध का पानी हर गांव तक पाइप लाइन्स डल चुकी हैं और डल भी रही है, वह भी स्लो गति से चल रही है, वह भी तेज गति से चलानी चाहिए और कम से कम जो पानी जहां पर पहुंच रहा है, वह भी घर-घर के अंदर नल नहीं दिये जा रहे हैं। जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अंदर भी यह कहा है कि हम घर-घर के अंदर नल लगवाएंगे, यह घोषणा माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी कर रखी है और मुख्य मंत्रीजी ने भी की है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन पानी के लिए घर-घर में कनेक्शन के लिए भी आपको आदेश जारी करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

जिस प्रकार आप व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो व्यवस्था सुधारने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बात कह दी है, कानून-व्यवस्था की बात को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि हर जगह पर वह ही घटनाएं हो रही हैं। ब्यावर में भी कोई नई नहीं है।

आज यह अतिक्रमण के लिए कह रहे हैं। शहरों के अंदर बसावट की बात कर रहे हैं तो आपका जो डी.एल.बी. बना हुआ है, माननीय सभापति महोदय, सब जगह की यह हालत है कि डी.एल.बी. के अंदर कहीं भी अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, अतिक्रमण होता है तो वहां से आयुक्त के द्वारा शिकायत भेजकर डी.एल.बी. भेज दी जाती है और डी.एल.बी. के

(श्री शंकर सिंह रावत)

अधिकारी, उनकी सैटिंग होती है, कौनसी स्वीकृति है, ले जाइए न, पैसा फेंको और तमाशा देखो। इस खेल को कम से कम बंद करना चाहिए। आज छोटी-छोटी गलियों के अंदर कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। कहीं पर कोई आगजनी हो जाती है तो वहां पर कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती है। उस जगह पर अपने काम्प्लैक्स चल रहे हैं, स्वीकृति यहां से मिल जाती है। जो हाई-वे की जमीन है, उसके ऊपर भी काम्प्लैक्स हो जाते हैं। जीरो सेटबैक छोड़ कर बिल्डिंग्स का निर्माण हो जाता है, चाहे उसके बाद में पीछे उनके जगह खाली पड़ी रहती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, इसमें कम से कम सुधार होना चाहिए।

ब्यावर की मैं बात करूं तो अस्पताल रोड के ऊपर, रोड पहले से ही संकरे हैं और उनके ऊपर भी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर हम कितने भी पार्षद चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डी.एल.बी. से उनको परमिशन मिल जाती है। क्या करेगा वह आर्डर, क्या करेगा वह आयुक्त? पार्टियां डाइरेक्ट यहां से आकर ले जाती हैं। इस डी.एल.बी. के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, तब जाकर शहरों की दशा सुधरेगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

पीने के पानी के लिए जल संसाधन विभाग से हमारे जवाजा फीडर का कार्य पूरा हो चुका है लेकिन चुलियादेह बांध से आंवा का काम है, वह अभी भी अधूरा है, वहां से एस्टीमेट बन कर यहां पर पहुंच चुका है लेकिन यहां से विभाग द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है उसको भी जारी करवाने के लिए हमारा निवेदन है।

आज माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपने दिनांक 14 फरवरी, 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स से बात की थी। आपने अजमेर जिले के कलेक्टर और सी.एम.एच.ओ. से नाराजगी भी प्रकट की थी। मैं उसका उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने आदेश निकाले हैं, आदेश क्रमांक 1259, दिनांक 01.05.2019 और दूसरा आदेश निकाला है, आदेश क्रमांक 16-17 और 2011, यह निकले हैं, 30.04.2018, अब यह दोनों की क्रियान्विति अब तक नहीं हुई है। इन आदेशों के तहत ब्यावर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का

(श्री शंकर सिंह रावत)

पद रिक्त होने से जिला क्षय रोग कार्यालय के दस अधिकारी का जो स्टाफ है, वह अजमेर में ही बैठा हुआ है।

**श्री सभापति**: आप दो मिनट में समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करें।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): इसके दो-दो बार आदेश निकाल चुकी है यह सरकार लेकिन अभी तक भी वह अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि उन अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाएं कि वह कम से कम वहां पर ब्यावर में आये और वहां पर क्षय रोग कार्यालय के अंदर पूरा स्टाफ खाली है और पत्थर पीसने की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा उस क्षेत्र के अंदर हैं, माननीय सभापति महोदय, ताकि उन गरीबों का इलाज हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है।

साथ में, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह कहा है कि जिस प्रकार बजरी के लिए, बजरी माफिया का आज एक गिरोह बना हुआ है। उसके अंदर जिन काश्तकारों के पास में नदी के पास में अपनी काश्तकारी की खातेदारी जमीन है, उसके अंदर लीज अलाट होने के लिए भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन काश्तकारों को भी यह लीज अलाट हो और वह बजरी की समस्या हल हो।

रोड के लिए, जिस प्रकार ब्यावर शहर के अंदर सड़कों की जो दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा के लिए माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, जो हमारे उप-मुख्य मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों की क्वालिटी बिलकुल घटिया हो रही है और जो कार्य चल रहा है, कम से कम उनको पांच साल हो गया, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है और उसका पैसा नहीं पहुंचने की वजह से अभी तक भी ठेकेदार कह रहे हैं हमारा पेमेंट नहीं पहुंच रहा है, इस कारण से उन्होंने काम को रोक रखा है। काम में कोई गति नहीं है। इसके साथ ही, रोड के दोनों तरफ नाला निकले, तभी जाकर वह गौरव पथ सही बन पाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मिसिंग लिंक सड़कें इस सरकार ने एक भी किलोमीटर की नहीं दी हैं, कम से कम 15-20 किलोमीटर की पहले सड़कें मिलती थीं। इस प्रकार दूसरा बजट भी हो गया है।

**श्री सभापति**: समाप्त करें।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): अभी तक भी नहीं आयी है और

(श्री शंकर सिंह रावत)

विधायक कोष से कोई भी काम होता है, जिस प्रकार हमारे यातायात मंत्रीजी अभी कह रहे थे कि वहां पर विधायक कोष से पैसे खर्च करो।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): विधायक कोष तो बढ़वाओ कम से कम। हर जगह पर विधायक कोष से काम करवाया जा रहा है। सभापति महोदय, इसलिए बजट के अंदर ब्यावर को जिला बनाने के लिए मांग करता हूं और यह बरसों पुरानी मांग है कि ब्यावर जिला बने। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बजट पर रिप्लाई देंगे तो निश्चित रूप से ब्यावर को जिला बनाने के लिए घोषणा करेंगे। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

**श्री सुदर्शन सिंह रावत** (भीम): माननीय सभापति महोदय, बजट के ऊपर आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सात संकल्पों के द्वारा राजस्थान के विकास के परिदृश्य को तय किया। नीरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीक प्रधान, राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और युवा का विशेष ध्यान रखा और मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट राजस्थान को समृद्ध करने वाला और राजस्थान की हैप्पीनैस इंडेक्स को बढ़ाने वाला होगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ की बरसों पुरानी समस्या पीने के पानी की जो समस्या थी, उसका समाधान करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में उसकी डी.पी.आर. की स्वीकृति के आदेश दिये, इसके लिए मैं पूरे भीम-देवगढ़ की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि के क्षेत्र में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवगढ़ में स्वतंत्र मंडी का प्रस्ताव किया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। राजसमंद जिले के समस्त उद्यमियों की तरफ से, जो राजसमंद जिले के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रीको कार्यालय

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

की घोषणा की, जो कई सालों से हमारे उद्यमियों की मांग थी, उसको लेकर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले बजट में जो हमारे यहां पर युवाओं की रोजगार की समस्या, इलाके में उद्योग-धंधों की समस्या थी, उसके लिए बग्गड़ में देवगढ़ के अंदर कामली घाट चौराहे पर रीको की स्थापना की घोषणा की, जिसके आदेश भी अब जारी हो गये हैं। इससे जल्द से जल्द रीको का कार्य होगा, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं और वहां ग्रेनाइट पार्क की एक स्थापना होगी, क्योंकि हमारे इलाके में प्रचुर मात्रा में ब्लैक ग्रेनाइट की अवेलेबिलिटी है तो इसीलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का पुन: धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी क्षेत्रों में अपना ध्यान दिया, पर जिस इलाके से मैं आता हूं, जिस राजसमंद जिले से मैं आता हूं, वहां की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। इलाके में जैसाकि आपको विदित होगा, माननीय सभापति महोदय, कि हमारे इलाके का ग्राउंड वाटर बहुत बुरी तरह से ओवर एक्सप्लायटेड था, जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल था, वह भी फ्लोराइड वाला था और किसी तरह के कोई पीने के पानी की व्यवस्था कई वर्षों से नहीं हो पायी। राजसमंद की जनता, विशेष तौर पर पूर्ववर्ती सरकार को राजसमंद की जनता ने चार-चार विधायक चुनकर भेजे और उसमें राजसमंद के लिए खुशी की बात तो तब हुई थी कि जब 2014 में राजसमंद से आने वाली विधायक को मंत्री बनाया और वह भी पी.एच.ई.डी. का मिनिस्टर बनाया। पूरे इलाके में खुशी छाई, परन्तु वह काफूर हो गयी, क्योंकि पांच साल के उस कार्यकाल में राजसमंद जिले के पीने के पानी की समस्या का कतई समाधान नहीं हुआ और मैं यूं कहूंगा कि आज जो सारे विपक्ष के सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि माननीय पायलट साहब और गहलोत साहब के संबंध ठीक कराओ। अगर उस समय मेवाड़ की जो बीजेपी की पालिटिकल डायनामिक्स है, पावर स्ट्रगल ठीक होती, तो हमारे राजसमंद जिले को आज पीने के पानी से महरूम नहीं होना पड़ता, मोहताज नहीं होना पड़ता। पावर डायनामिक्स को अगर आप उस समय ठीक रखते और मेवाड़ में किसी भी तरह से राजसमंद में पानी लाने का प्रयास किया होता तो लोग आपको धन्यवाद देते।

माननीय सभापति महोदय, आप यह देखिए कि पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर उसी जिले से थे और कोई प्रयास नहीं हुआ। 2014-15 का बजट

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

एज ए पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर उन्होंने यहां देखा। बजट के अंदर एक शब्द भी राजसमंद के लिए नहीं बोला गया। इसकी मैं कठोर भर्त्सना करता हूं। 2015-16 में जनता को भ्रमित किया गया और देवास-फोर्थ का राजसमंद डैम में पानी लाने की बात कही गयी, उसकी डी पी आर बनाने की बात कही गयी। उसके बाद 2016-17 में देवास-थर्ड के लिए फिर कहा कि फर्स्ट फेज की डी पी आर के लिए 1,064 करोड़ रुपये देंगे, पर एक भी रुपया नहीं आया। 2017-18 में तो हद हो गयी, जब बीजेपी की सरकार ने घोषणा की कि हमने 13,473 करोड़ रुपये स्टेट के अंदर पेयजल योजनाओं में खर्च किये तो राजसमंद जिला शर्मिन्दा हुआ। वहां के पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर होने के बावजूद एक रुपये राजसमंद जिले को 13,473 करोड़ में से नहीं दे पाये। तीन साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी की सरकार ने पेश किया था। उसके बाद 2018-19 में फिर आपने गुमराह करने के लिए कहा कि हम माही से पानी लाएंगे। आपने कितनी बातें कीं, कभी जाखम बोला, कभी माही बोला। हमें मालूम है जाखम से पानी नेता, प्रतिपक्ष लाने नहीं देंगे, क्योंकि वह उदयपुर की जनता के लिए प्रतिबद्ध थे पर राजसमंद की जनता भी पीने का पानी मांग रही थी। कहां माही और कहां भीम, हमारा भीम विधान सभा क्षेत्र ब्यावर और अजमेर जिले से अड़ा हुआ है। कहां हमको माही से पानी लाने की बात कही। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यावहारिक बात कही और रीजनेबल बात थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र का 80-90 प्रतिशत एरिया भीलवाड़ा जिले से लगा हुआ है, जहां पर सब जगह चम्बल का पानी आ गया है। उसमें से पानी लाना आसान था।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहूंगा कि आपको कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकारों से सीखना चाहिए कि कैसे पेयजल योजनाओं पर काम किया जाता है, कैसे माननीय गहलोत साहब ने और सबने मिलकर इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर काम किया। कैसे सी.पी. जोशी साहब जब नाथद्वारा से विधायक थे तो बाघेरी नाका बना, उस बाघेरी नाका से आज नाथद्वारा शहर पानी पी रहा है। कैसे भीलवाड़ा से जब सी.पी. जोशी साहब सांसद बने और अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, तो 2009-10 में भीलवाड़ा के लिए चम्बल के पानी की घोषणा की गयी। 2010-11 में अभी आमेट से हमारे आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पीने के पानी की बहुत समस्या है। पांच-पांच साल आपको सरकार मिलती है, सत्ता

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मिलती है, आप मंत्री बनते हैं और उसके बाद भी उस इलाके के लिए काम नहीं होता तो वह बहुत दुख की बात है। माननीय धर्मनारायण जोशी जी भी बोल रहे थे कि मावली में भी पानी नहीं आया, तो क्या मेवाड़ के सभी लोगों को पानी से बेदखल रखा गया और पानी नहीं दिया गया, यह सोचने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य शंकर सिंहजी बोल रहे थे तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। शंकर सिंहजी, आपको माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहिए था। आपने एक पद-यात्रा निकाली ब्यावर से जयपुर तक, आपने जिला बनाने के लिए पद-यात्रा निकाली। परंतु गांधीवादी मुख्य मंत्री की देन थी कि आपको जिला तो नहीं दिया, पर बीसलपुर का पानी देकर आपको जयपुर से भेजा था। आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इस सदन में देना चाहिए था और उस घोषणा के अंदर आपको यह दिया गया 2013-14 के अंदर। इसीलिए आज आप गहलोत साहब के लिए बात करते हैं तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने जिसने जब चाहा, जो मांगा, पर मांगना तो पड़ेगा। विपक्ष के कई साथी बोल रहे थे कि हमको नहीं दिया, हमारे से नहीं पूछा। मुख्य मंत्रीजी के पास आप एक बार बोलोगे तो सही। माननीय शंकर सिंहजी से आप पूछिए, इनको जल मिला कि नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। आज 2017-18 में भी आप ला सकते थे। चम्बल फेज-टू चल रहा था। चम्बल फेज-टू से ही कनेक्ट कर देते भीम-देवगढ़ को, तो हम मानते कि पूर्ववर्ती सरकार की नजर में राजसमंद जिले का कोई मान था। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चम्बल के लिए डी.पी.आर. दी है और यह पासिबल काम है। हमें आस बंधी है कि एक बड़ी जल योजना हमारे भीम और देवगढ़ के लोगों को मिलेगी। जैसे कि हिण्डोली में पिछली बार डी.पी.आर. दिया और इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके लिए 900 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। मैं भी यह मांग करता हूं माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर यहां बैठे हैं कल्ला साहब, कि हमारे लिए डी.पी.आर. बनने के बाद में भीम और देवगढ़ के लिए जल्द से जल्द फाइनेंशियल सैंक्शन निकले, जिससे जनता की 50-60 साल पुरानी मांग स्वीकृत हो और हमारी जनता पीने का पानी पी सके।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की बात हो रही थी। जल जीवन मिशन के लिए कहना चाहूंगा, साढ़े तीन लाख करोड़ का फण्ड है। भारी-भरकम फण्ड है और सौभाग्य से फिर वही जो राजसमंद में हुआ था, राजस्थान से ही है जल शक्ति संसाधन के मंत्री भी, तो मैं यह अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों से, विपक्ष के हमारे साथियों से, कि 25 सांसद आपके भी जनता ने चुनकर भेजे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की जनता को पीने के पानी के लिए 50 प्रतिशत स्टेट ग्रांट की जगह 90 प्रतिशत देने के लिए अनुरोध किया है, क्या हम लोग सब एकजुट होकर के नहीं जा सकते? राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए हम लोग सब मिलजुल कर जाएं और आप और हम मिलकर के केन्द्र सरकार से, केन्द्र के मंत्री से इसकी मांग करें कि साढ़े तीन लाख करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा हिस्सा राजस्थान को मिले, इस मरुस्थलीय प्रदेश को मिले जिससे कि हमारे यहां के पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके।

पिछली सरकार के कार्यकलापों की बात करें तो उन्होंने ज्यादातर वह सारे प्रोजेक्ट्स डिसकंटीन्यू किये जो कि पिछली सरकारों ने किये, इससे हमारा फाइनेंशल मैनेजमेंट खराब होता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यह देखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाना है। विपक्ष के कई साथी बोल रहे थे कि बजट में यह नहीं मिल रहा, वह नहीं मिल रहा, हम लोग एक फैडरल स्ट्रक्चर आफ गवर्नेंस में काम करते हैं, जो केन्द्र में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है उससे हम अपने आपको विमुख नहीं रख सकते, उससे अलग नहीं रख सकते। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, वह आपके सामने दिख रही है।

**श्री सभापति**: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री सुदर्शन सिंह रावत** (भीम): इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग और हम लोग सब मिलकर के एम्प्लायमेंट के ऊपर काम करें, इकोनोमी के बैटरमेंट के ऊपर काम करें और इस तरह की बेहतरी के लिए काम करें जिससे हमारे राज्य में और हमारे इलाके में सब कुछ अच्छा हो सके।

मनरेगा जैसी योजना के लिए कई महीनों से, चार महीनों से सेंटर से

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

पैसा नहीं आया था, अभी पांच-दस दिन पहले ही सेंटर से वह पैसा आया है, मजदूरी का पैसा नहीं जा रहा था तो कम से कम इन मामलों में तो हम पक्ष और विपक्ष के साथी भेदभाव भुला करके आगे ऊपर उठें।

राजस्थान की लोक कल्याणकारी सरकार, माननीय मुख्य मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा 10 हजार करोड़ की कटौती के बावजूद कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि 12 हजार करोड़ का राजस्व घाटा प्रस्तावित किया गया है।

मैं हमारे इलाके की दो बातों को करके मेरी बात को समअप करूंगा। माननीय सभापति जी, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, यह भी एक बहुत गंभीर समस्या है। हमारे इलाके में जो छोटी काश्त है, एक बीघा, दो बीघा, पांच बीघा के काश्तकार हैं और उनके लिए थ्री फेज एग्रीकल्चर कनेक्शन न तो काम का है न उनको मिलने वाला है तो मैं चाहूंगा कि सरकार राजसमंद जिले के लिए विशेष तौर पर सिंगल फेज एग्रीकल्चर कनेक्शन की व्यवस्था कराए जिससे कि किसानों को फायदा हो सके।

मैं हमारे यहां भीम और देवगढ़ में मैं 25-25 बैडेड अस्पताल की मांग करता हूं। जो भी विद्यालय बंद हुए थे उनको सरकार ने पुन शुरू किया, वो एक सराहनीय कदम है, हम उनकी सराहना करते हैं।

डी.एम.एफ.टी., निश्चित तौर पर मैं भी इस बात की मांग करता हूं कि डी.एम.एफ.टी. का फंड जनप्रतिनिधियों को और जनता की मांग के लिए इसमें जो भी मसला है उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए जिससे हमारे जिन जिलों में हमारे पास डी.एम.एफ.टी. फंड अवेलेबल है, उसमें हम कर सकें। हमको मिसिंग लिंक की सड़कें मिलें। संविदाकर्मियों की मांगों पर ध्यान दिया जाए और नरेगा मद से स्कूलों में खेल मैदान बनें।

मैं आखिरी बात बोलूंगा। कल मैं एक बात सुन रहा था, शहीद स्मारक के लिए भी माननीय सदस्या ने कहा था, उसी राजसमन्द जिले में एक शहीद शेखावास में भी हुए थे और उस शेखावास के शहीद के लिए मैंने भी मेरे विधायक कोष से फंड दिया, नरेगा से भी हुआ और वन क्षेत्र में आज 50 लाख रुपये की स्वीकृति शहीद स्मारक के लिए बनी है। इसलिए कुछ कदम तो हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर हम शहीद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम विधायक कोष से भी कुछ दें जिससे शहीदों के लिए हमारा मान सम्मान बढ़े।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

आपने बोलने का मौका दिया, सरकार के इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और इतना शानदार बजट दिया, उसके लिए मुख्य मंत्री जी का पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति**: श्री गोतमलाल।

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 2020-21 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद। जो जनता को उम्मीद थी कि यह बहुत अच्छा बजट आएगा, पहले बजट में कुछ नहीं था लेकिन यह उससे भी और कमजोर बजट है और जनता ठगी हुई महसूस कर रही है।

आपका पहला संकल्प है नीरोगी काया। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर ही आ जाता हूं जहां हमारे पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, लैब टैक्नीशियन सबके पद रिक्त पड़े हैं, यहां तक कि एम्बुलेंस कहीं पर है नहीं और कहीं पर है तो वह खटारा 108 है और वह भी 2 लाख किलोमीटर चलकर हैं और एएनएम के जो उप-स्वास्थ्य केंद्र पर है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी वसुन्धरा जी की सरकार में सब पद भरे हुए थे लेकिन यह सरकार आते ही सबके ट्रांसफर कर दिये और वहां पर आप कितनी भी फ्री दवाई दो लेकिन वहां पर दवाई देने वाला कोई नहीं है। मैं अभी आपको एक ताजा उदाहरण दूंगा कि हमारे ट्राइबल बैल्ट में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। मैं उदयपुर की जिला कलेक्टर आनंदी बहन को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने गांवों में जाकर सर्वे किया और पंचायत समिति स्तर पर चार-पांच दिन का शिविर लगाकर उन बच्चों को दवाई दी और एक शिविर में मैं खुद भी गया था तो बात यह है कि वहां पर उनको दवाई और गोली देने वाला कोई नहीं है। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माननीय वसुन्धरा जी ने ...

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): एक साल से नहीं है या पहले से नहीं है?

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): एक साल से संख्या ज्यादा बढ़ी है। इतने ट्रांसफर कर दिये कि जहां दो एएनएम थी वहां पर आज की तारीख में एक भी नहीं है और डाक्टर्स का भी ट्रांसफर कर दिया। (व्यवधान) वह तो आपके पास रिकार्ड है देख लेना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मंत्री जी, आप खाली हमारा समय खराब मत करना।

(श्री गोतमलाल)

पिछली सरकार वसुन्धरा जी ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जहां पर लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि अब हमारे कोई गारंटी है, तो वसुन्धरा जी सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में ...(व्यवधान) मंत्री जी, ध्यान रखना फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, बीच में नहीं।

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): वहां पर 30 हजार से 3 लाख रुपये तक का बड़े अस्पताल में जो लोगों का इलाज हो रहा था तो कई लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया था, आपने उस योजना को बंद कर दिया। अगर मान लो उस पर मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी का फोटो था तो आपका फोटो लगा देते पर उस योजना को आपको बंद नहीं करना चाहिए था, उसको बंद करके आपने गरीबों के साथ में धोखा किया है। आप यह नीरोगी राजस्थान चाहो तो इसमें सबसे पहले आप स्टाफ लगाओ, डाक्टर्स वगैरह जो भी हैं वह करवाओ। यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा, आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद में कृषि मंडी की घोषणा की है लेकिन मैं सरकार की जानकारी में लाऊंगा कि वर्ष 1990 में धरियावद में सब यार्ड कृषि मंडी खुली थी और जमीन भी अवाप्त कर दी थी, उन खातेदारों ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया और वह मामला 30 साल से कोर्ट में पड़ा है। मेरे से पहले भी जो भी माननीय एम.एल.ए. बने, उन्होंने भी प्रयास किया और मैं भी 15-16 साल से इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। 2008 के पहले यह थे उदयपुर में और 2008 के बाद में प्रतापगढ़ में हैं लेकिन उन अधिकारियों ने खाली चक्कर लगाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। किसी ने न तो जिम्मेदारी से कोई वकील किया, कुछ नहीं है, 30 साल से वह केस आज भी कोर्ट में अटक रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि किसी जिम्मेदार अधिकारी को लगाकर कोर्ट में उस केस का फैसला कराएंगे तो हमारे वहां पर हमारे किसानों को उसका फायदा जरूर मिलेगा।

किसानों के लिए आपने घोषणा की कि सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे और युवाओं को 3500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन वसुन्धरा जी की सरकार ने 50 हजार रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ किया, आपने कहीं पर भी कर्जा माफ नहीं किया और न किन्हीं लोगों को आपने भत्ता दिया।

(श्री गोतमलाल)

आप खाली असत्य बोलकर सत्ता में आ गये और हमारा जो विकास का काम हो रहा था उस विकास के काम को भी आपने रोका है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में लसाडिया, झल्लारा में आपने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोलने का इसमें लिया है लेकिन यह घोषणा केवल घोषणा ही रह जाएगी क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुन्धरा जी ने मेरे लसाडिया में एक कालेज खोला था, हमारे मंत्री जी किरण माहेश्वरी जी भी यहां बैठी हैं, उसका शिलान्यास हो गया और उसका काम भी शुरू हो गया, दो साल में प्लिंथ लेवल तक काम हो गया लेकिन अब वह काम धीरे-धीरे रुक गया। कभी 15 दिन चलेगा तो एक महीने बंद रह जाएगा और अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है जबकि उसमें 6 करोड़ का बजट था और 6 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गये, टेंडर होने के बाद में भी उसमें अभी तक भी मुझे नहीं लग रहा कि दो साल पहले वह काम हो सकता है।

पिछली सरकार ने जनजाति क्षेत्र में भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्य एवं विषय अध्यापक के रिक्त पद भरे थे, वर्तमान सरकार ने ट्रांसफर करके उन विद्यालयों में सारे के सारे, अब बहुत सारी जगह प्रिंसिपल भी नहीं हैं, हमारी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने हर पंचायत हैडक्वार्टर के ऊपर बारहवीं तक के स्कूल किये और पद भी भरे लेकिन आपने आ करके वहां पर शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। बहुत सारी स्कूलों के अंदर प्रधानाचार्य के पद भी आज की तारीख में बिल्कुल खाली पड़े हैं। आप विकास की बात करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वसुन्धरा जी ने बहते हुए पानी को रोकने के लिए मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना लागू की थी, आपने उसका नाम बदल करके राजीव गांधी जल संचय योजना कर दी। नाम बदल दिया कोई बात नहीं लेकिन थोड़ा-बहुत भी कोई काम तो करते, कोई भी काम नहीं किया। मेरे क्षेत्र में जो पानी था, वह बहकर के समुद्र में चला जाता था। वहां इतना विकास का काम हुआ। उसमें लोगों ने बढ़चढ़कर के काम किया। भामाशाहों ने भी काम किया। हर डिपार्टमेंट ने काम किया। उसका फायदा यह हुआ कि 300-400 फीट पर जो पानी नहीं आता था, वह 150-200 फीट पर

(श्री गोतमलाल)

पानी आने लग गया था। उस योजना का आपने नाम बदला, लेकिन काम नहीं किया।

सभापति महोदय, जब भी देखो तो खजाना खाली। लोगों का वैसे तो कांग्रेस के प्रति विश्वास उठ गया है। मैं अभी 2-4 दिन पहले गांवों में गया था। सलूम्बर से बीड़ावल तक की सड़क में 3-3 फीट तक के खड्डे पड़े हुए हैं। मैं वहां गया था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप यह काम करवाओ। हमने आपको वोट देकर के, जिता करके भेजा है। मैंने कहा कि आपने मुझे इसलिए जिता करके भेजा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा मुख्य मंत्री बनेगा। लेकिन गलती से वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई और मुख्य मंत्री अशोक गहलोत बन गए। आपको मालूम है कि जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत बनेंगे तो खजाना तो खाली होना ही होना है।

सभापति महोदय, प्रदेश में आए दिन संविदा कर्मी, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना, प्रदर्शन रहता है। जो पंचायत सहायक हैं, उनको 6 हजार रुपया मिलता है। अब उनका कैसे गुजारा हो? अब उनका या तो मानदेय भत्ता बढ़ाएं अथवा उनको नियमित करें।

सभापति महोदय, सभी किसानों को 1 अप्रैल, 2023 तक चरणबद्ध तरीके से दिन में बिजली दी जाएगी। मेरे धरियावद विधान सभा में तो दिन में ही नहीं, रात को भी कब जाती है पता नहीं चलता। सुबह ही वापस आती है। दिन को बिजली आती ही नहीं है। ट्रांसफार्मर्स बदलने का जो आपका तरीका है उसमें किसान एक-एक महीने तक चक्कर काटते रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी के लिए भी कहूंगा। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी ने क्या किया? प्रधान मंत्री जी ने बड़े-बड़े काम किये हैं। धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, हम कभी नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन हम भी सोचते थे कि यह कभी होगा कि नहीं होगा। उन्होंने उसको करके दिखाया है। राम मंदिर का मुद्दा हो गया। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। गरीब कभी सोचता नहीं था कि हमारे भी पक्का मकान होगा। कभी शौचालय होगा। बिजली का बल्ब लगेगा। इसके अलावा जो उन्होंने बड़ा काम किया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं साल भर की लकड़ियां सर्दियों में माथे पर ढोकर के लाती थीं। साल भर की लकड़ियां वह इकट्ठा करती थीं। बरसात के मौसम में

(श्री गोतमलाल)

उन लकड़ियों के धुएं से उनको परेशानी होती थी, लेकिन प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उस गरीब को भी गैस का कनेक्शन देकर के उन माता-बहनों के माथे पर जो भार होता था, उसको उतार दिया। उसको कहने में तो आपको शर्म आती है।

सभापति महोदय, नोटबंदी के पहले जब आप जाते थे और गाड़ियों में तेल भराते थे तो वहां नोट को दस बार देखते थे कि असली है कि नकली हैं। जो पाकिस्तान से आतंकवादी लोग आते थे वह नकली नोट लाकर के फिर यहां पर धमाका करते थे। आपको पता नहीं है क्या कि यहां जयपुर में भी धमाके हुए थे? जो बढ़िया काम हुए हैं, उनके लिए प्रधान मंत्री जी की आपको तारीफ करनी चाहिए।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): सभापति महोदय, कल भी 8 बजे तक इंतजार किया। गौरव पथ हमारी सरकार ने बनाए थे। गांव के गौरव थे। आपने नाम बदलकर विकास पथ कर दिया, लेकिन एक भी विकास पथ नहीं बना। मुझे लगता है कि आगामी 3 वर्षों में भी कहीं बनने वाले नहीं हैं। नहीं बने तो भी कोई बात नहीं।

डीएमएफटी का जो बजट है, इसमें हमारे गुलाब जी भाई साहब ने और सबने मिलकर के काम स्वीकृत कराए। वहां पर काम शुरू भी हो गए। गिट्टी भी पड़ गई। जिला कलेक्टर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी पावर हटा दी गई हैं। वहां पर अब आपको प्रभारी मंत्री पैसा देंगे। अब हम प्रभारी मंत्री को कहां ढूंढते फिरेंगे? वहां काम स्वीकृत हो गए, वहां गिट्टी पड़ गई। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो गए हैं।

सभापति महोदय, फसल खराबे के बारे में मैंने एक तारांकित प्रश्न लगाया था। मंत्री जी ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने माना कि 33 से 70 परसेंट तक खराबा हुआ। काश्तकारों की संख्या भी एक लाख से ऊपर दी है। इस खराबे का पैसा किसानों को कब तक मिलेगा? यह उसमें कहीं पर भी नहीं बताया है। कम से कम उन किसानों को खराबे का पैसा मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, अब टोंटी कब लगेगी? घर-घर पानी मिलेगा। वह तो मिलेगा लेकिन गर्मी के समय में हैंड पंप खराब हो जाते हैं। पुराने हैंड पंप

(श्री गोतमलाल)

मिस्त्री रिटायर हो गए हैं। एक-एक हैंड पंप मिस्त्री के लिए 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतें रहती हैं।

**श्री सभापति**: कितनी देर और बोलना है?

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): यह समस्या सभी के है। मेरे अकेले के ही नहीं है। हैंड पंप मिस्त्रियों की सरकार भर्ती करे। एक पंचायत में कम से कम एक हैंड पंप मिस्त्री होगा तो जनता वहां पानी पी सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र में आपकी नल योजना कब शुरू होगी? यह योजना शुरू होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कब होगी? लेकिन इससे पहले इनकी आप भर्ती करें।

सभापति महोदय, वन मंत्री चले गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3-4 वन क्षेत्र आते हैं। सीता माता सैंक्चुअरी, धरियावद वन क्षेत्र, धरियावद, बानसी और सलूम्बर का हिस्सा भी आता है। वहां पर तेंदूपत्ता का टेंडर होता है। हर साल करोड़ों रुपये का टेंडर ठेकेदार लेते हैं। मई में जब टेंडर खुलता है, तब वह जल्दी पत्ते के लिए जंगल में आग लगा देते हैं। वन विभाग के पास में कोई साधन, सुविधा नहीं होती है। उसमें कई जानवर मर जाते हैं। मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। वह पैसे जा कहां रहे हैं? वह पैसा किस फंड में जा रहा है? जिस वन क्षेत्र से पत्ते तोड़ते हैं, वहां वह पैसा लगे। वहां और पेड़ लगाएं। वह पेड़ लगाने का काम नहीं करते हैं। उसमें आग लगाने का काम करते हैं।

**श्री सभापति**: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): सभापति महोदय, मैं तो समाप्त ही कर रहा हूं। मैं तो काम की ही बात कर रहा हूं। दूसरी कोई बात कर नहीं रहा हूं। जो सही बात है, वही कह रहा हूं। अगर उसमें भी आपको कोई तकलीफ है तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय, मेरा यह है कि उस पैसे का कम से कम सरकार हिसाब तो पूछे। चाहे वन मंत्री पूछे या आपके माध्यम से इनका वन मंत्री पूछे। कितने साल से वह टेंडर हो रहा है? करोड़ों रुपये में वहां टेंडर जाता है।

**श्री सभापति**: अब आप समाप्त करें।

**श्री गोतमलाल** (धरियावद): सभापति महोदय, इस बजट में कुछ नहीं है। यह निराशाजनक बजट है। इसका मैं विरोध करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री रफीक खान।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मुझे आपने बजट की चर्चा में बोलने का मौका सबसे आखिर में दिया, लेकिन मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान का बजट एक निरंतर विकास की ओर बढ़ता हुआ बजट है। पारदर्शी, प्रगतिशील, सेवाभावी, दूरदर्शी, औद्योगीकरण की तरफ मुखातिब, रोजगारोन्मुखी बजट हमारे मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक बहुत शानदार बजट दिया है।

सभापति महोदय, यह बजट नहीं, एक तरह से विजन डॉकूमेंट है। हम आने वाले साल में क्या-क्या डवलपमेंट के काम करेंगे? कैसे हम फाइनेन्स को मैनेज करेंगे? किस तरीके से हम राजस्थान को डवलप करेंगे? राजस्थान के डवलपमेंट में 7 संकल्पों का एजेंडा बनाकर के शामिल किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं इसके लिए एक छोटी-सी पंक्ति कहता हूं,

**'बजट नहीं है, यह सुनहरे कल की गौरव गाथा लिखी है,**
**उन बातों का जिक्र नहीं शरणागत हो जहां थकानें, कठिनाइयां,**
**जहां उड़ानें मुक्त रहें, उन आकाशों की कथा लिखी है'।**

इस एक नजरिये के साथ में उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। बहुत सारी बातें आज भी हुई और कल भी हुई। जो सात संकल्प थे उनमें नीरोगी राजस्थान की कल्पना मुख्य मंत्री जी ने की है। बहुत से हमारे साथियों ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर के डिफरेंट डाटा प्रस्तुत किए। पूरे हिन्दुस्तान में, भारतवर्ष में राजस्थान एक ऐसा इकलौता प्रदेश बना है, जिसने यह सोचा कि हम राजस्थान को नीरोगी कैसे करें। क्या फैसेलिटी हम अडाप्ट करें? क्या पालिसी हम अडाप्ट करें जिससे कि आने वाले वर्षों में राजस्थान नीरोगी हो जाए। मैं समझता हूं कि इस बात के लिए इन सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए था, धन्यवाद देना चाहिए था। इस बात में शामिल होना चाहिए था कि नीरोगी राजस्थान के आह्वान में हम आपके साथ हैं, लेकिन मुझे बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि शामिल होना, साथ देना तो दूर, इन्होंने क्रिटिसिज्म में कोई कमी नहीं छोड़ी।

सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे प्रश्न इन्होंने उठाए। आप मुझे यह बताने की कोशिश करें कि अगर राजस्थान की फैसेलिटी में, दवाइयों में इतनी खामियां हैं तो राजस्थान के चारों ओर 3 प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं। क्यों वहां से सारे

(श्री रफीक खान)

मरीज, दो लाख मरीज हर साल राजस्थान, एसएमएस अस्पताल, जयपुर में आते है और यहां से इलाज करवाकर जाते हैं। अकेले हरियाणा और यूपी से एक लाख पेशेंट एसएमएस में दिखाकर जाते हैं, अकेले हरियाणा और यूपी के, तो कुछ तो हम राजस्थान में कर रहे होंगे। आपको यह चाहिये कि आप हरियाणा और यूपी की सरकारों को सीख दो, समझाओ, राजस्थान की जो पालिसी है उस पर चलो। नीरोगी राजस्थान की कल्पना की है उसमें हमारा साथ दो, उससे सीखो और उससे सीख कर वहां भी एडाप्ट करने की कोशिश करो।

माननीय सभापति महोदय, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पहला सुख नीरोगी काया, हमारे पुरखों की दी हुई एक कहावत है और उस पर आधारित बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 14,533 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बहुत सारी क्रिटिसिज्म आयी कि 14,500 करोड़ रुपये का आपने बजट रखा, यह नाकाफी है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार का टोटल बजट है 30 लाख 42 हजार 230 करोड़ रुपये। वहां केन्द्र की सरकार बजट दे रही है, 69 हजार करोड़ रुपये, हमारा बजट है 1 लाख 84 हजार करोड़ रुपये। हम बजट दे रहे हैं 14 हजार करोड़ रुपये, कोई कम्पेरिजन ही नहीं है। अच्छा होता कि आप केन्द्र सरकार को रिकमण्ड करते कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने बजट दिया है, केन्द्र सरकार भी उतना रिजर्वेशन, उतना बजट स्वास्थ्य के लिए, हैल्थ के लिए अलाट किया जाये तो पूरे देश में एक स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे ऐब इन्होंने गिनाये, हमारा बजट 7 परसेंट है, केन्द्र का बजट 2 परसेंट है। यूपी और हरियाणा के दोनों के पेशेंट मिलाकर हमारे खाली एसएमएस में एक लाख है। अगर आप पूरे राजस्थान की बात करोगे तो पेशेंट की संख्या कितनी निकलेगी, आजकल तो ऑनलाइन है। आप देख सकते हैं कि यूपी से कितने आ रहे हैं, हरियाणा से कितने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हरियाणा और यूपी में जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो इसलिए वे राजस्थान आते हैं और राजस्थान से इलाज कराकर जाते हैं। (व्यवधान) राजस्थान में आ रहे हैं और यहां से इलाज कराकर जा रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर बात कह रहा हूं, आपकी तरह से हवा में बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) आपने जैसे बात की, उस तरह से हवा में बात नहीं की है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: शांत रहें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, अहमदाबाद तो आप जैसे पैसे वाले जाते हैं, गरीब आदमी तो यहीं आता है। घुटनों का इलाज करवाते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप डाइरेक्शन अपना इधर रखिये, इधर-उधर नहीं। आप उनको व्यवधान डालने के लिए इन्वाइट न करें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): नीरोगी राजस्थान, एक संकल्प है जो उन्होंने लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान को अगर थोड़ा बहुत भी कोआपरेशन रहा केन्द्र सरकार का तो आने वाले पांच वर्षों में तमाम तरह की बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेकेंगे। आज कोरोना वायरस चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का भय है, एयरपोर्ट खाली पड़े हैं, चाइना खाली हो गया, बहुत सारी मौतें हो गयीं। इन सबसे पहले एक मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेप लिया और यह कोशिश की कि नीरोगी राजस्थान कैसे हो, आप लोग सीखकर एक चिट्ठी हमारे साथ मिलकर लिखनी चाहिए कि आप हमारे नीरोगी राजस्थान से प्रेरणा लो और केन्द्र में यह लागू करने की कोशिश करो।

माननीय सभापति महोदय, एजुकेशन की बात हुई बहुत सारे ऐब निकाले गये। एजुकेशन में पैसा नहीं दिया, हमें यह नहीं दिया, हमें वह नहीं दिया। सारी चीजें किताब में लिखी है डिटेल डिस्कस करूंगा तो आप मेरा समय काट लेंगे। 39 हजार करोड़ रुपये, कुल 1 लाख 84 हजार करोड़ के बजट में शिक्षा को दिये हैं। इन्होंने क्या दिया 30 लाख करोड़ रुपये के बजट में? इन्होंने 30 लाख करोड़ रुपये के बजट में दिये हैं 99 हजार करोड़ रुपये, हमने दिया हमारे बजट का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा, ये दे रहे हैं 3 प्रतिशत हिस्सा, क्या मैच है? कोई मैच नहीं है, कोई फिगर नहीं है, आप खाली बातें ही करे जा रहे हो हवा के अंदर। जो बात आप यहां कहना चाह रहे हो, वह एक चिट्ठी के अंदर सरकार में भी लिखो कि राजस्थान में शिक्षा के प्रति इतनी अवेयरनैस है, इतना बजट एलोकेट किया जा रहा है तो वहां भी बजट एलोकेट किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक शेर भी कह दिया किसी ने कि जिनके घर शीशे से बने होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अब वहां क्या कहेंगे आप?

(श्री रफीक खान)

माननीय सभापति महोदय, पानी की बात करें। राजस्थान के जयपुर शहर में 165 करोड़ रुपये की एक योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस की, जिसमें पूरे जयपुर की जो जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनें हैं जिसमें मेरी कांस्टीट्यूएंसी का बहुत बड़ा हिस्सा आता है, ब्रह्मपुरी का एरिया आता है, आमेर तक का एरिया आता है और बीसलपुर पाइप लाइन बिछाने का एक नया काम उन्होंने अनाउंस किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बात और सामने आयी कि प्रधान मंत्री योजना का जल जीवन मिशन है। पहले मिशन का नाम था हर घर नल, हर घर नल से सम्भव नहीं हो पाया, यह उस पर कार्य कर नहीं पाये तो इन्होंने उसका नाम जल जीवन मिशन कर दिया। जल जीवन मिशन क्या है कि 2024 तक हम पूरे राजस्थान में हर गांव में पानी का कनेक्शन देंगे, हर आबादी को, तमाम हिस्से को पानी का कनेक्शन देंगे, 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का बजट बना दिया कि 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये लगेगा, यह लागत आयेगी। केन्द्र सरकार बजट क्या दे रही है, वह सुनो आप। केन्द्र सरकार का अभी जो 2020-21 का जो प्रोविजन है वह 11,500 करोड़, जब आपका इतना प्रोविजन है तो आप कहां से 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की योजना को इम्प्लीमेंट कर लेंगे 5 सालों में? मतलब सिवाय जनता को बावळा बनाने के, मूर्ख बनाने के और कोई काम नहीं है? 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की योजना आप अनाउंस करते हो और बजट पूरे हिन्दुस्तान का 11,500 करोड़ रुपये लगाते हो, कोई मैच नहीं करते हैं आपके आंकड़े, यह 50 परसेंट भी मैच नहीं करता, आपको देना 90 परसेंट चाहिए। अच्छा होता कि आप 90 परसेंट की बात करते, हमारे साथ चलते और कहते कि राजस्थान डेजर्ट प्लेस है, हमें यहां 90 परसेंट पैसा मिलना चाहिये। आपके फोर्च्युनेटली जो जल संसाधन मंत्री हैं, वे राजस्थान से हैं, जोधपुर से एमपी हैं, उनकी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी बनती है कि राजस्थान को तो एटलीस्ट 90 परसेंट पैसा वहां से दिलाएं।

माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब ने, अनफोर्च्युनेटली और फोर्च्युनेटली हर बात में राठौड़ साहब का नाम आ ही जाता है इत्तेफाक से, 28 हजार करोड़ को 28 लाख करोड़ रुपये बोल गये। वह वर्ड हटवा लेना आप, इसमें अच्छा नहीं लगेगा कि राजस्थान में बजट में 28 लाख करोड़ रुपये की बात आ जाये क्योंकि 28 लाख करोड़ रुपये के फिगर का किसी तरह से कोई

(श्री रफीक खान)

लेना-देना नहीं है। आपने कहा कि बजट में जो टार्गेट थे, आरई और बीई का स्पेशल इन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि जो टार्गेट था वह 44 हजार करोड़ रुपये था सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन्होंने टोटल बजट जोड़कर बता दिया, मैं इनको थोड़ा डिवाइड करके बता देता हूं कि जो डेफिसिट है, जितना पैसा कम है, वह पैसा स्टेट के राजस्व का नहीं है, 8 हजार करोड़ रुपये का जो लोस आ रहा है, जो कमी आ रही है वह केन्द्र सरकार के राजस्व में आ रही है, जो किताब आप पढ़ रहे थे उसी किताब में लिखा है, उसी पैरे के अंदर 44 हजार करोड़ रुपये का टार्गेट था, आप 36 हजार करोड़ रुपये दे रहे हो। स्टेट के राजस्व में कटौती कर रहे हो और फिर बात कर रहे हो कि आप पूरा पैसा नहीं दे रहे हो, कटौती कर रहे हो, आप पूरा पैसा मिलाकर बोल रहे हो। स्टेट का शेयर 73 हजार करोड़ रुपये था, 70 हजार करोड़ रुपये आ रहा है, 3 हजार करोड़ रुपये की कटौती है, यह 8 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर रहे हैं 44 हजार करोड़ रुपये में। आपको चाहिये कि हमारे साथ मिलो और मिलकर देश की जनता के लिए आवाज उठाओ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, अभी मैं जयपुर की बात कर रहा था। यहां जब भी शाम को बात होती है तो जयपुर का कोई विधायक नहीं होता है, इनकी सिंसियरिटी जयपुर के प्रति नजर आती है। एक भी विधायक पिछले 15 दिन में जब से सिस्टम से सदन चल रहा है, बीजेपी का एक भी विधायक आफ्टर लंच यहां पर मौजूद नहीं रहता है। कल तो फोर्च्युनेटली नेता प्रतिपक्ष और उप नेता भी नहीं थे। आपको यह चाहिये कि हमारे साथ मिलकर आप हमें सहयोग करो और आप बोलो उनको कि कटौती नहीं की जाए, राजस्थान का शेयर पूरा दिया जाए ताकि हम जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना चाहें वह कर सकें। (व्यवधान) मैडम, बैठो आप।

**श्री सभापति**: व्यवधान न करें। (व्यवधान) विराजिये आप।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): बैठो आप, बैठो।

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री सभापति**: अंकित नहीं होगा, विराजिये आप।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): सारी सुनी है, सबको तसल्ली से सुना है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): 000

**श्री सभापति**: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): गुमराह आपने किया है, किताब राठौड़ साहब दिखा रहे थे, वह किताब हाथ में है 44 हजार करोड़, 36 हजार करोड़ रुपये, यह फिगर हाथ में है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, यह फ्री डिबेट है क्या?

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): वह बीच में बोल रहे हैं।

**श्री सभापति**: मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, आप अपनी बात कहें। आसन की तरफ देखकर अपनी बात कहें।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): मैं आप ही को कह रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जीएसटी यह सोच कर लागू किया गया कि पूरे देश में अगर जीएसटी लागू होगा तो स्टेट का शेयर, स्टेट को मिलेगा। (व्यवधान) इयां मत करो।

**(20.00 बजे)**

**श्री सभापति**: हो गया क्या पूरा? नहीं, ऐसे नहीं। तो बोलें फिर।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): सर, बोल रहा हूं। एक कहावत सुनी है...

**श्री सभापति**: चलिए, कहावत पूरी कर दीजिये अब।

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): एक कहावत सुनी है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा है। दिल्ली जल रहा है और हमारे प्रधान मंत्री महिमामंडन में लगे हुए हैं।

**डा. महेश जोशी** (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण तक बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सदन का समय कोई दो-चार मिनट.... (व्यवधान)

**श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): थैंक यू वैरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।

**श्री सभापति**: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनंतर सदन की बैठक 20.00 बजे गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

## श्रीडूंगरगढ़ में संचालित छात्रावास

**199. श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ में छात्रावास संचालित है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त छात्रावास में कितने छात्र हैं? छात्रवार, कक्षावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावास पर 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2020 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावास में विगत पांच वर्षों में मरम्मत और रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त छात्रावास में छात्र संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त छात्रावास में पीने के पानी की समस्या है? यदि हां, तो उक्त के समाधान के लिए क्या-क्या प्रयास किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय अम्बेडकर (अनु. जाति) बालक छात्रावास संचालित है। उक्त छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 40 छात्रों की है, जिसके विरुद्ध 37 छात्र आवासित हैं एवं छात्रावास में आवासित छात्रों का कक्षावार विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | कक्षा का नाम | आवासित छात्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कक्षा 12वीं | 18 |
| 2 | कक्षा 11वीं | 8 |
| 3 | कक्षा 10वीं | 3 |
| 4 | कक्षा 9वीं | 3 |
| 5 | कक्षा 8वीं | 3 |
| 6 | कक्षा 7वीं | 1 |
| 7 | कक्षा 6ठी | 1 |
| | **योग** | **37** |

छात्रावास विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) उक्त छात्रावास में 01.01.2016 से 31 जनवरी, 2020 तक विभिन्न मदों में किये गये व्यय का वर्षवार, मदवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त छात्रावास में विगत 5 वर्षों में मरम्मत और रख-रखाव में कुल राशि 257194 रुपये का व्यय किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। छात्रावास में छात्र संख्या बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि प्रस्ताव प्राप्त होता है तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(5) जी नहीं। छात्रावास में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## भेड़पालकों को मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भेड़ों की मौतों पर सहायता

**210. श्री छगनसिंह** (आहोर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश के होशंगाबाद, इटारसी, खण्डवा आदि के आस पास के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रदेश के घुमन्तु पशुपालकों की अनुमानित संख्या दस हजार के करीब भेड़ों की मौतें हुई थीं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पीड़ित भेड़ पालकों को कोई सहायता राशि दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी नहीं। प्रदेश के घुमन्तु पशुपालकों की प्राकृतिक आपदा से भेड़ों की मौत होने पर सहायता प्राप्त करने हेतु जिलों में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

## शाहपुरा में सहकारी समिति के गोदामों का निर्माण

**212. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

मुख्यालय की ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए गोदाम निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है? यदि हां, तो तत्संबंधी प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के अंतर्गत कितनी सहकारी समितियां कहां- कहां पर कार्यरत हैं और उनमें से किस-किस सहकारी समिति में गोदाम निर्माण हो चुका है और शेष में कब तक गोदामों का निर्माण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यरत नहीं है अपितु राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण का विचार रखती है। गोदाम निर्माण हेतु नवगठित समितियां एवं ऐसी समितियां जिनके पास गोदाम उपलब्ध नहीं है, को प्राथमिकता दी जाती है तथा गोदाम निर्माण हेतु समितियों के पास भूमि उपलब्ध होने एवं समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की बनेड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं एवं उन सभी समितियों में गोदाम निर्मित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा एवं बनेड़ा क्षेत्र में निम्न 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:-

1. खेडलियां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
2. अरनियां घोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
3. देवरियां ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

उक्त समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं तथा समितियों के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

## उदयपुर में जनजाति कल्याण हेतु व्यय राशि

**215. श्री धर्मनारायण जोशी** (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में वर्ष 2018-19 में जनजाति कल्याण हेतु किन-किन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कुल आबंटित बजट की कितनी धनराशि का उपयोग अब तक कर लिया गया है? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मावली में टी.एस.पी. की पंचायतें व उनमें आने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर जिले के अनुसूचित क्षेत्र माडा एवं बिखरी क्षेत्र हेतु विभिन्न कार्यों पर वर्ष 2018-2019 में जनजाति कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र में कुल 1624.17 लाख रुपये तथा माडा एवं बिखरी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) में कुल 344.84 लाख राशि व्यय की गयी। वर्ष 2018-19 में कार्यवार तथा पंचायतवार अनुसूचित क्षेत्र के कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा माडा एवं बिखरी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के कार्यवार तथा पंचायतवार कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उदयपुर जिले के अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं बिखरी क्षेत्र हेतु संचालित योजनाओं में वर्ष 2018-19 में अनुसूचित क्षेत्र में कुल आबंटित बजट 6462.64 लाख रुपये के विरुद्ध 5875.50 लाख रुपये तथा माडा एवं बिखरी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) में कुल आबंटित बजट 457.41 लाख रुपये के विरुद्ध 453.75 लाख रुपये अर्थात् कुल आबंटित बजट 6920.05 लाख रुपये के विरुद्ध 6329.25 लाख रुपये व्यय (हस्तान्तरण अनुसार) किया गया। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) मावली विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति बडगांव एवं पंचायत समिति मावली के टीएसपी की पंचायतों व उनमें आने वाली गांवों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## चित्तौड़गढ़ में वानिकी पर्यटन विकास की कार्ययोजना

**216. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2018-19 से अब तक वन संरक्षण के क्या-क्या कार्य किये गये व उक्त कार्यों पर कुल कितना व्यय किया गया एवं क्या-क्या भौतिक उपलब्धियां अर्जित हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वानिकी पर्यटन की क्या-क्या संभावना है एवं किन-किन क्षेत्रों में वानिकी पर्यटन विकसित हो सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्ष में उक्त जिले में वानिकी पर्यटन विकास के क्या-क्या कार्य किये गये एवं उक्त पर कितना-कितना व्यय किस-किस मद से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में वानिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अब सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कराये गये विकास कार्यों एवं व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट ए-1 से ए-3 अनुसार है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में वानिकी पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। संभावित स्थलों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी अनुसार है।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में वानिकी पर्यटन विकास अंतर्गत कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वानिकी पर्यटन पर राशि 7.90 लाख रुपये का व्यय बस्सी अभयारण्य अंतर्गत प्रवेश द्वार निर्माण हेतु किया गया है।

(4) जिला चित्तौड़गढ़ में वानिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा विभिन्न स्तर पर समय-समय पर प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-सी अनुसार है। प्रस्तावों की स्वीकृति उपरांत बजट उपलब्धतानुसार कार्य करवाये जा सकेंगे।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मनोहरथाना के पंजीकृत बेरोजगार

**217. श्री गोविन्द प्रसाद** (मनोहरथाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में कितनी महिलाओं तथा कितने पुरुषों को माह दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला रोजगार कार्यालय, झालावाड़ में 31 दिसम्बर, 2019 तक विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के कुल 4282 विभिन्न योग्यताधारी बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। उक्त पंजीकृत बेरोजगार में से स्नातक योग्यताधारी तथा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शर्तों को पूरा करने वाले कुल 528 बेरोजगार आशार्थियों को 31 दिसम्बर तक बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है जिनमें से 144 महिला तथा 384 पुरुष बेरोजगार आशार्थी हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। किन्तु शेष रहे समस्त बेरोजगारों को नहीं अपितु रोजगार कार्यालय में पंजीकृत स्नातक तथा मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार आशार्थियों को ही नियमानुसार वरीयता के आधार पर भत्ता देय है। वर्तमान में इस योजना में राज्य में एक वर्ष में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 1 लाख 60 हजार है तथा 31 दिसम्बर, 2019 तक राजस्थान में कुल 1 लाख 59 हजार 728 बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। किन्हीं कारणों से वर्तमान लाभान्वितों में से बेरोजगारी भत्ता बंद होने की स्थिति में ही निर्धारित अधिकतम सीमा तक वरीयता के आधार पर नई स्वीकृतियां संभव हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बस्सी में बनाये गए श्रमिक कार्ड

**218. श्री लक्ष्मण मीणा** (बस्सी): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत पांच वर्षों में किस-किस योजनान्तर्गत कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये तथा कितने श्रमिकों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों ने श्रमिक कार्ड हेतु आवेदन किये, उनमें से कितने प्रक्रियाधीन हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) असंगठित क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित अथवा निर्माण श्रमिकों का मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन किया जाता है। तत्पश्चात् मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने पर पात्रतानुसार लाभ दिया जाता है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विगत 5 वर्षों में कुल 6419 निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया। ग्राम पंचायतवार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा 2221 निर्माण श्रमिकों को मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित श्रमिकों का योजनावार व ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गत 5 वर्षों में कुल 11091 आवेदनकर्ताओं ने पंजीयन हेतु आवेदन किये। वर्तमान में हिताधिकारी के स्तर पर 3084 एवं विभाग के स्तर पर 419 आवेदन लंबित हैं। प्राप्त, स्वीकृत एवं लंबित पंजीयन आवेदनों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## श्रीडूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

**207. श्री गिरधारीलाल** (डूंगरगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

रीको द्वारा श्रीडूंगरगढ़ में 25 एकड़ भूमि पर अविकसित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था जिसमें कुल 36 भूखण्डों का नियोजन कर आबंटित किये गये हैं एवं वर्तमान में 25 औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं।

वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कोई भी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है।

यद्यपि जिला कलेक्टर बीकानेर के निर्देशानुसार वर्तमान में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के समीपस्थ रिक्त सरकारी भूमि की उपलब्धता पता करने के निर्देश की अनुपालना में संबंधित उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध होने वाली रिक्त भूमि चिह्नीकरण संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

## पचपदरा में लघु उद्योगों के लिए भूमि का आबंटन

**208. श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु जिला बाड़मेर की तहसील पचपदरा की ग्राम पंचायत पचपदरा एवं मण्डापुरा में विभाग के नाम भूमि आरक्षित एवं आबंटित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आबंटित भूमि पर लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं भूखण्ड आबंटन हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु ग्राम मण्डापुरा तहसील पचपदरा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ 103.02 बीघा भूमि जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा आरक्षित की हुई का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त भूमि पर औद्योगिक भूखण्ड आबंटन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित विवाद एवं शिकायत निवारण तन्त्र बैठक दिनांक 25.11.2019 में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देश दिया गया था कि उक्त भूमि संबंधी नक्शा एवं जमाबन्दी, रीको अधिकारी बालोतरा को प्रेषित कराएं, ताकि इस संबंध में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर आबंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा सके। इस क्रम में जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर द्वारा पत्र क्रमांक 3236 दिनांक 08.01.2020 द्वारा उक्त भूमि पर प्रदूषण रहित लघु एवं शिल्प कुटीर उद्योग लगाने बाबत उक्त भूमि की जमाबन्दी नकल एवं ट्रेस नक्शे की प्रति रीको बालोतरा को प्रेषित कर दी गई है। राज्य में उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019, रिप्स-2019, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 जारी कर दी गई है, जिनका लाभ लेकर उद्यमी इसमें उद्योग स्थापित कर सकेंगे।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## लघु सीमान्त किसानों को अंशदायी पेंशन देने की योजना

**209. श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वृद्ध किसानों को पेंशन दिये जाने की घोषणा की है? यदि हां, तो किस-किसको व कितनी-कितनी पेंशन राशि दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा बजट में उक्त पेंशन हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(4) प्रदेश के कितने वृद्ध किसानों को अब तक कितनी पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार लघु व सीमान्त किसानों को अंशदायी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा है, को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 के तहत निम्नलिखित दर से पेंशन देय हैः

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रति माह
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशन को रुपये 1000 प्रति माह

जारी नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2019 को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 जारी किए गए, जो दिनांक 1.03.2019 से प्रभावी हैं।

दिनांक 20.02.2020 को इस योजनान्तर्गत 2,77,670 लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 30,000.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत 2,77,670 किसानों को 16050.26 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) जी हां। राज्य में सहकारिता विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को अंशदायी पेंशन देने की योजना दिनांक 9 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत 32,709 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## टोंक में बीपीएल परिवारों के पुत्री विवाह में देय सहायता राशि

**210. श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला टोंक में बीपीएल परिवारों को पुत्री विवाह के अंतर्गत विगत दो वर्षों में कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन लंबित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लंबित आवेदनों पर कार्यवाही कर उक्त आवेदकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) टोंक जिले में विभाग के माध्यम से संचालित सहयोग एवं उपहार योजना अन्तर्गत विगत दो वर्षों में वर्ष 2017-18 में 310 आवेदकों एवं वर्ष 2018-19 में 224 आवेदकों कुल 534 आवेदकों की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। विधान सभावार लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। साथ ही वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में लाभान्वित परिवारों की विधान सभावार संख्या विवरण निम्नानुसार है:

1. टोंक विधान सभा 362
2. देवली-उनियारा विधान सभा 58
3. टोडा-मालपुरा विधान सभा 49
4. निवाई विधान सभा 65

(2) जी हां। वर्ष 2018-19 के 80 आवेदन पत्र आक्षेप में थे। आवेदकों द्वारा समय पर आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण लम्बित रहे।

(3) जी हां। लम्बित 80 आवेदन पत्रों के आक्षेपों की पूर्ति पश्चात् स्वीकृति जारी कर दी गयी है। बजट उपलब्धता पर शीघ्र आवेदकों को भुगतान कर दिया जाएगा। लम्बित आवेदनों का विधान सभावार विवरण निम्नानुसार हैः

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

| **क्र.सं.** | **विधान सभा का नाम** | **लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | टोंक | 79 |
| 2 | देवली-उनियारा | 1 |
| 3 | टोडा-मालपुरा | 0 |
| 4 | निवाई | 0 |

## बसेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

**211. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा** (बसेड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसेड़ी को 100 शय्या के चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी नहीं। बसेड़ी जिला धौलपुर में वर्तमान में 50 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वीकृत है। उक्त संस्थान पर स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2018 में शय्या उपयोगिता दर 53.55 प्रतिशत रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसेड़ी की शय्याओं में वृद्धि किया जाना विचाराधीन नहीं है।

## फलौदी के चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

**212. श्री पब्बाराम** (फलौदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कितने प्राथमिक व सामुदायिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों में सभी संवर्गों के अनेक पद रिक्त हैं? यदि हां, तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रक्रियाधीन भर्ती पूर्ण होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को स्थानान्तरण से भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जायेगा।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## दरा (सांगोद) में चिकित्सक का रिक्त पद

**213. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (सांगोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में विभाग में कुल कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि "ग्राम दरा" में चिकित्सक का पद लम्बे समय से रिक्त है? यदि हां, तो उक्त पद को कब तक भर दिया जाएगा?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के कुल 06 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

| **क्र.सं.** | **पद** | **रिक्त** |
|---|---|---|
| 1 | कनिष्ठ विशेषज्ञ | 1 |
| 2 | चिकित्सा अधिकारी | 05 |
| | **योग** | **06** |

विधान सभा क्षेत्र सांगोद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अराजपत्रित संवर्ग के कुल 112 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

| **क्र.सं.** | **पद नाम** | **रिक्त** |
|---|---|---|
| 1 | एलएचवी | 7 |
| 2 | लैब टैक्नीशियन | 8 |
| 3 | कनिष्ठ लेखाकार | 1 |
| 4 | महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक | 1 |
| 5 | प्रयोगशाला सहायक | 8 |
| 6 | प्रसाविका | 20 |
| 7 | संगणक | 1 |
| 8 | सहा. रेडियो | 6 |
| 9 | सहा. लेखाधिकारी द्वितीय | 1 |
| 10 | स्वीपर | 1 |
| 11 | वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन | 3 |
| 12 | वरिष्ठ सहायक | 3 |
| 13 | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 1 |
| 14 | वार्ड बाय | 16 |
| 15 | फार्मासिस्ट | 7 |
| 16 | तकनीकी सहायक | 3 |
| 17 | नर्स ग्रेड-1 | 14 |
| 18 | नर्स ग्रेड-2 | 11 |
| | **योग** | **112** |

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरा (मोरूकलां) में चिकित्सा अधिकारी का पद माह सितम्बर 2019 से रिक्त चल रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानान्तरण या राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से भर्ती प्रक्रिया से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर शीघ्र भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

## जोधपुर में यूनानी औषधालय की स्थापना

**214. श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जोधपुर जिले में नवीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन विहीन आयुर्वेद व यूनानी औषधालय कौन-कौनसे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त औषधालयों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला जोधपुर में 121 आयुर्वेद तथा 9 यूनानी औषधालय पूर्व से संचालित हैं।

निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कोई भी आयुर्वेद व यूनानी औषधालय भवन विहीन नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार कोई भी आयुर्वेद व यूनानी औषधालय भवन विहीन नहीं है।

## अजमेर में भामाशाह स्वास्थ्य योजनान्तर्गत स्वीकृत निजी अस्पताल

**215. श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भामाशाह स्वास्थ्य योजनान्तर्गत मरीजों के नि:शुल्क इलाज के लिए अजमेर शहर में कौन-कौनसे निजी अस्पताल अधिकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) उक्त निजी अस्पतालों में विगत एक वर्ष में कितने रोगियों ने उक्त योजनान्तर्गत इलाज करवाया? अस्पतालवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अस्पतालों द्वारा विगत एक वर्ष में उक्त योजनान्तर्गत किये गये इलाज की एवज में कितनी राशि के बिल पुनर्भरण हेतु सरकार को प्राप्त हुए तथा उनमें से कितना भुगतान किया गया व कितना शेष है? अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अस्पतालों को राशि का पुनर्भरण समय पर नहीं होने पर उनके द्वारा इलाज नहीं करने की चेतावनी दी गई है? यदि हां, तो इससे मरीजों को भविष्य में इलाज से वंचित करने का जिम्मेदार कौन होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अजमेर शहर के अधिकृत निजी अस्पतालों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त निजी चिकित्सालयों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत गत एक वर्ष में कुल 11,930 मरीजों का इलाज कर लाभान्वित किया गया है, जिनका अस्पतालवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत गत एक वर्ष में (दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2019 तक) अजमेर शहर के उक्त अधिकृत निजी अस्पतालों के द्वारा किये गये इलाज के एवज में बीमा कम्पनी को पुर्नभरण हेतु प्राप्त बिल, किये गये भुगतान व शेष भुगतान हेतु राशि की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## तिलम संघ का राजफैड में विलय की योजना

**216. श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या तिलम संघ राजस्थान की तेल पिराई परियोजनाएं कोटा, बीकानेर, गंगानगर, फतेहनगर, मेड़ता सिटी व गंगापुर वर्तमान में बंद हैं ? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उक्त बंद परियोजनाओं के कर्मचारियों एवं संसाधनों के नियोजन एवं निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(2) क्या सरकार राजफैड एवं तिलम संघ को समान प्रकृति के व्यवसाय होने के कारण विलय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार घाटे में चलने वाली सहकारी संस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु भविष्य के लिए कोई कार्ययोजना बनाकर उसको क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। कोटा परियोजना में वर्ष 2008-09 से, बीकानेर में वर्ष 2007-08 से, गंगानगर में वर्ष 2008-09 से, फतेहनगर में वर्ष 2014 से, मेड़ता सिटी में वर्ष 1998-99 से व गंगापुर सिटी में वर्ष 1998-99 से तेल पिराई कार्य बन्द है।

बंद परियोजनाओं गंगापुर सिटी एवं मेड़ता सिटी के संसाधनों के निस्तारण का निर्णय लिया जाकर गंगापुरसिटी परियोजना की प्लांट व मशीनरी का निस्तारण कर दिया गया है तथा मेड़तासिटी की भूमि व मशीनरी के विक्रय संबंधी वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निर्णय पश्चात् ही निस्तारण की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में संघ की गतिविधियों हेतु आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को पंचायती राज एवं अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/समायोजित करवाया गया है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) घाटे में चलने वाली सहकारी संस्थाओं के पुर्नर्निर्माण हेतु समय-समय पर संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्य योजना बनाई जाकर क्रियान्विति की जाती है।

## कार्यरत पैराटीचरों का नियमितीकरण

**217. श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के मदरसों में कुल कितने पैराटीचर कब से कार्यरत हैं तथा उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार उक्त मदरसों में कार्यरत पैराटीचर को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(2) क्या सरकार की पैराटीचरों की भर्ती करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में सन् 2001 से चरणवार कुल 5897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। चरणवार शिक्षा सहयोगियों की सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है। वर्तमान में शिक्षा सहयोगियों को चरणवार संविदा पर रखे जाने के फलस्वरूप न्यूनतम 7602 रुपये व अधिकतम 9475 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प. 5 (1) मम/2019/दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकीदास कल्ला, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में चाही गई सूचना दिनांक 14.03.2019 एवं 16.01.2020 को मंत्रीस्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है।

(2) वर्तमान में मदरसा बोर्ड में पैराटीचर्स की कोई भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## परबतसर में संचालित मदरसे

**218. श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर के कौन-कौनसे गांवों में मदरसे संचालित हैं? उक्त में कितने विद्यार्थी तालीम प्राप्त कर रहे हैं? मदरसेवार तालीम प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कौन-कौनसे मदरसों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि अनुदान हेतु दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में जन सहभागिता के आधार पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी राशि कौन-कौनसे मदरसों को दान दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनिवास गावड़िया)

(4) उक्त दान राशि के आधार पर उक्त वित्तीय वर्षों में कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कौन-कौनसे मदरसों में कार्य किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में संचालित मदरसों व उनमें तालीम प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में संचालित मदरसों को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में (दिनांक 18.02.2020 तक) नकद अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में परबतसर विधान सभा के सभी मदरसों में स्टील फर्नीचर तथा मदरसा गरीब नवाज, शेरानियों की ढाणी ग्राम पोस्ट पीपलाद तहसील परबतसर, जिला नागौर, पंजीयन संख्या 2836 को ड्यूल डेस्क एवं बैंच दी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में परबतसर विधान सभा क्षेत्र के सभी मदरसों में स्पोर्ट्स सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।

(3) उक्त क्षेत्र में जन सहभागिता योजना अन्तर्गत जन सहयोग की किसी भी मदरसे द्वारा मदरसा बोर्ड में राशि जमा नहीं करवाई गयी है।

(4) उक्त मदरसों से मदरसा बोर्ड को राशि प्राप्त नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का कार्य करवाया जाना शेष नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नोखा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

**219. श्री बिहारीलाल** (नोखा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निजी भवनों में संचालित उक्त केन्द्रों को भी सरकारी भवनों में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र नोखा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा के अन्तर्गत दो परियोजना क्रमशः नोखा एवं पांचू संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की स्थिति निम्नानुसार है-

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** | **कुल संचालित केन्द्र** | **किराये के भवनों में संचालित** |
|---|---|---|---|
| 1. | नोखा | 172 | 16 |
| 2. | पांचू | 137 | 21 |
| | **योग** | **309** | **37** |

इसके अन्तर्गत परियोजना नोखा में 16 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना पांचू मे 21 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(3) विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में विदयुत कनेक्शन हेतु बजट का प्रावधान नहीं है। विधान सभा क्षेत्र नोखा में संचालित परियोजना नोखा में 29 आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा परियोजना पांचू में 30 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्य संसाधनों से विदयुत कनेक्शन हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन

**220. श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार सप्लाई बाबत विभाग द्वारा आदेश व परिपत्र जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या उक्त के अनुसार पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के संबंध में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? यदि हां, तो कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए तथा कितनों में गठन किया जाना शेष है व उक्त का गठन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। आंगनबाड़ी केन्दों पर पोषाहार वितरण हेतु आदेश/परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं उसी अनुरूप पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। उक्त के सम्बन्ध में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 58 हजार 916 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 67 हजार 781 (टेक होम राशन एवं गर्म पूरक पोषाहार आपूर्ति हेतु) स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 2579 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये स्वयं सहायता समूहों का गठन किये जाने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## थानागाजी के जनजाति बहुल क्षेत्र को टीएसपी योजना का लाभ

**221. श्री कान्ति प्रसाद** (थानागाजी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के जनजाति बहुल क्षेत्र को टीएसपी योजनान्तर्गत लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। थानागाजी विधान सभा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना अन्तर्गत योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

## तहसील स्तर पर टीएसपी केन्द्र की स्थापना

**222. श्री समाराम गरासिया** (पिण्डवाडा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार टीएसपी मुख्य कार्यालय उदयपुर के अतिरिक्त तहसील मुख्यालय स्तर पर भी टीएसपी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्यालय उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आबूरोड में स्थापित है।

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में तहसील स्तर पर टीएसपी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से प्रदूषण

**223. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (नेता, प्रतिपक्ष): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर स्थित मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित कौन-कौनसी फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैल रहा है? क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है? यदि हां, तो वर्ष 2017, 2018 व 2019 की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदूषण मंडल ने मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कुछ फैक्ट्रियों को प्रदूषणात्मक मानते हुए बंद करने की घोषणा की है? यदि हां, तो किस-किसको और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जो सरकार की बंद सूची में होते हुए भी संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) उदयपुर स्थित मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गत तीन वर्षों क्रमश: 2017, 2018 व 2019 में कुल 15 उद्योगों को प्रदूषण फैलाते हुए पाया गया, जिनकी सूची एवं जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गत तीन वर्षों क्रमश: 2017, 2018 व 2019 में कुल 5 उद्योगों को प्रदूषणात्मक मानते हुए जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बन्द कराने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी उद्योग संचालित नहीं है, जिनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बन्द कराने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जोधपुर में हिरणों की हत्या के दर्ज मुकदमे

**224. सुश्री दिव्या मदेरणा** (ओसियां): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में पिछले पांच वर्षों में कुल कितने हिरणों का शिकार हुआ तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध हिरणों की हत्या के मुकदमे दर्ज हुए? उक्त दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशु-पक्षियों की हत्या रोकने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जोधपुर जिले में विगत 5 वर्षों में शिकार हुए हिरणों की संख्या, दर्ज प्रकरण एवं प्रकरणों की वर्तमान स्थिति संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी नहीं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू है, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। उक्त प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के क्रम में उपलब्ध स्टाफ द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित गश्त की जाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आवश्यकता होने पर पुलिस की मदद भी ली जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जसवन्तपुरा (जालोर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रारम्भ करने की योजना

**225. श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड जसवन्तपुरा मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का भवन बनकर तैयार है किन्तु अनुदेशकों की नियुक्ति के अभाव में बन्द है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड जसवन्तपुरा मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), जसवन्तपुरा का भवन बनकर तैयार है एवं राज्य में समस्त संचालित एककों में अनुदेशकों के रिक्त पद का कार्य गेस्ट फेकल्टी के माध्यम से किये जाने की अनुमति जारी की जा चुकी है। नियमित भर्ती के संदर्भ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर नियमित कार्मिकों के पदस्थापन की कार्य्रवाही की जायेगी।

वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जसवंतपुरा का संचालन राजकीय आईटीआई जालोर में वर्ष 2018 से किया जा रहा है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जसवंतपुरा के भवन हैण्डओवर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगामी प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में संस्थान स्वयं के भवन में संचालित किया जायेगा।

## उदयपुर में तहसील मुख्यालयों पर स्टेडियम का निर्माण

**226. श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर की किस-किस तहसील मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के लिये भूमि आबंटित नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खेल स्टेडियम से वंचित तहसील मुख्यालयों पर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) उदयपुर जिले की बडगांव, झाड़ोल तहसील मुख्यालय पर खेल विभाग को भूमि आबंटित की गयी है। शेष तहसीलों में विभाग के नाम जमीन आबंटित नहीं है। अपितु शिक्षा विभाग को सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया, फलासिया, गोगुन्दा, भीण्डर, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, कोटड़ा, मावली, झल्लारा, बम्बोरा, सायरा, गिर्वा एवं वल्लभनगर में भूमि आबंटित है।

(2) जी हां। समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

माननीय सांसदों द्वारा सांसद निधि कोष एवं माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद से राशि उपलब्ध करवाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है।

स्टेडियम निर्माण के निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।

## सिरोही में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के लाभार्थी

**227. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत सिरोही जिले में 2019-20 में युवाओं ने आवेदन किया था? यदि हां, तो उक्त योजनान्तर्गत कितने युवाओं को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु सिरोही जिले में वर्ष 2019-20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक 3012 पूर्ण भरे गये ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले 1947 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है।

## झुंझुनूं में औद्योगिक संस्थाओं में वर्क्स कमेटियों का गठन

**228. श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झुंझुनूं में कौन्कौनसे औद्योगिक संस्थाओं में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत वर्क्स कमेटियों का गठन किया हुआ है एवं कौन-कौनसे औद्योगिक संस्थाओं ने उक्त नियमों के आधार पर कमेटियां गठित की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कमेटियों के चुनाव समय पर हो रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुभाष पूनियां)

(3) वर्ष 2018-19 व 2019-20 में किन-किन औद्योगिक संस्थानों के विरुद्ध श्रमिकों ने क्या-क्या शिकायतें दर्ज करायी हैं? क्या उक्त शिकायतों को दर्ज किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाली औद्योगिक संस्थाओं में वर्क्स कमेटियों का गठन करने का प्रावधान है। झुंझुनूं जिले में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्क्स कमेटी का गठन किया हुआ है।

(2) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, झुंझुनूं संस्थान में गठित उक्त वर्क्स कमेटी का गठन दिनांक 03.06.2019 को किया गया था। संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार समय पर चुनाव करवाये जा रहे हैं। झुंझुनूं जिले में अन्य किसी औद्योगिक संस्थान में वर्क्स कमेटी गठित नहीं है।

(3) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2018-19 में झुंझुनूं जिले में वर्क्स कमेटी के गठन को लेकर कोई शिकायत दर्ज प्राप्त नहीं हुई। झुंझुनूं कार्यालय में निम्न औद्योगिक संस्थानों के विरुद्ध श्रमिकों ने निम्न शिकायतें दर्ज करवायी है तथा कार्यालय द्वारा उन सभी शिकायतों को दर्ज किया गया।

**वर्ष 2018-19:-**

1. रजिस्ट्रार बी.आई.टी.एस. पिलानी के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति की दो शिकायतें,
2. मैसर्स जानी स्पोट आउटसोर्सिंग प्रा. लि. जरिये आईडीबीआई बैंक के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति एवं ओवर टाइम,
3. रिलायंस नियोन लाइफ इंश्योरेन्स के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति।

**वर्ष 2019-20:-**

1. महादेव सिन्धी नेत्र चिकित्सालय, पिलानी के खिलाफ सेवा से पृथक करने बाबत,
2. ALKEM LABORATORIES LTD. के खिलाफ स्थानान्तरण
3. व्यवस्थापक होटल सारा विलास के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति एवं वेतन भुगतान

(राज्य मंत्री, श्रम)

4. व्यवस्थापक, होटल अलसीसर महल अवैध सेवा मुक्ति एवं वेतन भुगतान

5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं सदस्य सचिव जिला मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, रा.बी.डी.के. अस्पताल, झुन्झुनूं एवं प्रबन्धक, श्यामपुरा जनकल्याण एवं गौ विकास समिति, झुन्झुनूं के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति बाबत

6. ASTER PVT. LTD. के खिलाफ वेतन भुगतान बाबत

7. मैसर्स अनुपमा ट्रेडिंग कम्पनी, गड़जी का बास, हेतमसर के खिलाफ वेतन भुगतान बाबत

8. यूनीटेक पावर ट्रान्समिशन लि. के खिलाफ वेतन भुगतान बाबत

9. मैसर्स रायल कनस्ट्रशन कम्पनी के खिलाफ वेतन भुगतान बाबत

10. एच.डी.बी. फाइनेंशल सर्विस प्रा. लि. के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति एवं वेतन भुगतान

11. निशा इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जरिये मैनेजर एक्सीस बैंक, मुकुन्दगढ़ के खिलाफ अवैध सेवा मुक्ति एवं वेतन भुगतान

12. वर्कशाप इंचार्ज, गहलोत मोटर्स प्रा. लि., झुंझुनूं के खिलाफ सेवा मुक्ति बाबत।

## कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पद

**229. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं संबद्ध राजकीय महाविद्यालय में टीचिंग और नान टीचिंग के कुल कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक कितनी बार भर्ती प्रक्रिया हुई तथा उसमें किन-किनको नियुक्ति दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भर्ती प्रक्रियाओं से विश्वविद्यालय को कितना राजस्व मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(4) सरकार द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा सहित संबद्ध महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में टीचिंग और नान टीचिंग के कुल रिक्त पदों का विभागवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त विश्वविद्यालय, कोटा से संबद्ध राज्य अन्तर्गत स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में टीचिंग और नान टीचिंग के कुल रिक्त पदों का विभागवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से लेकर अभी तक छह बार (वर्ष 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2018) भर्ती प्रक्रिया हुई। नियुक्ति संबंधी विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) उक्त भर्ती प्रक्रियाओं से विश्वविद्यालय को रुपये 1,06,20,286/- (रुपये एक करोड़ छह लाख बीस हजार दो सौ छियासी मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है। वित्त विभाग की सहमति अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार रिक्त पदों को भरे जाने हेतु आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य अन्तर्गत स्वायत्तशाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्राचार्यों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, अन्य शैक्षणिक पदों की भर्ती के क्रम में गाइड लाइन बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट का परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जा सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में संचालित संस्कृत महाविद्यालय

**230. श्री सतीश पूनियां** (आमेर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में संस्कृत शिक्षा हेतु कितने महाविद्यालय संचालित हैं? जिलेवार, नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सतीश पूनियां)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा हेतु संचालित महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने और कब से? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की अंतिम बार भर्ती कब की गई थी? क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन वर्तमान में 12 राजकीय आचार्य एवं 18 राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्राचार्य आचार्य के वर्ष 2013-14 से, प्राचार्य शास्त्री के वर्ष 2000-2001 से तथा व्याख्याता के वर्ष 2004-05 से पद रिक्त हो रहे हैं।

(3) व्याख्याता के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर वर्ष 2005 में नियुक्ति की गई थी।

वर्तमान में राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियमों के अधिसूचित किए जाने के उपरान्त रिक्त पदों के भरे जाने के लिए भर्ती/चयन प्रक्रिया सम्भव हो सकेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# परिशिष्ट

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

### आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार की राशि में बढ़ोतरी

महोदय,

महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत तीन से छह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को गरम पूरक पोषाहार में दलिया एवं खिचड़ी तथा नाश्ते में चावल, मुरमुरे, गुड़ चना और हलवा उपलब्ध कराया जा रहा था। इस हेतु नाश्ते के लिए प्रतिदिन साढ़े 3 रुपये और भोजन के लिए साढ़े 4 रुपए निर्धारित किए गए हैं लेकिन सरकार द्वारा अब उक्त कीमत पर ही रेसिपी में परिवर्तन किया गया है। बदले हुए नाश्ते में सोमवार को पका केला या मौसमी फल और गरम पोषाहार में गेहूं मूंग का मीठा दलिया, मंगलवार को पका केला या मौसमी फल, रोटी-सब्जी और दाल, बुधवार को 100 एमएल दूध, चावल मूंग की खिचड़ी, गुरुवार को 55 ग्राम गर्मी में बेसन, सर्दी में तिल के लड्डू एवं चावल, चना व लौकी, शुक्रवार नींबू और टमाटर के साथ मुरमुरे/पोहा, बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी चावल तथा शनिवार को अंकुरित दाल, आंवला चटनी या नींबू के साथ खिचड़ी देने का प्रावधान किया गया है।

उक्त पोषाहार के लिए पूर्व मे निर्धारित राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विरोध किया गया है। कीमत नहीं बढ़ाने की स्थिति में विभागीय स्तर पर पोषाहार वितरण करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। हम भी यह भली प्रकार जानते हैं कि आठ रुपये में उक्त सामग्री भोजन एवं नाश्ते में नहीं दी जा सकती आज एक लीटर दूध 40 रुपये में आता है, यदि एक बालक को 100 एमएल दूध दिया गया तो उसका मूल्य चार रुपये होगा जबकि विभाग साढ़े तीन रुपये दे रहा है। यदि उन्हें वास्तव में उक्त रेसिपी के अनुसार पोषाहार देना है तो दरों को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा, नहीं तो बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पायेगा।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि उक्त दरों में शीघ्रताशीघ्र परिवर्तन कर नाश्ते हेतु आठ रुपये एवं भोजन हेतु दस रुपये निर्धारित किये जाएं।

**अनिता भदेल**

(अजमेर दक्षिण)

# नीमराना उप खण्ड पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे अलवर जिले का विश्व विख्यात औद्योगिक क्षेत्र फोर्ट, कुए, बावड़ी आदि के कारण विश्व के पर्यटन मैप पर स्थित नीमराना उपखण्ड पर वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं होने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

नीमराना में तहसील का प्रथम दर्जा सन् 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किया गया एवं तहसील एवं उप खण्ड न्यायालय की स्थापना की गई तथा एक ग्राम न्यायालय भी स्थापित किया गया। नीमराना उपखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत तीन पुलिस थाने क्रमश: नीमराना, शाहजहांपुर, मांढण आते हैं तथा नीमराना क्षेत्र हरियाणा की सीमा से जुड़ा हुआ है जिसके कारण आये दिन अपराध की बढ़ोतरी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। नीमराना उपखण्ड के लगभग 3500 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लगभग 3500 फौजदारी एवं दीवानी मुकदमे बहरोड़ के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिससे जनता को लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी तय कर बहरोड़ न्यायालय में जाना पड़ता है जिससे जनता के समय व धन दोनों की बर्बादी होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि नीमराना उपखण्ड पर उक्त न्यायालय स्थापित किये जाने के लिए भवन की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि पहले से ही पुराना तहसील भवन खाली पड़ा हुआ है।

राजस्थान में नीमराना उपखण्ड को छोड़कर सभी उपखण्ड स्तर पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हैं तथा 1100 मुकदमों पर उक्त न्यायालय खोलने जाने का प्रावधान है जबकि यहां पर 3500 के लगभग प्रकरण हैं।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि नीमराना में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खोले जाने की इस बजट में घोषणा कर जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरी करने की कृपा करें।

**बलजीत यादव**

(बहरोड़)

## आसपुर में स्वीकृत एनिकटों के रोके कार्य को चालू करवाना

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा आसपुर जिला डूंगरपुर में दो एनीकट वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुए हैं। सोनार माता एनीकट का बजट 955 लाख था व मांडवा खापरवाडा दांता वाला एनीकट पं.स. दोवड़ा में टीएडी मद से स्वीकृत हुए थे व पूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा शिलान्यास भी कर दिया था, बाद में कांग्रेस की सरकार बनते ही दोनों कार्यों को रोक दिया है जिससे जनता को भारी ठेस पहुंची है कि इन एनीकटों से क्षेत्र के काश्तकारों को सिंचाई का लाभ मिलता व आस पास के कुंऐ व हैण्डपंपों में भी जल स्तर बढ़ता तो क्षेत्र में खुशहाली होती।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इन दोनों एनिकटों का निर्माण कार्य कराने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

**गोपीचंद मीणा**

(आसपुर)

## अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हो रही समस्या

महोदय,

उपरोक्त विषय मे लेख इस प्रकार है कि पांचवीं अनुसूची के प्रावधान सिर्फ जनजातियों के लिये है। संविधान की कल्पना थी कि जनजाति इलाकों में गवर्नेंस का रोल राज्यपाल का हो और जनजाति सलाहकार परिषद् की प्रमुख भूमिका हो, जिससे जनजातियों का स्वशासन बना रहे। सामान्य क्षेत्र की पंचायती राज व्यवस्था से अनुसूचित क्षेत्र में इसकी कल्पना अलग थी लेकिन एक लाठी से हांका जा रहा है। अंग्रेजों ने भी सामान्य कानून जनजातियों पर लागू नहीं किये थे। अनुसूचित क्षेत्र मे संसद या विधान सभा का कोई कानून सीधे लागू नहीं होता है या लागू होगा तो जनजातियों की प्रथाओं, परम्पराओं, उनकी संस्कृति का संरक्षण करते हुए भविष्यलक्षी हितों के अनुसार होगा। पूर्व सरकार के समय जनजाति सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष पद जनजाति से गैर जनजाति बना दिया गया है। टी.ए.सी. मे 20 से अनअधिक सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें तीन-चौथाई सदस्य विधान सभा के जनजाति प्रतिनिधि

होंगे, भरे जाने वाले स्थानों से कम होने पर शेष सदस्य भी जनजातियों से भरे जाने का प्रावधान है। 14 माह बाद भी टी.ए.सी. का गठन और बैठक नहीं होना गम्भीर बात है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूं कि जनजाति सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष पद जनजाति को ही दिया जाये ताकि किसी भी समस्या के बारे में सरकार को आवश्यक सलाह दे सके।

**रामप्रसाद**

(सागवाड़ा)

## रेवदर ब्लाक में विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण किसानों व आमजन को हो रही परेशानी

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि कृषि प्रधान रेवदर ब्लाक में बड़ी संख्या में कृषि कनेक्शन, व्यावसायिक एवं घरेलू विद्युत कनेक्शनों के साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रतिदिन विद्युत मांग की तुलना में नित्य प्रति शोर्ट विद्युत सप्लाई दिये जाने की मार से किसान वर्ग बुरी तरह से आहत है। किसान की फसल की बुआई के बाद से ही मांग के अनुरूप विद्युत सप्लाई के अभाव में किसानों की फसल सूख कर बर्बाद हो रही है। अन्य सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ता भी बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की चिकित्सा, शिक्षा व सामाजिक कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ आम जन को समय पर नहीं मिल पा रहा है। लगभग सभी कार्यालयों में डिजीटल वर्क ठप पड़ा रहता है।

किसान वर्ग आये दिन धरने प्रदर्शन पर उतारू हैं। क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से की गई घोषणाओं एवं विभिन्न योजनान्तर्गत आबंटित बजट व निर्धारित लक्ष्य अपर्याप्त विद्युत सप्लाई से पिछड़ते ही जा रहे हैं। लम्बे समय से किसान एवं सभी वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए किये गये सर्वे में विद्युत विभाग के इंजीनियर्स ने रेवदर ब्लाक पर 220 केवी जीएसएस स्थापना की फिजीबिलिटी को भी उचित करार दिया हुआ है।

अतः समूचे रेवदर ब्लाक में फसल के समय नित्य प्रति विद्युत की

शोर्ट सप्लाई, विद्युत की अनुपलब्धता, सभी श्रेणी के विद्युत उपभोग में भारी विद्युत कंजम्पशन, खपत के चलते रेवदर ब्लाक के किसान वर्ग की गंभीर पीड़ा को समझते हुए रेवदर ब्लाक में डिजीटलाइज्ड सरकारी सेवाओं, सरकारी सहायता, पेंशन, छात्रवृत्तियां आदि सरकारी योजनाओं, स्कीम्स का आमजन को उचित समय सीमा में लाभ देना, उद्योग एवं व्यापार व्यवसाय की अग्रेतर प्रगति के लिए इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को कारगर बनाने, स्कूली, कालेज स्तर के छात्रों, प्रतियोगी युवा वर्ग के उज्ज्वल भविष्य के लिये अबाधित रूप से पर्याप्त विद्युत सप्लाई हेतु रेवदर ब्लाक में एक 220 केवी जीएसएस स्थापित किये जाने की कार्यवाही करवाकर अनुगृहीत करावें।

**जगसी राम**

(रेवदर)

## ब्यावर के श्रम कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण

महोदय,

निवेदन है कि श्रम कार्यालय ब्यावर में काफी समय से अधिकारियों/ कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों के इस कार्यालय से संबंधित कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारी नहीं होने के कारण शुभशक्ति योजना एवं श्रमिक कार्ड बनाने सहित अन्य कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण आम गरीब मजदूर को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्रमिक कार्ड बनाने हेतु हजारों की संख्या में आवेदन लंबित हो गये हैं।

यहां पर अधिकारियों की कमी के चलते दलाल बहुत ही सक्रिय हो रखे हैं। जिन दलालों ने कार्यालय सेवा शुल्क पहुंचा दिया है उसका काम प्राथमिकता से कर देते हैं, जबकि गरीब का कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि श्रम कार्यालय ब्यावर में शीघ्रातिशीघ्र अधिकारी लगाकर आम जनता को राहत पहुंचाएं तथा दलालों से मिलकर सेवा शुल्क वसूलने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कष्ट कराएं।

**शंकर सिंह रावत**

(ब्यावर)

## सीकरी तहसील में उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में केवल एक उपखण्ड कार्यालय है जो कि कस्बा नगर में स्थित है तथा सीकरी तहसील में लगभग 17 पंचायतें हैं, जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है। यहां कृषि मण्डी, सी.एच.सी., 132 के.वी. जीएसएस, पुलिस थाना आदि पर्याप्त सुविधाएं हैं। इस उपखण्ड कार्यालय पर आबादी के अनुपात अत्यधिक कार्यभार है और कुछ ग्राम पंचायतें 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं और उनके कार्य अवरुद्ध होते हैं। जन भावनाओं एवं परेशानियों को देखते हुए सीकरी तहसील में एक उपखण्ड कार्यालय खुलवाने से यहां की ग्रामीण जनता को राहत प्रदान होगी।

**वाजिब अली**

(नगर)

## सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी निर्माण करवाया जाना

महोदय

उपरोक्त विषान्तर्गत मैं आपका ध्यान सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए उनकी चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में दिलवाना चाहती हूं। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत तो की जाती है लेकिन इनकी सुरक्षा हेतु चारदीवारी के लिए कोई भी बजट नहीं दिया जाता है। भवन के आस पास की जमीन चारदीवारी के अभाव में खुली रहती है जिस पर दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है जिसको बाद में खाली करवाना काफी मुश्किल होता है।

अतः सरकारी भवनों के निर्माण हेतु बजट के साथ ही चारदीवारी के निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत करने की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

धन्यवाद।

**जाहिदा खान**

(कामां)

## राज्य में गौ तस्करों के विरुद्ध कठोर कानून का निर्माण

महोदय,

प्रदेश में इस समय गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गौ तस्कारों के हौंसले बुलन्द हैं। वर्ष 2011 से 2015 तक तस्करों के विरुद्ध सैकड़ों मामले दर्ज किए गये किन्तु 2015 के बाद प्रशासन के भरोसे इसमें कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

हरियाणा पंजाब बोर्डर क्षेत्र से रोजाना गौ तस्करी के वाहन सैकड़ों की संख्या में गुजर रहे हैं। हाइटेक गौ तस्करी हो रही हैं। बन्द बाडी कन्टेनर बन्द बाडी ट्रक से गौतस्करी हो रही है। प्रदेश से देशी नस्ल का गौवंश तस्करी कर ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने आंख बन्द कर मौन धारण कर रखा है।

कई बार दबाव में प्रशासन इनको पकड़ तो लेता है फिर भी दबाव में आकर इनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। गौ तस्करों को पकड़ा जाता है। इसके पश्चात् काफी स्थानों पर पुलिस द्वारा गौ वंश की स्थानीय गौशाला मे रखने के लिए भेजती है। लेकिन स्थानीय गौशालाएं इन्हें रखने से मना कर देती हैं। सरकार पकड़े गये गौवंश को रखने के लिए कोई व्यवस्था करे एवं इसके लिए स्थानीय उपखण्ड स्तर पर नन्दी शाला खोली जाकर व्यवस्था कराये।

गौ तस्करी का कार्य मुख्यतः धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों से हरियाणा, पंजाब बोर्डर के माध्यम से रोजाना तस्करी हो रही है। सरकार द्वारा संवेदनशीलता नहीं दिखाने के कारण ये लोग छूट जाते हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कानून बनाये एवं शीघ्र मुकदमा दर्ज करवाकर गैर जमानती कानून बनाया जाए।

**धर्मेन्द्र कुमार**

(पीलीबंगा)

## जोधपुर नगर निगम द्वारा राज्य सरकार के बिल्डिंग बायलाज के विरुद्ध पार्किंग शुल्क में वृद्धि

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने दिनांक 24.10.2018 को गजट नोटिफिकेशन के जरिये नई बिल्डिंग के बाईलाज लागू किये जिनमें भूखण्डों की

पार्किंग शुल्क 75,000/- प्रति ई.सी.यू. तय किया गया। वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर भी पार्किंग शुल्क 75,000/- प्रति ई.सी.यू. चार्ज ले रहा है। लेकिन नगर निगम जोधपुर की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करके दिनांक 24.11.2017 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा पार्किंग शुल्क में वृद्धि करके 5.00 लाख रुपये प्रति ई.सी.यू. कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है।

कृपया जनहित में इसे पुनः 75,000/- प्रति ई.सी.यू. कर आमजन को राहत प्रदान कराएं। सादर,

**मनीषा पंवार**

(जोधपुर)

## कुशलगढ़ में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र जिला बांसवाड़ा से चुनकर आती हूं। मैं आपका ध्यान 2008 से 2013 माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा कुशलगढ़ में कृषि उपज मण्डी खोलने हेतु 03 करोड़ की घोषणा की थी। आज तक यह कृषि मण्डी नहीं खुली है। मेरा क्षेत्र मध्यप्रदेश, गुजरात राज्य से जुड़ा होकर राजस्थान के दक्षिणी भाग जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित है। 100 किमी. की परिधि में कोई भी कृषि उपज मण्डी नहीं है। यहां पर बड़ी मात्रा में अनाज मक्का, गेहूं, सोयाबीन, चना तथा दालें उत्पन्न होती हैं। किसानों को कृषि मण्डी नहीं होने से अपने अनाज को बेचने के लिये पड़ौसी राज्यों में जाना होता है जहां पर भी किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। किसान काफी परेशान है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा कराएं जिससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके तथा अन्य राज्यों में नहीं भटकना पड़े।

**रमीला खड़िया**

(कुशलगढ़)

## संगरिया की ग्राम पंचायत डबलीखुर्द में पम्पिंग स्टेशन का विद्‌युत बिल सरकार द्‌वारा वहन किया जाना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं संचालन नियम, 295 के जरिये आपका ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र संगरिया की ग्राम पंचायत डबली खुर्द में इन्दिरा गांधी नहर की आर.डी. 19 पर बायीं तरफ लगे पम्पिंग स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। इस ग्राम पंचायत में इन्दिरा गांधी नहर की सीपेज का पानी लगभग 38 वर्षों से 8 फुट तक का भराव कृषि भूमि में हो गया था। इस पानी की निकासी के लिए विशेषज्ञों से राय लेकर एक पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ग्राम की "डबलीखुर्द विकास सेवा समिति" के माध्यम से किया गया तथा उस पानी को उठाकर नहर में डाल दिया गया, जिससे भूमि पर दोबारा काश्त होने लगी। उस समय बिजली का बिल कम आता था, जिसे विकास समिति द्‌वारा चुका दिया जाता था। अब उक्त बिल 9 रु. प्रति यूनिट के हिसाब से आने की वजह से किसान उक्त पम्पिंग स्टेशन के बिल को भरने में असमर्थ है। इस कारण पम्प एक वर्ष से बन्द पड़े हैं व पानी पुनः एकत्रित हो रहा है और कृषि भूमि को बर्बाद कर रहा है। यदि उक्त विद्‌युत बिल का भुगतान राज्य सरकार द्‌वारा करवा दिया जाए तो ग्राम के अनेकों किसान अपनी कृषि भूमि पर काश्त कर सकेंगे तथा कृषि भूमि बर्बाद होने से बच जायेगी।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत डबलीखुर्द के पम्पिंग स्टेशन का सरकारीकरण करवाकर इसका संचालन सरकार द्‌वारा अपने स्तर पर करवाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

**गुरदीप सिंह**

(संगरिया)

## व्यापारियों को मण्डी टैक्स से मुक्ति

महोदय,

निवेदन है कि गुड़, शक्कर, घी व अरण्डी पर गुजरात की सीमा से सटे सिरोही, पाली व जालौर जिले के व्यापारियों को मण्डी टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि गुजरात में इन पर किसी तरह का मण्डी टैक्स नहीं है। इस कारण ज्यादातर व्यापारी मजबूरी में बिना बिल गुजरात से माल लाते हैं और बेचते हैं। इस तरह राज्य सरकार को करोड़ों रुपये जी एस टी का नुकसान हो रहा है। यदि कोई व्यापारी बिल से इन वस्तुओं को लाये तो उसे बिना बिल लाने वाले

व्यापरी की तुलना में महगा पड़ता है और प्रतिस्पर्धा में वह टिक नहीं सकता। मजबूरी में उसे भी बिना बिल के माल लाना पड़ता है। इस तरह करोड़ो रुपये का राजस्व नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है। बिना बिल के माल पकड़ा भी जाता है तो अधिकारी अपना हित साधते हैं और व्यापारी को दोहरी मार झेलनी पड़ती है।

सिरोही जिला व्यापार महासंघ का प्रतिनिधि मण्डल मुझे मिला और इस संबंध में गुड, शक्कर, घी व अरण्डी से मण्डी टैक्स हटाने का ज्ञापन दिया। मैने कृषि विपणन निदेशक से दूरभाष पर बात की और उन्हें ज्ञापन की प्रति भेजी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि गुड़ घी, शक्कर व अरण्डी से आगामी बजट में टैक्स हटाने की कृपा करें।

**संयम लोढ़ा**

(सिरोही)

## फुलेरा में अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों एवं कस्बों में माह दिसम्बर, 2019 में भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि हुई जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। किसानों द्वारा विभिन्न स्तरों पर नष्ट हुई फसल के मुआवजे हेतु ज्ञापन देकर एवं अन्य माध्यमों से अपनी मांग पहुंचाकर मुआवजे की मांग की गई परन्तु आज दिनांक तक फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

महोदय, मेरे क्षेत्र के अधिकतर गांवों में लोगों का आजीविका का मुख्य साधन खेती है और अतिवृष्टि से सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा अभी तक सुनवाई नहीं करने से किसानों में रोष व्याप्त है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अतिवृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने की स्वीकृति शीघ्र जारी कर मुआवजा वितरित कर किसानों को राहत प्रदान करें।

धन्यवाद।

**निर्मल कुमावत**

(फुलेरा)

## गढ़ी में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के अन्तर्गत गढ़ी, अरथूना, जौलाना, परतापुर, खोडन, पालोदा, सरेडी बड़ी, तलवाडा, बोरी, आदि क्षेत्रों में आए दिन चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों द्वारा मोटरसाइकिल, पानी की मोटर, भैंसें एवं घरों व केबिनों एवं बड़े बाजारों में दुकानों के ताले तोड़कर चोरियां रोजाना कहीं न कहीं हो रही हैं तथा गिरोह ने क्षेत्र के किसानों के कृषि कनेक्शन की डी.पी. भी बोरी बिलोदा क्षेत्र में चोरी की है। सम्पूर्ण क्षेत्र में आम जनता में चोरों से भय का माहौल बना हुआ है, लोग रात्रि में गश्त का काम सम्भाल रहे हैं। खोडन पालोदा क्षेत्र में रात्रि में चोरों से भिड़न्त के मामले सामने आए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी गांव में गश्ती दल से कहीं न कहीं मुकाबला हो रहा है, जिससे क्षेत्र में विशेष टोली बनाकर रात्रि में पुलिस गश्ती दल बनाकर क्षेत्र में शान्ति कायम रखना आवश्यक है। इसी प्रकार गढ़ी क्षेत्र में आए दिन सरे आम दिन-दहाड़े हत्याएं, लूट, बलात्कार, मारपीट के मामलों की दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। वर्तमान गढ़ी क्षेत्र मे एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर मार दिया एवं नथैली के पास नहर में लाश पायी गई, जिसका खुलासा नहीं हुआ है।

इसी प्रकार बोरी गांव के पास हथोलिया तालाब की नहर में नवयुवक की हत्या कर लाश फेंक दी जिसका आज दिन तक पता नहीं चला है। अरथूना थाना क्षेत्र ओडया में एक पशु चरवाह महिला की दिन दहाड़े लूट-पाट एवं बलात्कार कर हत्या कर दी जिसका आज तक पता नहीं चला है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय एवं आक्रोश है। एसी बड़ी-बड़ी घटनाएं होने के बाद भी अपराधी घूम रहे हैं। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्याएं आदि घटनाएं दिन दहाड़े हो रही हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर निवदेन है कि समय रहते आमजन में विश्वास पैदा कर सुरक्षा बढ़ाई जाये एवं घटनाओं का खुलासा कराया जाये जिससे जनता में शान्ति बनी रहे।

**कैलाश चन्द्र मीणा**

(गढ़ी)